संपादकीय

नई दिल्ली, सोमवार 7 अक्टूबर 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

अब महाराष्ट्र की बारी ?

10 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का शासन, किसान आंदोलन के दौरान अन्नदाताओं के साथ हुई शासन की ज्यादतियां, महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार, विनेश फेक्टर समेत कई मुद्दे एक तरफ, तो दूसरी ओर राहुल गांधी का अपने दम पर किया गया प्रचार हरियाणा में कांग्रेस को बड़ी जीत की दहलीज पर खड़ा दिखला रहा है। इसके लिये मतदान शनिवार को हुआ था। ज्यादातर एक्जिट पोल साफ बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने वहां जो आंधी चलाई थी, वह भाजपा समेत अन्य सारे दलों को उड़ा ले जायेगी। हरियाणा में जारी वोटिंग के बीच राहुल ने शनिवार को ही महाराष्ट्र में जो चुनावी प्रचार का बिगुल फूंका है, उसी से सवाल उठ रहा है कि क्या अब महाराष्ट्र की बारी है ? सवाल इस सन्दर्भ में है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी को बहाकर ले जाने की तैयारी में कांग्रेस है; वैसे यहां आंधी या तूफान नहीं, सुनामी की बात कही जा रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता उसका ट्रेलर था।

हरियाणा में कांग्रेस के सामने कई तरह के अवरोध थे। पहला तो यह कि यहां भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और सैलजा कुमारी के बीच मनमुटाव। वे राहुल ही थे जिन्होंने नूंह की सभा में दोनों के हाथ मिलवा कर पार्टी के एकजुट होने का संदेश दिया। यहां इंडिया की एक सहयोगी आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। विधानसभा में सीटों की संख्या के लिहाज से महाराष्ट्र हरियाणा के मुकाबले तीन गुना बड़ा है। हरियाणा में 90 सीटें हैं, तो महाराष्ट्र में 288। जाहिर है कि यहां मुकाबला भी बड़ा है। यहां भाजपा ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस के साथ चल रही सरकार को गिराकर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनाई थी। इसमें शिवसेना के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तथा एनसीपी के अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। स्वयं देवेन्द्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं। इसके कारण जनता तो नाराज है ही, खुद भाजपा के भीतर असंतोष है। यहां के सामान्य नागरिक अब भी ठाकरे की शिवसेना तथा शरद पवार की एनसीपी को असली मानते हैं- बेशक अदालती फैसले क्रमश: शिंदे एवं अजित के पक्ष में गये हों। एनडीए कमजोर स्थिति में है। चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद वह कितनी एकजुट रह पाती है, यह देखने वाली बात होगी।

अजित पवार को लेकर भाजपा में सर्वाधिक नाराज़गी है। दूसरी तरफ उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे कभी भी अपने चाचा शरद पवार के पास लौट सकते हैं। वे एनसीपी से अलग होने की अपनी गलती मान चुके हैं। साथ ही वे सम्भवत: अब चुनाव न लड़ें। ऐसा होता है तो वे अपने चाचा के लिये काम करते दिख सकते हैं। दूसरी तरफ यहां इंडिया बेहद मजबूत है तथा राहुल सर्वमान्य नेता हैं। पिछले दिनों इंडिया की जितनी भी बड़ी सभाएं या कार्यक्रम हुए हैं- सभी में उद्धव तथा शरद पवार शामिल हुए। वैसे तो उद्धव सीएम पद के सबसे बड़े चेहरे हैं लेकिन पिछले दिनों एक बैठक में उन्होंने साफ कर दिया था कि उनके लिये मुद्दा यह नहीं है कि सीएम कौन होगा। भाजपा को हराना उनका लक्ष्य है। सीएम पद का विवाद उन्होंने यह कहकर समाप्त कर दिया था कि सभा में उपस्थित कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले तथा शरद पवार जिसे चाहें अभी भावी मुख्यमंत्री की घोषणा कर सकते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तथा वे इंडिया के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।

इस राज्य में राहुल बड़ी तैयारी से उतरे हैं। उनकी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' का समापन 16 मार्च को मुम्बई में ही हुआ था और उसके पहले शिवाजी पार्क में एक विशाल रैली भी हुई थी। रास्ते में वे नागपुर के चैत्य भूमि पर एक बड़ा कार्यक्रम कर चुके थे, जहां बाबासाहेब अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों को दीक्षा देकर नव बौद्ध बनाया था। फिर, राहुल का सामाजिक न्याय का मुद्दा इस प्रदेश में खूब रंग पकड़ रहा है जो सामाजिक सुधारों की भूमि है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार यहां 26 नवम्बर के पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी करने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में राहुल की शनिवार को कोल्हापुर में हुई विशाल सभा ने बता दिया है कि कांग्रेस व इंडिया को वैसा ही बड़ा समर्थन मिलता हुआ दिखेगा जैसा कि हरियाणा में दिखलाई पड़ा था। उल्लेखनीय है कि कोल्हापुर में ही शाहूजी महाराज ने 1902 में पहली बार आरक्षण की व्यवस्था की थी।

चुनाव-दर-चुनाव राजनैतिक रूप से परिपक्व होते राहुल मुद्दों को पकड़ना और जनता के बीच उछालना बखूबी सीख गये हैं। यहां उन्होंने शिवाजी को लेकर बड़ा दांव खेल दिया है। याद हो कि पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में शिवाजी की वह मूर्ति ढह गयी थी जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। इस पर मोदी ने बार-बार सभी से माफी मांगी थी। इसे लेकर राहुल पीएम पर टूट पड़े। उन्होंने कहा कि 'मोदी और भाजपा शिवाजी को नहीं मानते इसलिये शिवाजी की मूर्ति ढह गयी।' इतना ही नहीं, राहुल के हाथों कोल्हापुर में ही एक मूर्ति का अनावरण कराकर भाजपा को उसी की भाषा में कांग्रेस ने जवाब दिया है। महाराष्ट्र के कुछ प्रोजेक्ट गुजरात ले जाने तथा मुम्बई की कुछ परियोजनाएं अदानी समूह को देना भी यहां भाजपा को महंगा पड़ रहा है। शनिवार की शाम आये एक्जिट पोल्स ने हरियाणा में कांग्रेस की बम्पर जीत बतलाई है, वहीं जम्मू-कश्मीर में भी कांग्रेस व नेशनल कांफ्रेंस की सरकार बनने के संकेत हैं। यही परिदृश्य महाराष्ट्र का भी दिखता है।

झारखंड में भाजपा के लिए एक नई चुनौती : कल्पना सोरेन

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के रिजल्ट से पहले भाजपा झारखंड को लुभा लेना चाहती है। 8 अक्टूबर को क्या होगा इसका शायद उसे अंदाजा है। इसलिए उसने पंचप्रण के नाम से झारखंड में घोषणाओं की बौछार कर दी। मजेदार बात यह है कि यह ऐसी घोषणाएं हैं जो वह पहले दूसरे राज्यों में भी कर चुकी है। मगर जीतने के बाद भूल भी गई।

नाम रखने में तो वह माहिर है। सूरदास का नाम नयनसुख रख सकती है। तो लक्ष्मी जोहार के नाम से पांच में एक योजना 500 रुपए में गैस सिलेंडर है। राजस्थान में यह वादा था। मगर किसी महिला को नहीं मिला। इसी योजना जिसे बहुत बड़ा नाम प्रण कहा गया है, में दो सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा है।

अभी अमित शाह ने तो कश्मीर में ईद और मोहर्रम पर एक-एक सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की थी। वहां तो अभी रिजल्ट आना है। मगर देखा जाए तो इसका रिजल्ट से क्या ताल्लुक ? गैस सिलेंडर तो केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है। अमित शाह को देना चाहिए। लेकिन आज तक किस राज्य में बीजेपी की सरकार मुफ्त सिलेंडर दे रही है और कहां 500 रुपए में ?

हरियाणा, जम्मू-कश्मीर का नतीजा आने दीजिए लोग अब यह सवाल पूछेंगे। लोगों में डर खत्म हो रहा है। दूसरी मजेदार घोषणा है सुनिश्चित रोजगार ! यह वादा करने से पहले वे भूल गए कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में जैसा एक्जिट पोल कह रहे हैं, वैसा ही रिज्ल्ट आया, तो इसका सबसे बड़ा कारण रोजगार ही होगा। दोनों जगह दस साल से इनकी सरकार थी। मगर एक नौकरी नहीं दी। न केन्द्र में न राज्य में। और जो नौकरियां थीं सेना में उसे भी खत्म करके अग्निवीर की बिना पेंशन और सिर्फ चार साल की बना दी। बाकी सुरक्षा बलों में भी भर्ती बंद है। हरियाणा के साथ जम्मू का युवा भी सेना और सुरक्षा बलों में सबसे ज्यादा जाता था मगर अब उसका वह रास्ता भी बंद कर दिया।

लेकिन यहां झारखंड में वे नौकरियों की घोषणा नहीं बल्कि प्रण कर रहे हैं। यह बड़े-बड़े शब्द भोले, सरल लोगों को कितनी पीड़ा पहुंचाते हैं इसका बीजेपी को अंदाजा नहीं है।

हम टिहरी उत्तराखंड का वह दिन कभी नहीं भूल सकते जब टिहरी डेम में पानी छोड़ा जा रहा था और टिहरी नगर डूब रहा था। तब औरतें रो-रोकर कह रही थीं कि- भाजपा के नेताओं ने हमारे हाथ में गंगाजल देकर यह संकल्प करवाया था कि टिहरी नहीं छोड़ेंगे। अब क्या होगा हमारे संकल्प का ? पुलिस हमें यहां से ले जा रही है। केन्द्र में वाजपेयी की सरकार थी। टिहरी डेम केन्द्र सरकार का ही प्रोजेक्ट था। हमने दिल्ली वापस लौटकर भाजपा के नेताओं से पूछा कि बाकी सब ठीक है। मगर महिलाओं से ऐसा संकल्प क्यों करवाते हैं जिसे पूरा न कर सकें। और वे जीवन भर अपराधबोध से ग्रस्त रहें। कोई जवाब नहीं था। बस फर्क इतना था कि उल्टे हमसे कोई सवाल नहीं पूछने लगा था। आज तो आप किसी से यह कह दो वह उल्टा आप पर ही आरोप लगाने लगता है।

मगर खैर लोकसभा में साधारण बहुमत भी न मिलने और अब हरियाणा. जम्मू-कश्मीर में हार की आहट से भाजपा के लोगों और उसकी गोदी मीडिया की उग्रता में कमी आई है और जनता के बीच डर का माहौल कम हुआ है।

चुनाव नतीजों का अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो जल्दी आप देखेंगे कि जैसे वादे झारखंड में भाजपा ने किए हैं उन पर फिर जनता ही सीधे सवाल पूछने लगेगी कि भाईसाहब क्या आपने बिल्कुल ही बेवकूफ समझ लिया है ? जैसे एक और प्रण है गोगो दीदी योजना। गोगो संथाली में मां को कहा जाता है। इसकेफार्म भरवाना भी भाजपा ने शुरू कर दिए। इसमें महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का प्रण है। जबकि हेमंत सोरेन सरकार पहले से मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को एक हजार रुपए महीना दे रही है। केवल नाम बदल कर और राशि बढ़ाकर नई योजना बताई जा रही है।

झारखंड मुक्ति मोर्चे (जेएमएम) के नेता इस पंचप्रण को प्रपंच कह रहे हैं। उनके नेता सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि महिला सशक्तिकरण बात कर रहे हैं। संसद विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रस्ताव पास कर दिया। मगर अभी हमारे यहां चुनाव है लागू कर दो। मगर नहीं वह जब जनगणना होगी जिसका कोई पता नहीं है उसके बाद सोचेंगे।

शकील अख्तर

> परिस्थितियोंवश एक महिला नेता का उदय हो जाना जेएमएम के लिए वरदान बन गया। अभी जिन दो राज्यों जम्मू-कश्मीर, हरियाणा में चुनाव हो चुके और जिन दो राज्यों में महाराष्ट्र, झारखंड में होना हैं, वहां केवल झारखंड ही ऐसा है जहां इंडिया गठबंधन को अपनी सरकार बचाना है। बाकी तीन राज्यों में उसे भाजपा एनडीए से छीनना है। इसलिए सरकार बचाने की लड़ाई बाकी तीन राज्यों के मुकाबले मुश्किल है।

जेएमएम बीजेपी के महिला पिच पर आने से बहुत खुश है। यहां वह खुद को बहुत मजबूत समझ रही है। और उसका कारण है कल्पना सोरेन।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना जेएमएम के लिए एक बड़ा मुश्किल समय था। चंपई सोरेन पर विश्वास करके जेएमएम ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया मगर उन्होंने ऐसा विश्वासघात किया कि झारखंड में ही नहीं देश में भी किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन इस बुरे समय ने ही जेएमएम को एक ऐसा सितारा दे दिया जिसका खुद उसे अंदाजा नहीं था।

एक सामान्य घरेलू महिला कल्पना सोरेन का कायाकल्प हो गया। हालांकि भारतीय नारियों की यह पुरानी परंपरा है कि पति पर संकट आने पर वे अचानक रणचंडी बन जाती हैं। कुछ ऐसा ही कल्पना सोरेन के साथ हुआ। वे विधानसभा का उपचुनाव लड़ीं और विधायक बन गईं। हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो वे इंडिया गठबंधन की बैठकों में शामिल हुईं। सोनिया गांधी ने खुद आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़कर अपनी बगल में बिठाया। बहुत कम समय में वे नेशनल मीडिया में छा गईं।

और अब जेएमएम उनका सर्वोत्तम उपयोग कर रहा है। उसने पूरे झारखंड में मंईयां सम्मान यात्रा शुरू कर दी। महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए। इसमें जेएमएम की दूसरी महिला नेता तो जा ही रहीं हैं। मगर सबसे ज्यादा क्रेज कल्पना सोरेन का है। भाजपा समझ गई है कि इस बार उसे एक नई नेता जो बहुत तेजी से लोकप्रिय हुई हैं, खासतौर से महिलाओं में, उनका मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी चुनाव की घोषणा से पहले ही दो दौरे कर चुके हैं। जमशेदपुर और हजारीबाग। मगर हजारीबाग जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है वहां भी भीड़ नहीं थी।

दूसरी तरफ कल्पना सोरेन की यात्रा में लोग खासतौर से महिलाएं भारी संख्या में शामिल हो रही हैं। जिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिलाएं 5- 6 बजे शाम के बाद घर से नहीं निकलतीं वहां रात साढ़े आठ बजे कल्पना सोरेन निकलती हैं तो महिलाएं सड़क पर खड़ी मिलती हैं। और मजेदार बात यह है कि केवल जेएमएम के झंडे के साथ नहीं कांग्रेस के झंडे वाली महिलाएं भी वहां होती हैं। यह वह इलाका है सारंडा जंगल के पार का जहां बाजार भी शाम को सूरज ढलने से पहले ही बंद हो जाते हैं।

परिस्थितियोंवश एक महिला नेता का उदय हो जाना जेएमएम के लिए वरदान बन गया। अभी जिन दो राज्यों जम्मू-कश्मीर, हरियाणा में चुनाव हो चुके और जिन दो राज्यों में महाराष्ट्र, झारखंड में होना हैं, वहां केवल झारखंड ही ऐसा है जहां इंडिया गठबंधन को अपनी सरकार बचाना है। बाकी तीन राज्यों में उसे भाजपा एनडीए से छीनना है। इसलिए सरकार बचाने की लड़ाई बाकी तीन राज्यों के मुकाबले मुश्किल है। मगर कल्पना सोरेन का जो एक नया फैक्टर आया है उसका तोड़ ढूंढना भाजपा के लिए आसान नहीं है। महिला नेता उसके पास झारखंड में तो क्या अब देश में भी नहीं है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है)

तिरुपति लड्डू पर चंद्रबाबू और पवन की नये तरह की रथयात्रा

■ सुशील कुट्टी

तिरुपति के लड्डू सर्वोच्च न्यायलय के आदेश पर नियुक्त जांचकर्ताओं की एक मिलीजुली टीम के मुंह में हैं। टीम में दो सीबीआई अधिकारी शामिल हैं। क्या इससे तिरुपति-तिरुमाला के भगवान वेंकटेश्वर को न्याय मिलने में तेज़ी आयेगी ? टीम इसमें कितनी और कब तक सफल हो पायेगी ? इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ समय से सीबीआई की छवि बहुत खराब हो गई है।

तिरुपति के लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किये गये घी में गोमांस की चर्बी, मछली का तेल और सूअर की चर्बी मिला हुआ पाया गया, जैसा कि एक जांच रपट के आधार पर दावा किया गया है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी उसे पुख्ता प्रमाण नहीं माना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू ने इस खोज को भगवान वेंकटेश्वर के संकेत के रूप में लिया और अपने पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ़ अभियान शुरू किया, जिसमें उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण सनातन धर्मावलंबियों की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं।

यह सेना गाय को कूड़े के ढेर और प्लास्टिक के कचरे के लिए छोड़ देगी, लेकिन गोमांस सहित किसी भी 'गोमांस' से कभी कोई लेना-देना नहीं रखेगी। यह आस्था का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। शायद यह तमिलनाडु के नये उप-मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के लिए संदेश हो, जिनके सनातन धर्म के खिलाफ़ कटु आलोचना से राजनेताओं और चिकित्सकों दोनों के ही समुदाय वाकिफ़ हैं।

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण के बारे में ज़्यादा चिंता रही होगी, जो सनातन धर्म को अपने भगवा रंग में पहनते हैं। पवन कल्याण और उदयनिधि स्टालिन दोनों ही अभिनेता-राजनेता हैं। वे टॉलीवुड और कॉलीवुड में अपने फ़िल्मी करियर के दौरान देवताओं को राजनीति के साथ मिलाते रहे हैं।

> सर्वोच्च न्यायालय को आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण के बारे में ज़्यादा चिंता रही होगी, जो सनातन धर्म को अपने भगवा रंग में पहनते हैं। पवन कल्याण और उदयनिधि स्टालिन दोनों ही अभिनेता-राजनेता हैं। वे टॉलीवुड और कॉलीवुड में अपने फ़िल्मी करियर के दौरान देवताओं को राजनीति के साथ मिलाते रहे हैं।

कल्याण के टॉलीवुड में इसकी शुरुआत एनटी रामाराव के मुख्यमंत्री बनने से हुई, क्योंकि उनके धार्मिक-फिल्मी अभिनय ने उन्हें जनता की नज़र में देवता बना दिया था। तमिलनाडु में एमजीआर सबसे आगे थे।

तिरुपति तिरुमाला मंदिर ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। इन अभिनेताओं का करियर तिरुपति मंदिर में चढ़ाये गये प्रसाद के बल पर तेजी से आगे बढ़ा। पवन कल्याण जैसे किसी व्यक्ति ने हजारों-हजारों तिरुपति लड्डू चढ़ाये होंगे। उदयनिधि स्टालिन ने शायद ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि वे एक अलग राजनीतिक ढांचे से बने हैं। यही वह बात है, जिस पर सारा विवाद है।

यह इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच का मामला है। क्या राजनेता वास्तव में इस बात की परवाह करते हैं कि तिरुपति लड्डू बनाने में क्या-क्या होता है ? शायद इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देवताओं को राजनीति में न लाया जाये, जैसे कि देवता असहाय हों।

पवन कल्याण का मानना है कि 'हां', हिंदू देवता असहाय हैं। भगवान वेंकटेश्वर और उनके भक्तों को खिलाये गये लड्डू का हश्र देखिए। तिरुपति के लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले घी जैसी महत्वपूर्ण चीज भी बेअसर हो गई है और भगवान कुछ भी नहीं कर सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि पवन कल्याण इतने भड़के हुए हैं और हथियार उठा रहे हैं।

अपने उत्साह और भक्ति में, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तिरुपति के लड्डू के इर्द-गिर्द शोर मचा दिया है। तिरुपति के लड्डू के इर्द-गिर्द आक्रोश को सनातन धर्म की संपूर्णता तक फैला दिया है और इस प्रक्रिया में, अपने हिंदू-द्वेषी तमिलनाडु के समकक्ष, उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को निशाना बनाया है।

प्रतिक्रिया ठंडी थी। द्रमुक की ओर से कहा गया कि वह पार्टी 'किसी भी धर्म या विशेष रूप से हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं करता है', लेकिन 'जाति अत्याचार, अस्पृश्यता और जाति पदानुक्रम के खिलाफ बात करना जारी रखेगा।' उपमुख्यमंत्रियों की लड़ाई में, यह इसे खत्म करने में मदद नहीं करता है। पवन कल्याण का कहना है कि तिरुपति के लड्डू में मिलावट 'हिमशैल की नोक' है और भ्रष्टाचार की जांच निष्कर्ष तक होनी चाहिए।

पवन कल्याण ने पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधने से पहले ही रोक लगा दी। उनकी मौखिक मिसाइलें केवल 'तमिलनाडु के नेता के लिए थीं, जो कहते हैं कि 'सनातन धर्म' एक वायरस की तरह है और इसे नष्ट किया जाना चाहिए।' उदयनिधि स्टालिन ने तर्क दिया है कि सनातन धर्म को मिटा दिया जाना चाहिए, न कि केवल इसका विरोध किया जाना चाहिए।

पवन कल्याण द्वारा उदयनिधि स्टालिन के हिंदू धर्म पर रुख पर विरोधी सख्त रुख अपनाने के साथ वह भगवान तिरुपति लड्डू को लेकर राजनीतिक विवाद में शामिल हो गये हैं। उनके पास अपनी मिसाइलों को दागने के लिए भाजपा का कंधा है। भाजपा, टीडीपी और पवन कल्याण की जन सेना दक्षिण भारत में देवताओं को राजनीति में लाने के लिए सबसे आगे हैं, भले ही सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी कहे या न कहे।

जहां तक उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण का सवाल है, सनातन धर्म के 'नरसंहार' को रोका जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने तिरुपति में एक रैली में कहा, 'सनातन धर्म को मत कहो, यह वायरस की तरह है और नष्ट कर देगा। जिसने भी यह कहा, मैं आपको बता दूं कि आप सनातन धर्म को मिटा नहीं सकते। अगर कोई कोशिश करेगा... तो आप मिट जाएंगे।' 'मैं एक बेबाक सनातनी हिंदू हूं। मैं बहुत स्पष्ट हूं।' तो, क्या मंदिर की राजनीति दक्षिण में आ गई है ? जिनके पास कई भगवान हैं, वे ईश्वरविहीन लोगों से लड़ रहे हैं। डीएमके ने पवन कल्याण और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दोनों की निंदा की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए उनकी आलोचना की। डीएमके के एक प्रवक्ता ने कहा कि पवन कल्याण, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और भाजपा 'हिंदू धर्म और मानवता के असली दुश्मन' हैं।

इसके साथ ही, डीएमके ने सनातन धर्म के अस्तित्व को स्वीकार किया है, न कि उसके उन्मूलन को। तो, क्या 'धर्म और हिंदू देवताओं का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करना' पेरियारवादियों और सनातनियों के बीच युद्ध का अगला स्तर है। पवन कल्याण 'सनातन धर्म' की रक्षा के लिए एक अखिल भारतीय समिति का गठन चाहते हैं और चेतावनी देते हैं कि 'किसी भी रूप में सनातन धर्म का अपमान' बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

तो, पवन कल्याण और सर्वोच्च न्यायालय अभिनीत इस फिल्म में 'बिगब्रदर इज़ वॉचिंग' की भूमिका कौन निभा रहा है, जिसमें उदयनिधि स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू भी प्रमुख भूमिका में हैं ? तिरुपति लड्डू की मुख्य भूमिका होगी, जिसमें ग्रामीण वातावरण पृष्ठभूमि के रूप में होगा, नायिका तिरुपति लड्डू के लिए घी प्राप्त करने के लिए दूध को मथती है।

सर्वोच्च न्यायालय को यकीन नहीं है कि तिरुपति लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किये गये घी में पशु वसा थी। कुछ लोग कहेंगे कि शीर्ष अदालत को भी आस्था के मामलों से दूर रहना चाहिए, जब तक कि वह सभी धर्मों के खिलाफ समान व्यवहार न करे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनके उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण दक्षिण भारत में एक नयी तरह की राजनीति की दिशा तय करने के लिए आडवाणी के रथ और सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। राजनीति में देवताओं को शामिल करना, जिसे न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने 'राजनीतिक नाटक' कहा है, हिंदू के लिए पुरानी बात है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आपके पत्र

अब राशन की चिंता से मुक्त हो रहे प्रवासी मजदूर

देश में रोज़गार प्रमुख समस्या बनी हुई है। इसका सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में नज़र आता है। गांव में रहने वाली एक बड़ी आबादी रोज़गार की तलाश में अन्य राज्यों में प्रवास करती है। ऐसे में इनके सामने अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के साथ-साथ सबसे बड़ी चुनौती जन वितरण प्रणाली द्वारा मिलने वाला राशन होता है। जिसके लाभ से ये मज़दूर अक्सर वंचित हो जाते हैं। चूंकि राशन कार्ड गांव में बना होता था, ऐसे में प्रवास के कारण वह अन्य स्थान पर इससे मिलने वाला सस्ते राशन का लाभ उठा नहीं पाते थे। लेकिन केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना ने इन प्रवासी मज़दूरों की समस्या को दूर कर दिया है। अब यह मज़दूर अपने प्रवास स्थान पर भी अपने राशन कार्ड के माध्यम से सस्ता अनाज खरीद कर परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम हो रहे हैं।

केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। माना जाता है कि इस योजना ने गरीबों के सामने भोजन की समस्या का हल कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी देश में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब और वंचित तबके को सस्ते में राशन उपलब्ध कराया जाता रहा है। लेकिन वन नेशन, वन राशन योजना ने न केवल लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की है बल्कि देश में एक एकीकृत और कुशल राशन वितरण प्रणाली स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना ने रोजगार के लिए पलायन करने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया है।

इस संबंध में क्रय विक्रय सहकारी समिति धुंवाला, भीलवाड़ा के सदस्य सत्यनारायण शर्मा बताते हैं कि यह योजना वर्ष 2019 में शुरू हुई थी। इसके तहत सुविधा का लाभ उठाने की पूरी प्रक्रिया बहुत सरल है। सबसे पहले इन मज़दूरों को सरकार द्वारा संचालित 'मेरा राशन एप' पर पंजीयन कराना होता है। जिसमें उन्हें अपने पैतृक गांव की डिटेल दर्ज करानी होती है। इसके बाद उन्हें अपने प्रवास स्थल का विवरण दर्ज कराने के साथ ही अपने फिंगर प्रिंट दर्ज कराने होते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही उन्हें उस जगह के स्थानीय जन वितरण प्रणाली की दुकान से जोड़ दिया जाता है। वह बताते हैं कि चूंकि यह एक राष्ट्रीय योजना है और पूरी तरह से ऑनलाइन है इसलिए किसी भी मज़दूर को नए जगह नाम दर्ज कराने से पहले पैतृक स्थल से नाम कटवाने की आवश्यकता नहीं है।

वह बताते हैं कि प्रवासी मज़दूरों के हितों में लाभकारी होने के बावजूद इस सिस्टम में अभी भी कुछ समस्याएं भी हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इनमें मज़दूरों की उपस्थिति और उसी अनुसार राशन का स्टॉक रखना एक बड़ी समस्या है। अक्सर राशन स्टॉक आ जाने के बाद नए मजदूर पंजीकृत होते हैं, जिन्हें अनाज उपलब्ध कराना राशन डीलरों के लिए चुनौती बन जाती है। इसके अलावा कुछ दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी और डिजिटल प्रणाली का अभाव इस योजना की सफलता में बाधक बन रहा है। हालांकि, सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके बावजूद यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रवासी मज़दूरों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है।

शैतान रैगर, उदयपुर, राजस्थान

ललित सुरजन की कलम से

यात्रा वृतांत: पश्चिमी सीमांत की ओर

'दिल्ली से फ़ाज़िल्का के कुछ पहले मलौट नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-9 चलता है। इसे अगर मैं वीवीआईपी राजमार्ग की संज्ञा दूं तो अतिशयोक्ति न होगी। बहादुरगढ़ चौक पार करने के बाद महम पड़ता है। यह आधुनिक हरियाणा के निर्माता बंशीलाल का नगर है। बंशीलाल ही थे जिन्होंने हरियाणा को देश में सबसे पहले पूर्ण विद्युतीकृत राज्य बनाने का काम किया था। यही बंशीलाल थे जो आगे चलकर आपातकाल की ज्यादतियों के लिए अपयश के भागीदार बने थे। महम से आगे बढ़ो तो हिसार आता है। यह भजनलाल का चुनाव क्षेत्र है। ओ.पी. जिंदल और उनके बेटे यहीं से आगे बढ़े हैं। सावित्री देवी जिंदल भारत की सबसे धनी महिला मानी जाती हैं। भजनलाल और जिंदल को पीछे छोड़ते हुए थोड़ी देर बाद हम अग्रोहा से गुजरते हैं जो अग्रवाल समाज के लिए एक तीर्थ का रूप ले चुका है। इसके बाद आता है सिरसा। पाठकों को ध्यान होगा कि गुरमत रामरहीम के कारण यह नगर हाल के दिनों में सुर्खियों में आ चुका है। हरियाणा के एक और पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें देश का उपप्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, उन चौधरी देवीलाल का गांव चौटाला सिरसा से बहुत दूर नहीं है। ताऊ के पुत्र ओमप्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

अभी तक हम हरियाणा में हैं। कुछ किलोमीटर आगे मंडी डबवाली है। यहां बीस वर्ष पूर्व 23 दिसम्बर 1996 को भीषण अग्निकांड में कई लोगों की मौत हो गई थी। इस नगर की खासियत है कि आधा शहर हरियाणा में और आधा पंजाब में पड़ता है। रेलवे स्टेशन शायद पंजाब में है। पंजाब के बुजुर्ग नेता और पांच बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाशसिंह बादल का गांव बादल तथा विधानसभा क्षेत्र लांबी भी इसी सड़क पर है। इस तरह लगभग तीन सौ किलोमीटर के भीतर हम एक उपप्रधानमंत्री, आधा दर्जन मुख्यमंत्री और लगभग उतने ही सांसदों के गांवों से गुजरते हैं। इन सबने भारत की राजनीति-वाणिज्य, व्यापार और धर्म-आध्यात्म को अपनी-अपनी तरह से प्रभावित किया है। ... तो हुआ न यह वीवीआईपी रोड !'

(देशबन्धु में 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)

https://lalit.surjan.blogspot.com/2017/12/blog-post_13.html

गुरवाणी विचार

देव गंधारी महला 5

माई जो प्रभु के गुण गावै
सफल आएआ जीवन फूल ताके पारब्रम्ह
सुन्दर सुघड़ सूर सोबेता, जो साधु संग पावै।
नाम आचार करे हरि रसना बाहुड़ि न जोनी
पूरन ब्रह्म रविआ मन तन माहि, आनंदृष्टि आवै।
नरक रोग नहीं होवत जन संगि नानकी जिस लड़लावै।

इस शब्द द्वारा पांचवे नानक गुरु अर्जुन देव जी मानवमन को समझाईश देते हुए फरमा रहं हैं कि इस संसार में आना उन्हीं प्राणियों का सफल है जो संसार में आकर प्रभु सिमरन बंदगी में मन रमाते हैं। रसना से सदा हरि परमात्मा की स्तुति करते रहते हैं। सिवाय प्रभु परमात्मा के और कहीं पर भी ध्यान नहीं रमाते। संसार में रहते हुए सांसारिक कार विहार करते हुए प्रभु सिमरन बंदगी में मन से जुड़ा रहे। हर वक्त उसका मन निरंकार से जुड़ा रहे। इसी बात को भगत नामदेव जी समझा रहे हैं-

नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम संभाल।
हाथ पांव कर काम मन चित निरंजन नाल।।

ऐसा करते रहने पर ही संसार में तो वह सुखपूर्वक जीवनयापन करता ही रहेगा परलोक गमन करने पर भी उसे प्रभु की सांचे दरगाह में स्थान प्राप्त होगा। जहां पर फिर वह सदा आनंद ही आनंद की अनुभूति करता रहेगा। इसीलिए सही मायने में वही पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है जो

कोई हारे या जीते पर असली जीत जम्मू-कश्मीर की होना तय

आज साफ-साफ बात करने का समय आ गया है। जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों का नतीजा कुछ भी आए व किसी की भी सरकार बने पर यह तय है कि चुनावी प्रक्रिया व नतीजे कई मायनों में जम्मू-कश्मीर से जुड़ी बहुत-सी भ्रांतियों व वर्जनाओं को तोड़ने वाले साबित होने जा रहे हैं। सही समझें तो ये नतीजे जम्मू-कश्मीर के नव-निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ यदि किसी स्वप्निल नव-निर्माण का सपना देखना हो तो उसके अतीत में दफन कुछ कड़वी सच्चाइयों पर दृष्टिपात भी कर लेना अच्छे भविष्य की सुरक्षा व उसके महत्व को समझने के लिए शुभ होता है। चलिए उस खोज को आपके सामने रखते हैं जो आपको उस बिंदू तक ले जाएगी जो कश्मीर में अलगाव के दरिया का सबसे पहले का स्रोत रहा, जहां से इसको पहली चिंगारी मिली। ये खोज जम्मू-कश्मीर में 1987 को हुए विधानसभा चुनाव के बारे में है। तब हालात सामान्य दिखते थे। फिल्मों के शूटिंग शैड्यूल 1988 तक इस तरह के थे जैसे गर्मी के मौसम में पहलगाम दूसरा मुंबई हो। पर वहां की जनता के मन में सरकारों की कारगुजारी से बहुत निराशा व गुस्सा था। लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी होती है कि जनता के मन का गुस्सा और गुबार वोट के माध्यम से निकल जाता है तो मानो सरकार बदलकर जनता के मन के प्रैशर कूकर की सीटी सारी भाप को रिलीज कर देती है।

दुर्भाग्य से ऐसा 1987 के चुनाव में जम्मू-कश्मीर में न हो सका। तब केंद्र में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सर्वशक्तिमान सरकार थी। इधर कश्मीर में शेख शाही का कुनबा लगातार सत्ता में बना हुआ था। 1987 में जम्मू-कश्मीर में नैशनल कांफ्रैंस (नैकां) व कांग्रेस पार्टी ने मिलकर गठबंधन वाला चुनाव लड़ा। विधानसभा की कुल 76 सीटों पर कांग्रेस 31 सीटों पर लड़ी व नैकां 45 सीटों पर। इनके विरोध में कोई दूसरा राजनातिक दल तो टक्कर देने में सक्षम नहीं था पर कश्मीर की जनता में इस गठबंधन के खिलाफ गहरा असंतोष था। तब विभिन्न छोटे दलों या संस्थाओं के प्रतिनिधियों के तौर पर जम्मू-कश्मीर के युवाओं ने कमर कस ली परन्तु तकनीकी तौर पर उनका संगठन न होने के चलते वे निर्दलीय की श्रेणी में मान लिए गए। जिस प्रकार मौजूदा चुनाव में निर्दलीयों का काफी बोलबाला है, 1987 के चुनाव में तो उससे भी बहुत ज्यादा था। उस समय 344 निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। वे एक-दूसरे से जुड़े थे पर उनका मजबूत राजनीतिक संगठन नहीं था। उस चुनाव में इस हद तक धांधली के समाचार आए कि पूरे देश के अखबार इस चुनाव में हुई गड़बड़ी से भरे हुए थे। जैसी कि आम धारणा है कि कश्मीर में लोग 15 से 18 फीसदी ही वोट देते हैं, उसके विपरीत 1987 में जम्मू-कश्मीर का मतदान 74. 88 फीसदी रहा। कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़कर 26 सीटें जीतीं, कांग्रेस को मिला मत प्रतिशत 20.20 फीसदी था। नैकां ने 45 सीटों पर चुनाव लड़ा जिनमें से 40 जीतीं और वोट फीसदी रहा 32.98 फीसदी। आजाद प्रत्याशियों ने सभी 76 सीटों पर चुनाव लड़ा परन्तु सीटें मिलीं 8 और मत प्रतिशत 34.76 फीसदी रहा।

इन नतीजों ने उन हारे नौजवानों, जिन्होंने व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव लड़ा व सिस्टम ने हरवाने के बाद उनका जिस प्रकार थानों में उत्पीड ? किया उस बेइज्जती को वे सहन नहीं कर पाए। याद कीजिए कि क्या 1987 में कभी कश्मीर में पत्थर चलते थे, गोलियां चलती थीं? अलगाव की कोई तेज बहने वाली हवा भी न थी। अमीरा कदल सीट से चुनाव हारा निर्दलीय मोहम्मद यूसुफ शाह बाद में सलाहुद्दीन बन गया व कितने हजार युवकों को उसने हथियार दिए, गिनती ही नहीं है। यदि ये जीत भी जाते तो सत्ता का सिस्टम उन्हें कुछ ही दिनों में व्यवस्था का हिस्सा बना लेता, पर धक्केशाही ने उन्हें पाकिस्तान के हाथों में धकेल दिया जिसका नतीजा सारे देश ने कई दशक तक भुगता। लेकिन इस बार हवा व फिजा बदली है। वैचारिक व सियासी विरोध के बावजूद जेल में बैठकर उमर अब्दुल्ला को 5 लाख वोटों से हराने वाले सांसद इंजीनियर रशीद भी इंटरव्यू के मौके पर कह ही गए कि जो भी हो पर मोदी साहिब ने चुनाव को इतना साफ-सुथरा करवा कर दिल जीत लिया है। मौजूदा चुनाव कोई हारे या जीते पर असली जीत कश्मीर की होना तय है और कश्मीरियों का दिल जीतने की बात करने वाले मोदी साहिब को कम से कम कोई कश्मीरी तो जुमलेबाज नहीं कह पाएगा। -अर्जुन शर्मा

पक्ष और विपक्ष की चुनावी समीक्षा

-विक्रम दयाल

चुनावी विगुल बजने के बाद जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं या हो रहें हैं वहाँ वहाँ के क्षेत्रों में पक्ष या विपक्षी दलों के लोग अपने अपने अजेंडों के साथ जनता को लुभाने के लिए अनेक प्रकार के लुभावने हथकंडे अपनाने में जुट गये हैं. जोड़ तोडं की गणित तो कुछ ज्यादा ही होने लगी है. कुछ नये चेहरे तो कुछ पुराने चेहरों के साथ सभी दल के अग्रणी नेता अपने नेतृत्व की शुरूवात करदी है. एक दूसरे की जमकर बुराई करते नेता लोग मतदाताओं के पास घर घर जाने लगे हैं.

चुनाव एक त्यौहार के जैसा भारत में आता है. नेताओं के कदम

उन बस्तियों में भी पहुँच जाते हैं जहाँ कभी उनके कदम की पहुँच नही होती हैं. टूटी फूटी झोपडिंयों में, गंदी से गंदी बस्तियों में, भी नेताओं का दर्शन मतदाता पाकर खुद को धन्य समझते हैं. क्यों कि शायद उन मतदाताओं के भाग्य बदलने वाले हों? गांवों में अभी भी बहुत ऐसे गरीब हैं जिनके चुल्हे रोज नही जलते हैं. कभी कभार ही जलते हैं. अगर ऐसे गाँव में गरीबों के दरवाजे पर कोई नेता पहुँचता है तो वह गरीब अपने को धन्य ही समझेगा. शायद नेताजी के द्वारा उस गरीब का भला हो जयेगा?. परन्तु ऐसा नही होता है. नेताजी तो केवल मत लेने के लिए उसके द्वार पर पांच साल में एकबार के लिए गये हैं? वोट मिलने के बाद नेताजी उस बस्ती या गांव को भी भूल जायेगें, जहाँ से उन्हें कभी विजयश्री मिली हुई थी. चुनाव के त्यौहार धीरे धीरे बीत रहे हैं, और नेताजी भी उस गाँव की गली को भी भूलने में लगे हुए हैं. चुनावी दंगल में एक दूसरे को सत्ता से दूर रखने की भरपूर कोशिष दोनों पक्ष करते हैं. एक दूसरे की जम कर बुराई करना, और जनता के बीच जाकर केवल अपनी ही बड़ाई करना, हर एक नेता अच्छी तरह जानता है. भूल चुकी जनता के सामने वर्षों की बीती हुई बातें याद दिलाना आज के नेताओं का पहला काम है. कभी अच्छे कर्म की बातें याद नही दिलाते हैं. लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे ताजा खबर बना कर जनता के सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे. जनता भी अब सब सही गलत का हिसाब रखती है. जनता जानती है और पहचानती भी है, कौन अच्छा है? और कौन बुरा है? किसी के बहकावे में अबके मतदाता नही आने वाले है. आजकल के मतदाता अपना बेशकीमती वोट उसे ही देगें जो जनमानस का भला करने वाला नेता हितैशी है. मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना, हर एक मीटिंग में केवल

हिंदू-मुस्लिम की चर्चा करना, हर समय केवल धार्मिक मुद्दों को ही भुनाना, मंदिर-मस्जिद की ही बात करना, क्या इन सब विषय के अलावा जनता को विश्वास में लेने के लिए अन्य कोई दूसरा विषय नही है? मंहगाई पर बात नही होगी। नौकरी की बात नही होगी, रोजगार पर बात नही होगी, किसानों की बात नही होगी। जब भी चुनाव आता है तो केवल हिंदू मुस्लिम की ही बातें होगी. देशको समृद्धि और शक्तिशाली बनाने की बातें होनी चाहिए, औरतों और बच्चियों के स्वाभिमान को बचाने की भी बातें होनी चाहिए. गरीबी मिटाने की बातें होनी चाहिए. देश को आत्मनिर्भर बनाने की बातें होनी चाहिए. बहुत सारे मुद्दे हैं. जो देश को आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होते हैं, उन सभी मुद्दों की बात होनी चाहिए. आजके मतदाता काम करने वाले नेता को ही अपना मत देगें?. जो नेता काम करेगा वही चुनावी दंगल में बाजी मारेगा.

क्या इस समय इंडिया गठबंधन का सितारा बुलंदी पर है?

अशोक भाटिया

इंडिया गठबंधन का जब गठन हुआ था तब दूसरे दलों से इस गठबंधन का खूब मजाक उड़ाया था कि यह गठबंधन क्या करेगा ? उत्तरप्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी फिर फेल जो जाएगी वगैरह , पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है । बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली अच्छी सफलता के बाद दो राज्यों हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में फिर से इस अलायंस की धमक दिखने लगी है। हाल ही में आए एग्जिट पोल के नतीजे तो यही बता रहे हैं। एग्जीट पोल के नतीजों में जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बहुमत के करीब दिख रही है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बड़ी जीत हासिल करने की ओर दिख रही है।

अगर एग्जिट पोल के नतीजे वास्तविक साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर इसके गहरे राजनीतिक असर देखने को मिलेंगे। खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी इस वक्त लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी की बीते दो दशक की राजनीति में यह संभवतः पहली बार होगा जब कांग्रेस पार्टी लगातार किसी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। एग्जिट पोल के औसतन नतीजे देखें जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस को 40-48 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा को 27 से 32 सीटें मिल सकती हैं। जबकि पीडीपी को 6-12 और अन्य को 6-11 सीटें मिलने की संभावना है। यहां निश्चित तौर पर पीडीपी-कांग्रेस बहुमत के करीब है। अगर वह बहुमत से दूर रहता है तो ऐसा संभव है कि उसे पीडीपी का साथ मिल जाए। दूसरी तरफ भाजपा और अन्य जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा समर्थित निर्दलीय हैं, के दम पर 40+ हो रही है। यदि हरियाणा के चुनाव बाद सर्वेक्षण देखें तो वहां की 90 सदस्यीय सीट पर कांग्रेस पार्टी 55 से 62 सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही है। उसके लिए यह एक बहुत बड़ी जीत कहलाएगी। इससे निश्चित तौर पर उत्तर भारत में पार्टी को अपने दम पर अपेक्षाकृत एक बड़े राज्य में सत्ता मिलेगी। अभी उत्तर भारत में वह केवल हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह तीन राज्यों में अपने दम पर सरकार में होगी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है।

एग्जिट पोल अगर वास्तविक नतीजे में तब्दील होते हैं तो निश्चिततौर पर यह राहुल गांधी और उनकी टीम के लिए यह बड़ी जीत होगी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं। वह हरियाणा में मतदान से चंद घंटों पहले वहां के बड़े दलित नेता अशोक तंवर को पार्टी में वापसी करवाते हैं। अशोक तंवर वही नेता हैं जिन्होंने बीते 2019 के विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले अध्यक्ष पद से हटाए जाने के कारण कांग्रेस छोड़ दिया था। वह बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर कुमारी सैलजा के खिलाफ मैदान में थे।

वह राज्य में हुड्डा कैंप और सैलजा कैंप से इतर शुरू से राहुल कैंप के नेता रहे हैं। लेकिन, बतौर आलाकमान राहुल गांधी के कमजोर पड़ने और हुड्डा से मनमुटाव के कारण अशोक तंवर को कांग्रेस छोड़ना पड़ा था। लेकिन, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राहुल गांधी 2019 वाले राहुल गांधी नहीं हैं। हुड्डा कैंप की तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी टीम ने हरियाणा के चुनाव में अपनी पकड़ बनाए रखी। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर हरियाणा में सरकार गठन में भी राहुल गांधी का असर दिखेगा।

इसके अलावा इन दोनों राज्यों के एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो यह भी साबित होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों में घटौती और इंडिया गठबंधन की सीटों में शानदार बढ़ोतरी कोई तुक्का नहीं था। बल्कि, इससे यह साबित होगा कि राष्ट्रीय के साथ राज्यों के स्तर पर अब एनडीए से जनता का मोहभंग होने लगा है। वह अब विकल्प तलाशने लगी है।

अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार और बीते लोकसभा में उसे वहां बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इसके आलावा महाराष्ट्र में विपक्षी इंडिया गठबंधन और आक्रामक होगी। महाराष्ट्र में पार्टी के सामने महाविकास अघाड़ी से मजबूती से निपटने की चुनौती है। पार्टी यहां शिवसेना (शिंदे गुट) के साथ सरकार में हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने वाली पार्टी ने एनसीपी से अलग होकर आए शरद पवार के भतीजे अजित पवार को अपने खेमे में कर चुकी है। ऐसे में पार्टी को चुनाव के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दे को लेकर सावधानी बरतनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी का मुद्दा उसके ऊपर ही भारी पड़ जाए। राज्य में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होगा। ऐसे में भाजपा के लिए समय के हिसाब से आगे बढ़ना होगा।दूसरी तरफ लोकसभा की हार के बाद एनडीए के नेताओं और कार्यकताओं का उत्साह भी कमजोर पड़ेगा।

झारखंड में भाजपा जेएमएम को हटाकर सत्ता में आने के लिए जोर आजमाइश कर रही है । पार्टी ने इस काम के लिए चंपाई सोरेन को अपने साथ मिलाया है। खास बात है कि भाजपा बड़ी संख्या में चुनाव से पहले विरोधी दल के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करती है। इसके अलावा उन्हें टिकट भी देती है। ऐसे में पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ही वरिष्ठ नेताओं में असंतोष पनपने लगता है। हरियाणा में पार्टी को इस बार टिकट बंटवारों में बड़े पैमाने पर बगावत का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी हरियाणा से सबक लेते हुए झारखंड में भी फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहेगी। देखा जाय तो पार्टी राज्य में सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए कई राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल देती है। हालांकि, इस चुनाव में भाजपा को यह दांव कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा पार्टी की तरफ से कई पुराने चेहरों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाया जाता है। इस बार पार्टी की यह रणनीति भी बेअसर साबित होती नजर आ रही है। इसके अलावा पार्टी चुनाव से पहले कलह को कंट्रोल करने में असफल रही है। ऐसे में पार्टी के लिए बागियों की चुनौती से निपटना भी काफी अहम है। वर्तमान में दो विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल से इतना तो तय है कि भाजपा को अब अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा।

एक बात और राहुल गाँधी अब अपनी तेजी से उड़ती पतंग देख अपने सहयोगियों पर ही दबाव बनाने की कोशिश करने लगे है । हाल के समाचारों के अनुसार असल में उत्तरप्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। इसके लिए कांग्रेस 50-50 सीट शेयरिंग फॉमूर्ला चाहती है यानी 5-5 सीटों पर दोनों दल लड़ें लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार ही नहीं हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ,राहुल गांधी से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है। इसी कोशिश में अखिलेश यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी से सीट की मांग की थी। लेकिन राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक भी सीट नहीं दी। जिसके बाद मजबूरी में अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में अपने दम पर उम्मीदवार उतारे। राहुल गांधी से मिला ये धोखा अखिलेश शायद ही भूले होंगे और हो सकता है कि उत्तरप्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस को यही सबक सिखाना चाहते हैं। वहीं भाजपा अखिलेश और राहुल की कथित दोस्ती पर कटाक्ष कर रही है। वैसे कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की रणनीति भी तैयार कर ली है। उत्तरप्रदेश में कांग्रेस ने उन सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है, जहां-जहां उपचुनाव होने वाले हैं।

कांग्रेस ने 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों के आवेदन मंगाने भी शुरू कर दिए हैं। इसके जरिए कांग्रेस ने अखिलेश तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थीं, जिसमें कांग्रेस 6 पर जीती थी। इसके बाद कहीं न कहीं अखिलेश यादव के कारण ही ?पी में अस्तित्व खोने की कगार पर खड़ी कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिली थी। अब विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस, अखिलेश यादव से उसी दरियादिली की उम्मीद जता रही है। साथ ही साथ उन्हें अकेले उपचुनाव लड़ने का तेवर भी दिखा रही है।

'कार्बन खेती' में छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभ का द्वार

-प्रियंका सौरभ

छोटे पैमाने के किसानों के लिए, कार्बन बाजार खेती के तरीकों को बेहतर बनाने, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और वैश्विक जलवायु समाधानों में उनके योगदान का अवसर प्रदान करते हैं। कई कार्बन परियोजनाओं का उद्देश्य वनों, आर्द्रभूमि और अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा और उन्हें बहाल करना है। ये पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और छोटे किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान कर सकते हैं। देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पिछले छह दशकों से भारतीय कृषि में गहन खेती की प्रथाएँ अपनाई गई हैं। इसके परिणामस्वरूप देश भर में प्रमुख खेती योग्य भूमि में मिट्टी के कार्बनिक कार्बन में महत्वपूर्ण कमी, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट और रासायनिक प्रदूषण हुआ है। इसके अलावा, प्रमुख अनाजों की एकल-फसल खेती के साथ गहन खेती ने जैव विविधता को नुकसान पहुँचाया और भूजल संसाधनों की कमी हुई। इन खेती प्रथाओं ने ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में भी वृद्धि की है जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। भारत का कृषि वानिकी क्षेत्र कार्बन वित्त परियोजनाओं के साथ एकीकरण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से वनरोपण, पुनर्वनरोपण और पुनर्वनीकरण पहलों के माध्यम से।

कार्बन वित्त परियोजनाओं के माध्यम से कार्बन पृथक्करण कार्बन को अलग करने की कृषि वानिकी की क्षमता इसे कार्बन वित्त पहलों का एक केंद्रीय घटक बनाती है। कार्बन वित्त परियोजनाओं में पेड़ लगाना या कृषि परिदृश्य में वृक्ष आवरण को बढ़ाना शामिल है, जिससे किसान कार्बन पृथक्करण गतिविधियों के माध्यम से कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। 2050 तक कृषि वानिकी क्षेत्र को 53 मिलियन हेक्टेयर तक विस्तारित करना बड़े पैमाने पर कार्बन पृथक्करण और वैश्विक कार्बन बाजारों में भागीदारी का अवसर प्रस्तुत करता है। कार्बन वित्त परियोजना पहल आय विविधीकरण की क्षमता भी प्रदान करती है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए। हालांकि, छोटे किसानों को अभी भी कार्बन बाजारों से बड़े पैमाने पर लाभ नहीं मिला है - मुख्य रूप से कम कीमतों की पेशकश और व्यापार योग्य, अद्वितीय और सत्यापन योग्य कार्बन क्रेडिट बनाने की उच्च लागत के कारण। इसके अलावा, कार्बन बाजारों में भाग लेने के लिए समय और संसाधनों के महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि कार्बन बाजार कार्बन पृथक्करण के लिए वित्तीय लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन किसानों द्वारा वहन की जाने वाली लागतों को कवर करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन अपर्याप्त हो सकते हैं। फिर भी, बाजार तेजी से बदल रहा है, और नई प्रौद्योगिकियां जो संभव है उसकी सीमा का विस्तार कर रही हैं।

कार्बन पृथक्करण से परे, कार्बन वित्त परियोजनाओं के तहत कृषि वानिकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, जल प्रतिधारण में सुधार करती है और कटाव को कम करती है, जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, यह क्षरित भूमि को बहाल करके तथा जलवायु संबंधी जोखिमों के विरुद्ध एक बफर प्रदान करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। कृषि वानिकी का समर्थन करने वाली सरकारी नीतियाँ जैसे राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, 2014 भारत में कृषि वानिकी के विस्तार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। कार्बन वित्त के साथ आगे एकीकरण के लिए, इस नीति को कार्बन वित्त परियोजनाओं पहलों का स्पष्ट रूप से समर्थन करने तथा कार्बन बाजारों तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए। कार्बन पृथक्करण के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता, वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे कि पेड़ लगाने या वन आवरण को बनाए रखने के लिए सब्सिडी, छोटे किसानों को व्यवस्थित रूप से कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्षमता निर्माण और जागरूकता अभियान कृषि वानिकी और कार्बन वित्त के लाभों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं। विस्तार सेवाएँ और गैर सरकारी संगठन सूचना प्रसारित करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसान कार्बन वित्त पहलों में भाग ले सकें।

निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन वित्त प्लेटफार्मों के साथ जुड़ना कृषि वानिकी-आधारित कार्बन वित्त परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। वेरा और गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे वैश्विक प्लेटफार्मों को भारत-केंद्रित मानकों की आवश्यकता को पहचानने की आवश्यकता है जो छोटे किसानों की कृषि की अनूठी चुनौतियों को ध्यान में रखते हैं। भारत में कृषि वानिकी में कार्बन पृथक्करण, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान करने की अपार क्षमता है। भारत में कृषि क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को कार्बन क्रेडिट लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। किसानों को कार्बन बाजार से परिचित कराने से उनकी आय में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों की स्वीकृति में तेजी आ सकती है। किसान टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपना सकते हैं और कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही मिट्टी, पानी, जैव-विविधता आदि जैसी बेहतर प्राकृतिक पूंजी के संदर्भ में अन्य कृषि-पारिस्थितिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि में कार्बन क्रेडिट बाजार अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसके लिए सख्त निगरानी और नियामक प्रणाली की आवश्यकता है। ऐसी चिंताएं हैं कि असममित जानकारी, पारदर्शिता की कमी और अपर्याप्त विनियमन कार्बन क्रेडिट के लिए अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं को जन्म दे सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त, किसानों और ग्रामीण समुदायों में ज्ञान और जागरूकता की कमी उनके शोषण का कारण बन सकती है। देश में इस बारे में पारदर्शिता, विनियमन और व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपायों की तत्काल आवश्यकता है। देश में कुशल और पारदर्शी कामकाज के लिए ये प्रणालियाँ आवश्यक हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित लाभ किसानों तक पहुँचें। कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजारों के लिए रूपरेखा कृषि समुदाय के बीच कार्बन बाजार को बढ़ावा देने, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने और वित्तपोषित करने में मदद करेगी। वीसीएम रूपरेखा का मुख्य उद्देश्य हितधारकों को जागरूक बनाना और उनका क्षमता निर्माण करना, किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आगे चलकर यह सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देगा, ग्रामीण आजीविका में सहायता प्रदान करेगा और कृषि में लचीलापन बढ़ाएगा।

छोटे पैमाने के किसान जो कम कार्बन और वनों की कटाई से मुक्त पद्धतियों को लागू करते हैं, वे कार्बन बाजारों से लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में हैं। कार्बन बाजार उन किसानों को मुआवजा देने या प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान करते हैं जो महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि ग्रीनहाउस गैसों को अलग करना या टिकाऊ खेती प्रथाओं का उपयोग करना। कार्बन पृथक्करण से परे, कार्बन वित्त परियोजनाओं के तहत कृषि वानिकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, जल प्रतिधारण में सुधार करती है और कटाव को कम करती है, जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, यह क्षरित भूमि को बहाल करके तथा जलवायु संबंधी जोखिमों के विरुद्ध एक बफर प्रदान करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

वंशवाद की गिरफ्त में हरियाणा की राजनीति

भारतीय राजनीति में वंशवाद की बहस नई नहीं है। हर चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा उठता है, पर टिकता नहीं। शायद इसलिए कि उससे परहेज तो किसी को नहीं। तीन लालों की राजनीति के लिए हरियाणा देश भर में च?चत रहा। बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल ने दशकों तक हरियाणा की राजनीति पर राज किया। तीनों लाल जीवनकाल में ही अपने लालों को भी राजनीति में स्थापित कर गए। अब उन लालों की अगली पीढ़ी भी राजनीति में आ चुकी है। चर्चा भले अक्सर 3 लालों और उनके परिवारवाद की होती रही हो, पर चंद अपवादों को छोड़ दें तो हरियाणा की पूरी राजनीति ही वंशवाद की गिरफ्त में है।

अब जबकि हरियाणा की 15वीं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे उम्मीदवार बड़ी संख्या में हैं, परिवारवाद की पूंछ पकड़ कर ही राजनीति कर रहे हैं। यह और भी आश्चर्यजनक है कि परिवारवाद से पोषित राजनीति अब परिवार तोड़ भी रही है। कभी कहा जाता था कि एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग दल में इसलिए रहते हैं कि सत्ता कभी परिवार से बाहर न जाने पाए, पर वह रणनीति भी अब रार में बदलती साफ नजर आती है। संख्या के लिहाज से चुनाव मैदान में सबसे ज्यादा सदस्य चौधरी देवीलाल के परिवार के हैं। देवीलाल परिवार 2 दल चला रहा है। एक, मूल पार्टी इंडियन नैशनल लोकदल यानी इनैलो, जिसके सर्वेसर्वा देवीलाल के राजनीतिक उत्तराधिकारी ओमप्रकाश चौटाला और उनके छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला हैं। दूसरा, परिवार में अलगाव के बाद बनी जननायक जनता पार्टी यानि जजपा, जिसके सर्वेसर्वा ओमप्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला और उनके दोनों बेटे दुष्यंत एवं दिग्विजय हैं।

जजपा साढ़े 4 साल हरियाणा में भाजपा के साथ सरकार में जूनियर पार्टनर रही और दुष्यंत डिप्टी सी.एम. देवीलाल के ही एक बेटे रणजीत सिंह चौटाला 2019 में रानिया से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। उन्हें भाजपा ने न सिर्फ मंत्री बनाया, बल्कि इसी साल लोकसभा चुनाव में हिसार से पार्टी टिकट भी दिया, पर हार गए। अब जब भाजपा ने रानिया से विधानसभा टिकट लायक नहीं समझा, तो रणजीत फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। दिलचस्प यह कि चाचा रणजीत के मुकाबले अभय चौटाला ने अपने बेटे अर्जुन को चुनाव मैदान में उतार दिया है। मंडी डबवाली से भाजपा टिकट न मिलने पर अपने एक और चाचा जगदीश के बेटे आदित्य को अभय ने इनैलो उम्मीदवार बना दिया, लेकिन रणजीत के मामले में वैसी उदारता नहीं दिखाई। शायद इसलिए कि रणजीत के रिश्ते दुष्यंत से ज्यादा अच्छे रहे हैं। मंडी डबवाली से जजपा ने दुष्यंत के छोटे भाई दिग्विजय को मैदान में उतार कर चुनाव को राजनीति के साथ-साथ पारिवारिक मुकाबला भी बना दिया है। अभय के एक और चचेरे भाई रवि की पत्नी सुनैना चौटाला फतेहाबाद से इनैलो उम्मीदवार हैं।

दुष्यंत दूसरी बार उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला आई.ए.एस. की नौकरी छोड़ कर राजनीति में आए बृजेंद्र सिंह से है। बृजेंद्र भी वंशवादी राजनीति से हैं। वह उत्तर भारत के बड़े किसान नेताओं में शुमार रहे चौधरी छोटू राम के वंशज बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। बीरेंद्र सिंह कहते रहे हैं कि राजीव गांधी की हत्या हो जाने के कारण 1991 में वह हरियाणा का मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए। 2014 में कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में आए बीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री बने, पत्नी प्रेमलता हरियाणा में विधायक और फिर बेटा बृजेंद्र 2019 में हिसार से सांसद, लेकिन इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले पूरा परिवार कांग्रेस में लौट आया। बंसीलाल के दोनों बेटे रणबीर महेंद्रा और सुरेंद्र सिंह राजनीति में रहे। रणबीर राजनीति के साथ-साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी सक्रिय रहे और उसके अध्यक्ष बने।

सुरेंद्र सिंह को बंसीलाल ज्यादा पसंद करते थे। इसलिए अ

दैनिक इबादत सम्पादकीय

उन्नत तकनीक बनाम पेजर अटैक

लेबनान में हजारों पेजरों और उसके बाद वाकी टाकी रेडियो, लैपटॉप और और सोलर उपकरणों में में एक साथ हुए धमाकों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इन धमाकों में 30 से ज्यादा मौतें हुईं और 3000 से ज्यादा लोग गंभीर रुप से घायल हैं। इसे आतंकी संगठन हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायली सुरक्षा एजेंसी मोसाद का आपरेशन माना जा रहा है। तकनीक पर निर्भर व्यवस्थाएं चिंतित हैं। अगर यह संभव है तो जाने और कितना कुछ भी संभव होगा जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नई तकनीकों के समंदर में गोते लगा रही युवा पीढ़ी तो शायद जानती भी न हो कि पेजर है क्या ? 80 के दशक में आया यह संचार माध्यम मोबाइल के आने से जल्द विदा हो गया। भारत में तो इसके आगमन प्रस्थान की भनक भी नहीं लगी। जीपीएस मोबाइल की तुलना में पेजर की बेहद बेसिक तकनीक इसकी ट्रैकिंग मुश्किल बनाती है। संभवतः इसीलिए इजरायली एजेंसियों द्वारा ट्रेस किए जाने से बचने के हिजबुल्ला ने इस पुरानी तकनीक पर निर्भर होना ठीक समझा। बहरहाल यह आश्वस्ति झूठी ही साबित हुई है। धमाकों के पीछे पहली थ्योरी यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हैकिंग से पेजर में लगी लिथियम बैटरी का टैंपरेचर बढ़ाकर ये धमाके किए गए। दूसरी थ्योरी के अनुसार हिजबुल्ला ने यह पेजर ताईवानी कंपनी गोल्ड अपोलो से खरीदे थे जिनकी बैटरी के साथ मोसाद ने विस्फोटक प्लांट कर दिए। एक संदेश ने विस्फोटक एक्टिवेट किया और हजारों पेजर एक साथ फट गए। इस घटना से उपजी चिंताएं भयावह हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.) तकनीक ने साईबर पहुंच को उपयोग की लगभग हर वस्तु तक पहुंचा दिया है। इस तकनीक से बिजली, मोटर वाहन, सुरक्षा और निगरानी, स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि, स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी जैसे बुनियादी ढाँचे को उन्नत किया जा रहा है। उपभोक्ता भी चाहता है कि दैनिक उपयोग की हर वस्तु हर वक्त उसकी पहुंच हो। कंपनियां इस कमजोरी का फायदा उठाकर हर उपभोक्ता उपकरण में यह तकनीक अपना रही हैं। कंपनियों को छुपा फायदा यह भी है कि उन्हें मार्केटिंग के लिए महत्वपूर्ण डाटा फ्री मिल रहा है जिसका उपयोग वे न सिर्फ खुद करती हैं बल्कि उसे बेचकर पैसा भी कमाती हैं। अनुमान है कि 2025 तक वैश्विक स्तर पर लगभग 11.4 बिलियन उपभोक्ता और 13.3 बिलियन इंटरप्राइजेज़ आई.ओ.टी. डिवाइस से युक्त होंगे और साईबर हमलों की पहुंच में होंगे। इनमें मोबाइल, कार, स्मार्ट वॉच, हैल्थ मानीटर, फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशनर समेत पेसमेकर जैसे बैटरी से चलने और शरीर के अंदर लगाए जाने वाले मेडिकल उपकरण भी शामिल हैं। पेजर धमाके बताते हैं कि ऐसे किसी भी उपकरण को बम में तब्दील करना संभव है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि वैश्विक सुरक्षा की भी सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक चुनौतियों में से एक है। राज्य विशेष या आतंकवादी समूह के हाथ में पहुंचकर ऐसी तकनीक कितनी विध्वंसक हो सकती है, सोच कर ही सिहरन होती है। बुनियादी ढांचे या सैन्य रसद नेटवर्क को नष्ट करने के लिए किया गया साईबर हमला कभी भी अंतरराष्ट्रीय संकट साबित हो सकता है।

आइए ! थार के सांगवान रोहिड़ा को संरक्षित करें !

आज रोहिड़ा की स्थिति बहुत खराब है। पहले 60 से 70 के दशक में हल से खेती होने के कारण इसके बीज जमीन में पनप जाते थे। वर्तमान में ट्रेक्टर से व अन्य आधुनिक उपकरणों से खेती,अतिक्रमण,वृक्षों की अवैध व अंधाधुंध कटाई के बाद हालात बदल गए हैं। लोगों का यह मानना है कि इसके पेड़ के नीचे फसलें पैदा नहीं होती हैं,इसलिए काश्तकार इसे अपने खेतों में लगाने में रूचि नहीं दिखाते हैं।

- सुनील कुमार महला

मारवाड़ टीक या रोहिड़ा, संस्कृत में जिसे चलचड़ा कहा जाता है और जिसे राजस्थान के राजकीय पुष्प का दर्जा प्राप्त है तथा जिसका वानस्पतिक नाम टिकोमेला उंडुलता है, तथा जो राजस्थान की जैव-विविधता संरक्षण में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है, मुख्यतया राजस्थान के थार मरूस्थल और पाकिस्तान के कुछ भागों में पाये जाने वाला प्रमुख वृक्ष है। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में इसके वृक्ष विशेषतया पाये जाते हैं। वैसे कुछ अरब देशों मे यह वृक्ष मिलता है। यह ओमान में और दक्षिण-पश्चिम ईरान से उत्तर-पश्चिम भारत तक अनेक स्थानों पर पाया जाता है। रोहिड़ा शुष्क क्षेत्रों और बाहरी हिमालय का एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी वृक्ष है। भारत में राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में यह बहुतायत में मिलता है। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र (चूरू, झुंझुनूं व सीकर) व मारवाड़ अंचल यानी कि जोधपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में यह वृक्ष मुख्य रूप से पाया जाता है और यहां पर यह वृक्ष इमारती लकड़ी का विशेष व मुख्य स्रोत कहलाता है, क्यों कि बुजुर्गों का यह मानना है कि इसकी लकड़ी स्वाद में कड़वी होने के कारण इसमें दीमक नहीं लगती हैं, इसकी लकड़ी सैकड़ों वर्षों तक भी खराब नहीं होने के कारण एवं मजबूत व टिकाऊ लकड़ी होने के कारण से इसे अधिकतर फर्नीचर के काम में लिया जाता है। आज विभिन्न हैंडीक्राफ्ट्स आइटमों, खिलौनों में इसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। यही वजह है कि रोहिड़ा धीरे-धीरे सिमट गया है। कहना ग़लत नहीं होगा कि रोहिड़ा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखा जाए तो यह इन क्षेत्रों की जीवनरेखा ही है। जोधपुर के अलावा राजस्थान में यह जैसलमेर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर आदि जिलों में भी बहुत बड़ी संख्या में मिलता है। इस वृक्ष की लकड़ी की उपयोगिता को देखते हुए इसे 'राजस्थान का सागवान' या 'मारवाड़ का सागवान' भी कहा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र (जोधपुर व इसके आसपास का क्षेत्र) में इसकी (इस वृक्ष की) अधिकता होने के कारण यह वृक्ष इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया है कि लोग इसे 'मारवाड़ी' टीक के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आज बढ़ती आधुनिकता, शहरीकरण, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण के लगातार होते ह्रास (ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव), बढ़ती जनसंख्या के साथ लकड़ी की फर्नीचर के लिए बढ़ती मांग, आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से कृषि कार्य करने से, कीटनाशकों व पेस्टीसाइडों के खेती में बढ़ते उपयोग तथा चारागाहों की लगातार अनदेखी करने से राजस्थान में इन पेड़ों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। दूसरे शब्दों में, यह कहना ग़लत नहीं होगा कि राजस्थान का सागवान कहलाने वाले रोहिड़ा के वृक्ष आज शनैः शनैः मरूधरा से कम होते चले जा रहे हैं। कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की शुरुआत की गई थी और इस पहल का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाना एवं इस धरा के भविष्य को सुरक्षित रखना है, लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है।धरती पेड़ों की कमी के कारण तपने लगी है। तपती धरती में रोहिड़ा के वृक्ष राजस्थान की धरती का तापमान कम करने में सहायक है, लेकिन अब यहां के तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ के साथ ही रोहिड़ा के वृक्ष विशेष रूप से पाए जाते हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में अब दोनों ही वृक्षों की संख्या में अभूतपूर्व कमी देखने को मिली है। रोहिड़ा में कमी आने का एक प्रमुख कारण इसकी लकड़ी का बेशकीमती होना है, वहीं इसके वृक्ष (रोहिड़ा के वृक्ष) भूमि या मृदा कटाव को रोकने में काफी सहायक होते हैं। यह तेज हवा के बहाव को भी कम करता है तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मददगार है। इसके फूल मरू की शोभा बढ़ाते हैं, भले ही इसके फूलों में अन्य फूलों की तरह इतनी खुशबू नहीं होती है और न ही इसके फूलों को पूजा इत्यादि में काम में ही लिया जाता है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि रोहिड़ा के फूल को 21 अक्तूबर, 1983 को राजस्थान सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया था। यह विडंबना से कम बात नहीं है कि आज के समय में रोहिड़ा के पेड़ राष्ट्रीय औसत से भी कम हैं। यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि रोहिड़ा का पेड़ औसतन 20-25 फीट तक ऊंचा होता है तथा यह बिगोनिएसी परिवार के टेकोमेला वंश/प्रजाति का एक प्रमुख वृक्ष है। यह अधिकतर शुष्क व अर्ध शुष्क भागों में समुद्र तल से 1100-1200 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। रोहिड़ा पतझड़ वाला वृक्ष है लेकिन वर्ष के अधिकांश महीनों में इसके वृक्ष पर हरी पत्तियां रहती हैं तथा ऐसा बहुत कम होता है जब यह पूरी तरह पत्तियों से रहित हो जाता है। इसकी पत्तियां लंबी, नुकीली होती हैं तथा फल कुछ मुड़े हुए होते हैं एवं इसके बीज बालदार होते हैं, जो हवा के साथ रेगिस्तान में इधर-उधर बहकर पेड़ का रूप धारण कर लेता है। रोहिड़ा पर फूल सर्दियों के मौसम में आते हैं और इसके फूल पीले, नारंगी और लाल रंग के होते हैं, जिनकी आकृति घंटीनुमा होती है। सच तो यह है कि दिसंबर से अप्रैल माह तक तीन प्रकार के चटकीले फूलों से गुलजार होने वाला यह वृक्ष हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। रोहिड़ा की जड़ें अन्य रेगिस्तानी पेड़ों की भांति काफी लंबी होती हैं और यह रेगिस्तान में गहराई तक फैली होने के कारण मिट्टी को आसानी से कटने नहीं देती हैं। इसे लगभग सदाबहार वृक्ष अथवा अर्ध-सदाबहार वृक्ष कहा जा सकता है। रेतीले धोरों में कम तापमान और कम पानी में यह आसानी से पैदा हो सकता है। इसमें सूखा सहने की विशेष क्षमता होती है। आश्चर्यजनक है कि यह गर्म व ठंडा दोनों प्रकार के तापमान को सहन कर लेता है, क्यों कि रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी भी हो जाती है। इसकी लकड़ी पर सुंदर नक्काशी आसानी से की जा सकती है, क्यों कि इसकी लकड़ी मखमली टाइप की होती है और लोग आमतौर पर इसका फर्नीचर बनाने में उपयोग करते हैं। लकड़ी ही नहीं इसकी छाल भी उपयोगी होती है जो कि विभिन्न बीमारियों/रोगों यथा मूत्र रोगों, त्वचा रोगों, गर्मी और लीवर संबंधी रोगों के उपचार में काम में ली जाती है।

उल्लेखनीय है कि औषधीय गुणों के कारण रेगिस्तान में रोहिड़ा की पूजा की जाती है। राजस्थानी बुजुर्ग यह मानते हैं कि है कि अगर कोई बीमार है, तो उसके कपड़े पेड़ की शाखाओं पर लटका दिए जाने चाहिए। इससे औषधीय प्रभाव अंदर तक पहुँचता है और फिर जब व्यक्ति उन्हें पहनता है, तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। फोड़े-फुंसियों, पेट के रोग, घाव, कान का रोग, आंख के रोग की दवा में भी रोहिड़ा का उपयोग होता है। जानकारी मिलती है कि पेट संबंधी रोगों में यह विशेष गुणकारी है और लिव-52 औषधि में भी इसका उपयोग किया जाता है। आज रिहायशी क्षेत्र बढ़ने, चरागाह भूमि कम होने के कारण और वन्य क्षेत्र के लगातार घटने से रोहिड़ा पर जबरदस्त असर पड़ा है। आज यदि अंधाधुंध कटाई, व्यावसायिक उपयोग रोककर इसका सघन पौधरोपण किया जाए तो यह फिर राज्य और देश की शान बन सकता है। रोहिड़ा की समस्या यह है कि रोहिड़ा का बीज संग्रहण कोई आसान काम नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके बीज की संरक्षण-संवर्धन क्षमता बहुत कम होती है है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून सीजन में तत्काल नहीं रोपने पर यह बहुत जल्दी खराब हो जाता है। आज रोहिड़ा की स्थिति बहुत खराब है। पहले 60 से 70 के दशक में हल से खेती होने के कारण इसके बीज जमीन में पनप जाते थे। वर्तमान में ट्रेक्टर से व अन्य आधुनिक उपकरणों से खेती, अतिक्रमण, वृक्षों की अवैध व अंधाधुंध कटाई के बाद हालात बदल गए हैं। लोगों का यह मानना है कि इसके पेड़ के नीचे फसलें पैदा नहीं होती हैं, इसलिए काश्तकार इसे अपने खेतों में लगाने में रूचि नहीं दिखाते हैं। जो भी हो रोहिड़ा वर्तमान में राजस्थान का राज्य पुष्प है और बेशकीमती वृक्ष। पर्यावरण संरक्षण में इसकी भूमिका अतुलनीय है। थार का यह शृंगार सरकार के साथ साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं, आम नागरिकों द्वारा एक अदद पहल और संरक्षण की बाट जोह रहा है। आइए राजस्थान के सांगवान को संरक्षित रखने के लिए हम सभी गंभीरता से अपने यथेष्ट व अनूठे प्रयास करें ताकि राजस्थान की इस अमूल्य, अनूठी निधि को हम आने वाली पीढ़ियों के हितों के लिए छोड़ सकें। हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि एक पेड़ दस पुत्रों के समान होता है।

(फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड)

नेत्रपीठ के रुप में प्रसिद्ध है मुंगेर का चंडिका स्थान

- कुमार कृष्णन

देश में बावन शक्तिपीठ हैं, सभी शक्तिपीठों में देवी मां के शरीर का एक हिस्सा गिरा था। जिसके कारण यहां मंदिर स्थापित हुए। ऐसा ही एक शक्तिपीठ बिहार के मुंगेर जिले से करीब चार किलोमीटर दूर है। यहां देवी सती की बाईं आंख गिरी थी। इस मंदिर को चंडिका स्थान और श्मशान चंडी के नाम से जाना जाता है।

मान्यताओं के अनुसार मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की हर मुराद पूरी होती है। इस स्थान को लेकर लोगों का कहना है कि यहां आंखों से संबंधित हर रोग का इलाज होता है। जी हां, यहां खास काजल मिलता है जिसे आंखों में लगाने से व्यक्ति के आंख से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। वैसे तो यहां नित्य ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है लेकिन नवरात्रि में तो यहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। यह मंदिर के पूर्व और पश्चिम में श्मशान है और मंदिर गंगा किनारे स्थित है। जिसके कारण यहां तांत्रिक तंत्र सिद्धियों के लिए आते हैं। नवरात्र के समय मंदिर का महत्व और भी अधिक हो जाता है। सुबह के समय मंदिर में तीन बजे देवी का पूजन शुरु होता है और शाम के समय भी श्रृंगार पूजन किया जाता है। नवरात्र के दौरान कई विभिन्न जगहों से साधक तंत्र सिद्धि के लिए भी जमा होते हैं।

चंडिका स्थान में नवरात्र की अष्टमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन होता है। इस दिन सबसे अधिक संख्या में भक्तों का यहां जमावड़ा होता है। सिद्ध-पीठ होने के कारण, चंडिका स्थान को सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। यह गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर जैसा ही महत्वपूर्ण है। चंडिका स्थान के मुख्य पुजारी नंदन बाबा बताते हैं कि चंडिका स्थान एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ है। नवरात्र के दौरान सुबह तीन बजे से माता की पूजा शुरू हो जाती है। संध्या में श्रृंगार पूजन होता है। अष्टमी के दिन यहां विशेष पूजा होती है। इस दिन माता का भव्य श्रृंगार होता है। यहां आने वाले लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहां देवी के दरबार में हाजिरी लगाने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मंदिर प्रांगण में काल भैरव, शिव परिवार और बहुत सारे देवी- देवताओं के मंदिर हैं। नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ अन्य दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। नवरात्र अष्टमी के दिन यहां खास पूजा होती है। यहां के पुजारी ने बताया कि मुंगेर-खगड़िया जिला का एप्रोच पथ जब से बना है तब से नवरात्र में गंगा पार खगड़िया, बेगूसराय जिले के श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं।

श्रद्धालुओं ने बताया कि मां शक्तिपीठ चंडिका स्थान का बहुत बड़ा महत्व है और वे कई सालों से मां की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। मां से जो भी मुराद मांगते हैं मां पूरी करती है। तंत्र साधना में इसका स्थान असम के कामाख्या मंदिर के जैसा है। पहले यहां एक बहुत छोटा प्रवेश द्वार था लेकिन 20 वीं शताब्दी में, इसका प्रवेश द्वार बड़े द्वार में बदल दिया गया। चंडिका स्थान का विकास 40-50 साल पहले राय बहादुर केदार नाथ गोयनका ने किया था, फिर वर्ष 1991 में श्याम सुंदर भंगड़ ने किया था। आईटीसी ने भी सामाजिक दायित्व के तहत मंदिर परिसर को विकसित किया। दोनों नवरात्रि में परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती सत्संग होता है।

कविता

सेवा सियान के

रखै नहीं सेवा भाव, चढ़े रथे रोज ताव,
जियत मा रोज रोज, झगरा मतात हे।।
आड़ी कॉड़ी करै नहीं, कोनो कोती टरै नहीं,
बेटा बहू गारी दे के, आँखी ला देखात हे।।

नीम कस करू बोली, भूलगे हँसी ठिठोली,
बूढ़त मा डोकरी ला, बड़ तरसात हे।।
भात साग देवें नहीं, सुध कोनो लेवैं नहीं,
खटिया मा परे रथे, परोसी बतात हे।।

दाई अब बोझा होगे, बूढ़त मा दुःख भोगे,
अँचरा मा ऑसू पोंछ, पीरा ला लुकात हे।।
मोह माया छूटगे हे, मन अब टूटगे हे,
धुक धुक हिया करे, देह घुन खात हे।।

झन कर अपमान, महतारी हे सियान,
बेटा बन राम कस, 'प्रियू' समझात हे।।
बहू कर सास सेवा, मिलही अबड़ मेवा,
तोरो होही इही गति, समय के बात हे।।

प्रिया देवांगन 'प्रियू'

(राजिम जिला - गरियाबंद छत्तीसगढ़)

सर्वशक्तिमान मोबाइल

- पंकज शर्मा

जबसे लैंड लाइन फोन चलन से बाहर हुआ है और मोबाइल जीवन का प्रमुख अंग बन गया है तब से इस चलित बेतार यंत्र ने मानव जीवन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन कर दिया है कि वह पूरी तरह शक्तिमान में परिवर्तित हो गया है। शक्तिमान सीरियल अपने देखा होगा? नहीं देखा तो मैं उसके बारे में संक्षेप में जानकारी दे देता हूं कि शक्तिमान एक सुपर हीरो जैसा ही होता है, जो अपने वैदिक मंत्रों को पढ़ कर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसकी दृष्टि में कोई भी काम कठिन नहीं रह जाता। वह हर भले आदमी और बच्चों की मुसीबत पड़ने पर सहायता करता है तथा बुरी शक्तियों से उनको बचाता है। वह आसमान में उड़ता है और चक्रवात की भांति वापस आसमान में चला जाता है। आजकल स्मार्ट मोबाइल फोन भी उसी शक्तिमान की भांति सबकी मदद कर रहा है। विज्ञान के इस चमत्कारिक आविष्कार ने इंसान का जीवन आसान कर दिया है। दुनिया पूरी तरह मुट्ठी में आ गई है। इंटरनेट ने इस विशाल दुनिया को छोटे से गांव में परिवर्तित कर दिया है। जो चुटकियों में हजारों मील दूर कहीं यूरोपीय या अमेरिकी देश में बैठे हमारे अपनों से वीडियो कॉल के माध्यम से आमने- सामने बैठ कर बात करवा देता है। एक दूसरे को भौतिक रूप से आसानी से देखा जा सकता है। इसी प्रकार इंटरनेट के माध्यम से हम बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से मनचाही वस्तु घर बैठे मंगवा सकते हैं, सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि यदि आपको यह ज्ञात होता है कि जो वस्तु आपको दिखाई गई थी वह भेजी गई वस्तु से गुणवत्ता में कमजोर है तो उसको वापस भी किया जा सकता है, और आपके द्वारा भुगतान की गई राशि वापस मिल जाती है। है ना आश्चर्य की बात? अब आपको इस स्मार्ट मोबाइल फोन ने अपने अस्तित्व में आने के बाद किन - किन वस्तुओं को अपने उदर में डाला लिया है, उसके बारे में बताता हूं। सर्वप्रथम तो इसने हमारी कलाई घड़ी को निगल लिया। यह उस समय की बात है जब साधारण प्रारंभिक मोबाइल चलन में आया इसके बाद यह हमारे घर में रखी टॉर्च जो अंधेरे में हमारी मदद करती थी उसको खा गया। उसके बाद हमारे रेडियो को खा गया, टेप रिकॉर्डर को खा गया, अलार्म घड़ी निगल गया, स्क्रीन बड़ी हुई तो फिल्में तक निगल गया। हमारी सबसे अच्छी दोस्त पुस्तकें हुआ करती थी उनको खा गया। परिवार का आपसी प्यार, मुहब्बत भाई- चारा लेन -देन, आपसी तकरार, चिट्ठी- पत्री, पत्र -पत्रिका, अखबार, कलाकार, सब खा चुका है। अस्पताल में भर्ती किसी करीबी से मिलने जाते हैं तो लोग हैलो हाय करने के बाद अपने - अपने मोबाइल निकाल कर बैठ जाते हैं और या तो रील देखने लगते हैं, गेम खेलने लगते हैं या सेल्फी खींचने लगते हैं। आदमी का आदमी से केवल आभासी रिश्ता या दोस्ती रह गई है। इसके साथ ही इस मोबाइल के कुछ और भी गंभीर साइड इफेक्ट या यूं कहे हानियां भी हुई हैं। जब से दुनिया में मोबाइल क्रांति आई है हर आदमी मोबाइल युक्त हो गया है चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। पुरुष हो या महिला इवन जबसे स्मार्ट फोन एंड्रॉयड और आई फोन का आगमन हुआ, इंटरनेट के साथ। तब से तो नन्हे नन्हे बच्चे भी टच स्क्रीन की गिरफ्त में आ गए हैं। प्रारंभिक काल में तो माताएं जब बच्चे रोने लगते थे तो उन्हें चुप कराने बहलाने के लिए कुछ फोटो, कुछ कार्टून दिखाती, इसके बाद यह मोबाइल इन्हें पकड़ा कर अपने काम में लग जाती उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा नुस्खा कितना भारी पड़ने वाला साबित होगा। आज दो साल का बच्चा भी इन टच स्क्रिन्स के इंस्ट्रूमेंट्स को इतनी तेज गति से चलाता है कि सब अचंभित हो रहे हैं। जो फंक्शन बड़ों को नहीं आते वे यह बच्चे बड़ी ही आसानी से खोल लेते हैं और बंद कर देते हैं। ऐप्स को डाउनलोड करना इनके बांए हाथ का खेल बन गया है। कई बार तो मैं किसी एप को बंद करने की तकनीक नहीं जान पाता तो अपनी पोती से पूछना पड़ता है और वह कहती है अरे दादू आपको इतना भी नहीं आता और वह करके बता देती है। मुझे तो तब और हैरानी हुई जब देखा कि उसने हजारों की संख्या में मोबाइल पर रील्स बना कर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड कर रखी है। उसकी दादी भी उससे सारे फंक्शन सीखती रहती है। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था थर्ड ए सी में मेरी बर्थ के ठीक ऊपर एक युवती यात्रा कर रही थी, आप विश्वास करें या न करें सुबह के तीन बजे तक वह मोबाइल पर बतियाती रही जिससे मेरी नींद भी प्रभावित हो रही थी मैंने निवेदन किया तब उसने बातें बंद की।

जियो जैसी कंपनी ने मोबाइल का रिचार्ज प्रारंभिक समय में अत्यधिक सस्ता दिया और हर व्यक्ति को इसकी ऐसी लत लगा दी है कि आज वह कंपनी सबसे महंगा रिचार्ज दे रही है और हम खरीद रहे हैं क्योंकि एक अज्ञात नशे की लत लग चुकी है हम सबको। फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या व्हाट्स एप इनके बिना हम प्राणहीन होने लगे हैं। कभी अपना मोबाइल बंद करके किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे रील देखते हुए आप देखिएगा, आपको मेरी बात पर पक्का यकीन हो जाएगा। क्या आपको यह पता है कि इन रील बनाने वालों को लाखों रुपए मिलते हैं। जी हां आप जितनी बार और जितनी देर, इनको चलाते हैं, उससे आपका नेट का डेटा उड़ता है और एप वाले इनकी जितनी बार रील चलती है, उस हिसाब से उन्हें रुपयों तथा डॉलर्स में भुगतान करती है। तो अब आप भी अगली बार अपनी अच्छी रील बनाएं और पोस्ट करें न कि आप दूसरों की रील देख कर उन्हें मालामाल करें।मोबाइल का असली मजा तो तब ही आएगा।

स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के मेले और महोत्सव लगाए गये। यह मेले और महोत्सव आतंकवाद पनपने के कारण सालों से बंद थे। 2023 में नियंत्रण रेखा के पास स्थित मां शारदा देवी मंदिर का नवनिर्माण कराकर आजादी के बाद पहली बार पूजा के लिए खोला गया। सालों से बंद खीर भवानी मंदिर में फिर से दर्शन-पूजन का काम शुरू हुआ। खीर भवानी का मेला लगाया गया। इसमें पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे।

नये सुनहरे युग में प्रवेश करता जम्मू-कश्मीर

- आर.के. सिन्हा

बेखौफ होकर जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से मतदाताओं ने राज्य विधानसभा के तीन चरणों में हुए चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया उससे दूर तक संदेश चला गया है कि अब वहां हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किसी तरह की हिंसा भी नहीं हुई। चुनावों में राजनीतिक दलों ने भी निर्भीकतापूर्वक खुलकर प्रचार भी किया, रैलियां भी कीं और जमकर अपने-अपने मतों को खुलकर जनता के सामने रखा भी। यह सब पिछले कई दशकों से ठप्प पड़ा हुआ था।

बेशक, निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभा का चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित करने का श्रेय ले सकता है। याद रहे कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव था। यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि 1980 के दशक में जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद के बढ़ने का एक कारण 1987 का विधानसभा चुनाव था, जो कि पूरी तरह से फर्जी था और जिसने चुनावी लोकतंत्र के प्रति भारी निराशा पैदा की थी और उग्रवाद को बढ़ावा देने में भरपूर मदद की थी। देश को अब उम्मीद जगी है कि राज्य विधानसभा के आगामी 8 अक्टूबर को मतगणना भी इसी भावना से होगी और उसके बाद राज्य में नई सरकार का गठन बिना किसी पक्षपात या शिकायत के होगा। अब लगता तो यही है कि जम्मू-कश्मीर अपना अतीत भूलकर नया इतिहास रचने के लिए मन बना चुका है। गांधी जयंती के मौके पर राजभवन में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, 'बापू हमेशा जम्मू-कश्मीर में शांति और प्रगति देखना चाहते थे। उन्होंने नयी पीढ़ी से बापू के आदर्शों से प्रेरणा लेने का आग्रह किया।' दरअसल राज्य के नौजवान भी समझ चुके हैं कि हिंसा और अशांति से उन्हें ही नुकसान होगा। इसलिए उनके हाथों में अब बंदूक और पत्थर नहीं हैं, बल्कि उनकी आंखों में शांति और आकांक्षाओं के सपने दिखाई देते हैं। आप कह सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ है। सबसे पहले बीती मई में लोकसभा चुनाव हुए और फिर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। केन्द्र शासित प्रदेश के 1.40 करोड़ नागरिकों ने संवैधानिक मूल्यों में अपनी आस्था दोहराई है और अपने मतदान के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और देश के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया है। यह प्रमाण है कि पिछले चार-पांच वर्षों में भयमुक्त जम्मू-कश्मीर बनाने में बड़ी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों में किए गए कार्य, चाहे वह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का सशक्तीकरण हो या शांतिपूर्ण चुनाव कराना हो या विकास कार्य हो, इस बात का प्रमाण हैं कि जम्मू-कश्मीर अब विकास और खुशहाल के रास्ते पर चल पड़ा है। अब राज्य में स्कूल पूरे साल खुले रहते हैं। बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ रहे हैं।

हालिया चुनावों में, उन जगहों में जमकर मतदान हुआ जिन्हें अबतक आतंकवादी संगठनों के गढ़ के रूप में देखा जाता था। तीन चरणों में क्रमशः 61.38त्न, 57.31त्न और 69.65त्न मतदान हुआ। जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य भागों की तरह ही इतने भारी मतदान से साफ है कि कश्मीर की जनता भी चुनावी लोकतंत्र को गंभीरता से लेनी लगी है। उच्च मतदान दर का एक कारण यह भी हो सकता है कि घाटी में लगभग सभी राजनीतिक मतों और विचार धाराओं की पार्टियों ने चुनावों में भाग लिया। अपने स्तर पर जमात-ए-इस्लामी भी शामिल रही चुनावों में, जिसने बीते समय के दौरान राज्य में चुनावों का बहिष्कार करने की पुरज़ोर वकालत की थी। कुल मिलाकर, 90 सीटों के लिए 873 उम्मीदवार मैदान में थे। जमात ने स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में या इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी के सहयोगियों के रूप में चुनाव लड़ा।

यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि; यह संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्य वैचारिक दुश्मन रहा है। सीमा पार से बार-बार आतंकवादी हमलों के कारण सुरक्षा बल, विशेष रूप से पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में, तनाव में रहे हैं। लेकिन, सुरक्षा बलों की चौकसी ने निश्चित रूप से चुनाव बिना किसी हिंसा के सम्पन्न करवा दिये। यह तो मानना होगा कि जम्मू-कश्मीर तेजी से बदलत जा रहा है। राज्य में धारा 370 के हटने से पहले पत्थरबाजी की घटनाओं में सैकड़ों लोग घायल हो रहे थे और मारे जा रहे थे। सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे थे, जिसमें अब 80-85 फीसद तक की कमी आई है। धारा 370 खत्म करने के बाद केन्द्र सरकार ने घाटी में राज्य की पुरानी सभ्यता और संस्कृति को फिर से जीवित करने के लिए बड़ी योजना पर काम शुरू किया। इसके तहत आस्था के केंद्रों और आध्यात्मिक स्थलों को नया रूप दिया गया।

स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के मेले और महोत्सव लगाए गये। यह मेले और महोत्सव आतंकवाद पनपने के कारण सालों से बंद थे। 2023 में नियंत्रण रेखा के पास स्थित मां शारदा देवी मंदिर का नवनिर्माण कराकर आजादी के बाद पहली बार पूजा के लिए खोला गया। सालों से बंद खीर भवानी मंदिर में फिर से दर्शन-पूजन का काम शुरू हुआ। खीर भवानी का मेला लगाया गया। इसमें पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे। सरकार ने 123 पुराने स्थलों का व्यवस्थित रूप से जीर्णोद्धार और मरम्मत कराकर जनता के लिए फिर

सम्पादकीय

देश में मिलावट का कारोबार चरम पर

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 'ईट राइट इंडिया' अभियान के माध्यम से सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और पोषक भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास शुरू किया है। खाने-पीने के शौकीन अथवा महानगरों में नौकरी आदि के चलते कम मूल्य लागत वाला भोजन तलाशने वाले भारतीयों के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि स्वाद एवं सस्ते के चक्कर में न पड़कर स्वच्छता मानकों एवं साफ-सफाई को अपनी सेहत के दृष्टिगत स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन को अपनी प्राथमिकता में रखें। भारत में बढ़ती आबादी के कारण और मांग एवं आपूर्ति में अंतर के चलते प्राय: खाद्य वस्तुओं की किल्लत और दामों में बढ़ोत्तरी होती ही रहती है और इसी किल्लत का फायदा जमाखोरों की टोलियां उठाने से नहीं चूकती हैं, तो वहीं घटिया एवं मिलावटी चीजें बेचने वालों की पौ-बारह हो जाती है। भारत में इन दोनों तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले लड्डुओं को मिलावटी देसी घी से बनाने से भक्तों की धार्मिक आस्था आहत होने का मुद्दा चर्चा में है। देवस्थानम को देसी घी की आपूर्तिकर्ता कंपनी एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड से खाद्य नियामक ने पूछा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उसका केंद्रीय लाइसेंस निलंबित क्यों न कर दिया जाए? आज भारत में मिलावट का कारोबार उस स्तर को पार कर चुका है जहां खाद्य उत्पादों में सस्ते और घटिया पदार्थ मिलाकर बेईमान व्यापारी व विक्रेता सामान की मात्रा को बढ़ा देते हैं और भारतीयों की जान की कीमत पर भारी मुनाफा कमाते हैं। ऐसा अनुमान है कि 60 करोड़ लोग अर्थात विश्व में लगभग 10 में से 1 व्यक्ति हर वर्ष दूषित भोजन खाने के कारण बीमार पड़ते हैं तथा 420000 लोग मरते हैं। भारत में दूध और डेयरी उत्पाद, वसा और तेल, फल और सब्जियां, अनाज, कॉफी, चाय, शहद और मसाले सहित लगभग हर खाद्य सामग्री में मिलावट का प्रतिशत अत्यधिक बढ़ गया है और स्वच्छता मानकों की बुरी तरह से अनदेखी हो रही है। इतना ही नहीं, भारत के कई क्षेत्रों से ऐसे भी वीडियो की सोशल मीडिया में भरमार है जिसमें समोसे, चाट, ब्रेड, कुल्फी, प्लास्टिक के चावल और गुलाब जामुन से भरी कड़ाही में पेशाब करते युवक और गोलगप्पे वाले जलजीरा पानी से ही हाथ मुंह धोने, गंदे हाथ व पैरों से आलू और आटा गूंथने जैसे कृत्यों द्वारा गंदगी से परिपूर्ण खाद्य सामग्री आम लोगों को परोसी जा रही है। ऐसे कृत्य न केवल निंदनीय हैं अपितु दोषी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग भी करते हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को तत्काल जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या रासायनिक पदार्थों से युक्त असुरक्षित भोजन 200 से अधिक बीमारियों का कारण बनता है जिसमें डायरिया से लेकर कैंसर तक शामिल हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में असुरक्षित भोजन के कारण चिकित्सा व्यय में हर साल 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है।

क्या इस समय 'इंडिया गठबंधन 'का सितारा बुलंदी पर है?

अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार और बीते लोकसभा में उसे वहां बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इसके आलावा महाराष्ट्र में विपक्षी इंडिया गठबंधन और आ॒ ामक होगी। महाराष्ट्र में पार्टी के सामने महाविकास अघाड़ी से मजबूती से निपटने की चुनौती है। पार्टी यहां शिवसेना (शिंदे गुट) के साथ सरकार में हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने वाली पार्टी ने एनसीपी से अलग होकर आए शरद पवार के भतीजे अजित पवार को अपने खेमे में कर चुकी है। ऐसे में पार्टी को चुनाव के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दे को लेकर सावधानी बरतनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी का मुद्दा उसके ऊपर ही भारी पड़ जाए।

अशोक भाटिया

इंडिया गठबंधन का जब गठन हुआ था तब दूसरे दलों से इस गठबंधन का खूब मजाक उड़ाया था कि यह गठबंधन क्या करेगा ? उत्तरप्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी फिर फेल जो जाएगी वगैरह , पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है । बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली अच्छी सफलता के बाद दो राज्यों हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में फिर से इस अलायंस की धमक दिखने लगी है। हाल ही में आए एग्जिट पोल के नतीजे तो यही बता रहे हैं। एग्जीट पोल के नतीजों में जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बहुमत के करीब दिख रही है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बड़ी जीत हासिल करने की ओर दिख रही है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे वास्तविक साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर इसके गहरे राजनीतिक असर देखने को मिलेंगे। खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी इस वक्त लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी की बीते दो दशक की राजनीति में यह संभवत: पहली बार होगा जब कांग्रेस पार्टी लगातार किसी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। एग्जिट पोल के औसतन नतीजे देखें जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस को 40-48 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा को 27 से 32 सीटें मिल सकती हैं। जबकि पीडीपी को 6-12 और अन्य को 6-11 सीटें मिलने की संभावना है। यहां निश्चित तौर पर पीडीपी-कांग्रेस बहुमत के करीब है। अगर वह बहुमत से दूर रहता है तो ऐसा संभव है कि उसे पीडीपी का साथ मिल जाए। दूसरी तरफ भाजपा और अन्य जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा समर्थित निर्दलीय हैं, के दम पर 40+ हो रही है।

यदि हरियाणा के चुनाव बाद सर्वेक्षण देखें तो वहां की 90 सदस्यीय सीट पर कांग्रेस पार्टी 55 से 62 सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही है। उसके लिए यह एक बहुत बड़ी जीत कहलाएगी। इससे निश्चित तौर पर उत्तर भारत में पार्टी को अपने दम पर अपेक्षाकृत एक बड़े राज्य में सत्ता मिलेगी। अभी उत्तर भारत में वह केवल हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह तीन राज्यों में अपने दम पर सरकार में होगी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। एग्जिट पोल अगर वास्तविक नतीजे में तब्दील होते हैं तो निश्चिततौर पर यह राहुल गांधी और उनकी टीम के लिए यह बड़ी जीत होगी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं। वह हरियाणा में मतदान से चंद घंटों पहले वहां के बड़े दलित नेता अशोक तंवर को पार्टी में वापसी करवाते हैं। अशोक तंवर वही नेता हैं जिन्होंने बीते 2019 के विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले अध्यक्ष पद से हटाए जाने के कारण कांग्रेस छोड़ दिया था। वह बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर कुमारी सैलजा के खिलाफ मैदान में थे। वह राज्य में हुड्डा कैंप और सैलजा कैंप से इतर शुरू से राहुल कैंप के नेता रहे हैं। लेकिन, बतौर आलाकमान राहुल गांधी के कमजोर पड़ने और हुड्डा से मनमुटाव के कारण अशोक तंवर को कांग्रेस छोड़ना पड़ा था। लेकिन, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राहुल गांधी 2019 वाले राहुल गांधी नहीं हैं। हुड्डा कैंप की तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी टीम ने हरियाणा के चुनाव में अपनी पकड़ बनाए रखी। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर हरियाणा में सरकार गठन में भी राहुल गांधी का असर दिखेगा। इसके अलावा इन दोनों राज्यों के एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो यह भी साबित होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों में घटौती और इंडिया गठबंधन की सीटों में शानदार बढ़ोतरी कोई तुक्का नहीं था। बल्कि, इससे यह साबित होगा कि राष्ट्रीय के साथ राज्यों के स्तर पर अब एनडीए से जनता का मोहभंग होने लगा है। वह अब विकल्प तलाशने लगी है। राज्य में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होगा। ऐसे में भाजपा के लिए समय के हिसाब से आगे बढ़ना होगा।दूसरी तरफ लोकसभा की हार के बाद एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी कमजोर पड़ेगा। झारखंड में भाजपा जेएमएम को हटाकर सत्ता में आने के लिए जोर आजमाइश कर रही है । पार्टी ने इस काम के लिए चंपाई सोरेन को अपने साथ मिलाया है। खास बात है कि भाजपा बड़ी संख्या में चुनाव से पहले विरोधी दल के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करती है। इसके अलावा उन्हें टिकट भी देती है। ऐसे में पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ही वरिष्ठ नेताओं में असंतोष पनपने लगता है।

हरियाणा में पार्टी को इस बार टिकट बंटवारों में बड़े पैमाने पर बगावत का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी हरियाणा से सबक लेते हुए झारखंड में भी फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहेगी। देखा जाय तो पार्टी राज्य में सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए कई राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल देती है। हालांकि, इस चुनाव में भाजपा को यह दांव कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा पार्टी की तरफ से कई पुराने चेहरों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाया जाता है। इस बार पार्टी की यह रणनीति भी बेअसर साबित होती नजर आ रही है। इसके अलावा पार्टी चुनाव से पहले कलह को कंट्रोल करने में असफल रही है। ऐसे में पार्टी के लिए बागियों की चुनौती से निपटना भी काफी अहम है। वर्तमान में दो विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल से इतना तो तय है कि भाजपा को अब अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। एक बात और राहुल गाँधी अब अपनी तेजी से उड़ती पतंग देख अपने सहयोगियों पर ही दबाव बनाने की कोशिश करने लगे है । हाल के समाचारों के अनुसार असल में उत्तरप्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। इसके लिए कांग्रेस 50-50 सीट शेयरिंग फॉर्मूला चाहती है यानी 5-5 सीटों पर दोनों दल लड़ें लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार ही नहीं हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ,राहुल गांधी से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं । समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है। इसी कोशिश में अखिलेश यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी से सीट की मांग की थी। लेकिन राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक भी सीट नहीं दी। जिसके बाद मजबूरी में अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में अपने दम पर उम्मीदवार उतारे। राहुल गांधी से मिला ये धोखा अखिलेश शायद ही भूले होंगे और हो सकता है कि उत्तरप्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस को यही सबक सिखाना चाहते हैं। वहीं भाजपा अखिलेश और राहुल की कथित दोस्ती पर कटाक्ष कर रही है। वैसे कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की रणनीति भी तैयार कर ली है। उत्तरप्रदेश में कांग्रेस ने उन सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है, जहां-जहां उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों के आवेदन मंगाने भी शुरू कर दिए हैं। इसके जरिए कांग्रेस ने अखिलेश तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थीं, जिसमें कांग्रेस 6 पर जीती थी। इसके बाद कहीं न कहीं अखिलेश यादव के कारण ही यूपी में अस्तित्व खोने की कगार पर खड़ी कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिली थी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार है राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी चाँदमल चौधरी। बहुत ही संवेदनशील और विवेकवान अधिकारी के रूप में रहे हैं। जहां भी रहे है तनावमुक्त जीवनशैली के माध्यम से वैल पुलिसिंग कर समाज व पुलिस के लिए संदेश दिया। इनका जन्म जयपुर जिले में गोविंदगढ़ के पास ग्राम नांगल कला में वर्ष 1968 में जन्म हुआ। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजकीय माध्यमिक विद्यालय ढोढसर से व हायर सेकेंडरी शिक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ से वर्ष 1986 में प्राप्त की। तत्पश्चात वर्ष 1986 में गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा से ग्रेजुएशन किया। वर्ष 1988 में राजस्थान विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट तथा 1991 में एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1991 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस उप निरीक्षक के पद पर चयन हुआ। प्रारंभिक प्रशिक्षण राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में प्राप्त किया। तत्पश्चात व्यावहारिक प्रशिक्षण जयपुर शहर के विभिन्न थानों एवं कार्यालयों से प्राप्त किया गया। वर्ष 1993 में द्वितीय अधिकारी के रूप में पुलिस थाना अशोकनगर में प्रथम पोस्टिंग हुई। तत्पश्चात वर्ष 1994 में जिला सीकर में पदस्थापन किया गया एवं प्रथम बार थानाधिकारी के रूप में पुलिस थाना खंडेला पर पदस्थापित किया गया। तत्पश्चात वर्ष 1995 में थाना अधिकारी लक्ष्मणगढ़ सीकर के पद पर पदस्थापित रहे। थानाधिकारी थाना नेछवा के पद पर रहे। तत्पश्चात वर्ष 1997 में ही पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुआ एवं पुलिस अधीक्षक सीकर के रीडर के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात वर्ष 1999 में नव पदोन्नति पर महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय के स्टाफ ऑफिसर के रूप में कार्य किया। वर्ष 2001 में जिला सीकर में पुन: पदस्थापन हुआ तथा थाना अधिकारी नीम का थाना के पद पर वर्ष 2001 से 2005 तक कार्य किया। तत्पश्चात वर्ष 2006-07 में पुलिस अधीक्षक सीकर के अपराध सहायक के रूप में कार्य किया। वर्ष 2007 में जिला सीकर से जिला अलवर में स्थानांतरण होने के बाद पुलिस अधीक्षक अलवर के अपराध सहायक के रूप में कार्य किया। वर्ष 2008-09 में थानाधिकारी पुलिस थाना बहरोड में पुलिस के अधिकारियों ने इन्हे भेजा जहां काफी हद तक क्राईम कंट्रोल किया। 2009-10 थाना अधिकारी शिवाजी पार्क एवं वर्ष 2010-12 तक थाना अधिकारी पुलिस थाना कोतवाली अलवर के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात जिला अलवर से स्थानांतरण पर पुलिस मुख्यालय में सतर्कता शाखा में कार्य किया। वर्ष 2012 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विशेष चयन होने पर अगस्त 2012 से वर्ष 2017 तक बतौर पुलिस

चाँदमल चौधरी
(एडिशनल एसपी)

उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय जयपुर में पदस्थापित रहा। इसी दौरान वर्ष 2016 में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। तत्पश्चात वर्ष 2017 से 2021 तक क्रमश: सहायक कमांडेंट पांचवी बटालियन आरएसी, वृत्ताधिकारी झुंझुनू ग्रामीण वृत्ताधिकारी किशनगढ़ बास अलवर एवं सहायक कमांडेंट चतुर्थ बटालियन आरएसी जयपुर के पद पर कार्य किया। वर्ष 2021-22 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस कल्याण पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित रहा। वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पुलिस मुख्यालय में पद स्थापित हैं। बड़े सरल और स्वाभिमानी अधिकारी हैं चाँदमल जी। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

7 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- मुगल सेना ने 1586 को कश्मीर में प्रवेश किया।
- बंगाल में 1737 को 20 हजार छोटे जहाज के समुद्र में 40 फुट नीचे डूबने से तीन लाख लोगों की मौत।
- विलेम द्वितीय नीदरलैंड का राजा 1840 में बना।
- अमेरिका में कोर्नोल विश्वविद्यालय 1868 को खुला। इसमें 412 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था जो उस समय की सबसे बड़ी संख्या थी।
- गांधीजी की 'नवजीवन' पत्रिका 1919 में प्रकाशित।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक व्यापक सैन्य कार्रवाई में 1940 को रोमानिया जर्मनी के नियंत्रण में चला गया।
- अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने 1942 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की।
- पूर्वी जर्मनी, डेमोक्रेटिक सरकार के अस्तित्व में आने के साथ एक अलग देश 1949 को बना।
- चीन में 1950 को कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के एक वर्ष बाद इस देश की सेना ने तिब्बत पर आक्रमण कर के उसे अपने नियंत्रण में कर लिया।
- मदर टेरेसा ने 1950 को कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी।
- चंडीगढ़ 1952 में पंजाब की राजधानी बनी।
- सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान लूनर-3 द्वारा चंद्रमा के छिपे हिस्से की तस्वीर 1959 को ली गई।
- सोवियत संघ ने 1977 में चौथे संविधान को अंगीकार किया।
- भारत में त्वरित कार्यवाइ बल का गठन 1992 में किया गया था। इसका गठन विशेष रूप से सांप्रदायिक दंगों से सहानुभूति पूर्वक और विशेषज्ञतापूर्वक निबटने के लिए हुआ था। प्रकृतिक आपदाओं से निबटने में भी यह बल नागरिक प्रशासन की मदद करता है।
- रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना 1992 में की गई।
- सूर्य बहादुर थापा द्वारा 1997 में नेपाल के नये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण, भारत और रूस सुरक्षा सहयोग 2010 तक बढ़ाने के लिए सहमत।
- जापान में मानव क्लोनिंग दंडनीय अपराध 2000 में घोषित किया।
- आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन 'एड्योरिंग फ्रीडम' 2001 को शुरू हुआ।

विशेष आलेख

नये सुनहरे युग में प्रवेश करता जम्मू-कश्मीर

आर.के. सिन्हा

बेखौफ होकर जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से मतदाताओं ने राज्य विधानसभा के तीन चरणों में हुए चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया उससे दूर तक संदेश चला गया है कि अब वहां हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किसी तरह की हिंसा भी नहीं हुई। चुनावों में राजनीतिक दलों ने भी निर्भीकतापूर्वक खुलकर प्रचार भी किया , रैलियां भी कीं और जमकर अपने - अपने मतों को खुलकर जनता के सामने रखा भी । यह सब पिछले कई दशकों से ठप्प पड़ा हुआ था । बेशक, निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभा का चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित करने का श्रेय ले सकता है। याद रहे कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव था। यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि 1980 के दशक में जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद के बढ़ने का एक कारण 1987 का विधानसभा चुनाव था, जो कि पूरी तरह से फर्जी था और जिसने चुनावी लोकतंत्र के प्रति भारी निराशा पैदा की थी और उग्रवाद को बढ़ावा देने में भरपूर मदद की थी।देश को अब उम्मीद जगी है कि राज्य विधानसभा के आगामी 8 अक्टूबर को मतगणना भी इसी भावना से होगी और उसके बाद राज्य में नई सरकार का गठन बिना किसी पक्षपात या शिकायत के होगा। अब लगता तो यही है कि जम्मू-कश्मीर अपना अतीत भूलकर नया इतिहास रचने के लिए मन बना चुका है।

गांधी जयंती के मौके पर राजभवन में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, बापू हमेशा जम्मू-कश्मीर में शांति और प्रगति देखना चाहते थे। उन्होंने नयी पीढ़ी से बापू के आदर्शों से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। दरअसल राज्य के नौजवान भी समझ चुके हैं कि हिंसा और अशांति से उन्हें ही नुकसान होगा। इसलिए उनके हाथों में अब बंदूक और पत्थर नहीं हैं, बल्कि उनकी आंखों में शांति और आकांक्षाओं के सपने दिखाई देते हैं।आप कह सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ है। सबसे पहले बीती मई में लोकसभा चुनाव हुए और फिर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है।केन्द्र शासित प्रदेश के 1.40 करोड़ नागरिकों ने संवैधानिक मूल्यों में अपनी आस्था दोहराई है और अपने मतदान के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और देश के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया है। यह प्रमाण है कि पिछले चार-पांच वर्षों में भयमुक्त जम्मू-कश्मीर बनाने में बड़ी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों में किए गए कार्य, चाहे वह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का सशक्तीकरण हो या शांतिपूर्ण चुनाव कराना हो या विकास कार्य हो, इस बात का प्रमाण हैं कि जम्मू-कश्मीर अब विकास और खुशहाल के रास्ते पर चल पड़ा है। अब राज्य में स्कूल पूरे साल खुले रहते हैं। बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ रहे हैं। हालिया चुनावों में, उन जगहों में जमकर मतदान हुआ जिन्हें अबतक आतंकवादी संगठनों के गढ़ के रूप में देखा जाता था। तीन चरणों में क्रमश: 61.38%, 57.31% और 69.65% मतदान हुआ। जम्मू - कश्मीर में देश के अन्य भागों की तरह ही इतने भारी मतदान से साफ है कि कश्मीर की जनता भी चुनावी लोकतंत्र को गंभीरता से लेनी लगी है। उच्च मतदान दर का एक कारण यह भी हो सकता है कि घाटी में लगभग सभी राजनीतिक मतों और विचार धाराओं की पार्टियों ने चुनावों में भाग लिया। अपने स्तर पर जमात-ए-इस्लामी भी शामिल रही चुनावों में, जिसने बीते समय के दौरान राज्य में चुनावों का बहिष्कार करने की पुरज़ोर वकालत की थी। कुल मिलाकर, 90 सीटों के लिए 873 उम्मीदवार मैदान में थे। जमात ने स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में या इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी के सहयोगियों के रूप में चुनाव लड़ा। यह महत्वपूर्ण है , क्योंकि ; यह संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्य वैचारिक दुश्मन रहा है। सीमा पार से बार-बार आतंकवादी हमलों के कारण सुरक्षा बल, विशेष रूप से पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में, तनाव में रहे हैं। लेकिन, सुरक्षा बलों की चौकसी ने निश्चित रूप से चुनाव बिना किसी हिंसा के सम्पन्न करवा दिये। यह तो मानना होगा कि जम्मू-कश्मीर तेजी से बदलत जा रहा है। राज्य में धारा 370 के हटने से पहले पत्थरबाजी की घटनाओं में सैकड़ों लोग घायल हो रहे थे और मारे जा रहे थे। सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे थे, जिसमें अब 80-85 फीसद तक की कमी आई है। धारा 370 खत्म करने के बाद केन्द्र सरकार ने घाटी में राज्य की पुरानी सभ्यता और संस्कृति को फिर से जीवित करने के लिए बड़ी योजना पर काम शुरू किया। इसके तहत आस्था के केंद्रों और आध्यात्मिक स्थलों को नया रूप दिया गया। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के मेले और महोत्सव लगाए गये। यह मेले और महोत्सव आतंकवाद पनपने के कारण सालों से बंद थे। 2023 में नियंत्रण रेखा के पास स्थित मां शारदा देवी मंदिर का नवनिर्माण कराकर आजादी के बाद पहली बार पूजा के लिए खोला गया। सालों से बंद खीर भवानी मंदिर में फिर से दर्शन-पूजन का काम शुरू हुआ। खीर भवानी का मेला लगाया गया। इसमें पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे।सरकार ने 123 पुराने स्थलों का व्यवस्थित रूप से जीर्णोद्धार और मरम्मत कराकर जनता के लिए फिर से खोल दिया।केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक हजरत बल दरगाह के विकास के लिए 42 करोड़ रुपये दिए।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारस्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी। व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। शुभ समय। घर में अतिथियों का आगमन होगा।

वृष
धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। कोर्ट व कचहरी के काम मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कुबुद्धि हावी रहेगी। चिंता तथा तनाव रहेंगे। मित्रों से संबंध सुधरेंगे।

मिथुन
व्यय होगा। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। अज्ञात भय रहेगा।

कर्क
दूसरों के कार्य में दखल न दें। बड़ों की सलाह मानें। लाभ होगा। अपेक्षित कार्यों में विलंब होगा। मानसिक बेचैनी रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय में निश्चितता रहेगी। धैर्य रखें। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी।

सिंह
कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। शत्रु पस्त होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। स्थायी संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल होंगे। निवेश शुभ रहेगा।

कन्या
घर के सदस्यों के स्वास्थ्य व अध्ययन संबंधी चिंता रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। व्यापार में वृद्धि होगी।

तुला
लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे। बेवजह कहासुनी हो सकती है। पुराना रोग उभर सकता है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। व्यापार ठीक चलेगा। नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा।

वृश्चिक
प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। बेवजह कहासुनी हो सकती है। कानूनी अड़चन दूर होगी। व्यापार में वृद्धि होगी।

धनु
निवेश शुभ रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी में उच्चाधिकारी सहयोग करेंगे। शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं। दु:खद समाचार मिल सकता है। व्यर्थ भागदौड़ रहेगी।

मकर
व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रह सकता है। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। पुराना रोग परेशानी का कारण रह सकता है।

कुंभ
निवेश शुभ रहेगा। प्रसन्नता रहेगी। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी अपने के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। शारीरिक कष्ट संभव है।

मीन
शत्रु पस्त होंगे। सुख के साधन जुटेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पराक्रम बढ़ेगा। लंब समय से रुके कार्य सहज रूप से पूर्ण होंगे। कार्य की प्रशंसा होगी। दुष्टजनों से दूरी बनाए रखें।

संपादकीय

"न्याय की अदालतों से भी बड़ी एक अदालत है और वह है अंतरात्मा की अदालत। -महात्मा गांधी

छत्तीसगढ़ में करीब तीस नक्सलियों का मारा जाना नक्सलवाद के खिलाफ लंबे अरसे से चली आ रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कामयाबी है। यह सही वक्त हो सकता है, जब सुरक्षाबलों के शौर्य की बदौलत कमजोर हो रहे नक्सलियों को बगैर हिंसा के मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करने के प्रयास भी हों।

महत्वपूर्ण कामयाबी

ऐसे वक्त में, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद क्षेत्र के दौरे पर हों, तभी बस्तर के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों की सीमा पर हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों द्वारा करीब तीस नक्सलियों को मार गिराना देश में नक्सलवाद के खिलाफ लंबे अरसे से चली आ रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कामयाबी को दर्शाता है। यह राज्य में नक्सलियों व सुरक्षा बलों के बीच हुई अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ तो है ही, इसका महत्व तब और बढ़ जाता है, जब अभियान में शामिल सभी जवान पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों वाले ये इलाके लंबे समय से नक्सलियों के गढ़ रहे हैं, जहां वे न केवल सरकारी ढांचे और सुरक्षा बलों पर हमले करते रहे हैं, बल्कि स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर भी उन्हें आतंकित करते रहे हैं। पर राज्य में पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के खिलाफ अभियानों में सुरक्षा बलों को जो कामयाबियां मिली हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि सुरक्षा बल अब नक्सलियों के खिलाफ अधिक सशक्त, संगठित और योजनाबद्ध ढंग से तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार को अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ है, ऐसे में इस दौरान रिकॉर्ड संख्या में नक्सलियों का मारा जाना, खुद में एक उपलब्धि है और यह इस समस्या को खत्म करने के प्रति राजनीतिक इच्छाशक्ति को ही दिखाता है। नक्सलियों से मुठभेड़ पहले भी होती थीं, लेकिन अब फर्क यह है कि पहले जहां हर नक्सलवादी में नक्सलियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को भी नुकसान पहुंचते थे, जो उत्तरोत्तर कम होते दिख रहे हैं। दरअसल, नक्सलवाद महज कानून-व्यवस्था की समस्या न होकर सामाजिक-आर्थिक समस्या भी है। लिहाजा, वर्तमान में केंद्र व नक्सलवाद पीड़ित राज्यों की सरकारों के तालमेल से 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो रणनीति अपनाई जा रही है, उसकी सबसे खास बात ही यह है कि इसमें नक्सलवादियों के खात्मे के बाद पैदा हुए शून्य

को सरकारी योजनाओं से भरने के प्रयास न सिर्फ हो रहे हैं, होते दिख भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में नक्सलियों पर काबू पाने के कड़े प्रयासों के बावजूद मानवाधिकारों के हनन की शिकायतों में भी कमी आना राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही रणनीति में संतुलन को ही दर्शाता है। सुरक्षाबलों द्वारा दिखाए जा रहे शौर्य से नक्सलवादी निस्संदेह कमजोर हुए हैं, ऐसे में, यह सही वक्त हो सकता है, जब बगैर हिंसा के उन्हें मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करने के भी प्रयास हों।

सबसे बड़ा सवाल, सबूत कहां से लाएंगे

मैरिटल रेप में क्या सिर्फ पत्नी के बयानों के आधार पर ही पति को सजा दी जा सकती है? यह सवाल कानून के संभावित दुरुपयोग का नहीं, बल्कि अपराधशास्त्र के बुनियादी उसूलों से जुड़ा है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से विवाह संस्था और परिवार के ध्वस्त होने का भी खतरा है।

फिल्मी अदालतों में सबसे प्रचलित डायलॉग है कि कानून को सबूत चाहिए। अगर यह मान लें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैरिटल रेप यानी वैवाहिक दुष्कर्म के मामले भी अपराध के दायरे में आ जाएंगे, तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल सबूतों का रहेगा। कानून के अनुसार, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जांच कराती है। विवाहित महिला की मेडिकल जांच में सेक्स संबंधों की पुष्टि होना स्वाभाविक है। रेप के मामले गैर-जमानती होते हैं, जिनमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होती है। एफआईआर के बाद मैकेनिकल तरीके से पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और अदालतों में जमानत की अर्जी रद्द करने का प्रचलन बढ़ा है। कई साल बाद जब मुकदमे में ट्रायल शुरू होगा, तो सबूतों को लेकर प्रश्न खड़े होंगे। बेडरूम में पति-पत्नी के अलावा तीसरा व्यक्ति या सीसीटीवी नहीं होता। यह निजता का भी उल्लंघन है। सहमति के बगैर जबरदस्ती बनाए गए संबंध, यानी मैरिटल रेप में क्या सिर्फ पत्नी के बयानों के आधार पर ही पति को सजा दी जा सकती है? यह सवाल कानून के संभावित दुरुपयोग का नहीं, बल्कि अपराधशास्त्र के बुनियादी उसूलों से जुड़ा है। मैरिटल रेप अगर अपराध घोषित हो गया, तो यह कानून सभी धर्मों के विवाहित पुरुषों के ऊपर लागू होगा।

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील

मैरिटल रेप को अपराध का दर्जा देने वाले लोगों के तीन बड़े तर्क हैं- पहला, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, 29 फीसदी महिलाएं पारिवारिक हिंसा और यौन-उत्पीड़न का शिकार होती हैं। वैवाहिक दुष्कर्म शारीरिक हिंसा के साथ मानसिक तौर पर भी पीड़ादायक होता है। दूसरा, नए बीएनएस कानून की धारा-63 में दिए गए कानूनी अपवाद से विवाहित महिलाओं को रेप के दायरे से बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद-14 और 15 का उल्लंघन है। विवाहित महिलाओं को भी रेप के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तीसरा, किसी भी पुरुष या पति को स्त्री के साथ जबर्दस्ती संबंध बनाने का अधिकार नहीं है।

औपनिवेशिक आईपीसी कानून में विवाहित पुरुषों को दी गई सुरक्षा पितृसत्तात्मक है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में मैरिटल रेप को अपराध माना गया है। इसलिए भारत में सुप्रीम कोर्ट को प्रगतिशील नजरिये से फैसला देना चाहिए।

इसका विरोध करने वालों के भी तीन बड़े तर्क हैं-पहला, शारीरिक हिंसा के लिए पतियों के खिलाफ कानून में प्रावधान है। घरेलू हिंसा के खिलाफ वर्ष 2005 में बनाए गए कानून में यौन-शोषण भी जुड़ा है। कानून के अनुसार, पीड़िता को क्षतिग्रस्त के आधार पर तलाक के साथ गर्भपात का भी अधिकार है। दूसरा, निर्भया कांड के बाद जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने इसे अपराध की श्रेणी में रखने की सिफारिश की थी, जिसे तत्कालीन यूपीए सरकार ने नहीं माना। तीसरा, मैरिटल रेप संबंधी कानून में बदलाव के लिए अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और यूएन की एजेंसियों का दबाव है। दहेज उत्पीड़न मामलों में आईपीसी की धारा-498-ए के दुरुपयोग के खिलाफ संसद और सुप्रीम कोर्ट में हो रही चर्चा के साथ मैरिटल रेप से जुड़े विषयों पर भी विमर्श होना चाहिए।

सरकार ने संसद में बार-बार कहा है कि भारतीय समाज में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने पर विवाह संस्था कमजोर होने के साथ कानून का दुरुपयोग बढ़ेगा, इसलिए यह अपवाद नहीं हटना चाहिए। इन्हीं तर्कों के आधार पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर सरकार ने जवाब नहीं दिया, तो वे संविधान के अनुसार मामले का निपटारा करेंगे। इसलिए इस मामले से जुड़े सांविधानिक बिंदुओं का आकलन जरूरी है।

पहला, सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती फैसले में सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों के विभाजन पर मोहर लगाई थी। संविधान के अनुसार, शादी का विषय समवर्ती सूची में आता है। इस मामले पर केंद्र सरकार ने राज्यों की राय मांगी थी। 19 राज्यों में से 10 राज्यों ने विरोध में, तीन राज्यों ने समर्थन में और छह राज्यों ने असम्पृक्त राय दी थी। महिला आयोग ने भी इस मांग का विरोध किया। संविधान ने संसद और विधानसभा को कानून बनाने और उसे बदलने का अधिकार दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी सरकार को कानून में बदलाव के लिए निर्देश दिए थे। इसलिए सभी राज्यों का पक्ष जाने बगैर इस मामले में सुनवाई और फैसला संविधान सम्मत नहीं है।

दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों से समलैंगिक विवाह (सेम सेक्स मैरिज) को मान्यता मिलने के साथ व्यभिचार और अप्राकृतिक सेक्स अपराध के दायरे से बाहर हो गए हैं। इस मामले में कुछ याचिकाओं के अनुसार, स्त्री-पुरुष की समानता के आधार पर दुष्कर्म संबंधी अपराध को लिंग निरपेक्ष होना चाहिए। ऐसा होने पर पत्नियों के खिलाफ पति भी रेप का मामला दर्ज करा सकेंगे। ऐसा होने पर पारिवारिक व्यवस्था ध्वस्त होने के साथ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। प्रगतिशील कानून बनाने के साथ गलत और फर्जी मुकदमेबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान होना चाहिए। इसलिए जल्दी में अदालती सुनवाई करने के बजाय विधि आयोग और संसदीय समिति को इस मामले से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।

तीसरा, नए बीएनएस कानून की धारा-63 के अनुसार, 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध रेप अपराध के दायरे में आ सकते हैं। राजस्थान सरकार ने इस मामले में पक्षकार बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। हिमाचल प्रदेश ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दी है। दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट के अनेक जज किशोर बच्चों के बीच सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर रखने की बात कर रहे हैं। जनवरी 2019 में दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अगर लिव-इन रिलेशनशिप में पुरुष और महिला के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बने और बाद में पुरुष शादी से मुकर जाए, तो उसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। मैरिटल रेप से जुड़े फैसले का समाज के साथ कई अन्य कानूनों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस मामले पर तीन के बजाय पांच जजों की संविधान पीठ में सुनवाई होनी चाहिए।

जीवन धारा

स्वामी विवेकानंद

अपने प्रेम और नम्रता की परीक्षा करो। ईर्ष्यालु व्यक्ति नम्र और प्रेममय नहीं होता। ईर्ष्या एक भयंकर, भयावह पाप है। यह मनुष्य में अत्यंत रहस्यमय रीति से प्रवेश कर जाती है।

जिनका हृदय शुद्ध है, वे ईश्वर का दर्शन पाएंगे

हमसे पूछा जाता है, 'आपके धर्म से समाज को क्या लाभ है? समाज को सत्य की कसौटी बनाया गया है। यह तो बड़ी तर्कहीनता है। समाज केवल विकास की एक अवस्था है, जिसमें होकर हम गुजर रहे हैं। इस प्रकार तो हम एक वैज्ञानिक आविष्कार के लाभ अथवा उसकी उपयोगिता को एक शिशु के लिए उसकी उपयोगिता से जांचेंगे। यह अत्यंत असंगत है। यदि सामाजिक अवस्था स्थायी होती, तो यह शिशु के सदा शिशु ही बने रहने जैसी बात होती। पूर्ण मनुष्य शिशु नहीं हो सकता। यह शब्द 'मनुष्य-शिशु' ही विरोधाभासी है। इसलिए कोई समाज पूर्ण नहीं हो सकता। मनुष्य को ऐसी आरंभिक अवस्थाओं से आगे बढ़ना होगा और वह बढ़ेगा। समाज एक अवस्था तक अच्छा है, पर वह आदर्श नहीं बन सकता, वह निरंतर परिवर्तनशील है। संसार को जो चाहिए, वह है व्यक्तियों के माध्यम से विचार शक्ति। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, 'तुम स्वयं अपने कमल के फूल को खिलने में सहायता क्यों नहीं देते? भ्रमर तब अपने आप आएंगे।' संसार को ऐसे लोग चाहिए, जो ईश्वर के प्रेम में मतवाले हों। पहले अपने आप पर विश्वास करो, तब तुम ईश्वर में विश्वास करोगे। संसार छह श्रद्धालु मनुष्यों का इतिहास, छह गंभीर शुद्ध चरित्रवान मनुष्यों का इतिहास है।

हमें तीन वस्तुओं की आवश्यकता है। अनुभव करने के लिए हृदय की, कल्पना करने के लिए मस्तिष्क की, और काम करने के लिए हाथ की। पहले हमें बाहर निकलना चाहिए और अपने लिए समुचित उपकरण तैयार करने चाहिए। अपने को एक डाइनेमो बनाओ। पहले संसार के लिए महसूस करो। ऐसे समय में, जब संसार में सब मनुष्य काम करने को तैयार हैं, तो भावनाशील व्यक्ति कहां है? वह अनुभूति कहां है, जिसने इम्पेशियस लाथिला को उत्पन्न किया था? अपने प्रेम और नम्रता की परीक्षा करो। ईर्ष्यालु व्यक्ति नम्र और प्रेममय नहीं होता। ईर्ष्या एक भयंकर, भयावह पाप है। यह मनुष्य में अत्यंत रहस्यमय रीति से प्रवेश कर जाती है। अपने से पूछो, तुम्हारा मन घृणा अथवा ईर्ष्या की प्रतिक्रिया करता है या नहीं? संसार में जो टनों घृणा और क्रोध उड़ेला जा रहा है, उससे संसार का कितना भला हो रहा है? यदि तुम पवित्र हो, यदि तुम सशक्त हो, तो तुम, एक व्यक्ति, समस्त संसार के बराबर हो।

शुभ कार्य करने का दूसरा माध्यम- मस्तिष्क केवल सूखा सहारा रेगिस्तान मात्र है, क्योंकि वह अकेला उस समय तक कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पीछे अनुभूति न हो। उस प्रेम को, जो कभी असफल नहीं रहा, साथ लो, और तब मस्तिष्क कल्पना करेगा और हाथ पलाई करेगा। ऋषियों ने ईश्वर के स्वप्न देखे थे और उसके दर्शन किए हैं। जिनका हृदय शुद्ध है, वे ईश्वर का दर्शन पाएंगे। सब महान पुरुष ईश्वर दर्शन कर चुकने का दावा करते हैं। हजारों वर्ष पहले यह दिव्य दर्शन उपलब्ध हुआ है और इसके परे जो एकता है, वह स्वीकृत की जा चुकी है, और अब हमें जो करना है, वह है केवल इन महत्वपूर्ण रूप-रेखाओं को भरना।

घृणा को दूर करें

सूत्र

आजकल पूरी दुनिया में तेजी से नफरत फैलाई जा रही है। लेकिन दूसरों के प्रति घृणा और ईर्ष्या व्यक्तिगत ही नहीं, सामाजिक जीवन के लिए भी अभिशाप हैं। इससे किसी का भला नहीं हो सकता। यह पाप है, जो हमारे जीवन को कलुषित बनाता है। हमें घृणा एवं ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए और जीवन का वास्तविक आनंद पाने के लिए विनम्रता सीखनी चाहिए।

दूसरा पहलू

'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना ने प्रवासी मजदूरों की समस्या दूर कर दी है। मजदूर अब प्रवास स्थान पर राशन ले रहे हैं।

अब राशन की चिंता से मुक्त हो रहे प्रवासी मजदूर

देश में रोजगार प्रमुख समस्या बनी हुई है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आता है। गांव में रहने वाली एक बड़ी आबादी रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में प्रवास करती है। ऐसे में इनके सामने अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के साथ-साथ सबसे बड़ी चुनौती जन वितरण प्रणाली द्वारा मिलने वाला राशन होता है, जिसके लाभ से वे मजदूर अक्सर वंचित हो जाते हैं। चूंकि राशन कार्ड गांव में बना होता था, ऐसे में प्रवास के कारण वे अन्य स्थान पर इससे मिलने वाले सस्ते राशन का लाभ उठा नहीं पाते थे। लेकिन केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना ने इन प्रवासी मजदूरों की समस्या को दूर कर दिया है। अब वे मजदूर अपने प्रवास स्थान पर भी अपने राशन कार्ड के माध्यम से सस्ता अनाज खरीद कर परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम हो रहे हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए देश भर में एक केंद्रीय डाटाबेस विकसित किया गया है, जिसमें हर योग्य व्यक्ति का डाटा संग्रहीत होता है। यह योजना 'डिजिटल इंडिया' की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले लोकेश रविदास बताते हैं, 'मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का रहने वाला हूं और पिछले 20 वर्षों से परिवार के साथ काम के लिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों में जाता रहा हूं। मुझे स्थानीय दुकानदार से राशन खरीद कर लाना पड़ता था, जो अक्सर महंगा होता था। लेकिन अब काम की जगह पर ही मेरे परिवार को पीडीएस के माध्यम से सस्ता राशन मिल जाता है।' इसी ईंट भट्ठे पर काम करने वाले बिहार के बांका जिले के प्रमोद मांझी बताते हैं कि पीडीएस से राशन प्राप्त करने के लिए अब उन्हें बार-बार गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह कहते हैं, 'हम मजदूर यहीं काम करते हैं और पास के गांव से सस्ता राशन भी प्राप्त करते हैं, जिससे मेरे परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम हो गया है।' वह बताते हैं, 'पहले जब साल-दो साल पर हम अपने गांव वापस जाते थे, तो सरकारी राशन दुकान का मालिक कहता था कि दो साल से राशन नहीं लेने की वजह से दुबारा नाम काट दिया गया है। लिस्ट में दोबारा नाम जुड़वाने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने होंगे। इससे हमें आर्थिक और मानसिक, दोनों रूप से परेशानी होती थी। लेकिन इस योजना ने रोजगार के लिए अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले हम जैसे मजदूरों के जीवन को आसान बना दिया है। (जरूरी फीचर)

दीपांश रेंगर

यह 'डिजिटल इंडिया' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इससे राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।

ईंट भट्ठे पर काम करने वाले लोकेश रविदास बताते हैं कि 20 वर्षों से बाहर हैं। अब काम की जगह पर ही उनके परिवार को पीडीएस के माध्यम से सस्ता राशन मिल जाता है। बार-बार गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।

आंकड़े

स्वास्थ्य में सुधार

परिवारों द्वारा स्वास्थ्य सेवा पर किए जाने वाले खर्च में गिरावट दर्ज की गई है। 2021-22 में ओओपीई घटकर 39.4 प्रतिशत रह गई।

2013-2014	64.2%
2014-2015	62.6%
2017-2018	48.8%
2019-2020	47.1%
2021-2022	39.4%

आंकड़े स्वास्थ्य सेवा पर जेब से किए गए खर्च के

चोट : NHA

जाजलि की घोर तपस्या के बाद उन्हें सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें लगा कि उनके समान और कोई विद्वान नहीं है। तभी एक आकाशवाणी ने उनका घमंड तोड़ दिया।

ज्ञान का अधिकारी

काशी में तुलाधार वैश्य रहते थे। वह व्यापार करते हुए भी सदैव भगवान की भक्ति में रमे रहते थे। इनकी प्रशंसा सभी लोग करते। उन्हीं दिनों जाजलि नाम के एक ब्राह्मण समुद्र किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। एक बार सूखा वृक्ष समझकर जाजलि की जटा में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, वहीं उनके अंडे फूटे और बच्चे सयाने हुए। तब भी उनका ध्यान नहीं हटा।

इस घोर तपस्या से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें घमंड हो गया। जाजलि को ज्ञान कि उनके समान और कोई विद्वान नहीं। तभी आकाशवाणी हुई-आपका यह सोचना ठीक नहीं। आपको अभी ज्ञान ही कितना हुआ है? काशी में तुलाधार रहते हैं, वह भी ऐसी बात नहीं करते। इतना सुनते ही जाजलि तुलाधार के दर्शन के लिए काशी पहुंच गए। तुलाधार ने स्वागत-सत्कार किया और नम्रता से कहा- 'मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? जाजलि ने पूछा, आपको ऐसा निर्मल ज्ञान और व्यावसायिक बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? तुलाधार ने कहा कि सारा जगत भगवान का स्वरूप है, इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है। मिट्टी और सोने में जरा भी अंतर नहीं। जो मनुष्य किसी का भी बुरा नहीं सोचता, वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी है। जिन लोगों को ज्ञान का अभिमान हो जाता है, उन्हें वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। यह कहकर तुलाधार ने जाजलि को सदाचार का उपदेश दिए।

अंतर्यात्रा
संकलित

आज का इतिहास

टेरेसा को 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' की स्थापना की इजाजत मिली

मदर टेरेसा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और गरीबों तथा बंचितों के लिए उनकी सेवा के बारे में भी सभी जानते हैं। मदर टेरेसा को 7 अक्टूबर 1950 को वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी' की स्थापना करने की इजाजत मिली थी और इसकी शुरुआत उन्होंने कलकत्ता (अब कोलकाता) से की। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित की गई पहली संस्था में केवल 13 सदस्य थे, लेकिन उनसे जुड़े लोगों के सेवाभाव और गरीबों के लिए कुछ करने के जज्बे के दम पर आज संस्थान से जुड़े लाखों लोग देशभर में सैकड़ों अनाथालय, अस्पताल और धर्मार्थ केन्द्रों का संचालन कर रहे हैं। 1708 में सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह जी का नांदेड़ में निधन। उनपर अफगानिस्तान के एक हत्यारे गुल खान ने 19 सितंबर को चाकू से हमला किया था।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक और भारत के बाजार

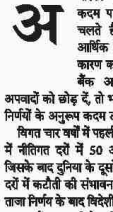

फेडरल रिजर्व की नीतिगत दरों में कटौती के बाद यदि विदेशी संस्थागत निवेशक चीन के बजाय भारतीय बाजारों का रुख कर रहे हैं, तो यह बेहतर संकेत है।

सतीश सिंह | आर्थिकी

अमेरिका के फेडरल रिजर्व के नक्शे-कदम पर दुनिया भर के केंद्रीय बैंक चलते हैं। हालांकि, सभी देशों की आर्थिक स्थिति अलग-अलग होने के कारण कभी-कभी कुछ देशों के केंद्रीय बैंक अलग निर्णय लेते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो भारत भी फेडरल रिजर्व बैंक के निर्णयों के अनुरूप कदम उठाता है।

विगत चार वर्षों में पहली बार फेडरल रिजर्व ने हाल ही में नीतिगत दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की, जिसके बाद दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंकों द्वारा भी नीतिगत दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। फेडरल रिजर्व के ताजा निर्णय के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार में ज्यादा निवेश किया है। दरअसल, डॉलर के कमजोर पड़ने, उधारी दर में कमी आने, निवेश व कारोबारों में तेजी आने आदि की संभावना बढ़ी है, जिसकी पुष्टि निवेश में तेजी से हो रही है। चीन फिलहाल सुशासन की समस्या से जूझ रहा है, जिसके कारण विदेशी निवेशक वहां निवेश करने से परहेज कर रहे हैं और कुछ निवेशक भारत का रुख कर रहे हैं। अमेरिका की तरह चीन में भी उत्पादन, खपत आदि मापदंडों की वृद्धि अपेक्षा से अधिक धीमी है। अगस्त महीने में बेरोजगारी दर छह महीनों के उच्चतम स्तर 5.3 प्रतिशत पर पहुंच गई और शहरी बेरोजगारी दर जुलाई में 17.1 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जो जून में 13 प्रतिशत थी। विकास दर में तेजी लाने के लिए चीन के केंद्रीय बैंक ने उधारी दरों में कटौती की है, ताकि उधारी में उठाव आए और आर्थिक गतिविधियों में तेजी। सवाल उठता है कि क्या फेडरल रिजर्व की तर्ज पर आगामी मौद्रिक समीक्षाओं में भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर में कटौती करेगा, क्योंकि महंगाई और विकास के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए फरवरी, 2023 के बाद से रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और यह 6.5 प्रतिशत पर बरकरार है। रिजर्व बैंक को रेपो दर में कटौती करने से पहले मौजूदा आर्थिक स्थिति, जीडीपी वृद्धि दर, महंगाई की स्थिति, आर्थिक गतिविधियों की गति आदि पर गहन विमर्श करना होगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े निरंतर बेहतर हो रहे हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, मूडीज ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखा है, लेकिन 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.6 प्रतिशत जताया है। ये आंकड़े विश्व के कई विकसित देशों से बेहतर हैं। खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई और अगस्त महीने में चार प्रतिशत से नीचे रही है और बारिश के खत्म होने के बाद खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आने का अनुमान है, जिससे आगामी महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति में और भी कमी आने के कयास लगाए जा रहे हैं। मूडीज ने 2025 और 2026 में भारत में मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत जताया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भी वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति घटकर 4.5 प्रतिशत रह सकती है। एचएसबीसी विनिर्माण पीएमआई सितंबर 2024 में घटकर 56.7 रह गया, जो अगस्त महीने में 57.5 रहा था। सेवा पीएमआई भी सितंबर महीने में घटकर 58.9 प्रतिशत रह गया, जो अगस्त महीने में 60.9 रहा था। बेशक, विनिर्माण और सेवा पीएमआई में अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। फिर भी, यह अभी 50 से ऊपर है, जो दर्शाता है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में तेजी का रुख बना हुआ है। रेपो दर फरवरी 2023 से 6.5 प्रतिशत के स्तर पर कायम है। फिर भी, उधारी के उठाव में तेजी बनी हुई है। दिसंबर, 2023 की तुलना में ऋण उठाव में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 9 अगस्त 2024 को समाप्त पखवाड़े के लिए क्रमिक रूप से 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निरपेक्ष रूप से, पिछले आठ महीनों में, ऋण उठाव 9.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 9 अगस्त, 2024 तक 168.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह एक अच्छा संकेत है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर नाहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर नाहेश्वरी, संपादक : राकेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ मुख्यनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 235 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

जेलों में जातीय आधार पर श्रम विभाजन

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में जेलों में जातिगत भेदभाव के साथ श्रम विभाजन पर रोक लगाने के लिये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत प्रभाव से जेल मैनुअल में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसे संविधान के आर्टिकल 15 का सरासर उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने कहा कि रसोई व सफाई का काम जाति के आधार पर बांटा जाना अनुचित है। दरअसल, एक महिला पत्रकार द्वारा दायर जनहित याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि जेल नियमावली जाति के आधार पर कामों के बंटवारे में भेदभाव करती है। खाना बनाने का काम ऊंची जाति के लोगों को देना व सफाई का काम निचली जातियों के कैदियों को देना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। जो जेलों में जातिगत भेदभाव को बढ़ाता है। कोर्ट का कहना था कि जाति के आधार पर कामों का बंटवारा औपनिवेशिक सोच का पर्याय है, जिसे स्वतंत्र भारत में जारी नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट है जेल नियमावली साफ तौर पर भेदभाव करती है। साथ ही कहा कि नियमावली में जाति से जुड़ी डिटेल्स का उल्लेख असंवैधानिक है। कोर्ट ने खरी-खरी सुनाते हुए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के जेल मैन्युअल में तुरंत बदलाव करने को कहा है। साथ ही राज्यों को इस फैसले के अनुपालन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस जेबी परदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। दरअसल एक पत्रकार सुकन्या शांता ने सबसे पहले यह मामला उठाया था। उनका कहना था कि देश के 17 राज्यों की जेलों में कैदियों के साथ यह भेदभाव हो रहा है। उन्होंने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तीन महीनों में नियमों में बदलाव करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पहली सुनवाई जनवरी 2024 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। छह महीने के भीतर केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने ही अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया। उल्लेखनीय है कि पत्रकार सुकन्या ने वर्ष 2020 में एक शोध रिपोर्ट तैयार की थी। जिसमें तीन मुख्य राज्यों का उदाहरण दिया गया था। जिसमें राजस्थान का उल्लेख किया गया था कि यदि कैदी नाई है तो उसे बाल व दाढ़ी बनाने का काम मिलेगा, ब्राह्मण कैदी को खाना बनाने का काम मिलेगा और वाल्मीकि कैदी को सफाई का काम दिया जाता था। वहीं उत्तर प्रदेश के जेल मैन्युअल 1941 में जातिगत पूर्वाग्रहों को बनाये रखने वाले प्रावधानों का उल्लेख पाया गया। गृह मंत्रालय ने भी फरवरी में एक नोटिस जारी करके कहा था कि ये भेदभाव गैरकानूनी है। साथ ही कहा कि जेल मैन्युअल कैदियों को धर्म व जाति के आधार पर बांटते हैं। उसी आधार पर काम बांटते हैं। साथ ही राज्यों व केंद्र सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि उनके राज्यों में जेल के नियमों में किसी तरह का भेदभावपूर्ण प्रावधान न हो। शीर्ष अदालत ने इस भेदभाव को औपनिवेशिक शासन की विरासत बताते हुए तुरंत खत्म करने को कहा क्योंकि हर कैदी भी गरिमा से जीवन जीने का अधिकार रखता है।

दक्षिण की रोचक जंग : पवन कल्याण बनाम उदयनिधि

नीरज कुमार दुबे

दक्षिण की राजनीति में दो राजनेता हाल के समय में तेजी से उभर कर आये हैं। एक हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जिन्होंने सनातन धर्म का विरोध कर अपना राजनीतिक कॅरियर चमकाया और राज्य के उपमुख्यमंत्री पद पर जा पहुँचे। दूसरे नेता हैं फिल्मों से राजनीति में आये पवन कल्याण जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पद पर जा पहुँचे। अब स्थिति यह है कि एक उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण चेतावनी देते हैं कि सनातन को मिटाने की इच्छा रखने वाले

हम आपको याद दिला दें कि उदयनिधि ने पिछले साल सनातन के उन्मूलन की अपील की थी, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने पिछले साल सितंबर में यह टिप्पणी करके राजनीतिक आक्रोश पैदा कर दिया था कि 'सनातन धर्म' को मिटा दिया जाना चाहिए। इस धर्म को मच्छरों, डेंगू, मलेरिया, बुखार और कोरोना के बराबर बताते हुए उन्होंने कहा था कि इसे उन बीमारियों की तरह खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का समूल नाश दरअसल मानवता और समानता को बनाए रखने के हित में होगा। उदयनिधि ने बाद में स्पष्ट किया था कि उन्होंने कभी भी 'सनातन धर्म' का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह धर्म लोगों को जाति एवं धर्म के नाम पर विभाजित करता है। जहां तक पवन कल्याण के बयान की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि ह्यसनातन धर्मह्ल का विरोध करने वालों का सफाया हो जाएगा। जनसेना पार्टी के प्रमुख ने कहा था कि आप सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकते। अगर कोई सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो बता दूं, आप खत्म हो जाएंगे। पवन कल्याण ने तिरुपति लड्डू विवाद पर वाराही घोषणा पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह मत कहिए कि सनातन धर्म एक वायरस की तरह है और यह नष्ट कर देगा... जिसने भी यह कहा है, मैं आपको बता दूं सर... आप सनातन धर्म को मिटा नहीं सकते। अगर कोई सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करता है, तो मैं आपको बता दूं, भगवान बालाजी के समक्ष कह रहा हूं, आप मिट जाएंगे।

खुद मिट जायेंगे तो जवाब में दूसरे उपमुख्यमंत्री उदयनिधि कहते हैं कि देखते हैं।

हम आपको बता दें कि तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने आंध्र प्रदेश के अपने समकक्ष पवन कल्याण की ह्यसनातन धर्मह्ल संबंधी टिप्पणी पर अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए सिर्फ इतना कहा, ह्यदेखते हैं और इंतजार करते हैं।' जब पत्रकारों ने पवन कल्याण की चेतावनी पर उदयनिधि की प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने कहा, ठीक है, इंतजार करते हैं और देखते हैं।'

हम आपको याद दिला दें कि उदयनिधि ने पिछले साल ह्यसनातनह्ल के ह्यउन्मूलनह्ल की अपील की थी, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने पिछले साल सितंबर में यह टिप्पणी करके राजनीतिक आक्रोश पैदा कर दिया था कि 'सनातन धर्म' को मिटा दिया जाना चाहिए। इस धर्म को मच्छरों, डेंगू, मलेरिया, बुखार और कोरोना के बराबर बताते हुए उन्होंने कहा था कि इसे उन बीमारियों की तरह खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का समूल नाश दरअसल मानवता और समानता को बनाए रखने के हित में होगा। उदयनिधि ने बाद में स्पष्ट किया था कि उन्होंने कभी भी 'सनातन धर्म' का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह धर्म लोगों को जाति एवं धर्म के नाम पर विभाजित करता है।

जहां तक पवन कल्याण के बयान की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि ह्यसनातन धर्मह्ल का विरोध करने वालों का सफाया हो जाएगा। जनसेना पार्टी के प्रमुख ने कहा था कि आप सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकते। अगर कोई सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो बता दूं, आप खत्म हो जाएंगे। पवन कल्याण ने तिरुपति लड्डू विवाद पर वाराही घोषणा पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ह्यह्ययह मत कहिए कि सनातन धर्म एक वायरस की तरह है और यह नष्ट कर देगा... जिसने भी यह कहा है, मैं आपको बता दूं सर... आप सनातन धर्म को मिटा नहीं सकते। अगर कोई सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करता है, तो मैं आपको बता दूं, भगवान बालाजी के समक्ष कह रहा हूं, आप मिट जाएंगे।

पवन कल्याण ने साथ ही लड्डू में मिलावट के मुद्दे को पिछले पांच सालों से ह्यसनातन धर्मह्ल पर किया जा रहा हमला बताया। हम आपको बता दें कि पवन कल्याण ने इस सप्ताह तिरुमला मंदिर में अपनी 11 दिवसीय तपस्या (प्रायश्चित दीक्षा) संपन्न की थी जो उन्होंने पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार के कथित पापों का प्रायश्चित करने के लिए की थी।

बहरहाल, दक्षिण की राजनीति में धर्म पहले इतनी प्रभावी भूमिका नहीं निभाता था जितनी अब देखी जा रही है। देखना होगा कि पवन कल्याण और उदयनिधि स्टालिन के बीच शुरू हुई यह राजनीतिक जंग किस मुकाम पर पहुंची है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

एग्जिट पोल ने बढ़ाया कांग्रेस का हौसला

अशोक भाटिया, मुंबई

इंडिया गठबंधन का जब गठन हुआ था तब दूसरे दलों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था कि यह गठबंधन क्या करेगा? उत्तरप्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी फिर फेल जो जाएगी वगैरह , पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है । बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली अच्छी सफलता के बाद दो राज्यों हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में फिर से इस अलायंस की धमक दिखने लगी है। एग्जीट पोल के नतीजों में जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बहुमत के करीब दिख रही है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बड़ी जीत हासिल करने की ओर है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही होते हैं तो राहुल गांधी के लिए इसके गहरे राजनीतिक असर होंगे। राहुल गांधी की बीते दो दशक की राजनीति में यह संभवतः पहली बार होगा जब कांग्रेस पार्टी लगातार किसी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है।

एग्जिट पोल के औसतन नतीजे देखें जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस को 40-48 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा को 27 से 32 सीटें मिल सकती हैं। जबकि पीडीपी को 6-12 और अन्य को 6-11 सीटें मिलने की संभावना है। यहां निश्चित तौर पर पीडीपी-कांग्रेस बहुमत के करीब है। अगर वह बहुमत से दूर रहता है तो ऐसा संभव है कि उसे पीडीपी का साथ मिल जाए। दूसरी तरफ भाजपा और अन्य जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा समर्थित निर्दलीय हैं, के दम पर 40+ हो रही है। यदि हरियाणा के चुनाव बाद सर्वेक्षण देखें तो वहां की 90 सदस्यीय सीट पर कांग्रेस पार्टी 55 से 62 सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही है। उसके लिए यह एक बहुत बड़ी जीत कहलाएगी। इससे निश्चित तौर पर उत्तर भारत में पार्टी को अपने दम पर अपेक्षाकृत एक बड़े राज्य में सत्ता मिलेगी। अभी उत्तर भारत में वह केवल हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह तीन राज्यों में अपने दम पर सरकार में होगी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है।

लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं। वह हरियाणा में मतदान से चंद घंटों पहले वहां के बड़े दलित नेता अशोक तंवर को पार्टी में वापसी करवाते हैं। अशोक तंवर वही नेता हैं जिन्होंने बीते 2019 के विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले अध्यक्ष पद से हटाए जाने के कारण कांग्रेस छोड़ दिया था। वह बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर कुमारी शैलजा के खिलाफ मैदान में थे।

वह राज्य में हुड्डा कैंप और सैलजा कैंप से इतर शुरू से राहुल कैंप के नेता रहे हैं। लेकिन, बतौर आलाकमान राहुल गांधी के कमजोर पड़ने और हुड्डा से मनमुटाव के कारण अशोक तंवर को कांग्रेस छोड़ना पड़ा था। लेकिन, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राहुल गांधी 2019 वाले राहुल गांधी नहीं हैं। हुड्डा कैंप की तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी टीम ने हरियाणा के चुनाव में अपनी पकड़ बनाए रखी। दोनों राज्यों के एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो यह भी साबित होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों में घटौती और इंडिया गठबंधन की सीटों में शानदार बढ़ोतरी कोई तुक्का नहीं था। इससे यह साबित होगा कि राष्ट्रीय के साथ राज्यों के स्तर पर अब एनडीए से जनता का मोहभंग होने लगा है। वह अब विकल्प तलाशने लगी है।

दो राज्यों में कांग्रेस की बढ़त का असर महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है। बीते लोकसभा में उसे वहां बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इसके आलावा महाराष्ट्र में विपक्षी इंडिया गठबंधन और आक्रामक होगी।

महाराष्ट्र में पार्टी के सामने महाविकास अघाड़ी से मजबूती से निपटने की चुनौती है। पार्टी यहां शिवसेना (शिंदे गुट) के साथ सरकार में हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने वाली पार्टी ने एनसीपी से अलग होकर आए शरद पवार के भतीजे अजित पवार को अपने खेमे में कर चुकी है। ऐसे में पार्टी को चुनाव के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दे को लेकर सावधानी बरतनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी का मुद्दा उसके ऊपर ही भारी पड़ जाए। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होगा। ऐसे में भाजपा के लिए समय के हिसाब से आगे बढ़ना होगा।दूसरी तरफ लोकसभा की हार के बाद एनडीए के नेताओं और कार्यकताओं का उत्साह भी कमजोर पड़ेगा।

झारखंड में भाजपा जेएमएम को हटाकर सत्ता में आने के लिए जोर आजमाइश कर रही है । पार्टी ने इस काम के लिए चंपाई सोरेन को अपने साथ मिलाया है। खास बात है कि भाजपा बड़ी संख्या में चुनाव से पहले विरोधी दल के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करती है। इसके अलावा उन्हें टिकट भी देती है। ऐसे में पार्टी के पुराने कार्यकताओं के साथ ही वरिष्ठ नेताओं में असंतोष पनपने लगता है। हरियाणा में पार्टी को इस बार टिकट बंटवारों में बड़े पैमाने पर बगावत का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी हरियाणा से सबक लेते हुए झारखंड में भी फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहेगी।देखा जाय तो पार्टी राज्य में सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए कई राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल देती है। हालांकि, इस चुनाव में भाजपा को यह दांव कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा पार्टी की तरफ से कई पुराने चेहरों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाया जाता है। इस बार पार्टी की यह रणनीति भी बेअसर साबित होती नजर आ रही है।वर्तमान में दो विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल से इतना तो तय है कि भाजपा को अब अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा।

उधर राहुल गाँधी अपनी तेजी से उड़ती पतंग देख अपने सहयोगियों पर ही दबाव बनाने की कोशिश करने लगे है ।

उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। इसके लिए कांग्रेस 50-50 सीट शेयरिंग फॉमूर्ला चाहती है यानी 5-5 सीटों पर दोनों दल लड़ें लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार ही नहीं हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ,राहुल गांधी से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं । समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है। इसी कोशिश में अखिलेश यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी से सीट की मांग की थी। लेकिन राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक भी सीट नहीं दी।

राहुल गांधी से मिला ये धोखा अखिलेश शायद ही भूले होंगे और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते हैं। वहीं भाजपा अखिलेश और राहुल की कथित दोस्ती पर कटाक्ष कर रही है। वैसे कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की रणनीति भी तैयार कर ली है।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने उन सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है, जहां-जहां उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों के आवेदन मंगाने भी शुरू कर दिए हैं। इसके जरिए कांग्रेस ने अखिलेश तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है।

झारखंड में भाजपा जेएमएम को हटाकर सत्ता में आने के लिए जोर आजमाइश कर रही है । पार्टी ने इस काम के लिए चंपाई सोरेन को अपने साथ मिलाया है। खास बात है कि भाजपा बड़ी संख्या में चुनाव से पहले विरोधी दल के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करती है। इसके अलावा उन्हें टिकट भी देती है। ऐसे में पार्टी के पुराने कार्यकताओं के साथ ही वरिष्ठ नेताओं में असंतोष पनपने लगता है। हरियाणा में पार्टी को इस बार टिकट बंटवारों में बड़े पैमाने पर बगावत का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी हरियाणा से सबक लेते हुए झारखंड में भी फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहेगी।देखा जाय तो पार्टी राज्य में सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए कई राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल देती है। हालांकि, इस चुनाव में भाजपा को यह दांव कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा पार्टी की तरफ से कई पुराने चेहरों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाया जाता है। इस बार पार्टी की यह रणनीति भी बेअसर साबित होती नजर आ रही है।वर्तमान में दो विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल से इतना तो तय है कि भाजपा को अब अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। उधर राहुल गाँधी अपनी तेजी से उड़ती पतंग देख अपने सहयोगियों पर ही दबाव बनाने की कोशिश करने लगे है । उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। इसके लिए कांग्रेस 50-50 सीट शेयरिंग फॉमूर्ला चाहती है यानी 5-5 सीटों पर दोनों दल लड़ें लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार ही नहीं हैं।

संपादकीय

कैदियों जातिगत भेदभाव अमानवीय

देश की सर्वोच्च अदालत ने उप्र सहित 17 राज्यों की जेलों में कैदियों से जातिगत भेदभाव और जाति के आधार पर काम आवंटित करने की अमानवीय परंपरा पर सख्त और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्यों को उनके जेल मेन्युअल बदलने का आदेश दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में निचली जातियों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम देना और ऊंची जाति के कैदियों को खाना पकाने का काम सौंपना सरासर गलत और भेदभावपूर्ण है। यह संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने कुछ राज्यों के जेल मैनुअल के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव, कार्य बंटवारे और कैदियों को उनकी जाति के अनुसार अलग वार्डों में रखने की प्रथा की निंदा की। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेलों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सुकन्या शांता ने जेलों में जातिगत भेदभाव के इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने 'सुकन्या शांता बनाम भारत सरकार' मामले पर गुरूवार को अपना फैसला सुनाया। सुकन्या की याचिका में आरोप लगाया गया था कि देश के कुछ राज्यों के जेल मैनुअल जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी 17 राज्यों से जेल के अंदर जातिगत भेदभाव और कैदियों को जाति के आधार पर काम दिए जाने पर जवाब मांगा था। हालांकि छह महीने बीतने के बाद भी केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने ही अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया। तीन जजों की पीठ ने फैसले में कहा कि इस तरह की प्रथाओं से जेलों में श्रम का गलत बंटवारा होता है तथा जाति आदि के आधार पर श्रम आवंटन की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के जेल नियमावली में जाति-आधारित भेदभाव की प्रथा की निंदा की। अदालत ने कहा कि सभी जातियों के कैदियों के साथ मानवीय तरीके से और समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कुछ वर्ग के कैदियों को जेलों में काम का सही बंटवारा मिलना अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि कैदियों को खतरनाक परिस्थितियों में सीवर टैंकों की सफाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पीठ ने जाति के आधार पर भेदभाव के मामलों से निपटने के लिए पुलिस को ईमानदारी से काम करने का आदेश दिया और राज्य जेल मैनुअल के आपत्तिजनक नियमों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने राज्यों से तीन महीने के भीतर इनमें संशोधन करने का आदेश दिया। आजादी के पचहत्तर साल बाद भी देश की जेलों में कैदियों को काम के बंटवारे के मामले में भी घोर जातिवाद चल रहा है, यह खबर ही अपने आप में चौंकाने वाली है। और यह केवल जातीय घृणा के कारण नहीं बल्कि देश के राज्यों के जेल मेन्युअल के हिसाब से हो रहा है। यह बात ही अपने आप में गुलामी की निशानी है। जब हर क्षेत्र से जातिगत भेदभाव समाप्त करने की बात की जा रही हो, जेल में यह अमानवीय प्रथा वैधानिक ढंग से लागू हो, यह अपने आप शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एकदम सही और प्रगतिशील फैसला सुनाया है। इससे जेलों में बंद कैदियों को काम के बंटवारे में जातिगत दुराग्रह पर अंकुश लगेगा। जेल में बंद कैदी अपराधी और उसी कारण सजायाफ्ता होते हैं। अपराधियों के बीच भी जातिगत भेदभाव करना बीमार मानसिकता की निशानी है। यह जितनी जल्द खत्म होगी, वह देशहित में है।

अरविंद केजरीवाल का संघ प्रमुख से प्रश्न

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जंतर - मंतर पर जनता की अदालत लगाई लेकिन उसमें उन्होंने प्रश्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से पूछा। बाद में इन पर पत्र लिख दिया। उन्होंने पांच प्रश्न पूछे। एक, जिस तरह से भाजपा देश भर में लालच देकर डराकर या ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी राजनीतिक पार्टी और उनके नेताओं को तोड़ रही है, गैर भाजपा सरकारों को गिरा रही है क्या यह देश के लिए सही है? क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? दो, सबसे भ्रष्ट नेताओं को भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल किया है। जिन नेताओं को पहले भाजपा के नेताओं ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला था कुछ दिन बाद उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हैं क्या ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? तीन, भाजपा आरएसएस की कोख से पैदा हुई है। कहा जाता है कि यह देखना संघ की जिम्मेदारी है कि भाजपा पदभ्रष्ट न हो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप आज की भाजपा के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी बीजेपी को यह सब करने से रोकने की कोशिश की उनसे इस बारे में सवाल पूछे?

अवधेश

प्रश्न चार, जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है। जब नड्डा ने यह कहा तो आपके दिल पर क्या गुजरी? आपको दुख नहीं हुआ? आरएसएस बीजेपी के लिए मां सम्मान है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि वह पलटकर मातृ तुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है? पांच, आप लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि पार्टी में 75 साल से ऊपर के नेता रिटायर होंगे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कई नेताओं को रिटायर कर दिया गया। अब अमित शाह कह रहे हैं कि यह नियम मोदी पर लागू नहीं होगा। क्या आप इससे सहमत हैं? आम देखेंगे की हाल के वर्षों में विरोधी पार्टियां ,नेता , एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया पर सक्रिय नैरेटिव सेटर्स सभी भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध करते हुए, हमले करते हुए संघ को निशाना बनाते हैं और कुछ तो भाजपा से ज्यादा संघ को ही हमले का शिकार बनाते रहते हैं। राहुल गांधी उनमें शीर्ष पर हैं जिनका कोई भाषण और वक्तव्य संघ पर हमले के बिना नहीं संपन्न होता। किंतु राजनीतिक नेताओं में अरविंद केजरीवाल की तरह प्रश्न इससे पहले कभी किसी ने पूछा नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने नेताओं को डराने-धमकाने या ईडी सीबीआई आदि का डर दिखाने या फिर 75 वर्ष की उम्र आदि को लेकर जो कहा यह उनका अपना दृष्टिकोण है। इन प्रश्नों और वक्तव्यों की मूल बात दूसरी है। जेल से बाहर आने के बाद जब उन्होंने इस्तीफा की घोषणा की तो यही कहा कि वह जनता के बीच जाएंगे और जनता उन्हें निर्दोष साबित कर देगी तो फिर वह मुख्यमंत्री बन जायेंगे। इस तरह जंतर मंतर पर जनता की अदालत उनके उसी अभियान की शुरुआत थी। स्वाभाविक ही ऐसे अभियान में हुए बहुत सोच समझकर साधे हुए अंदाज में और अपनी चतुर और चालक राजनीति के तहत ही कोई विषय उठाएंगे। इसलिए कम से कम अरविंद केजरीवाल और आपकी दृष्टि से संघ प्रमुख के पूछे गए इन प्रश्नों को आप यूं ही खारिज नहीं कर सकते।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य प्रणाली में कभी भी राजनीतिक प्रश्न तो छोड़िए नियमित होने वाली निंदा आलोचना या हमले के उत्तर देने या किसी भी प्रश्न पर स्पष्टीकरण देने का चरित्र नहीं है। संघ पर गहरी दृष्टि रखने वाले जानते हैं कि इन सबसे अप्रभावित रहते हुए अपने उद्देश्यों के लिए निर्धारित कार्यों और आयोजनों में लगे रहते हैं। यही नहीं वह मीडिया या अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से सक्रिय लोगों से भी निवेदन करते हैं कि संघ की आलोचना या होने वाले हमले के उत्तर में अपना उत्तर में समय ना लगे। संघ के किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात करिए तो उनका उत्तर यही होता है कि यह सब हमें अपने लक्ष्य और उद्देश्यों में बाधा डालने वाली होती है इसलिए इन सबसे अप्रभावित होकर चरैवेति चरैवेति के सिद्धांत पर केवल काम करते रहना है। हमारा काम ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। इसलिए हमारे स्वयंसेवक प्रतिबद्ध समर्थक कभी इन सब से प्रभावित होकर विचलित नहीं होते। कारण, उनका हमारा सच पता है और वह स्वयं इस सच के साथ एकाकार होते हैं।

वैसे अरविंद केजरीवाल के राजस्व अधिकारी के समय एनजीओ और सूचना अधिकार कार्यकर्ता फिर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना अभियान और अंततः आम आदमी पार्टी की अब तक की गतिविधियों पर ध्यान रखने वाले बिना किसी हिचक के बोल सकते हैं कि किसी सकारात्मक उद्देश्य से उन्होंने ये पांचो प्रश्न नहीं पूछे होंगे। यह सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद सत्ता और राजनीति के स्तर पर हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रवाद पर फोकस कर विचारधारा पर ऐसे ऐसे ऐतिहासिक निर्णय और कार्य हुए जिनकी पहले कल्पना नहीं की गई थी। नरेंद्र मोदी के भाषणों , वक्तव्यों, नीतियों और व्यवहारों से हिंदुत्व विचारधारा वाले केवल संघ संगठन परिवार ही नहीं बाहर के संगठनों समूहों के अंदर भी उत्साह और आशा का संचार हुआ। इसके साथ यह भी सच है कि पिछले कुछ समय से मोदी सरकार और भाजपा के संदर्भ में निराशा चिंता कुछ हद तक विरोध और कार्यकर्ताओं समर्थकों के अंदर निष्क्रियता का व्यवहार देखा गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के समाचार पत्र के साक्षात्कार में भाजपा अब बड़ा संगठन हो गया और उसे संघ की उस रूप में आवश्यकता नहीं है जैसे आसपास और अचंभित करने वाले वक्तव्य ने पूरे संगठन परिवार और प्रतिबद्ध समर्थकों के मन में वैचारिक उथल-पुथल पैदा किया। इस पर भाजपा ने कभी स्पष्टीकरण नहीं दिया और संघ की ओर से कोई सार्वजनिक वक्तव्य आने का कारण नहीं था। इसलिए इसे लेकर पैदा हुआ संभ्रम किसी न किसी रूप में अभी भी कायम है। हालांकि विरोधियों द्वारा सनातन हिंदुत्व भारत की एकता अखंडता या जाति संप्रदाय क्षेत्र भाषा आदि के आधार पर दिए गए वक्तव्य के विरुद्ध प्रतिक्रियाएं हैं और इसका काम या ज्यादा लाभ राजनीति में भाजपा को मिलेगा। बावजूद अरविंद केजरीवाल और उनके जैसे लोगों को अच्छी तरह पता है कि लोगों के अंतर मन में ऐसे प्रश्न है और अगर कुछ प्रतिशत के भीतर भी या भाव पैदा करने में सफल रहे की भाई प्रश्न तो उन्होंने सही पूछा है तो फिर उनकी राजनीति की दृष्टि से या लाभकारी होगा। दिल्ली प्रदेश में खासकर विधानसभा चुनाव में भाजपा 2015 से आज तक अरविंद केजरीवाल के समक्ष किसी तरह की चुनौती नहीं पेश कर सकी और उनके लिए की राजनीति के लिए भले वह जेल में रहे हो या बाहर एक प्रकार से खुला मैदान रहा है। यहां सॉन्ग पुराने जनसंघ और दूसरे संगठनों से जुड़े लोगों की बड़ी संख्या है और उनमें एक बड़ा वर्ग आम आदमी पार्टी के साथ भी आया। अनेक विधायक आपको पूर्व में भाजपा से प्रत्यक्ष परोक्ष जुड़े हुए रहे। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद स्वयं आम आदमी पार्टी के अंदर या भाव पैदा हुआ कि भ्रष्टाचार तो हुआ है और हमारे नेताओं ने अनैतिक और भ्रष्ट आचरण किया है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के मुड़कर दूसरी ओर यानी भाजपा की ओर जाने की संभावना का खतरा भी बड़ा हुआ है। राजनीतिक परिस्थितियों में भाजपा ने बाहर से आए अनेक नेताओं को वह स्थान दिया जिनके आचरण की पहले आलोचना की जाती थी और चीन के विरुद्ध नेताओं कार्यकर्ताओं और संगठन परिवार के लोगों ने संघर्ष किया। लोगों के अंतर्मन में इसे लेकर नाराजगी और नायरस्य का भाव है जिसे ना करना केवल सच की अनदेखी करना होगा। भाजपा की ओर से अरविंद केजरीवाल के प्रश्न पर मुख्य उत्तर यही है कि पहले वह बताएं कि अन्ना हजारे के बारे में उनकी क्या राय है या उन्होंने उन्हें धोखा क्यों दिया? वे अपने भ्रष्टाचार के बारे में स्पष्टीकरण दें। हमारी राजनीति में प्रश्न का सीधा उत्तर देने की परंपरा समाप्त है और इसके और प्रतिक्रिया में केवल ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जो दूसरे के लिए और सुविधा उत्पन्न करें। इस मामले में एक हफ्ता केजरीवाल किया रणनीतिक सफलता है क्योंकि संघ के बारे में और स्वयं भाजपा पर उठाए गए उनके प्रश्नों का उत्तर भाजपा की ओर से नहीं मिल सकता।

निश्चय ही वह इसके आगे की रणनीति बना चुके होंगे और भाजपा के साथ संघ को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। किंतु यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य इस बात का स्वयं प्रमाण है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज भी एक नैतिक आदर्शऔर सुचित्रा से भरा हुआ संगठन मानते हैं और तभी उन्होंने इस तरह के प्रश्न किया है। केजरीवाल को भी स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर संघ के बारे में उनकी सोच क्या है। कारण राहुल गांधी और दूसरे नेता संघ को हमेशा अपनी राजनीति साधने और मुसलमानों सहित एक बड़े वर्ग का वोट पाने के लक्ष्य से संघ को एक फासिस्ट हिंसक दूसरे समुदायों से नफरत करने वाला अनैतिक संगठन घोषित करते रहते हैं। भले अपनी राजनीतिक हित की दृष्टि से ही केजरीवाल ने इसके विपरीत संघ को तत्काल वर्तमान झूठ अनैतिक और भट्ट की हुई राजनीति तथा सार्वजनिक जीवन में ऐसा संगठन माना है जिसके अपने चरित्र में नैतिक अतः शक्ति विद्यमान है। या बात अलग है कि अन्ना हजारे अभियान के समय जब सॉन्ग ने कहा की राष्ट्र हित का ध्यान रखते हुए संघ के स्वयंसेवक अपने आप उसमें सहयोग के लिए लगे थे तो उन्होंने इसका खंडन कर दिया था। तब उनका बयान संघ प्रमुख के विरुद्ध अनदर वाला था। सच यह है कि अरविंद केजरीवाल ही नहीं उनके जैसे सक्रीय ज्यादातर एक्टिविस्टों का संघ के स्वयंसेवकों के साथ व्यक्तिगत और कार्यगत संबंध होते हैं क्योंकि वह देखते हैं कि उनके कार्यक्रमों अभियानों में किस तरह ही है स्वार्थ रहित और अनुशासित होकर सक्रिय रहते हैं। लेकिन राजनीति की दृष्टि से उन्हें समर्थन करना शायद लाभकारी नहीं लगता और फिर व्यक्तिगत संबंध रखते हुए भी सार्वजनिक रूप से अनर्गल बयान बाजी करते रहते हैं। किंतु अरविंद केजरीवाल की राजनीति में भाजपा के विरोध और स्वयं उनके संस्कार के कारण अनेक असत्य अनैतिक सत्यता अनैतिकता आदि होते हुए भी हिंदुत्व भारत राष्ट्रवादके संदर्भ में हमेशा मुखर और अलग स्वर रहे हैं। जेल से आने के बाद उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाया तथा भाजपा को राष्ट्र विरोधी शक्तियां कहते हुए कहा कि यह विकास में बाधा डालते हैं उनके विरुद्ध संघर्ष करना है। आपके विरोधी नेताओं में कोई भी महाराष्ट्र या सार्वजनिक मन से भारत माता की जय आदि कहते हुए नहीं मिलेगा। तो यह एक मौलिक अंतर अरविंद केजरीवाल और बाकी नेताओं में है। किंतु उनकी राजनीतिक रणनीति जो भी हो एक बार संघ के बारे में उन्होंने अपनी राय जरूर सामने रखनी चाहिए।

अध्यात्म

संत तुकाराम ने बताया तीर्थ यात्रा का महत्व

हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का बहुत ही महत्त्व है। पहले के समय यात्रा में जाना बहुत कठिन था। पैदल या तो बैल गाड़ी में यात्रा की जाती थी। थोड़े थोड़े अंतर पे रुकना होता था। विविध प्रकार के लोगो से मिलना होता था, समाज का दर्शन होता था। विविध बोली और विविध रीति-रीवाज से परिचय होता था। कंई कठिनाईओ से गुजरना पड़ता, कंई अनुभव भी प्राप्त होते थे। एकबार तीर्थ यात्रा पे जाने वाले लोगो का संघ, संत तुकाराम जी के पास जाकर उनके साथ चलने की प्रार्थना की। तुकारामजी ने अपनी असमर्थता बताई। उन्होंने तीर्थयात्रियो को एक कड़वा कद्दू देते हुए कहा- मै तो आप लोगो के साथ आ नहीं सकता लेकिन आप इस कद्दू को साथ ले जाईए और जहाँ-जहाँ भी स्नान करे, इसे भी पवित्र जल में स्नान करा लाये। लोगो ने उनके गूढार्थ पे गौर किये बिना ही वह कद्दू ले लिया और जहाँ-जहाँ गए, स्नान किया वहाँ-वहाँ स्नान करवाया। मंदिर में जाकर दर्शन किया तो उसे भी दर्शन करवाया। ऐसे यात्रा पूरी होते सब वापस आए और उन लोगो ने वह कद्दू संतजी को दिया। तुकारामजी ने सभी यात्रियों को प्रीतिभोज पर आमंत्रित किया। तीर्थयात्रियो को विविध पकवान परोसे गए। तीर्थ में घूमकर आये हुए कद्दूकी सब्जी विशेष रूप से बनवायी गयी थी। सभी यात्रियों ने खाना शुरू किया और सबने कहा कि यह सब्जी कड़वी है। तुकारामजी ने आश्चर्य बताते कहा कि यह तो उसी कद्दू से बनी है, जो तीर्थ स्नान कर आया है। बेशक यह तीर्थाटन के पूर्व कड़वा था, मगर तीर्थ दर्शन तथा स्नान के बाद भी इसी में कड़वाहट है ! यह सुन सभी यात्रियों को बोध हो गया कि, हमने तीर्थाटन किया है लेकिन अपने मन को एवं स्वभाव को सुधारा नहीं तो तीर्थयात्रा का अधिक मूल्य नहीं है। हम भी एक कड़वे कद्दू जैसे कड़वे रहकर वापस आये है।

लोकतंत्र में जवाबदेही, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व

धर्म और जाति भारत की दूसरी बड़ी समस्या है। लोकतंत्र की दृष्टि से देखें तो यह पूर्वाग्रही वोट बैंक का निर्माण करती है। धर्म और जाति-आधारित राजनीति भारतीय लोकतंत्र को विभाजित करती है और लक्ष्य से भटकाती है। इससे समाज में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव भी बना रहता है। यह लोकतंत्र के समानता और सामाजिक एकता के सिद्धांतों को कमजोर करती है। क्योंकि यह सुविधाजनक है इसलिए राजनेता भी धर्म और जाति आधारित राजनीति करते हैं। हमने एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर ली है जो चुनाव की प्रक्रिया को धार्मिक और जातिगत सशक्तिकरण के एक अवसर के रूप में देखती है। जाति संख्याबल के आधार पर पार्टियाँ भी उम्मीदवार को टिकट देती है। वोटर में वह दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाया है कि वह अपने बीच से अपना प्रतिनिधि चुने।

जवाहर चौधरी

यह कहना कठिन है कि भारतीय लोकतंत्र अपने इतिहास में सबसे कमजोर स्थिति में है या नहीं है । कई गंभीर चुनौतियां दिखाई देती हैं । भारतीय लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल लोकतंत्रों में से एक है । भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव भी हासिल है। यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत में धर्म और भाषाओं की विविधताएं बहुत है। तीन चौथाई शताब्दी पार कर चुके लोकतंत्र को परिपक्वता की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। लेकिन पहले देखें कि आज हमारे लोकतंत्र की स्थिति क्या है। जिस तरह हम अपनी ऐतिहासिक और बहुमूल्य वस्तुओं को ठीक रखने के लिए समय समय पर उसकी झाड़ पोछ करते रहते हैं, धूप दिखाते हैं। ठीक उसी तरह लोकतंत्र की समीक्षा करने और उसमें आई खामियों और खूबियों को भी देखने की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता है।

सबसे पहले भ्रष्टाचार को लें । यह समस्या कोई नई नहीं है। और सरकारें कोई भी हो, इसे खत्म करने की मंशा व्यक्त करती रही हैं । लेकिन हम देखते हैं चुनाव दर चुनाव इसमें कमी आने की बजाय निरंतर वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी कमजोरी है, जो चुनावों में धनबल का प्रभाव, पद का दुरुपयोग और भाई-भतीजावाद जैसे रूपों में प्रकट होता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में असमानता और अन्याय को जन्म देता है। दुखद है, लेकिन कहना होगा कि चुनाव अब एक व्यवसाय में तब्दील होता जा रहा है। चूंकि करोड़ों खर्च किए जाते हैं तो करोड़ों वसूले भी पड़ते हैं। जन सामान्य का अनुमान है कि पार्षद के चुनाव में करोड़ से ऊपर और विधायक सांसदों के चुनाव में बीस-पच्चीस करोड़ लग जाना मामूली बात है। समझा जा सकता है कि यह पैसा मात्र पोस्टर बैनर में खर्च नहीं होता, यह जिन मदों में खर्च किया जाता है वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। लोक में से उठे हुए साधारण आदमी की हैसियत नहीं है कि वह चुनाव लड़ सके।

धर्म और जाति भारत की दूसरी बड़ी समस्या है। लोकतंत्र की दृष्टि से देखें तो यह पूर्वाग्रही वोट बैंक का निर्माण करती है। धर्म और जाति-आधारित राजनीति भारतीय लोकतंत्र को विभाजित करती है और लक्ष्य से भटकाती है। इससे समाज में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव भी बना रहता है। यह लोकतंत्र के समानता और सामाजिक एकता के सिद्धांतों को कमजोर करती है। क्योंकि यह सुविधाजनक है इसलिए राजनेता भी धर्म और जाति आधारित राजनीति करते हैं। हमने एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर ली है जो चुनाव की प्रक्रिया को धार्मिक और जातिगत सशक्तिकरण के

एक अवसर के रूप में देखती है। जाति संख्याबल के आधार पर पार्टियाँ भी उम्मीदवार को टिकट देती है। वोटर में वह दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाया है कि वह अपने बीच से अपना प्रतिनिधि चुने। उसे अपने सामने परोसे गए दागी, कम दागी और ज्यादा दागी में से एक के पक्ष में अपना मत देना होता है। यद्यपि चुनाव में नोटा की व्यवस्था है, लेकिन वह बस एक व्यवस्था ही है।

भारतीय राजनीति में वंशवाद और राजनीतिक परिवारवाद प्रचलित हैं, जो समाज सेवकों को समान अवसर से वंचित करते हैं। देखने में आता है कि आजादी के बाद से भारतीय लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक परिवारों का वर्चस्व बना हुआ है। लगता है राजनीति उनका पैतृक व पारिवारिक व्यवसाय है। लगता है लोकतंत्र के भीतर राजतंत्र पल रहा है। कहने को वे जनप्रतिनिधि होते हैं लेकिन अपने रसूख का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। आज के हालत में जनता को उसी का एक आसरा है। लोकतंत्र में मीडिया के पास विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। यदि विपक्ष पर्याप्त संख्या में नहीं चुना गया है, या कमजोर है, तब विपक्ष का दायित्व मीडिया को निभाना पड़ता है। सच तो यह है कि मीडिया लोकतंत्र में एक समर्थ चौकीदार है। पुलिस हो, प्रशासन हो या सरकार ही क्यों ना हो, मीडिया सब पर प्रभावी निगाह रख सकता है। हाल के वर्षों में, भारतीय मीडिया की भूमिका ने उसके इस सम्मान को खंडित किया है। सोशल मीडिया एक नई चीज हो गई है, जिसका भरपूर इस्तेमाल राजनीति में होने लगा है। तकनीकी विकास ने टीवी को मोबाइल के स्क्रीन तक पहुंचा दिया। टीवी, मीडिया के बजाए मनोरंजन का एक उपकरण बन गया। जैसे जैसे उसे झूठ के बाजार का पता चला, धीरे-धीरे सच तक पहुंच कम होने लगी। नेता भी अपने वादों को पूरा करने में विफल रहते हैं और गलतियों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रायः अनिच्छुक होते हैं। जबकि स्वच्छ और मजबूत लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है । इससे नागरिकों में अविश्वास पैदा होता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निराशा पैदा होती है। लोकतंत्र पर इन दीर्घकालिक हमलों और नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट के कारण चिंताएं बढ़ रही हैं। यदि ये रुझान जारी रहे, तो भारतीय लोकतंत्र की गरिमा के प्रतिकूल हो सकता है। हमारी राजनितिक व्यवस्था में लोकतंत्र के उच्च मूल्यों की स्थापना के लिए कमजोरियों को दूर करना और नवीनीकृत जवाबदेही, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है।

आज का कार्टून

राशिफल

मेष
नये लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे और उसमें काम भी करेंगे। आप उत्सव के मूड में रहेंगे। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के ऊपर से काम का तनाव कम होगा।

वृषभ
परिजनों का व्यवहार आपको खराब लग सकता है। इसके बावजूद भी आज आप लोगों का मनोबल बढ़ाने में काफी मदद कर सकते हैं।

मिथुन
बोलचाल में भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। अनावश्यक बोलने के कारण मज़ाक का पात्र बन सकते हैं। व्यवसाय में धीमेपन को लेकर थोड़ा चिन्तित हो सकते हैं।

कर्क
मानसिक तनाव में कमी आयेगी। कई दिनों से जिस मामले को लेकर अनिर्णय की स्थिति में थे, उसको लेकर निष्कर्ष में पहुँच सकते हैं।

सिंह
कारोबार को लेकर आपका अनुमान पूरी तरह से गलत सिद्ध हो सकता है। किसी आवश्यक कार्य के पूर्ण न होने से आप क्रोधित हो सकते हैं।

कन्या
घर पर काफी आराम का वक्त बितायेंगे। दैनिक दिनचर्या काफी उलझी हुयी सी प्रतीत होगी। स्वास्थ्य को लेकर आप काफी गम्भीर रहेंगे।

तुला
किसी प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, तो सावधानी रखें। लोग आपके सही कार्यों का भी विरोध करेंगे। मित्रों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो सकता है।

वृश्चिक
आज छात्र नये विषयों के अध्ययन में रुचि ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नये अनुभव मिलेंगे। रुके कार्यों में गति आयेगी। भावनात्मक रूप से काफी मजबूत रहेंगे।

धनु
व्यवसाय में पारदर्शिता रखें। आपको जो काम सोच रहे थे वो समय से पूरा हो जायेगा। जॉब में काम का दबाव अधिक रहेगा। आर्थिक मामलों को लेकर थोड़े परेशान होंगे।

मकर
उधार दिया हुआ धन वापस लौटाने का दबाव बन सकता है। अपने अन्तर्मन की आवाज को अनसुना न करें। अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करें।

कुंभ
व्यवसाय में फाइनेन्स को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। ऑफिस में जूनियर्स की बातों से मन व्यथित होगा। दिन उतार-चढ़ाव से भरपूर रहने वाला है।

मीन
धर्म-कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी से शानदार सहयोग मिलेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनन्द उठायेंगे। व्यापार में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सुभाषित *भयसे ही दुख आते हैं, भयसे ही मृत्यु होती है और भयसे ही बुराइयां उत्पन्न होती हैं।* ❑ *स्वामी विवेकानन्द*

अग्निवीरकी राहपर

सेनाके लिए शुरू की गयी अग्निवीर भर्ती योजनाकी राहपर अब देशके सरकारी बैंक भी चल पड़े हैं। कर्मचारियोंकी कमीका संकट झेल रहे सार्वजनिक क्षेत्रके बैंकोंपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिससे ग्राहक सेवा भी प्रभावित हुई है। बैंकोंपर कामका बोझ बढ़ा है लेकिन इसके लिए कर्मचारियोंकी संख्या पर्याप्त नहीं है। वित्तीय वर्ष २०१४ में सरकारी बैंकोंमें ८,४२,८१३ कर्मचारी थे, जबकि वित्तीय वर्ष २०२४ के अन्ततक इन कर्मचारियोंकी संख्या घटकर ७६४,६७९ रह गयी है। वहीं निजी बैंकोंमें २०१४ में कुल कर्मचारियोंकी संख्या ३०३,८५६ थी, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष २०२४ में ७९६,८०९ हो गयी। सरकारी और निजी क्षेत्रोंके बैंकोंमें कर्मचारियोंकी संख्यामें यह बड़ा अन्तर है, जबकि बैंकोंका कामकाज निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी बैंकोंमें कर्मचारियोंकी कमीके संकटका समाधान निकालनेके लिए बैंकोंके प्रबन्ध तंत्रने अग्निवीर जैसी भर्ती योजनापर चलना शुरू कर दिया है। इसके लिए बैंकोंने २१ से २५ वर्षकी उम्रवाले युवाओंको प्रशिक्षुके रूपमें रखनेके लिए नियुक्तियोंकी घोषणा कर दी है। सरकारी बैंक पहली बार प्रशिक्षु कर्मचारियोंकी नियुक्तियां कर रहे हैं। इन बैंकोंमें सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ इण्डिया, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, केनरा बैंक और इण्डियन ओवरसीज बैंक शामिल हैं और इन बैंकोंने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सभी नियुक्तियां अस्थायी तौरपर होंगी और चयनित युवाओंको पांच हजारसे १५ हजार रुपयेकी राशि मासिक मानदेयके तौरपर दी जायगी। बैंकिंगके क्षेत्रमें अग्निवीरों जैसी नियुक्तियोंका उद्देश्य युवाओंमें ग्राहक सम्बन्धको बढ़ाना, दूरदराज क्षेत्रोंमें बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराना है। नियुक्त प्रशिक्षु बैंकोंकी सेवाओंको ग्राहकोंतक पहुंचानेमें सहायता करेंगे। इनसे ऋणकी वसूली, बिल कलेक्शन, डाक्यूमेण्टेशन, वेरिफिकेशन और ऋणसे सम्बन्धित कार्य सौंपे जा सकते हैं। ऐसे प्रशिक्षुओंको बैंकमें नौकरी देनेकी कोई गारण्टी नहीं दी जायगी। यह योजना कितनी व्यावहारिक है और यह कितनी सफल होगी, इसके बारेमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कुछ आशंकाएं भी हैं। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघटनके पूर्व संयुक्त सचिव डी.एन. त्रिवेदीका कहना है कि बैंकिंग उद्योगमें स्थायी कर्मियोंकी नियुक्ति होनी चाहिए, जो सेवा शर्तोंकी जिम्मेदारीके साथ कार्य कर सकें। अप्रेंटिसशिपका नया प्रयोग नियमित बहालीका विकल्प नहीं हो सकता। देशमें बेरोजगारीकी बड़ी संख्या है, वे अपने भविष्यके प्रति चिन्तित हैं। अग्निवीर जैसी योजनासे उनकी चिन्ताएं किस सीमातक कम होगी, यह भी अनिश्चित है और इससे सेवाकी गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।

किसानोंको सौगात

अन्नदाताओंके खातेमें बीस हजार करोड़ रुपयेसे अधिक धनराशिका पहुंचना देशके किसानोंको केन्द्र सरकारकी बड़ी सौगात है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने शनिवारको महाराष्ट्रसे 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि' की १८वीं किस्त जारी की। इससे देशके ९.५१ करोड़ किसान लाभान्वित हुए जिनके खातोंमें २०,५५२ करोड़ रुपयेकी राशि डीबीटीके माध्यमसे हस्तान्तरित की गयी है। इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेशके २.२५ करोड़ किसानोंको मिला जिनके खातेमें करीब पांच हजार करोड़ रुपये पहुंच गये। इसके लिए प्रदेशके मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथका प्रधान मंत्री मोदीको आभार व्यक्त करते हुए यह कहना सही है कि शारदीय नवरात्रिकी तृतीयापर देशके साथ उत्तर प्रदेशके किसानोंका घर भी धन-धान्यसे परिपूर्ण हुआ। इसके पूर्व प्रधान मंत्रीने १८ जूनको अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसीसे किसान सम्मान निधिकी १७वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान प्रधान मंत्रीने वाराणसीमें किसानोंके जीवनको संवारने और उनके विकासके लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओंका उपहार दिया था जो किसानोंके जीवनको सुगम, स्वावलम्बी और समृद्ध बनानेके संकल्पके प्रति समर्पित उनकी भावनाको रेखांकित करती है। भारत कृषिप्रधान गांवोंका देश है, जिसमें कृषकोंका उत्थान अत्यन्त जरूरी है। किसान जितना ही समृद्ध होगा, देश उतना ही आर्थिक दृष्टिसे मजबूत होगा। देशकी सुदृढ़ अर्थव्यवस्थामें किसानोंका योगदान महत्वपूर्ण है। सरकारका किसानोंका आत्मनिर्भर बनानेका संकल्प स्वागतयोग्य है। इसकी सराहना की जानी चाहिए।

लोक संवाद

श्रद्धा और आस्थाका प्रतीक

महोदय,-भारतकी भूमि उत्सव एवं मेलोंकी प्रतीक है। यहांपर प्रत्येक दिवसका अपना महत्व है। भारतकी देव दर्शन संस्कृति विश्वभरमें प्रचलित है। इसी परंपराकी श्रृंखलामें नवरात्रि पर्व भी सम्मिलित है। नवरात्रिका अर्थ है नौ रातोंका समय, जिसमें शक्तिकी पूजा की जाती है। भारतीय सनातन धर्म परम्परामें एक वर्षमें चार बार नवरात्रि पर्व होता है जो चैत्र, आषाढ़, आश्विन एवं माघ मास शुक्ल प्रतिपदासे आरम्भ होते हैं। आषाढ़ एवं माघ गुप्त नवरात्रि पर्व हैं जिनका विधान योगियोंसे संबंधित है। चैत्र एवं आश्विन नवरात्रिका विधान गृहस्थ जीवनमें रहनेवाले साधकोंके लिए है। चैत्र एवं शारदीय नवरात्रिका विशेष महत्व एवं प्राचीन इतिहास है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको हिंदू नव वर्षके रूपमें मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदासे आरंभ होते हैं। भारतके विभिन्न राज्योंमें नवरात्रोंमें पूजनकी क्षेत्रीय विधियां भी हैं जो वहांकी संस्कृतिकी प्रतीक हैं। गुजरातमें गरबा नृत्य करके देवीको प्रसन्न किया जाता है। नवरात्रिका इतिहास वैदिक कालसे भी पूर्वके समयसे जुड़ा हुआ है। जिस भावनासे भक्त अपनी देवीकी उपासना करता है, विधि-विधानसे दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती पाठ एवं आरती करता है, मां उसी भावनाके साथ उसके मनोरथ पूर्ण करती है। प्रत्येक एक दिन देवीके प्रत्येक अवतारका प्रतीक है। प्रथम नवरात्रि ३ अक्तूबर प्रात: ब्रह्म मुहूर्तमें नित्य कर्मसे निवृत्त होकर स्नान करके सर्वप्रथम गणेश स्तुति करनेके बाद कलश स्थापना करें। इसके साथ जौं बोनेकी विधिको भी सम्पन्न करें। जौंको शास्त्रोंमें प्रथम फसल स्वीकार किया गया है। हवन सामग्रीमें भी जौंकी आहुति अग्नि देवीको दी जाती है। जौं बीजना समृद्धि एवं प्रगतिके सूचक हैं। इसके बाद आप देवी मांका स्मरण करते हुए संकल्प लें कि हे मां! हम आपकी शरणागत हैं और आप हमारी यह पूजन विधि सफल करना। आपके आशीर्वादसे ही यह कार्य सफल होगा। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्तमें उठकर स्नान करनेके पश्चात पुष्प, लाल सिंदूर, लौंग, इलायची, फल आदि अर्पित करें। आप अपनी सुविधानुसार गायके घीका दीपक सुबह-शाम कर सकते हैं। यदि आपके पास समय एवं सामर्थ्य है तो आप नौ दिन उपवास एवं अखंड ज्योति भी प्रज्वलित करके भगवती मांको प्रसन्न कर सकते हैं। प्रथम नवरात्रिसे नवम नवरात्रितक मांके नौ अवतारोंकी पूजा विधि-विधानसे की जाती है। नवरात्रिके नौवें दिन नौ कन्याओंको श्रद्धा एवं प्रेमके साथ घरपर आमंत्रित करके हलवा-पूड़ी, सब्जी, फल एवं चने आदि सात्विक आहारका भोग लगाया जाता है और सामर्थ्यके अनुसार उपहार एवं दक्षिणा दी जाती है। देवीका पूजन कुछ क्षेत्रीय मान्यताओंपर भी आधारित है। कई स्थानोंपर भक्त महा अष्टमीको यह कार्यक्रम करते हैं। कुछ भक्त रामचरितमानसका पाठ भी करते हैं। शारदीय नवरात्रिमें प्रभु श्रीराम रामेश्वरम धाममें समुद्र तटपर भगवती मांके नौ स्वरूपोंकी आराधना करते हैं और चार वेदोंके ज्ञाता सभी ग्रहोंको अपने वशमें करनेवाले महान विद्वान लंकापति राजा रावणको पराजित करनेका वरदान प्राप्त करते हैं। नवरात्रिके दसवें दिन राम-रावणका समर असत्यपर सत्य, छलपर विश्वास एवं अहंकारपर परोपकारकी विजयके साथ समाप्त होता है जिसे हम विजयदशमी या दशहराके रूपमें उत्सव मनाते हैं। मांके नौ स्वरूप हैं- शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धीदात्री। शैलपुत्री-शैलका शाब्दिक अर्थ चट्टान है। शैलपुत्रीका अर्थ पहाड़की बेटी है। मां पार्वतीका पुनर्जन्म है। यह पहली नवदुर्गाका स्वरूप है। मां शैलपुत्री अरुणोदयमें प्रकट हुई और सूर्यप्रभासे इनका रंग नारंगी हो गया। इनकी सवारी बैल है। पहले नवरात्रिको इस मंत्रका जाप अवश्य करें- या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:। ब्रह्मचारिणी- ब्रह्मका अर्थ है तप। ब्रह्मचारिणीका अर्थ है तपका आचरण करनेवाली एक समर्पित देवी। मांका यह स्वरूप अंतर्मनकी ऊर्जाको जागृत करनेका प्रतीक है। मां पार्वती शिवको पति रूपमें पानेके लिए वाम हस्तमें कमंडल तथा दाहिनी हाथमें माल लेकर तप करनेके लिए जाती हैं। उनके इसी स्वरूपको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इस दिन आप ऐसी कुंवारी लड़की जिसका विवाह तय हो गया हो, लेकिन विवाह अभी होना हो, उसे शामको देवी स्वरूपमें बुलाकर श्रद्धा भावसे भोजन करवा कर उपहार दे सकते हैं। इस मंत्रका जाप अवश्य करे- या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:। तीसरा नवरात्रि मां चंद्रघंटाको समर्पित है। शिवके साथ विवाहके पश्चात मां पार्वतीने चंद्रमाको अपने मस्तकपर सुशोभित किया, जिससे मांका यह स्वरूप विकसित हुआ। स्वर्णसे आभामय मांका दस भुजाओंवाला स्वरूप है। अस्त्र-शास्त्र धारण करके मां सिंहकी सवारी करती हैं। देवीके इस स्वरूपके पूजनसे भक्तोंको आरोग्य, सुख-संपदाकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार देवीके सभी नौ रूप भक्तको आनन्द देते हैं। **-संतोष कुमारी, वाया ईमेल।**

अब कौन है इसरायलके निशानेपर

इसरायलने संकेत दिया है कि वह नफ्ताली बेनेटके ऑक्टोपस सिद्धांतका पालन कर रहा है जो हिजबुल्ला या हमास जैसी छाया शक्तियोंसे लड़नेकी बजाय ईरानके साथ अब सीधा भिड़ना चाहता है। अर्थात् ईरानके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमेनी अब निशानेपर हैं। ईरानने खेमेनीको अज्ञात सुरक्षित स्थानपर स्थानांतरित किया है।

❑ पुष्परंजन

इसरायली रक्षा बल (आईडीएफ) और मोसाद का मनोबल इस समय ऊंचा है। ५८ दिनोंके भीतर मध्य पूर्वमें दो 'शक्तिशाली' नेताओं, हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाहको खत्म करनेके बादए सवाल यह है कि इसरायलका अगला लक्ष्य कौन होगा। इसरायलने संकेत दिया है कि वह नफ्ताली बेनेटके 'ऑक्टोपस सिद्धांत' का पालन कर रहा है, जो हिजबुल्ला या हमास जैसी छाया शक्तियोंसे लड़नेकी बजाय, ईरानके साथ अब सीधा भिड़ना चाहता है। अर्थात् ईरानके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई अब निशानेपर हैं। नसरल्लाहकी हत्याके बाद ईरानी अधिकारियोंने खामेनेईको देशके अंदर एक अज्ञात सुरक्षित स्थानपर स्थानांतरित कर दिया था, जहां सुरक्षाके कड़े उपाय किये गये हैं। इसपर प्रतिक्रिया देते हुए इसरायलने कहा कि हम आतंकवादी समूहोंको समर्थन देनेवालोंको पातालसे खोजकर निकाल लेंगे। ३० जुलाई, २०२४ को याद कीजिये, जब इसरायलने लेबनानकी राजधानी बेरूतपर हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाके शीर्ष कमांडरोंमेंसे एक, फुआद शुक्रकी मौत हो गयी। कुछ घंटों बाद एक विस्फोटमें हमासके शीर्ष राजनीतिक नेता इस्माइल हनियाकी तेहरानमें मौत हो गयी, जहां वे ईरानके नये राष्ट्रपतिके उद्घाटन समारोहमें भाग ले रहे थे। इसरायलने पिछले हफ्ते दहियाहमें एक आवासीय इमारतके नीचे समूहके भूमिगत मुख्यालयपर लक्षित हमलेमें हिजबुल्ला प्रमुख सैय्यद हसन नसरल्लाहको मार डाला था। नसरल्लाह, जिन्होंने तीन दशकोंसे अधिक समयतक हिजबुल्लाका नेतृत्व किया था, खामेनेईके खास और ईरानकी क्षेत्रीय प्रॉक्सी रणनीतिमें एक प्रमुख चेहरा थे। हमास नेता इस्माइल हानियाके बाद हसन नसरल्लाह इन दो ताकतवर चेहरोंके बूते ईरानकी लीडरशिप इसरायलको सबक सिखानेका दम भरती थी।

ईरान, जिसने नसरल्लाहकी मौतके बाद बदला लेनेकी कसम खायी थी, ने मंगलवार रातको इसरायलपर लगभग २०० बैलेस्टिक मिसाइलें दागीं। रॉयटर्सके अनुसार ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने दावा किया कि मिसाइल हमला हालमें लेबनान और गाजामें नेताओंकी इसरायली हत्याओं और ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाके खिलाफ आक्रामकताका जवाब था। लेकिन इसे फुस्स हमला माना जाये, जिसमें इसरायलके जान-मालकी हानि लगभग नहीं के बराबर हुई। ८५ वर्षीय खामेनेई १९८९ से हिजबुल्लाका समर्थन कर रहे हैं। बेरूतमें इसरायलके हमलेके बाद उन्होंने कहा, क्षेत्रमें सभी प्रतिरोधक ताकतें हिजबुल्लाके साथ खड़ी हैं। खामेनेईके बयानोंपर प्रतिक्रिया देते हुए, नेतन्याहूने कहा, आपके दोस्त ऐसे ही नारे लगाते थे, अब देखिये वे कहां हैं। इसरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहूने चेतावनी दी कि ईरानको इसरायलपर मिसाइल हमलेके लिए परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने सिनवार, डेफ और नसरल्लाहका हवाला देते हुए दावा किया कि जो प्रतिद्वंद्वी इसरायलके सेल्फ डिफेंसको कम आंक रहे हैं, वह परिणाम भुगतनेको तैयार रहें। दिलचस्प यह है ईरानके सर्वोच्च नेता अब रेवोल्यूनेशनरी गार्डके रहमोकरमपर है। कभी अयातुल्ला अली खामेनेईकी मर्जीके बिना ईरानका पत्ता नहीं हिलता था। अब उन्हें डर है कि कोई विभीषण, मोसादको उनके ठिकानेकी सूचना न लीक कर दे। सिनवार, डेफ, हानिया और नसरल्लाहकी हत्याएं सत्ताके गलियारेमें सक्रिय विभीषणोंकी सूचनाओंकी वजहसे हुई थी। अयातुल्ला अली खामेनेईपर जानलेवा हमला पहले हो चुका है। २७ जून १९८१ को मुजाहिदीन-ए-खल्क द्वारा की गयी हत्याके प्रयासमें वह बाल-बाल बच चुके हैं, जब टेप रिकॉर्डरमें छिपा हुआ एक बम, उनके बगलमें फट गया। अयातुल्ला अली खामेनेईके इलाजमें कई महीने लग गये, तबसे उनका दाहिना हाथ काम नहीं कर पाता।

ईरानी मीडियाने शनिवारको बताया कि लेबनानकी राजधानीके बाहर इसरायली हमलोंमें ईरानी रिवोल्यूशनरी गाड्र्सके डिप्टी कमांडर अब्बास निलफोरुशनकी भी मौत हो गयी। सर्वोच्च नेताकी सुरक्षाके वास्ते जो उपकरण लगाये गये हैं, उनकी सबसे पहले जांच की गयी। क्या रूस और चीनकी खुफिया एजेंसियां अयातुल्ला अली खामेनेईकी सुरक्षाको कोऑर्डिनेट कर रही हैं। इस सवालपर बिलकुल चुप्पी है। अब जब सर्वोच्च नेताके ही जानके लाले पड़े हुए हों तो ईरान इसरायलसे बदला क्या लेगाज

ईरानने हिजबुल्ला और हुथी लड़ाकोंका इस्तेमाल जिस तरहसे किया है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। भूमध्यसागरके पूर्वी तटपर स्थित एक संकीर्ण पट्टीपर अवस्थित लेबनान, दुनियाके छोटे मुल्कोंमेंसे एक है। इस समय आप राजधानी बेरूत चाहकर भी नहीं जा सकते। कभी लेबनान, मध्य-पूर्वका स्विट्रलैंड माना जाता था। अब लेबनान एक फेल्ड स्टेट है। यह भी दिलचस्प है कि युद्ध इसरायल और लेबनानके बीच नहीं हो रही, बल्कि हिजबुल्ला एक राष्ट्रीय फोर्सके रूपमें एक्ट कर रहा है। यह सब ईरानकी शहपर हुआ। लेबनानी सशस्त्र बलों (एलएएफ) में ७२,००० सक्रिय कर्मी हैं, जिनमें वायु सेनामें ११०० और नौसेनामें १००० शामिल हैं। एलएएफको हिजबुल्लाकी तुलनामें कम शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। हिजबुल्लाके पास २०,००० सक्रिय लड़ाके और २०,००० रिजर्व हैं। उसे ईरानसे रॉकेट और ड्रोन सहित उन्नत हथियार मिलते हैं। आप कह सकते हैं, हिजबुल्ला राजनीतिक रूपसे भले सत्तामें नहीं है, लेकिन पूरा देश उसके नियंत्रणमें है।

यमनमें हूथी विद्रोही भी ईरानकी देन हैं। लेकिन सवाल यह है कि मध्य-पूर्वकी यह लड़ाई कहां जाकर रुकेगी। जिन अतिवादी संघटनोंके नेता मारे गये, वहां उनके उत्तराधिकारी बैठाये जा चुके हैं। आज हमासके हमलेकी बरसी है। गाजामें जो बचे हुए बंधक हैं, उनका क्या होगा। हालिया हमलेमें इसरायली डिफेन्स फोर्स और उनकी आंतरिक सुरक्षा सेवा शिन बेतकी ताकतें बढ़ी हैं। नेतन्याहूकी कुर्सी भी ७ अक्तूबर, २०२३ के बादसे बचती रही है। लेकिन यह सब किसकी तबाहीकी कीमतपर। क्या नवम्बरमें अमेरिकी चुनावके बाद मिडल ईस्टमें शांति आयगी। जो अमेरिकी वोटबैंक है, उसे क्या मिडल ईस्टमें अशांति सत्तापक्षके लिए सहानुभूति पैदा करती है। ये तमाम सवाल हैं। दोनों पक्षकी आम जनता मूकदर्शक होकर अपनी बर्बादी देख रही है, हमारे देशमें बुलियन मार्केटमें निवेश करनेवाले खुश हैं कि सोना-चांदी महंगा हो रहा है। महबूबा मुफ्तीको लग रहा है कि हसन नसरल्लाहकी हत्याके विरुद्ध एक दिनका चुनाव प्रचार बंद कर देनेसे पीडीपी सत्तामें आ जायगी। सबके अपने-अपने एजेंडे हैं।

यमनमें हूती विद्रोही भी ईरानकी देन हैं। लेकिन सवाल यह है कि मध्य-पूर्वकी यह लड़ाई कहां जाकर रुकेगी? जिन अतिवादी संघटनोंके नेता मारे गये, वहां उनके उत्तराधिकारी बैठाये जा चुके हैं। आज हमासके हमलेकी बरसी है। गाजामें जो बचे बंधक हैं, उनका क्या होगा? हालिया हमलेमें इसरायली डिफेंस फोर्स और उनकी आंतरिक सुरक्षा सेवा शिन बेतकी ताकतें बढ़ी हैं। लेकिन यह सब किसकी तबाहीकी कीमतपर? क्या नवम्बरमें अमेरिकी चुनावके बाद मध्य-पूर्वमें शांति आयेगी? जो अमेरिकी वोटबैंक है, उसे क्या मध्य-पूर्वमें अशांति सत्तापक्षके लिए सहानुभूति पैदा करती है?

देशमें एक साथ चुनावका विचार

अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि देशमें एक साथ चुनाव वाली स्थिति हैं। भारतकी ही तरह फ्रांसमें नेशनल असेंबलीके साथ ही वहांके सभी चुनाव हर पांच सालमें एक साथ कराये जाते हैं।

❑ आर.के.सिन्हा

'एक देश, एक चुनाव' का सपना अब तो साकार होता नजर आ रहा है। केन्द्रकी नरेन्द्र मोदी सरकारने देशमें सभी चुनाव एक साथ करवानेके लिए बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमिटीकी रिपोर्टको स्वीकार कर लिया। मतलब यह कि अब देशमें 'एक देश, एक चुनाव' की राहका सारा व्यवधान सारा सस्पेंस दूर हो गया है। पिछले दिनों स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाहने भी अपने एक वक्तव्यमें साफ किया था कि मोदी सरकारके इसी कार्यकालमें देशका यह सबसे बड़ा चुनाव सुधार लागू हो जायगा। जैसे कि आपको ज्ञात ही होगा कि केन्द्र सरकारने अपने पिछले कार्यकालमें एक देश, एक चुनावपर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदके अध्यक्षतामें एक समिति बनायी थी। रामनाथ कोविंद कमिटीको जिम्मेदारी दी गयी थी कि वह देशमें एक साथ चुनाव करवानेकी संभावनाओंपर रिपोर्ट दे। अब कमिटीकी सिफारिशोंपर देशकी सभी राजनीतिक मंचोंपर इसपर चर्चा की जायगी। सभी नौजवानों, कारोबारियों, पत्रकारों समेत सभी संघटनोंसे इसपर बात होगी। इसके बाद इसे लागू करनेके लिए ग्रुप बनाया जायगा। फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू किया जायगा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीने इस साल १५ अगस्तको स्वाधीनता दिवस समारोहके दौरान लालकिलेसे अपने भाषणमें भी एक देश एक चुनावकी वकालत की थी। उनका कहना था कि देशमें बार-बार चुनावसे विकास कार्यमें बाधा आती है। किसी भी चुनावकी घोषणा होते ही अंतिम रिजल्ट नहीं आनेतक कोई नया विकास कार्य शुरू ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि 'एक देश, एक चुनाव' के लिए देशको आगे आना होगा। उन्होंने देशके सभी राजनीतिक दलोंसे भी आग्रह किया था कि देशकी प्रगतिके लिए इस दिशामें आगे बढ़े। यहांतक कि इसी साल हुए लोकसभा चुनावसे पहले भाजपाने इसे अपने चुनावी घोषणा-पत्रमें भी प्रमुखतासे शामिल किया था।

एक साथ चुनाव करानेसे चुनाव प्रक्रियाकी चुनावपर होनेवाले खर्चमें कमी आयगी, क्योंकि कई चुनावोंके लिए बार-बार तैयारी और कार्यान्वयन करनेकी आवश्यकता नहीं होगी। क्या आपको पता है कि कुछ माह पहले देशमें हुए लोकसभा चुनावमें कितना खर्चा हुआ। २०२४ के लोकसभा चुनावपर २०१९ के लोकसभा चुनावके मुकाबले करीब दोगुनासे भी ज्यादा खर्चा आया। चुनावी खर्चपर रिपोर्ट जारी करनेवाली गैर-लाभकारी संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने अनुमान लगाया है कि इस बार लोकसभा चुनावमें करीब १.३५ लाख करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। साल २०१९ के लोकसभा चुनावमें कुल खर्च ५५ से ६० हजार करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इस तरह देखा जाय तो इस बार दोगुनेसे भी ज्यादा पैसा चुनावमें खर्च किया गया है। अमेरिकाने भी साल २०२० में हुए राष्ट्रसपति चुनावमें करीब १.२० लाख करोड़ रुपये ही खर्च किये थे। क्या आपको पता है कि १९५१-५२ में भारतके पहले चुनावके दौरान महज १०.५ करोड़ रुपये था। चुनाव खर्चका एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया प्रचारपर खर्च किया जाता है। भारतीय राजनेता मतदाताओंको प्रभावित करनेके लिए असाधारण और नये-नये तरीके अपना रहे हैं।

यह सबको पता है कि देशमें बार-बार चुनाव होनेसे जनता और सरकारी अधिकारियोंका समय और संसाधन बर्बाद होता है। एक साथ चुनाव करानेसे यह सब नहीं होगा। एक साथ चुनाव होनेसे राजनीतिक स्थिरतामें सुधार आयगा। क्योंकि सरकारको बार-बार चुनावोंकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ ही एक साथ चुनाव होनेसे प्रशासनपर भी कामका दबाव कम होगा और वे अपने कामपर अधिक ध्यान केंद्रित कर पायंगे तो आप कह सकते हैं कि 'एक देश, एक चुनाव' से कई मसलोंका हल हो जायगा। चुनावोंकी अवधि कम हो जानेसे शासन और विकास कार्यक्रमोंपर ध्यान बेहतर ढंगसे केंद्रित किया जा सकेगा। यह जानना जरूरी है कि भारतमें साल १९६७ तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओंके लिए चुनाव एक साथ ही होते थे। साल १९४७ में आजादीके बाद भारतमें नये संविधानके तहत देशमें पहला आम चुनाव साल १९५२ में हुआ था। उस समय राज्य विधानसभाओंके लिए भी चुनाव साथ ही कराये गये थे, क्योंकि आजादीके बाद विधानसभाके लिए भी पहली बार ही चुनाव हो रहे थे। उसके बाद साल १९५७, १९६२ और १९६७ में भी लोकसभा और विधानसभाके चुनाव साथ ही हुए थे। यह सिलसिला पहली बार उस वक्त टूटा था जब केरलमें साल १९५७ के चुनावमें ईएमएस नंबूदरीबादकी वामपंथी सरकार बनी। साल १९६७ के बाद कुछ राज्योंकी विधानसभा जल्दी भंग हो गयी और वहां प्रधान मंत्री इंदिरा गांधीने मनमाने ढंगसे राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके अलावा साल १९७२ में होनेवाले लोकसभा चुनाव भी समयसे पहले कराये गये थे। साल १९६७ के चुनावोंमें कांग्रेसको कई राज्योंमें विधानसभा चुनावोंमें हारका सामना करना पड़ा था। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे कई राज्योंमें विरोधी दलों या गठबंधनकी सरकार बनी थी। इनमेंसे कई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पायीं और विधानसभा समयसे पहले भंग कर दी गयी। वैसे यह बात भी है कि यदि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायोंके चुनाव एक साथ कराये जायं तो इसके लिए मौजूदा संख्यासे तीन गुना ज्यादा ईवीएमकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन वह तो एक बार ही होनेवाला खर्च होगा। अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदिमें एक देश, एक चुनाववाली स्थिति हैं। अमेरिकामें हर चार सालमें एक निश्चित तारीखको ही राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेटके चुनाव कराये जाते हैं। भारतकी ही तरह फ्रांसमें संसदका निचला सदन यानी नेशनल असेंबली है। वहां नेशनल असेंबलीके साथ ही संघीय सरकारके प्रमुख राष्ट्रपतिके साथ ही राज्योंके प्रमुख और प्रतिनिधियोंका चुनाव हर पांच सालमें एक साथ कराया जाता है। स्वीडनकी संसद और स्थानीय सरकारके चुनाव हर चार सालमें एक साथ होते हैं। यहांतक कि नगरपालिकाके चुनाव भी इन्हीं चुनावोंके साथ होते हैं। वैसे तो कनाडामें हाउस आफ कॉमंसके चुनाव हर चार सालमें कराये जाते हैं, जिसके साथ कुछ ही प्रांत स्थानीय चुनावको संघीय चुनावके साथ कराते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जैस देशके लिए एक देश, एक चुनावका विचार बहुत ही उपयुक्त और आदर्श है। परन्तु दिक्कत यह है कि हमारे विपक्षी दल इतने शानदार विचारकी बिना सोचे-समझे राजनीतिक स्वार्थ साधनेके चक्करमें निन्दा करने लगे हैं। उम्मीद कीजिए कि वे भी अंतमें सरकारका ही साथ देंगे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ज्ञानकी ओर

❑ श्रीराम शर्मा

बनारसकी गलियोंमें घूमते नन्हें कबीर बचपनसे ही एक तीखी दृष्टि रखते थे। वे अन्य बच्चोंकी तरह नहीं सोचते थे। वे हर बातपर सवाल भी बहुत पूछा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके गुरुके पिताका श्राद्ध था। श्राद्धका अर्थ एक ऐसी परम्परा है, जिसके तहत पंडितोंको बुलाकर भरपेट भोजन कराया जाता है, ताकि जिस मृत रिश्तेदारका श्राद्ध मनाया जा रहा हो उस तक इन पंडितोको खिलाया जानेवाला भोजन पहुंच जाय। सो अपने मृत पितातक भोजन पहुंचाने हेतु गुरुने काफी पंडितोंको भोजनपर बुलवाया और इधर अपने शिष्योंको सुबहसे ही तैयारियोंमें भी लगा दिया। कबीरके जिम्मे दूध ले आनेका कार्य आया। गुरुकी आज्ञा थी, कबीर एक बाल्टी लेकर दूध लाने निकल पड़े। परन्तु जाने क्या हुआ कि सुबहके निकले कबीर दोपहर चढ़ते-चढ़ते भी वापस नहीं आये। इधर गुरुको बिना दूधके ही पंडितोंका भोजन निबटाना पड़ा। यह तो ठीकपर कार्यक्रम निबटनेके बाद गुरुको चिन्ता होने लगी। वे अपने दो-चार शिष्योंके साथ बनारसकी तंग गलियोंमें कबीरको खोजने निकल पड़े। जल्द ही उन्हें एक मरी हुई गायके पास बाल्टी हाथमें लिये एवं सिरपर हाथ रखकर बैठे नन्हें कबीर दिख गये। गुरुके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। उन्होंने तत्क्षण जिज्ञासावश पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो। कबीर बड़ी मासूमियतसे बोले, गायके दूध देनेका इंतजार कर रहा हूं। इसपर गुरु बड़े लाड़से कबीरका गाल सहलाते हुए बोले, अरे मेरे भोल शिष्य, मरी गाय भी कहीं दूध देती है। यह सुन कबीर बड़े नटखट अंदाजमें बोले, जब आपके मृत पितातक भोजन पहुंच सकता है तो मरी गाय भी दूध दे ही सकती है। आचार्य स्वामीका तो पूरा नशा ही उतर गया। उन्होंने कबीरको गले लगा लिया और तुरंत बोले, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तू तो अभीसे ही परमज्ञानकी ओर एक बड़ा कदम बढ़ा चुका है। यदि आप वाकई ज्ञानकी ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो बातोंका अंधा अनुसरण करना बंद करें और हर बातको अपनी भीतरी विवेकके तराजूपर तौलें। क्योंकि ज्ञानी होना एवं ज्ञान पाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। मानव जीवनमें सुखकी वृद्धि करनेके उपायोंमें स्वाध्याय एक प्रमुख उपाय है। स्वाध्यायसे ज्ञानकी वृद्धि होती है। मनमें महानता, आचरणमें पवित्रता और आत्मामें प्रकाश आता है। स्वाध्याय एक प्रकारकी साधना है, जो अपने साधकको सिद्धिके द्वारतक पहुंचाती है। जीवनको सफल, उत्कृष्ट एवं पवित्र बनानेके लिए स्वाध्यायकी बड़ी आवश्यकता है। प्रतिदिन नियम पूर्वक सद्ग्रंथोंका अध्ययन करते रहनेसे बुद्धि तीव्र होती है, विवेक बढ़ता है और अंत:करणकी शुद्धि होती है, अत: प्रतिदिन चिंतन-मननके साथ स्वयं पढ़ें एवं दूसरोंको पढ़ानेका प्रयास करें। अपने अंतर्मनकी गहराइ

एनकाउंटर की स्थिति

अनुज और अक्षय के मामले में समान तथ्य यह है कि जब उनका एनकाउंटर हुआ, वे पुलिस हिरासत में थे। इसलिए यह बात लोगों के गले नहीं उतर रही है कि उन्होंने कैसे पुलिस के लिए इतना खतरा पैदा कर दिया कि एनकाउंटर की स्थिति बन गई?महाराष्ट्र में बदलापुर बाल यौन शोषण कांड के आरोपी का एनकाउंटर आरंभ से संदिग्ध था और अब यह एक बड़ा विवाद बन गया है। पुलिस ने कहानी यह बताई कि वह आरोपी अक्षय शिंदे को जांच-पड़ताल के सिलसिले में अपने साथ ले जा रही थी, तभी शिंदे ने एक पुलिस अधिकारी के रिवॉल्वर को छीन लिया और गोली चलाने की कोशिश की। तभी दूसरे पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की, जिसमें वह मारा गया।अब शिंदे के पिता के साथ-साथ पीड़ित बच्चियों के परिजनों ने भी हाई कोर्ट की पनाह ली है। उन्होंने कोर्ट से मामले की अपनी निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की गुजारिश की है। जिस रोज (सोमवार को) ये घटना हुई, उसी दिन उत्तर प्रदेश में जौहरी लूट कांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह भी एनकाउंटर में मारा गया। इसके पहले इस कांड का एक और आरोपी मंगेश यादव भी एनकाउंटर में मारा गया था। तब समाजवादी पार्टी सहित तमाम हलकों से आरोप लगा था कि पुलिस ने जाति देख कर मंगेश को मारा गया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहजातीय आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। मामला कुछ ज्यादा गरम हुआ था। अब संदेह जताया गया है कि जातिवाद के आरोप को गलत साबित करने के लिए अनुज का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। अनुज और अक्षय दोनों के मामले में समान तथ्य यह है कि जब उनका एनकाउंटर हुआ, वे पुलिस हिरासत में थे। इसलिए यह बात लोगों के गले नहीं उतर रही है कि उन्होंने कैसे पुलिस के लिए इतना खतरा पैदा कर दिया कि एनकाउंटर की स्थिति बन गई? कभी यह चलन में था कि पुलिस हिरासत की हर मौत के बारे में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को तुरंत रिपोर्ट करना जरूरी था तथा ऐसे मामलों की अनिवार्य जांच होती थी। लेकिन अब संस्थाएं अपनी धार खो चुकी हैं। उधर आरोप है कि खासकर भाजपा की राज्य सरकारों ने एनकाउंटर को राजकीय नीति बना लिया है। यह न्याय और संविधान की भावना का खुला उल्लंघन है, लेकिन इस दौर में इन भावनाओं का ख्याल कम-से-कम सरकारी स्तर पर शायद ही बचा है।

भाजपा संघ को अपना संरक्षक नही मानता

एक तरफ शताब्दी वर्ष के दौर की खुशी तो दूसरी ओर उपेक्षा का गम, आज इसी दौर से गुजर रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आज उसकी सबसे बड़ी चिंता यही है, उसकी सोच है कि आजादी के बाद से अब तक सर्वाधिक काल तक कांग्रेस सत्ता में रही, किंतु उस दौर में भी उसकी (संघ की) केंद्रीय सत्ता द्वारा इतनी उपेक्षा नही हुई, जितनी की आज भाजपा के शासनकाल में हो रही है। पिछले साल लगभग इन्हीं दिनों महाराष्ट्र के पूणे में संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक हुई थी, जिसमें भाजपा की चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई थी जिसमें संघ की उपेक्षा के गंभीर आरोप लगे थे, इसके बाद इसी साल केरल में आयोजित संघ की समन्वय बैठक में भाजपाध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का अचानक पहुंचना और वहां यह प्रकट करना कि संघ भाजपा को अपने अधीन न समझे, भाजपा का संघ से समान विचारधारा के अतिरिक्त कोई रिश्ता नही है, यह स्पष्ट करता है कि देश पर राज कर रही भाजपा संघ को अपना संरक्षक नही मानता। इन्हीं दो प्रसंगों ने संघ की चिंता बढ़ा दी हे, यद्यपि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अब तक इन दोनों घटनाक्रमों के संदर्भ में कुछ नही कहा है, किंतु वे चिंतित अवश्य है और अपने संघ के भावी अस्तित्व के प्रति गंभीर भी। अब इस स्थिति में यह भी संभव है कि संघ प्रमुख भागवत जी स्वयं अपने अस्तित्व की चुनौति को स्वीकार लें और अपने ही स्तर पर संघ को हर दृष्टि से मजबूत और आदर्श संगठन बनाने की ठान ले, इस घटना के बाद संघ प्रमुख की अपनी राष्ट्रव्यापी शाखाओं के प्रति बढ़ी सक्रीयता तो यही संदेश दे रही है, अब उन्होंने देश के सभी राज्यों के संघ प्रमुखों से जीवंत सम्बंध बनाए रखने तथा समय-समय पर उनसे चर्चा करते रहने का भी निश्चय कर लिया है, इसलिए अब संघ ने भाजपा शासित राज्यों में भी अपनी सक्रीयता बढ़ा दी है तथा वह अब अपने अस्तित्व की रक्षा में पूरी तरह जुट गया है। संघ की इस सक्रीयता से भाजपा तथा केन्द्र की चिंता बढऩा स्वाभाविक है, इसलिए राज्यों के भाजपा प्रमुखों के केंद्रीय संगठन से गोपनीय आदेश जारी किए गए है, जिनमें संघ की दैनंदिनी गतिविधियों पर तीखी नजर रखने को कहा गया है, अर्थात् अब संघ और भाजपा दोनों की ही एक-दूसरे पर तीखी नजर है। आज संघ की सबसे बड़ी और अहम् शिकायत ही यही है कि आजादी से अब तक के पचहत्तर वर्षों के कार्यकाल में अधिकांश समय कांग्रेस ही सत्ता में रही किंतु कांग्रेस के शासनकाल में भी संघ की इतनी उपेक्षा नही की गई, जितनी पिछले एक दशक से केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है।

दैविक ज्योति ज्ञान- विज्ञान को जागृत करने का अवसर नवरात्र

आरती कुमारी

वैदिक मतानुसार वेद सब सत्य विधाओं की पुस्तक है। वेद अपौरुषेय हैं। वेद ईश्वर की वाणी है। वेद सब सत्य विद्याओं का मूल है। इसलिए केवल वेद विद्या पर ही विश्वास करना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र उपाय महर्षि पतंजलि प्रणीत यम ,नियम, आसान, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि है। महर्षि दयानंद सरस्वती विरचित सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में यह कहा गया है कि देव अथवा देवी ईश्वर के ही गौणिक नाम है। ईश्वर को पुलिंग अथवा स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में पुकारा जा सकता है। ईश्वर की दिव्य शक्ति को ही दैवीय जिसका अपभ्रंश होकर देवी कहा जाता है। ईश्वर के विषय में तो वेद में लिखा है कि उस ईश्वर की कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं हो सकती- न तस्य प्रतिमा अस्ति। मूर्ति पूजा करना जड़ की पूजा करना है। इससे बुद्धि जड़ होती है। अज्ञानता और अंधकार को बढ़ावा मिलता है। जिससे पाप लगता है। इसलिए उस दिव्य शक्ति परमात्मा की कोई मूर्ति न तो बनानी चाहिए और न ही मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। लेकिन इस वैदिक सत्य को नकारकर लोग देवी -देवताओं की मूर्तियाँ बनाकर उन्हें मंदिर आदि स्थल पर प्रतिस्थापित करते हैं और नवरात्र सहित कई अवसरों पर उन प्रतिमाओं की पूजन -अर्चा करते हैं। भारत में अतिप्राचीन काल से नवरात्रि पर्व हर्षोल्लास पूर्वक धूमधाम से मनाए जाने की ऐतिहासिक, समृद्ध व विस्तृत परंपरा रही है। मान्यतानुसार इन दिनों में मन से माता दुर्गा की उपासना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता होने के कारण इन दिनों में शक्ति के नौ रूपों की पूजा -अर्चना की जाती है। इसलिए इस त्योहार को नौ दिनों तक मनाया जाता है, जिसे नवरात्र कहा जाता है। नवरात्र में दो शब्द है- नव और रात्र। नव शब्द संख्या का वाचक है, और रात्र का अर्थ है- रात्रि समूह अर्थात काल विशेष। इस नवरात्र शब्द में संख्या और काल का अद्भुत सम्मिश्रण है। शब्द नवरात्र- नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रम्। रात्राह्नाय पुंसि। (पाणिनी 2/4/9) तथा संख्यापूर्वे रात्रम् । (क्लीवम लि. सूक्त 131) से बना है। यों ही द्विरात्रं, त्रिरात्रं, पांचरात्रं (पांचरात्रादि में विष्णुरात्र, इंद्ररात्र, ऋषिरात्र आदि पद तत्व ज्ञानप्रद अर्थक भी प्रयुक्त हैं), गणरात्रम् आदि द्विगु समासांत शब्द हैं। इस प्रकार इस शब्द से जगत के सर्जन- पालन रूप अग्नीसोमात्मक द्वन्द्व (मिथुन) की पुष्टि होती है। आद्याशक्ति भगवती स्वयं कहती है-

शरत्काले महापूजा क्रियते या छ वार्षिकी।
तस्यां ममैतन्महात्म्य श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः।।
सर्वाबाधानिर्मुक्तों धनधान्यसुतान्वितः ।
मनुष्यों मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः।।
-देवी माहात्म्य, फलश्रुतिर्नाम द्वादश अध्याय 12-13

अर्थात- शरद ऋतु में मेरी जो वार्षिक महापूजा अर्थात नवरात्र पूजन होता है, (वर्षारंभ अर्थात चैत्र के नवरात्र में वार्षिकी वासंती नवरात्र एवं शरद ऋतु- आश्विन नवरात्र में मेरी जो महापूजा की जाती है, उसमें भी यह च कार से व्यंजित है।), उसमें श्रद्धा भक्ति के साथ मेरे इस देवी माहात्म्य (सप्तशती) का पाठ या श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर निःसंदेह मेरे कृपा प्रसाद से मानव सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होता है, और धन- धान्य, पशु- पुत्रादि संपति से सम्पन्न हो जाता है। मानव जीवन की प्राणप्रद ऋतुएं मूलतः छह होने पर भी मुख्यतः दो ही हैं- शीत ऋतु (सर्दी) और ग्रीष्म ऋतु (गर्मी)। आश्विन से शरद ऋतु से शीत तो चैत्र से वसंत से ग्रीष्म। ये दो ऋतु भी विश्व के लिए एक वरद मिथुन (जोड़ा) बन जाता है। एक से गेहूं (अग्नि) तो दूसरे से चावल (सोम) के युगल का सादर उपहार देती है। यही कारण है कि ये दो नवरात्र नवगौरी अथवा परब्रह्म श्रीराम का नवरात्र और और नवदुर्गा अथवा सबकी आद्या महालक्ष्मी के नवरात्र सर्वमान्य हो गए। नवरात्रि हमेशा दो मुख्य मौसमों के संक्रमण काल -प्रथम सर्दी के बाद गर्मी शुरु होते समय चैत्र मास में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल नवमी तक और द्वितीय गर्मी- वर्षा के बाद सर्दी शुरु होने पर आश्विन मास में आश्विन शुक्ल प्रथमा से लेकर आश्विन शुक्ल नवमी तक में आती है। जाड़े और वर्षा के बाद ही बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है। ऋतु परिवर्तन के दो मास बीतने वाले मास के अंतिम सात दिन और आने वाले मास के प्रथम सात दिन कुल चौदह दिन के इस समय को ऋतु संधि कहा जाता है। इन दोनों नवरात्रों अर्थात जाड़े और वर्षा ऋतु के बाद ऋतु परिवर्तन होते समय अर्थात ऋतु संधिकाल में हमारी सभी अग्नि जठराग्नि और भूताग्नि कम होने के साथ- साथ शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है। इस समय प्राप्त भोज्य सामग्री के दूषित होने की संभावना अधिक होती है। इस कारण इस ऋतु संधिकाल और इसके आस-पास के समय में विभिन्न रोग होने की संभावना बेतहासा बढ़ जाती है। इस मौसम में ज्वर अतिसार आंत्र ज्वर, पेट में जलन, खट्टी डकार, डेंगू, बुखार, मलेरिया. वायरल बुखार, एलेर्जी आदि-आदि कितने रोग पैदा हो जाते है। ऐसे रोगों से बचाव के लिए नवरात्र एक आयुर्वेदिक पर्व है। नवरात्र नामक इस भारतीय पर्व परंपरा के पीछे एक आध्यात्मिक, प्राकृतिक, आयुर्वेदीय, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी रहस्य निहित है। दो मुख्य मौसमों के संक्रमण काल में आने वाली अश्वनि नक्षत्र अर्थात शारदीय नवरात्र और चैत्र अर्थात वासन्तीय नवरात्रि, दोनों का ही अपना एक अलग महत्व होता है। प्राकृतिक आधार पर नवरात्रि ग्रीष्म और सर्दियों की शुरुआत से पहले होती है। प्रकृति के परिवर्तन का यह उत्सव होता है। नवरात्र के इन दोनों ही कालावधि के समय दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। इसी समय पर नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। आयुर्वेद मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के रोग की चिकित्सा आदि सिद्धांतों पर कार्य करता है। नवरात्र में नौ दिन नवरात्रि व्रत, उपवास -जागरण आदि किया जाता है। और शरीर के नौ द्वारों को जागरुक किया जाता है। वैदिक साहित्य में नव द्वार शब्द आया है- नवद्वारे पुरेदेहि।\

अर्थात -नौ दरवाजों का नगर ही हमारा शरीर है।

शरीर में नौ द्वार होते हैं- दो कान, दो आंख, दो नासाछिद्र, एक मुख और दो उपस्थ इन्द्रि अर्थात मल द्वार मूत्र द्वार। इन नौ द्वारों में छाए अंधकार को अनुष्ठान के माध्यम से एक -एक रात्रि में एक -एक इंद्रियों के द्वार के संबंध में मनन, चिंतन कर यह अनुभव प्राप्त करना, विचार करना चाहिए कि उनमें किस-किस प्रकार की विशेषताएं हैं, आभाएं हैं? तथा उनका किस प्रकार का विज्ञान है? उनसे शरीर के बेहतर संचालन के लिए कैसे कार्य लिया जा सकता है? ऐसे चिंतन, मनन, विचार का समय का नाम नवरात्रि है। इस प्रकार नव द्वार में छाए हुए रात्रि का अर्थ हुआ- अंधकार। अंधकार से प्रकाश में लाने की प्रक्रिया को ही जागरण कहा जाता है। जागरण का अर्थ है- जागरूक रहना। जागरूक रहने वाले मनुष्य के यहाँ रात्रि जैसी कोई वस्तु नहीं होती। रात्रि तो उनके लिए होती है, जो जागरूक नहीं रहते। इसलिए आत्मा से जागरूक हो जाने वाले परमात्मा के राष्ट्र में चले जाते हैं और वे नवरात्रियों में नहीं आते। माता के गर्भस्थल में रहने के नव मास भी रात्रि के ही रूप हैं, क्योंकि वहाँ पर भी अंधकार रहता है, वहाँ पर रूद्र रमण करता है और वहाँ पर मूत्रों की मलिनता रहती है। उसमें आत्मा नवमास तक वास करके शरीर का निर्माण करता है। वहाँ पर भयंकर अंधकार है। इसलिए नौ द्वारों से जागरूक रहकर उनमें अशुद्धता नहीं आने देने वाला मानव नव मास के इस अंधकार में नहीं जाता, जहाँ मानव का जीवन महाकष्टमय होता है। वहाँ इतना भयंकर अंधकार होता है कि मानव न तो वहाँ पर कोई विचार-विनिमय कर सकता है, न ही कोई अनुसंधान कर सकता है और न विज्ञान में जा सकता है। इस अंधकार को नष्ट करने के लिए भारतीय परंपरा में गृहस्थियों में पति-पत्नी को जीवन में दैव यज्ञ अनुष्ठान करने का विधान किया गया है। दैव यज्ञ का अर्थ है- ज्योति को जागरूक करना, जागृत करना। दैविक ज्योति का अर्थ है- दैविक ज्ञान-विज्ञान को अपने में भरण करने का प्रयास करना। वही आनंदमयी ज्योति, जिसका वर्णन वेदों में किया गया है, और जिसको जानने के लिए ऋषि- मुनियों ने प्रयत्न किया। इसमें प्रकृति माता की उपासना की जाती है, जिससे वायुमंडल में वातावरण शुद्ध हो और अन्न दूषित न हो। इस समय माता पृथ्वी के गर्भ में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ परिपक्व होती है। इसीलिए विद्वान, बुद्धिजीवी प्राणी माता दुर्गे की याचना करते हैं अर्थात प्रकृति की उपासना करते हुए माता से अपने घर को इन ममतामयी वनस्पतियों से भर देने की प्रार्थना करते हैं। बहरहाल, नवरात्र का वैदिक स्वरूप बदल गया है, और वर्तमान में प्रतिमा निर्माण कर नवरात्र के प्रथम दिन देवी शैलपुत्री की पूजा देवी पार्वती के रूप में की जाती है। द्वितीय दिन देवी पार्वती के यौवन रूप को प्रतिष्ठित करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होती है। तृतीय दिन प्रशांत स्वरूप को धरण करने वाली देवी चंद्रघंटा की पूजा होती है। चौथे दिन भयंकर और उग्र रूप वाली देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवे दिन कार्तिकेय की माता देवी स्कंदमाता की पूजा होती है। छठे दिन अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को प्राप्त करने वाली देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। सप्तमी दिन काली माता के रूप में कालरात्रि देवी की पूजा होती है। अष्टमी के दिन धर्म और भक्ति की प्रतीक देवी महागौरी की पूजा होती है। नवमी के दिन सभी सिद्धियों को देने वाली देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नवरात्रि का अंतिम दिन विजयादशमी (दशहरा) होता है, जिसे देवी दुर्गा के विजय का प्रतीक माना जाता है।

क्या इस समय 'इंडिया गठबंधन 'का सितारा बुलंदी पर है ?

अशोक भाटिया, मुंबई

इंडिया गठबंधन का जब गठन हुआ था तब दूसरे दलों से इस गठबंधन का खूब मजाक उड़ाया था कि यह गठबंधन क्या करेगा ? उत्तरप्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी फिर फेल जो जाएगी वगैरह , पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है । बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली अच्छी सफलता के बाद दो राज्यों हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में फिर से इस अलायंस की धमक दिखने लगी है। हाल ही में आए एग्जिट पोल के नतीजे तो यही बता रहे हैं। एग्जीट पोल के नतीजों में जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बहुमत के करीब दिख रही है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बड़ी जीत हासिल करने की ओर दिख रही है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे वास्तविक साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर इसके गहरे राजनीतिक असर देखने को मिलेंगे। खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी इस वक्त लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी की बीते दो दशक की राजनीति में यह संभवतः पहली बार होगा जब कांग्रेस पार्टी लगातार किसी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। एग्जिट पोल के औसतन नतीजे देखें जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस को 40-48 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा को 27 से 32 सीटें मिल सकती हैं। जबकि पीडीपी को 6-12 और अन्य को 6-11 सीटें मिलने की संभावना है। यहां निश्चित तौर पर पीडीपी-कांग्रेस बहुमत के करीब है। अगर वह बहुमत से दूर रहता है तो ऐसा संभव है कि उसे पीडीपी का साथ मिल जाए। दूसरी तरफ भाजपा और अन्य जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा समर्थित निर्दलीय हैं, के दम पर 40+ हो रही है। यदि हरियाणा के चुनाव बाद सर्वेक्षण देखें तो वहां की 90 सदस्यीय सीट पर कांग्रेस पार्टी 55 से 62 सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही है। उसके लिए यह एक बहुत बड़ी जीत कहलाएगी। इससे निश्चित तौर पर उत्तर भारत में पार्टी को अपने दम पर अपेक्षाकृत एक बड़े राज्य में सत्ता मिलेगी। अभी उत्तर भारत में वह केवल हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह तीन राज्यों में अपने दम पर सरकार में होगी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। एग्जिट पोल अगर वास्तविक नतीजे में तब्दील होते हैं तो निश्चिततौर पर यह राहुल गांधी और उनकी टीम के लिए यह बड़ी जीत होगी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं। वह हरियाणा में मतदान से चंद घंटों पहले वहां के बड़े दलित नेता अशोक तंवर को पार्टी में वापसी करवाते हैं। अशोक तंवर वही नेता हैं जिन्होंने बीते 2019 के विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले अध्यक्ष पद से हटाए जाने के कारण कांग्रेस छोड़ दिया था। वह बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर कुमारी सैलजा के खिलाफ मैदान में थे। वह राज्य में हुड्डा कैंप और सैलजा कैंप से इतर शुरू से राहुल कैंप के नेता रहे हैं। लेकिन, बतौर आलाकमान राहुल गांधी के कमजोर पड़ने और हुड्डा से मनमुटाव के कारण अशोक तंवर को कांग्रेस छोड़ना पड़ा था। लेकिन, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राहुल गांधी 2019 वाले राहुल गांधी नहीं हैं। हुड्डा कैंप की तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी टीम ने हरियाणा के चुनाव में अपनी पकड़ बनाए रखी। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर हरियाणा में सरकार गठन में भी राहुल गांधी का असर दिखेगा। इसके अलावा इन दोनों राज्यों के एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो यह भी साबित होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों में घटौती और इंडिया गठबंधन की सीटों में शानदार बढ़ोतरी कोई तुक्का नहीं था। बल्कि, इससे यह साबित होगा कि राष्ट्रीय के साथ राज्यों के स्तर पर अब एनडीए से जनता का मोहभंग होने लगा है। वह अब विकल्प तलाशने लगी है। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार और बीते लोकसभा में उसे वहां बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इसके आलावा महाराष्ट्र में विपक्षी इंडिया गठबंधन और आक्रामक होगी। महाराष्ट्र में पार्टी के सामने महाविकास अघाड़ी से मजबूती से निपटने की चुनौती है। पार्टी यहां शिवसेना (शिंदे गुट) के साथ सरकार में हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने वाली पार्टी ने एनसीपी से अलग होकर आए शरद पवार के भतीजे अजित पवार को अपने खेमे में कर चुकी है। ऐसे में पार्टी को चुनाव के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दे को लेकर सावधानी बरतनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी का मुद्दा उसके ऊपर ही भारी पड़ जाए। राज्य में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होगा। ऐसे में भाजपा के लिए समय के हिसाब से आगे बढ़ना होगा।दूसरी तरफ लोकसभा की हार के बाद एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी कमजोर पड़ेगा। झारखंड में भाजपा जेएमएम को हटाकर सत्ता में आने के लिए जोर आजमाइश कर रही है । पार्टी ने इस काम के लिए चंपाई सोरेन को अपने साथ मिलाया है। खास बात है कि भाजपा बड़ी संख्या में चुनाव से पहले विरोधी दल के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करती है। इसके अलावा उन्हें टिकट भी देती है। ऐसे में पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ही वरिष्ठ नेताओं में असंतोष पनपने लगता है। हरियाणा में पार्टी को इस बार टिकट बंटवारों में बड़े पैमाने पर बगावत का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी हरियाणा से सबक लेते हुए झारखंड में भी फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहेगी। देखा जाय तो पार्टी राज्य में सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए कई राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल देती है। हालांकि, इस चुनाव में भाजपा को यह दांव कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा पार्टी की तरफ से कई पुराने चेहरों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाया जाता है। इस बार पार्टी की यह रणनीति भी बेअसर साबित होती नजर आ रही है। इसके अलावा पार्टी चुनाव से पहले कलह को कंट्रोल करने में असफल रही है। ऐसे में पार्टी के लिए बागियों की चुनौती से निपटना भी काफी अहम है। वर्तमान में दो विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल से इतना तो तय है कि भाजपा को अब अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। एक बात और राहुल गाँधी अब अपनी तेजी से उड़ती पतंग देख अपने सहयोगियों पर ही दबाव बनाने की कोशिश करने लगे है । हाल के समाचारों के अनुसार असल में उत्तरप्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। इसके लिए कांग्रेस 50-50 सीट शेयरिंग फॉर्मूला चाहती है यानी 5-5 सीटों पर दोनों दल लड़ें लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार ही नहीं हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ,राहुल गांधी से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं । समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है। इसी कोशिश में अखिलेश यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी से सीट की मांग की थी। लेकिन राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक भी सीट नहीं दी। जिसके बाद मजबूरी में अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में अपने दम पर उम्मीदवार उतारे। राहुल गांधी से मिला ये धोखा अखिलेश शायद ही भूले होंगे और हो सकता है कि उत्तरप्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस को यही सबक सिखाना चाहते हैं। वहीं भाजपा अखिलेश और राहुल की कथित दोस्ती पर कटाक्ष कर रही है। वैसे कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की रणनीति भी तैयार कर ली है। उत्तरप्रदेश में कांग्रेस ने उन सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है, जहां-जहां उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों के आवेदन मंगाने भी शुरू कर दिए हैं। इसके जरिए कांग्रेस ने अखिलेश तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थीं, जिसमें कांग्रेस 6 पर जीती थी। इसके बाद कहीं न कहीं अखिलेश यादव के कारण ही यूपी में अस्तित्व खोने की कगार पर खड़ी कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिली थी। अब विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस, अखिलेश यादव से उसी दरियादिली की उम्मीद जता रही है। साथ ही साथ उन्हें अकेले उपचुनाव लड़ने का तेवर भी दिखा रही है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

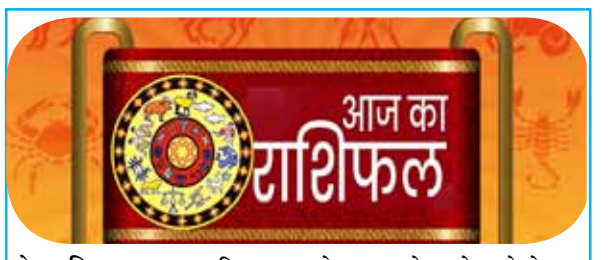

मेष राशिः आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपको घर के बड़ो से कुछ प्रेरणा मिलोगी। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे, वो सफल होगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा। कोई रिश्तेदार आज आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए सुझाव देगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढेगी। बडे बुजुर्ग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे, लोग आपकी वाह-वाही करेंगें। आज आपको वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

वृष राशिः आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके आस-पास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से साझेदारी करने पर विचार करेंगे। आज आपको उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होने वाला है। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में मान-सम्मान बढेगा, आपके क्रिएटिविटी की लोग सराहना करेंगे। दांपत्य जीवन में सुखों की बढ़ोतरी होगी।

मिथुन राशिः आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए है, लेकिन पढाई में और मेहनत करने की जरूरत है। आज घरवालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस मे सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जूनियर आपसे काम सिखाना चाहेंगे। लवमेट के साथ रिश्तों में सुधार आयेगा।

कर्क राशिः आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके व्यापार में रोज की अपेक्षा ज्यादा लाभ होगा। नवविवाहित दंपत्ति के बीच आज मीठी नोक झोंक होगी, इससे रिश्तों में और मिठास बढ़ेगी। आज पैसों के लेन-देन में सावधानी बरते। नौकरी कर रहे लोगों को आज अपना काम पूरा करने के लिए थोड़ाअधिक मेहनत करने की जरूरत है।

सिंह राशिः आज पूरे दिन भाग्य आपके साथ रहेगा। आज किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लवमेट आज अपने रिश्तें के बारे में घरवालों को बताएंगे, घरवाले इस पर विचार भी करेंगे। इस राशि के केमिस्ट शॉप वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आज आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाने की योजना बनायेंगे। महिलाएं आज रसोई घर में व्यस्त रहेंगी। दांपत्य जीवन में खुशियां बरकरार रहेगी।

कन्या राशिः आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आपको सरकारी कामों में कुछ लोगों से राय मिलेगी, जिससे आपका काम असान हो जायेंगा। आपका कोई पुराना दोस्त आपको फोन कर के आपको सरप्राइज देगा। आपकी किसी जरूरी बात पर घर वाले सहमति जतायेंगे। तरक्की आज आपके कदम चूमेगी। आपको अपना करोबार बढ़ाने के लिए आज कई मौके मिलेंगे।

तुला राशिः आज का दिन मिली-जुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आप सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आप घर पर ही परिवारवालों के साथ धार्मिक कार्यों का आयोजन करेंगें। आज आपकी तरक्की के कई रास्ते खुलेंगे। ऑफिस के काम को थोड़ा संभलकर करने की जरूरत है। कोई आपके काम की शिकायत कर सकता है। आज किसी से भी उलझने से आपको बचना चाहिए।

वृश्चिक राशिः आज आपको किसी अपने से कोई अच्छी खबर मिलने के योग बने हुए हैं। आज आप अपने घरेलू कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। आज आपके सकारात्मक रवैये से जीवनसाथी प्रसन्न रहेंगे। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जायेंगे। मार्केटिंग की जॉब कर रहे लोगों से आज कोई अच्छा क्लाइंट जुड़ेगा, जो भविष्य में अच्छा धन लाभ कराएगा।

धनु राशिः आज का दिन जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। आज व्यापार में किसी यैसी कंपनी के साथ डील फाइनल होगी, जो आपको उम्मीद से अधिक फायदा करायेगी। वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कोई नया केस हाथ लगेगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी, जीवनसाथी के साथ कोई अच्छी मूवी देखने का मन बनायेंगे। आज अपने दोस्त की किसी बात का बुरा ना माने, दोस्ती मजबूत होगी।

मकर राशिः आज आपका दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। आज आपको किसी भी प्रकार के क़ानूनी मामलों से दूर रहने की आवश्यकता है। आज बिना सोचे- समझे किसी अजनबी पर भरोसा न करें। इस राशि के छात्रों को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी विषय को समझने में आपको अपने सहपाठियों से सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिः आज आपके हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जायेगा। ऑफिस में आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी बेहतरीन राय देंगे, बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। आज आप लेखन कार्यों में रुचि लेंगे आपका लेखन और अच्छा होगा। आज आपकी बातें दूसरों पर प्रभाव डालेगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको परिवार का पूरा साथ मिलेगा।

मीन राशिः आज आपका दिन बढिया रहेगा। बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। किसी नयी बिजनेस डील

एक पूर्वानुमेय हार

माओवादियों को सशस्त्र संघर्ष त्यागना होगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रवेश करें

माओवादियों को एक और झटका तब लगा जब वरिष्ठ सदस्यों समेत उनके 31 कार्यकर्ता शुक्रवार को अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। अबूझमाड़ दक्षिण छत्तीसगढ़ का जंगली इलाका है जिसे उग्रवादियों का आखिरी गढ़ माना जाता है। हाल के महीनों में छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में कई वामपंथी उग्रवादी कार्यकर्ता मुठभेड़ में मारे गए हैं क्योंकि हाल के वर्षों में माओवादियों के बड़े हमलों के बाद विभिन्न अर्धसैनिक बलों और पुलिस की समन्वित कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। सुरक्षा बल इस तथ्य से परिचित हैं कि हालांकि माओवादियों ने मध्य और पूर्वी भारत के जंगलों में अपनी उपस्थिति और प्रभाव काफी हद तक खो दिया है, लेकिन उनकी बची हुई ताकत उन जगहों पर खतरा पैदा कर रही है जहां वे सक्रिय हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्ण समर्थन से चलाए जा रहे तीव्र अभियानों ने विद्रोहियों को लगातार झटके दिए हैं और कई विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि माओवादियों को झटका तब नहीं लग सकता था, जब आदिवासी इलाकों में लोग माओवादियों के साथ जुड़े होते, जहां विद्रोहियों ने गुरिल्ला संघर्ष किया है। भारत के सुदूर इलाकों में आदिवासी लोगों को कई सालों तक खतरे में डालने के बाद, माओवादी अब उनसे थक चुके हैं और अलगाव का सामना कर रहे हैं।

माओवादी सिद्धांत और राजनीतिक व्यवहार में कई समस्याएं हैं जो बताती हैं कि विद्रोह का कमज़ोर होना हमेशा से ही तय था। पेरू, फिलीपींस, मलेशिया और कोलंबिया में भी इसी तरह के विद्रोह विफल रहे। भारतीय माओवादियों के लिए, राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सैन्यवाद पर अत्यधिक निर्भरता और राजनीतिक-वैचारिक कार्यों की अधीनता, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा का एक चक्र बन गया, ने संभावित समर्थकों, जिनमें ज़्यादातर गरीब आदिवासी लोग हैं, को दूर कर दिया है। एक विविधतापूर्ण देश में माओवाद की कालबाह्य विचारधारा का पालन, जहाँ भूभाग और राजनीतिक व्यवस्था 1920 के दशक के चीन से बहुत कम मिलती-जुलती है, साथ ही चुनावी लोकतांत्रिक संस्थाओं और भारतीय राज्य की प्रकृति के लचीलेपन को पहचानने में असमर्थता अन्य कारक हैं। इन मुद्दों ने माओवादियों को भारतीय लोकतंत्र के भीतर उपलब्ध अवसरों की उपेक्षा करने के लिए प्रेरित किया है, इसके बावजूद कि इसके कई कारण हैं। अगस्त में सीपीआई (माओवादी) के गठन के बाद आंदोलन के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी एक हस्ताक्षर रहित पुस्तिका में, नक्सली आंदोलन के दो सबसे मजबूत अवशेषों के विलय के बाद, माओवादियों ने अपनी कमज़ोरी और असफलताओं पर शोक व्यक्त किया, लेकिन अपनी वैचारिक मंशा पर दोगुना ज़ोर दिया। यह उनके अपने अनुभवों से सीखने की अनिच्छा को दर्शाता है। आदिवासी लोगों की खातिर, जिनके हितों का प्रतिनिधित्व करने का वे दावा करते हैं, माओवादियों को हथियार छोड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रवेश करना चाहिए।

सीखने की अवस्था

पीएम इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों की निगरानी की आवश्यकता है

3 अक्टूबर को, बिना किसी शोर-शराबे के, केंद्र ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जो कार्यान्वयन के लिए मंच के रूप में काम करेगा- भारत के बेरोजगारों और काफी हद तक बेरोजगार युवाओं के लिए बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं में से एक है। यह पोर्टल, जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को क्रियान्वित करता है - रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई पांच-योजना पैकेज का हिस्सा - उन कंपनियों से मेल खाएगा जो नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के साथ साल भर की ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। सिद्धांत रूप में, मुख्य रूप से केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजना एक ऐसे देश के लिए समझ में आती है, जिसमें एक बड़ा, युवा कार्यबल है, जो युवा बेरोजगारी के चिंताजनक स्तरों से भी जूझ रहा है। छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा और नियोक्ताओं द्वारा वांछित वास्तविक दुनिया के व्यावहारिक कौशल के बीच की खाई को पाटने के अलावा, जानी-मानी फर्म इंटर्नशिप के अंत में किसी प्रकार का प्रमाणन प्रदान कर सकती हैं, जिससे संभावित नियोक्ताओं को नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की समीक्षा करने में सुविधा होगी। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान कर सकता है जिससे नियोक्ता अक्सर जूझते हैं: "वे नौकरी पा सकते हैं, लेकिन क्या वे काम पूरा कर सकते हैं?"

पायलट प्रोजेक्ट के तहत, 1.25 लाख इंटर्न का पहला बैच 2 दिसंबर को स्वैच्छिक रूप से भाग लेने वाली कंपनियों के साथ काम करना शुरू कर देगा। हालांकि सरकार ने योजना की घोषणा करने से पहले और बाद में उद्योग निकायों से परामर्श किया है, लेकिन मार्च 2029 तक एक करोड़ इंटर्नशिप बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने से पहले यह सही रूप से सतर्क है। पायलट प्रोजेक्ट से मिले सबक अंतिम योजना के डिजाइन को सूचित करेंगे। आवेदकों को कंपनियों से मिलाने की प्रारंभिक प्रक्रिया में कुछ अंतर्दृष्टि स्पष्ट होगी, लेकिन परिणामों की पूरी गुंजाइश दिसंबर 2025 के बाद ही आंकी जा सकती है, जब इंटर्न नौकरी के बाजार में फिर से प्रवेश करेंगे। साथ ही, ड्रॉपआउट दरों और शिकायतों पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत होगी। कुछ विशेषताएं चुनौतियां पेश करती हैं, जैसे कि इंटर्न को उनके जिले के भीतर या उसके आस-पास रखने की योजना, और यदि यह संभव नहीं है, तो उनके राज्य के भीतर। यह स्पष्ट नहीं है कि यह बिहार जैसे कम औद्योगीकृत और कम सेवा-उन्मुख राज्यों में कैसे चलेगा, जहां अधिक संख्या में आवेदकों को आकर्षित करने की संभावना है। भारत के विनिर्माण उत्पादन में आधे से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ़ पाँच राज्यों का है, और कम व्यावसायिक उपस्थिति वाले राज्यों में युवा बेरोज़गारी ज़्यादा है। व्यावसायिक कौशल के अलावा, इस योजना में डिजिटल और सॉफ्ट कौशल को भी शामिल करने की ज़रूरत है जो आधुनिक कार्यस्थल के लिए ज़रूरी हैं। पायलट प्रोजेक्ट के प्रक्षेपवक्र को बिना किसी आत्म-प्रशंसा दृष्टिकोण के एक मेहनती और स्पष्ट मूल्यांकन की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इच्छित परिणाम अंततः प्राप्त हों।

पश्चिम एशिया में त्रिस्तरीय युद्ध जिसका कोई अंत नहीं

स्टेनली जॉनी

मैंने एक निबंध *विदेशी ए एयर* अक्टूबर 2023 में पत्रिका में, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने लिखा, "...हालांकि मध्य पूर्व बारहमासी चुनौतियों से घिरा हुआ है, यह क्षेत्र दशकों की तुलना में शांत है... इजरायल-फिलिस्तीनी स्थिति तनावपूर्ण है, विशेष रूप से पश्चिमी तट पर, लेकिन गंभीर टकरावों के बावजूद, हमने गाजा में संकट को कम कर दिया है।" इस लेख को प्रेस में भेजे जाने के कुछ दिनों बाद, 7 अक्टूबर को, हमास ने इजरायल में अपना सबसे घातक हमला किया, जिसमें कम से कम 1,200 लोग मारे गए और लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया, जिससे इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष में युद्ध का नवीनतम दौर शुरू हो गया। एक साल बाद, पश्चिम एशिया (या मध्य पूर्व, जैसा कि श्री सुलिवन इसे कहते हैं) आज दशकों की तुलना में अधिक घातक है।

यदि इस क्षेत्र को अमेरिकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्री सुलिवन का अक्टूबर 2023 का पूर्वानुमान पूरी तरह से निराधार नहीं था। 2020 में इजरायल, यूएई, बहरीन और मोरक्को द्वारा हस्ताक्षरित अब्राहम समझौते ने अरब-इजरायल साझेदारी के एक नए युग की घोषणा की। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद कहा कि सऊदी अरब इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के एक उन्नत चरण में था। सितंबर 2023 में दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक महत्वाकांक्षी आर्थिक गलियारे की घोषणा की, जिसका उद्देश्य फारस की खाड़ी, जॉर्डन और इजरायल के माध्यम से भारत के पश्चिमी तट को यूरोप से जोड़ना था। लेकिन श्री सुलिवन, अरब और इजरायल ने फिलिस्तीन के सवाल को नजरअंदाज कर दिया।

दो कथाएँ

इजराइल का मानना था कि उसने एक नई यथास्थिति स्थापित की है - बिना किसी परिणाम के कब्ज़ा। अरबों का मानना था कि फिलिस्तीन मुद्दे ने अपनी भू-राजनीतिक वैधता खो दी है और वे इजराइल के साथ दशकों पुराने अपने गुप्त संबंधों को औपचारिक रूप देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अमेरिका अपनी पश्चिम एशिया रणनीति के दो स्तंभों सुन्नी अरबों और इजराइलियों को पश्चिम एशिया को नया आकार देने और ईरान को अलग-थलग करने के अपने प्रयास में करीब लाना चाहता था। लेकिन इजराइल में जानलेवा हमला करके हमास ने न केवल इस यथास्थिति को नष्ट कर दिया, बल्कि घटनाओं की एक शृंखला भी शुरू कर दी, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष शुरू हो गया, जिसने पुराने तर्क को मजबूत किया कि पश्चिम में शांति और स्थिरता नहीं होगी।

यह एक कॉनिक्ट लूप जहाँ कोई पक्ष नहीं इसकी रोकथाम कर रहा है प्रतिद्वंद्वी. बिना किसी तोड़ने का तरीका इस मामले से बाहर निकलकर, इज़राइल ने ऊपर चढ़ो वृद्धि सीढ़ी

आर

जब तक फिलिस्तीन के प्रश्न का समाधान नहीं किया जाता, एशिया में शांति और स्थिरता बनी रहेगी।

लेकिन इजरायल का एक अलग कथानक है। इसने हमेशा फिलिस्तीनी सैन्यवाद को फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर अपने कब्जे से अलग करने की कोशिश की है। 7 अक्टूबर से पहले, इजरायल फिलिस्तीनी हिंसा को सुरक्षा उपद्रव के रूप में देखता था। लेकिन हमास के हमले के बाद, जो 1948 के बाद से इजरायल में पहला बड़ा हमला था, कथानक बदल गया। अब, इजरायल आतंक के खिलाफ एक "अस्तित्ववादी युद्ध" लड़ रहा है। इजरायल ने विद्रोह और रोष के साथ गाजा की ओर कूच किया। पिछले 12 महीनों में, इजरायल रक्षा बलों (IDF) ने 41,000 से अधिक फिलिस्तीनियों (हर दिन 110 से अधिक) को मार डाला है और लगभग 1,00,000 फिलिस्तीनियों को घायल कर दिया है। गाजा की लगभग पूरी आबादी (2.3 मिलियन) विस्थापित हो गई है।

ऑक्टोपस सिद्धांत

गाजा पर हमला शुरू होते ही ईरान समर्थित लेबनानी मिलिशिया समूह हिजबुल्लाह ने इजरायल के उत्तर में एक "समर्थन मोर्चा" खोल दिया। इजरायल ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए हिजबुल्लाह पर अपने हमले को दोगुना करके युद्ध का विस्तार किया और दमिश्क में उसके दूतावास परिसर पर हमला करके युद्ध को ईरान तक ले गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायल पर सीधे हमले शुरू कर दिए। अब इजरायल पश्चिम एशिया में तीन-स्तरीय क्षेत्रीय युद्ध लड़ रहा है।

प्रत्येक स्तर पर इजराइल के अलग-अलग उद्देश्य हैं, जो सामूहिक रूप से पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन को बदलने की इसकी रणनीति को और अधिक लाभ पहुँचाने के लिए बनाते हैं। निचले स्तर पर, इजराइल दो घोषित उद्देश्यों के साथ गाजा गया था - हमास को नष्ट करना और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना। बीच में, यह लेबनान के सीमावर्ती क्षेत्र से हिजबुल्लाह को खदेड़ना चाहता है और शिया मिलिशिया को इजराइल में रॉकेट दागने से रोकना चाहता है ताकि ऊपरी गलील क्षेत्र के विस्थापित निवासी अपने घरों को लौट सकें। शीर्ष पर, यह अपने मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी ईरान को कमजोर करना चाहता है। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा, इजराइल इस संघर्ष को एक प्रतिद्वंद्वी ऑक्टोपस के खिलाफ युद्ध के रूप में देखता है। ईरान ऑक्टोपस का मुखिया है और मिलिशिया (हमास, हिजबुल्लाह, हौथी, हशद अल-शबी, आदि) टेंटेकल्स हैं। तीन-स्तरीय युद्ध में, इजराइल टेंटेकल्स को नष्ट या नीचा दिखाना चाहता है और ऑक्टोपस को कमजोर करना चाहता है और इस तरह पश्चिम एशिया को नया आकार देना चाहता है। क्या यह एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है?

गाजा में 12 महीने की लड़ाई के बाद, जो 2007 से इजरायल की नाकाबंदी के तहत है और 7 अक्टूबर 2023 से इजरायल द्वारा घेर लिया गया है, इजरायल अभी तक 365 वर्ग किलोमीटर के एन्क्लेव में अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया है, जो कि दोनों देशों के बीच में स्थित है।

भूमध्य सागर और इजराइल के बीच कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अब आईडीएफ भी कह रहा है कि यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। 100 से ज़्यादा बंधक, जिनमें से कई के बारे में माना जाता है कि वे मर चुके हैं, अभी भी हमास की कैद में हैं। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि जब तक इजराइल गाजा में अपना अभियान बंद नहीं कर देता, तब तक वह इजराइल में रॉकेट दागना बंद नहीं करेगा। इजराइल ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह गाजा में अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता।

श्री नेतन्याहू ने युद्ध को लेबनान तक विस्तारित करने का निर्णय इसलिए नहीं लिया कि इससे उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं।

इजरायल के पास अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वह ऐसा करने से कोसों दूर है। यह सच है कि इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह पर लगातार किए गए हमले, जिसमें हसन नसरल्लाह की हत्या भी शामिल है, जो शायद अयातुल्ला खामेनेई के बाद ईरान की धुरी में दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, हिजबुल्लाह और ईरान दोनों के लिए एक बड़ा झटका था। जब हिजबुल्लाह अपने नेता की हत्या के बाद सदमे में था, तब इजरायल ने लेबनान पर जमीनी हमला किया। यहां इजरायल के सामने दो सवाल हैं। पहला, क्या हिजबुल्लाह के नेतृत्व का सिर कलम करने से इजरायल को गाजा में युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी? दूसरा, क्या हिजबुल्लाह के नेतृत्व का सिर कलम करने से इजरायल को लेबनान में हिजबुल्लाह को हराने में मदद मिलेगी? पहले सवाल का जवाब साफ तौर पर 'नहीं' है। दूसरे सवाल का जवाब आने वाले हफ्तों, महीनों या सालों में दिया जाएगा।

इतिहास बताता है कि सिर काटने से मिलिशिया को नष्ट करने या रोकने में शायद ही कोई मदद मिलती है। इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह के सह-संस्थापक अब्बास अल-मुसावी की हत्या के बाद नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन इससे हिजबुल्लाह को वह बनने से नहीं रोका जा सका जो वह आज है: इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली गैर-राज्य मिलिशिया। इजरायल ने 2004 में हमास के दो संस्थापक नेताओं को मार डाला। लेकिन इससे हमास को 2005 में इजरायलियों को एन्क्लेव से बाहर निकालने, 2007 में इस क्षेत्र पर कब्जा करने और पिछले साल 7 अक्टूबर को सीमा पार से हमला करने से नहीं रोका जा सका। अगर इजरायल ने 12 महीनों में घेरे हुए गाजा में हमास को नष्ट नहीं किया है, तो वह हिजबुल्लाह को लेबनान से रॉकेट दागने से कैसे रोकेगा? नसरल्लाह के मारे जाने के बाद, हिजबुल्लाह ने इजरायल में सैकड़ों रॉकेट दागे हैं।

ईरान का प्रश्न

यह हमें तीसरी समस्या की ओर ले जाता है: ईरान। आईडीएफ के पास बहुत अधिक ताकत है। इजरायल ने अतीत में साबित कर दिया है कि वह ईरान के अंदर सटीक हमले कर सकता है, जो इस्लामिक गणराज्य में इसकी खुफिया जानकारी की गहरी पैठ को दर्शाता है। ईरान द्वारा 1 अक्टूबर को किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के प्रतिशोध में इजरायल ईरान में एक निर्णायक हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या यह ईरान को एक और हमला करने या धुरी का समर्थन करने से रोकेगा? अगर ऐसा नहीं होता है, तो इजरायल, ईरान और पूरे क्षेत्र को पश्चिम एशिया के दो सबसे शक्तिशाली अभिनेताओं के बीच गोलीबारी का मुकाबला मिलेगा। अगर गोलीबारी के मुकाबले में ईरान की पहले से ही कमजोर प्रतिरोधक क्षमता और कमजोर होती है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ईरान अपने परमाणु सिद्धांत को बदल देगा। जब तक तेहरान में शासन परिवर्तन नहीं होता, तब तक इजरायल के पास ईरान के साथ कोई स्पष्ट अंतिम खेल नहीं है।

यह एक ऐसा संघर्ष चक्र है जिसमें कोई भी पक्ष अपने प्रतिद्वंद्वी को रोक नहीं पा रहा है। इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने के कारण, इजराइल ने तनाव की सीढ़ी पर चढ़ना चुना। क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए, सबसे पहले गाजा में संघर्ष विराम होना चाहिए। दीर्घकालिक स्थिरता के लिए, फिलिस्तीन के प्रश्न को संबोधित करने की आवश्यकता है। इजराइल अभी इनमें से किसी के लिए भी तैयार नहीं है; इसके बजाय वह पश्चिम एशिया को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। पिछली बार जब किसी देश ने ऐसा करने की कोशिश की थी, तो वह अमेरिका था और दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र विफल हो गया था।

stanly.johny@thehindu.co.in

https://t.me/AllNewsExamHindi

गुरमीत राम रहीम सिंह और न्याय का उपहास

हामिद दाभोलकर

राज्य कार्य समिति के सदस्य MANS के साथ, एक विरोधी अंधविश्वास आंदोलन महाराष्ट्र

जेल में बंद सच्चा सौदा के प्रमुख उरमीत राम रहीम सिंह, जो बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले पैरोल पर रिहा हुए थे। उन्हें 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव और 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले पैरोल पर रिहा किया गया था। सिंह 15 बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। इनमें से कई मौके ऐसे भी रहे हैं जब चुनाव होने वाले थे। कुल मिलाकर, सिंह ने अपनी सजा के 250 से ज़्यादा दिन जेल से बाहर बिताए हैं।

बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया

उनकी रिहाई का स्पष्ट कारण यह है कि एक संप्रदाय के नेता के रूप में, हरियाणा और पंजाब से परे, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, अनुमानित 30 विधानसभा क्षेत्रों में उनका समर्थन और प्रभाव है। उनके राजनीतिक प्रभाव को अलग रखते हुए, यह तथ्य कि उन्हें दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार करने और एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो अदालत द्वारा हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, को दोहराया जाना चाहिए।

यह हास्यास्पद है कि ऐसे दोषियों को इस तरह की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, खासकर तब जब पत्रकार रामचंदर छत्रपति ने सिंह और उसके अपराधों को उजागर करके अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। *पूरा सच* (द होल ट्रुथ) में डेरा के एक अनुयायी का गुमनाम पत्र छपा था, जिसमें सिंह पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था। 2002 में छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

कि नौकरशाही-राजनीतिक वर्ग गठजोड़ चला गया अपनी सुविधा के लिए अपने रास्ते से हटकर हत्या और बलात्कार का दोषी एक खराब प्रतिबिंब है हमारे समाज का

उनके आवास पर। 2019 में ही सिंह को हत्या में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था। इसका मतलब है कि छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति को न्याय पाने के लिए कई बाधाओं से जूझना पड़ा। इतने सालों के संघर्ष के बाद नौकरशाही-राजनीतिक वर्ग गठजोड़ ने हत्या और बलात्कार के दोषी को मदद पहुंचाने के लिए अपनी हदें पार कर ली हैं, यह हमारे समाज की खराब छवि है और परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है।

राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग की भूमिका पहला सवाल राजनीतिक दलों की भूमिका से जुड़ा है। हरियाणा में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पैरोल देने के फैसले को लेकर बेबाक और बेशर्म रही है। ऐसा लगता है कि पैरोल दिए जाने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है और यही बात मायने रखती है। जबकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने पैरोल दिए जाने पर आपत्ति जताई, लेकिन दुखद सच्चाई यह है कि इस मामले में पिछली कांग्रेस नेतृत्व के विचार मौजूदा सरकार के विचारों से अलग नहीं थे। इन दलों को पूर्व प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने दोषसिद्धि के मामले में कानून के शासन को अपना काम करने देने का साहस दिखाया था। पार्टियों को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि वे हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के दोषी किसी व्यक्ति के माध्यम से राजनीतिक समर्थन मांगें।

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की भूमिका भी जांच के दायरे में है। श्री अंशुल छत्रपति ने ईसीआई से हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसमें हरियाणा सरकार को पैरोल आवेदन रद्द करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले पैरोल देना लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन होगा। यह विश्वास करना कठिन है कि ईसीआई ने विशिष्ट चुनावों से पहले सिंह को दिए गए पैरोल के अजीब पैटर्न पर ध्यान नहीं दिया है।

सिंह से जुड़े मामलों में न्याय दिलाने में न्यायालयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है - गुमनाम पीड़ितों द्वारा लिखे गए पत्रों का स्वतः संज्ञान लेने से लेकर यह सुनिश्चित करने तक कि मामलों की उचित सुनवाई हो और सज़ा मिले। उम्मीद है कि न्यायपालिका सिंह को उदारतापूर्वक पैरोल दिए जाने के रूप में न्याय के इस उपहास को रोकने में फिर से सक्रिय भूमिका निभाएगी।

मेरे पिता नरेंद्र दाभोलकर, एक तर्कवादी थे, जिन्होंने अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवा दी थी। वे इस बात पर जोर देते थे कि अंधविश्वास, तर्कहीन प्रथाओं और अपराधों के खिलाफ लड़ाई दशकों तक नहीं बल्कि सदियों तक लड़ी जानी चाहिए। सिंह की गाथा - उनके द्वारा किए गए अपराध और उन्हें मिली सजा - लगभग एक चौथाई सदी पूरी कर रही है, हमें एकजुटता दिखाने और श्री अंशुल छत्रपति जैसे लड़ाई में शामिल लोगों के लिए और अधिक शक्ति की कामना करने की जरूरत है।

संपादक के नाम चिठी

एक परिपक्व निर्णय
भारत का निर्णय
पाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेना सराहनीय है ("पाकिस्तान यात्रा एससीओ बैठक के लिए है, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए नहीं: जयशंकर", 6 अक्टूबर)। यह इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि कैसे एक देश को व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता को अलग रखते हुए अपने और क्षेत्र के हितों के लिए काम करना चाहिए।
भारत अपनी सच्ची प्रतिबद्धता दिखा रहा है

बहुपक्षवाद।
कीर्ति वधावन
कानपुर

एक दुखद स्थिति यह दुखद है कि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे मुद्दों पर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है जो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं ("जेल में जाति", 5 अक्टूबर)। ऐसे अन्य उदाहरण भी हैं जहाँ न्यायपालिका ने कार्यपालिका को संविधान के नियमों का पालन न करने के लिए फटकार लगाई है।
संविधान। यह हमारे संविधान पर एक दुखद टिप्पणी है।
सरकारें.
रवि माथुर
नोएडा

विचित्र और खतरनाक
विधायकों ने एक भयानक मिसाल कायम की है ("महाराष्ट्र में आदिवासी विधायक विरोध में इमारत से कूद गए", 5 अक्टूबर)। विधायकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विधानमंडल में मुद्दों पर चर्चा करें और समाधान निकालें। अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो वे दृढ़ रहना चाहिए। वे किस तरह का संदेश दे रहे हैं
क्या विरोध का ऐसा ख़तरनाक तरीका अपनाकर जनता को कोई संदेश भेजा जा रहा है? उनसे सीख लेते हुए, नागरिक भी विरोध के चरम रूपों का सहारा ले सकते हैं।
यदि विधिनिर्माता हमारा सम्मान चाहते हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से उचित व्यवहार करना सीखना होगा।
कोसाराजू चंद्रमौली
हैदराबाद

पश्चिम एशिया में तनाव यदि इजरायल ईरान के परमाणु स्थलों और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाता है, तो इससे वैश्विक तेल बाजारों में उथल-पुथल मच सकती है ("इजराइल ने लेबनान में अपनी बमबारी बढ़ा दी है" हज़ारों लोग पलायन कर रहे हैं", 6 अक्टूबर)। चूंकि भारत एक ऐसा देश है, जहां पश्चिम एशिया से तेल का प्रमुख आयातक, बढ़ी हुई लागत हमारी अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव डाल सकती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने के खिलाफ इजरायल को चेतावनी दी है, लेकिन इजरायल ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया है। कई तेल समृद्ध देश अमेरिकी शासन के अधीन हैं, जो भू-राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बना सकता है। इजरायल की गतिविधियों ने

इससे न तो शासन को और न ही पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया को कोई ठोस लाभ मिला।
राजेश हीरेमठ
बेंगलुरु

जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने हथियार प्रतिबंध का आह्वान किया, इजरायली प्रधानमंत्री ने उनकी कड़ी आलोचना की। जिस गति से इजरायल हमास और हिजबुल्लाह को खत्म कर रहा है
नेताओं ने संकेत दिया है कि वह युद्धविराम में दिलचस्पी नहीं रखता है। इसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर प्रतिबंध लगा दिया है
देश का दौरा कर रहे हैं। इसने 41,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला है। इजरायलियों की सामूहिक चेतना कहाँ है? कम गंभीर कृत्यों के लिए, राष्ट्रों ने पदच्युत कर दिया है
राजनीतिक नेताओं। क्या अब समय नहीं आ गया है कि दुनिया उनसे आह्वान करे
क्या आप इजराइल के लोगों से शासन परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं?
हेमचंद्र बसप्पा
बेंगलुरु

एक युग का अंत
सड़क पर वाहन कोलकाता में ट्रामों की लाइन खत्म होने वाली है, 6 अक्टूबर)। अलग-अलग ट्राम ट्रैक पर कब्जा किया जा रहा है।
हमारी सड़कों पर कीमती जगह। हम भावनात्मक रूप से ट्राम से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन वे अब कहीं भी परिवहन का वांछित साधन नहीं हैं।
वी. लक्ष्मणन
तिरुपुर

अधिक पत्र ऑनलाइन पढ़ने के लिए, क्यूआर कोड स्कैन करें।
ईमेल से भेजे गए पत्र
letters@thehindu.co.in
पूरा डाक पता और पूरा नाम या नाम के आरंभिक अक्षर अवश्य होने चाहिए।

उत्पादन पर जोर

गुणवत्तापूर्ण मैन्युफैक्चरिंग को विस्तार देकर आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के दिशा में उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआइ स्कीम) एक महत्वपूर्ण पहल है. इस योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपये का निवेश हासिल हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे रेखांकित करते हुए उम्मीद जतायी है कि पांच सेमी-कंडक्टर संयंत्र बहुत जल्दी दुनिया को भारत में निर्मित चिप की आपूर्ति करने लगेंगे. पीएलआइ स्कीम 14 प्रमुख क्षेत्रों में लागू की गयी है, जिनमें मोबाइल निर्माण, दवा एवं संबंधित तत्व, विशिष्ट इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, उन्नत बैटरी, ड्रोन और उसके पुर्जे, कपड़ा, मेडिकल सामान, दूरसंचार, खाद्य उत्पाद, सोलर मॉड्यूल आदि शामिल हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पीएलआइ स्कीम के लिए सरकार ने 1.97 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इससे बड़ी मात्रा के कारण निवेशक भी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं. सभी 14 क्षेत्रों में अब तक 755 आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है. इस योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में उत्पादकों को गुणवत्ता और निर्यात क्षमता के आधार पर सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान एवं अन्य प्रकार की सुविधाएं मुहैया करायी जाती हैं. यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इस वर्ष मार्च तक पीएलआई स्कीम के जरिये लगभग आठ लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. उल्लेखनीय है कि जब मार्च 2020 में इसका प्रारंभ हुआ था, तब इसमें तीन क्षेत्रों- मोबाइल एवं उसके पुर्जे, इलेक्ट्रिक और मेडिकल सामान- को ही शामिल किया गया था. चार वर्ष की अवधि में ही पीएलआइ स्कीम का दायरा 14 क्षेत्रों तक हो गया है. घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना अनेक कारणों से आवश्यक है. वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी तीन प्रतिशत से कुछ अधिक है. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अधिक भागीदारी प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की एक मुख्य प्राथमिकता है. भारत का घरेलू बाजार बहुत बड़ा है और यह बढ़ता जा रहा है. इस बाजार की मांग का बड़ा हिस्सा आयातित वस्तुओं से पूरा होता है. यदि देश में उत्पादन बढ़ता है, तो इस आपूर्ति के लिए आयात पर हमारी निर्भरता घटेगी तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को साकार करने में बड़ी सहायता मिलेगी. प्रधानमंत्री मोदी हमेशा देशवासियों को देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं. डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप इकोसिस्टम, वाहन, रक्षा, टेलीकॉम आदि में बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार तथा आर्थिक सुधारों से देश में उद्यमिता और औद्योगिक गतिविधियों को नयी दिशा एवं गति मिली है.

पीएलआइ स्कीम के लिए सरकार ने 1.97 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इससे बड़ी मात्रा के कारण निवेशक भी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं.

जयशंकर के पाकिस्तान दौरे के मायने

डॉ धनंजय त्रिपाठी
प्राध्यापक
साउथ एशियन यूनिवर्सिटी
नयी दिल्ली
dhananjay@sau.ac.in

शंघाई सहयोग संगठन की दो दिवसीय वार्षिक बैठक 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित हो रही है. इस आयोजन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे. लगभग एक दशक के बाद भारत के किसी वरिष्ठ मंत्री या अधिकारी की पाकिस्तान यात्रा होगी. ऐसे में स्वाभाविक है कि इस दौरे को लेकर उत्सुकता बहुत है और इस कारण इसके बारे में चर्चा भी खूब हो रही है. साल में इस संगठन की दो बैठकें होती हैं. एक में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेते हैं और दूसरे में शासनाध्यक्ष. इनके प्रतिनिधि के तौर पर वरिष्ठ मंत्री भी आयोजनों में भाग लेते हैं. भारत में 2023 में ये बैठकें हुई थीं, जिनमें से एक में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आये थे. प्रमुखों की बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई थी. बीते सालों में, खासकर 2019 से, भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बहुत गिरावट आयी है. हालांकि जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि उनकी यह यात्रा शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए है, न कि द्विपक्षीय वार्ता के लिए.

इस यात्रा को लेकर दो तरह की बातें हो रही हैं. पाकिस्तान के रवैये और द्विपक्षीय मसलों के कारण भारत सार्क सम्मेलन में हिस्सेदारी को लेकर हिचकता रहा है, जो पाकिस्तान में होना प्रस्तावित है. इस कारण वह बैठक नहीं हो पा रही है. ऐसे में विदेश मंत्री का जाना महत्वपूर्ण हो जाता है. दूसरी बात यह है कि क्या इससे हम द्विपक्षीय संबंधों के मामले में कुछ अपेक्षा कर सकते हैं. क्या इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और अधिकारियों की कोई बातचीत होगी और क्या इससे भविष्य में वार्ता के लिए कोई रास्ता खुल सकता है? पाकिस्तान में एक नयी सरकार सत्ता में है और उसकी ओर से भी ऐसे संकेत दिये गये हैं कि वह भारत के साथ संबंध बेहतर करना चाहते हैं. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू नहीं हो पा रही थी, इसके लिए कोई सिरा नहीं मिल पा रहा था, शायद उसके लिए एक अवसर मिल सकेगा. जयशंकर ने ऐसा कोई संकेत तो नहीं दिया है, पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह जरूर कहा है कि वह वापस आकर बतायेंगे कि वे दोनों देशों के संबंधों को कैसे परिभाषित करते हैं. तो, हमें उम्मीद के साथ कुछ इंतजार करना चाहिए.

इस यात्रा को लेकर दो तरह की बातें हो रही हैं. पाकिस्तान के रवैये और द्विपक्षीय मसलों के कारण भारत सार्क सम्मेलन में हिस्सेदारी को लेकर हिचकता रहा है, जो पाकिस्तान में होना प्रस्तावित है. इस कारण वह बैठक नहीं हो पा रही है. ऐसे में विदेश मंत्री का जाना महत्वपूर्ण हो जाता है. दूसरी बात यह है कि क्या इससे हम द्विपक्षीय संबंधों के मामले में कुछ अपेक्षा कर सकते हैं. क्या इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और अधिकारियों की कोई बातचीत होगी और क्या इससे भविष्य में वार्ता के लिए कोई रास्ता खुल सकता है?

शंघाई सहयोग संगठन की इस बैठक का महत्व इस वजह से बहुत बढ़ जाता है कि अभी दुनिया में अनेक गंभीर भू-राजनीतिक संकट हैं और स्थितियां किस दिशा में जायेंगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है. इस संगठन में रूस और चीन जैसी शक्तियों के साथ भारत, पाकिस्तान और ईरान भी सदस्य हैं तथा मध्य एशियाई गणराज्य भी इसके हिस्से हैं. अभी ईरान और इस्राइल के बीच के संघर्ष को लेकर दुनिया चिंतित है. इस बैठक में इस पर अवश्य चर्चा होगी. रूस-यूक्रेन युद्ध तो एक गंभीर मसला है ही. तुर्की और बांग्लादेश जैसे देश इस संगठन के संवाद सहभागी हैं और अनेक देश इस समूह की सदस्यता भी लेना चाहते हैं. तो, पश्चिम एशिया को लेकर बातचीत अपेक्षित है. अफगानिस्तान भी समूह का सदस्य है, पर तालिबान को मान्यता न होने के कारण उसकी सदस्यता अभी निष्क्रिय है. कुछ दिन पहले रूस में दस देशों के एक समूह की अफगानिस्तान को लेकर बैठक हुई है, जिसमें तालिबान शासन के प्रतिनिधि भी थे. उक्त समूह में भारत भी शामिल है. विशेष रूप से चीन और रूस की ओर से ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि तालिबान के साथ आधिकारिक संपर्क बने और उसे मान्यता दी जाए या उस जैसी कोई व्यवस्था हो. इस पर भी बातचीत अपेक्षित है.

पश्चिम एशिया का संकट हो या रूस-यूक्रेन युद्ध, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों पर इन घटनाओं का असर पड़ रहा है. इसी माह रूस में ब्रिक्स समूह का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है. संगठन के अनेक सदस्य ब्रिक्स के सदस्य या पर्यवेक्षक हैं. इस आलोक में भी इस्लामाबाद की बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है. यह संगठन दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय समूह है. इसका मुख्य सरोकार सुरक्षा को लेकर है. वैश्विक व्यवस्था में जो बदलाव हो रहे हैं, उसमें गैर-पश्चिमी शक्तियों की बड़ी अहमियत हैं. इनमें तीन बड़ी ताकतें- चीन, रूस और भारत- इस संगठन के सदस्य हैं. पश्चिमी देशों के सुरक्षा संगठन नाटो की दृष्टि स्वाभाविक रूप से पश्चिम केंद्रित है. उस संदर्भ में यह संगठन प्रभावी भूमिका निभाने की स्थिति में है. आज हम इस समूह को वैसे प्रभावशाली रूप में भले न देखें, इसकी बड़ी वजह है कि सदस्यों के बीच उनके अपने अनेक मसले अनसुलझे हैं, पर भविष्य में इसकी भूमिका को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए. अनेक देश सदस्य या संवाद सहभागी के रूप में इससे जुड़ने के इच्छुक हैं, जिनमें गैर-पश्चिमी देश और क्षेत्रीय शक्तियां हैं. सम्मेलन पाकिस्तान में हो रहा है और सभी सदस्य भाग ले रहे हैं, यह पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए सकारात्मक है.

हाल के दिनों में हमने देखा है कि भारत क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर अधिक सक्रिय हुआ है. इसका बहुत कुछ श्रेय, विशेषकर मालदीव के मामले में, विदेश मंत्री जयशंकर को जाता है. हाल में उन्होंने श्रीलंका में नये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बातचीत की है, जिनके चुनाव को लेकर भारत में कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं. उनकी कोलंबो यात्रा ने उन आशंकाओं पर विराम लगा दिया है. वे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के भी संपर्क में हैं. संयुक्त राष्ट्र की बैठक के मौके पर उन्होंने वहां के प्रतिनिधियों से बात भी की है. यूक्रेन और पश्चिम एशिया के मामले में भी वे सक्रिय रहे हैं. चीन के साथ भी उनका संपर्क और संवाद बना हुआ है. इन प्रयासों के उत्साहजनक नतीजे भी हम देख रहे हैं. इस्लामाबाद बैठक में दक्षिण एशिया पर भी चर्चा अपेक्षित है क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है तथा सभी सदस्य देशों के हित इससे जुड़े हुए हैं. पिछली बार जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत आये थे, तब उनकी कुछ टिप्पणियां भारत को नागवार गुजरी थीं और वे अनावश्यक टिप्पणियां भी थीं. आशा है कि पाकिस्तान की ओर से, या किसी अन्य सदस्य देश की ओर से, ऐसी बातें नहीं होंगी और इस सम्मेलन में सकारात्मक चर्चा के जरिये ठोस समझ बनाने की कोशिश होगी. निश्चित रूप से सबकी निगाहें सम्मेलन पर टिकी होंगी.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

कोलकाता से ट्राम की विदाई

कल्लोल चक्रवर्ती
टिप्पणीकार
kc5068@gmail.com

कोलकाता में ट्राम को परिवहन के साधन से हटा कर सिर्फ विरासत के रूप में सीमित कर देना अदूरदर्शिता का उदाहरण है. पिछले ही साल कोलकाता ने ट्राम सेवा के 150 साल पूरे होने का जश्न धूमधाम से मनाया था. एक समय शहर के चार सौ रूटों पर चार सौ ट्राम चलते थे. एक दशक पहले भी पैंतीस रूटों पर करीब पौने दो सौ ट्राम चलते थे. अंत तक दो रूटों पर पंद्रह ट्राम चलते थे. नतीजतन ट्राम डिपो में करोड़ों रुपये के करीब 250 ट्राम सड़ रहे थे. ट्राम की विदाई की पटकथा तो वाम मोर्चा सरकार के दौर में ही लिखी जा चुकी थी. इसके पीछे महत्वपूर्ण इलाकों में ट्राम डिपो की जगहों को बेच कर हजारों करोड़ रुपये कमाने की मंशा सक्रिय थी. जब तृणमूल सरकार 2011 में आयी, तब कोलकाता में 37 ट्राम रूट थे, जो 2017 में घट कर 17 और 2022 में महज दो रह गये.

कोलकाता देश का आखिरी शहर था, जहां ट्राम चल रहे थे. देश में ट्राम का इतिहास भी कोलकाता से शुरू हुआ था. कोलकाता की सड़कों पर 24 फरवरी, 1873 को पहली बार घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली ट्राम सेवा शुरू हुई थी, जो सियालदह से आर्मेनियन घाट स्ट्रीट तक 3.8 किलोमीटर तक थी. वर्ष 1874 में घोड़े से चलने वाली ट्राम सेवा मुंबई में भी शुरू हुई. वर्ष 1880 में लॉर्ड रिपन ने कोलकाता में इस सेवा को नये सिरे से शुरू किया. अब ट्राम स्टीम इंजन से चलने लगे, जिससे उनकी गति बढ़ी, पर प्रदूषण भी बढ़ा. चेन्नई में पहली बार बिजली चालित ट्राम सेवा 1895 में शुरू हुई. यह सेवा स्टीम इंजन वाली सेवा से बेहतर साबित हुई, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता था. धीरे-धीरे कानपुर, दिल्ली, मुंबई, नासिक और पटना में ऐसी सेवाएं शुरू हुईं. वर्ष 1886 में पटना में ट्राम परिवहन के लोकप्रिय साधन थे. साल 1902 में कोलकाता में भी बिजली चालित ट्राम सेवा शुरू हुई. पटना पहला शहर था, जिसने सवारी कम होने के कारण 1903 में ट्राम सेवा बंद कर दी. फिर 1933 में नासिक, 1953 में कानपुर, 1953 में मद्रास, 1963 में दिल्ली और 1964 में मुंबई में ट्राम सेवा बंद हो गयी.

लेकिन कोलकाता में ट्राम सेवा न सिर्फ जारी रही, बल्कि लोकप्रिय परिवहन माध्यम बने रहने के अलावा साहित्य और फिल्मों को भी इसने जाने-अनजाने प्रभावित किया. ट्राम दुर्घटना में मारे गये जीवनानंद दास ने अपनी कविता में ट्राम को आदिम सर्पिणी के रूप में देखा था. सत्यजित राय से लेकर मृणाल सेन और ऋत्विक घटक ने कोलकाता को चित्रित करने के लिए हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियल के बाद ट्राम को अपनी फिल्मों में दिखाया. अनेक हिंदी फिल्मों में कोलकाता के ट्राम हैं. वर्ष 1943 में दूसरे विश्वयुद्ध के समय अंग्रेज जब हावड़ा ब्रिज को खोलने का साहस नहीं कर पा रहे थे, तब रात के अंधेरे में ट्राम ही सवारियों को पुल पार कराने का जोखिम उठा रहे थे. वर्ष 1953 में किराये में एक पैसे की वृद्धि से कोलकाता में तूफान खड़ा हो गया और वाम राजनीति को पश्चिम बंगाल की राजनीति में पांव जमाने का मौका मिला. ट्राम की वजह से ही कोलकाता की सुदूर ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबॉर्न से जुगलबंदी बनी. दोनों देशों के बीच 1996 में 'ट्रामयात्रा' नामक एक सोसायटी बनी. इसके जरिये मेलबॉर्न की तरह कोलकाता के ट्रामों को सजाने की शुरुआत हुई और ट्राम लाइब्रेरी भी शुरू की गयी. करीब दो दशक पहले जीवनानंद दास की प्रसिद्ध कविता वनलता सेन के नाम पर 'वनलता' नाम से एक हेरिटेज ट्राम रूट भी तैयार किया गया.

लेकिन धीमी गति से चलने वाले ट्राम को जाम लगने का कारण बताया जा रहा था. यह भी कहा गया कि ट्राम के कारण कोलकाता की छवि सुस्त शहर की बन रही है और दूसरे शहरों की तुलना में कोलकाता की सड़कों पर स्पेस सबसे कम है. आर्थिक अभाव, खराब रख-रखाव, कम सवारियां, फ्लाईओवर निर्माण, कोलकाता मेट्रो के विस्तार, ट्राम की सुस्त रफ्तार और 'ट्राम को ज्यादा जगह चाहिए' की धारणा ने भी परिवहन के साधन के रूप में इसे बेपटरी कर दिया, पर विशेषज्ञ बताते हैं कि कोलकाता की सड़कों पर जाम लगने का कारण ट्राम नहीं हैं, क्योंकि ट्राम पटरी पर से गुजरते हैं. जाम का असल कारण बेतरतीब हॉकर्स, यत्र-तत्र पार्किंग और ऑटो, बस और निजी वाहनों की अनियंत्रित भीड़ है. दुनिया के लगभग चार सौ शहरों में आज ट्राम चल रहे हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि ट्राम एक साथ जितनी सवारियां ले जा सकता है, ट्रेन और मेट्रो छोड़ कर और कोई इतनी सवारियों को एक साथ नहीं ढो सकता. वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में बिजली के वाहन बढ़ रहे हैं. यूरोप के जिन देशों ने बीती सदी के 40 और 50 के दशकों में ट्राम को चलन से बाहर कर दिया था, उन्होंने 70 के दशक में तेल संकट के मद्देनजर ट्राम को फिर से महत्व दिया, पर कोलकाता में इसका उल्टा हुआ. तुर्की के नाटककार महमत मुरान इलादान का कहना है कि जिस शहर में ट्राम नहीं हैं, वह शहर कम शिक्षित, कम काव्यात्मक लगता है. पता नहीं, खुद को देश की सांस्कृतिक राजधानी कहने वाले कोलकाता ने इस टिप्पणी की अनदेखी कैसे कर दी!

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

विशेषज्ञ बताते हैं कि कोलकाता की सड़कों पर जाम लगने का कारण ट्राम नहीं हैं, क्योंकि ट्राम पटरी पर से गुजरते हैं. जाम का असल कारण बेतरतीब हॉकर्स, यत्र-तत्र पार्किंग और ऑटो, बस और निजी वाहनों की अनियंत्रित भीड़ है.

https://t.me/AllNewsPaperPaid

देश दुनिया

मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष और यूरोप की भूमिका

मध्य-पूर्व में हिंसा भड़क रही है और इस्राइल पर ईरान के हालिया मिसाइल हमले के बाद चौतरफा युद्ध की संभावना दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. फिर भी यूरोप का मुख्य राजनीतिक समुदाय कार्रवाई करता नहीं दिख रहा है. जबकि जून के यूरोपीय संसद चुनावों के बाद ब्रसेल्स में एक नया पांच वर्ष का चक्र शुरू हो चुका है. उर्सुला वॉन डेर लेयेन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए वापस आ गयी हैं. हालांकि फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और अब ऑस्ट्रिया में राष्ट्रवादी-लोकलुभावनवाद की नयी लहर ने यूरोपीय परिषद के भीतर दरार पैदा कर दी है, जहां यूरोपीय संघ की सरकारें गुट के लिए निर्णय लेती हैं. नये और मजबूत धुर दक्षिणपंथी समूह यूरोपीय संसद में अपनी शक्ति दिखा रहे हैं. कई लोगों को डर था कि यूरोपीय चुनावों से आंतरिक अराजकता और असमर्थता का एक लंबा दौर शुरू हो जायेगा. परंतु यूरोपीय समर्थक केंद्र बरकरार रहा. यूरोपीय संघ की सरकारें ब्रसेल्स में शीर्ष नौकरियों में नयी नियुक्तियों पर तेजी से सहमत हुईं. जटिल परिस्थितियों को देखते हुए अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है. कह सकते हैं कि कम से कम यूरोपीय संघ के पास एक योजना है जो उसे आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होने, अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी का लाभ उठाने, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने और रूस के खतरे से निपटने में सक्षम बनाती है. हालांकि, जब बात वैश्विक दक्षिण की आती है, तो यूरोप पूरी तरह भ्रमित लगता है, जिसके लिए इस दुनिया के अधिकांश हिस्से अवांछित प्रवासियों के स्रोत के अलावा और कुछ नहीं हैं, जिससे बचने की जरूरत है. पर यह हमेशा से ऐसा नहीं था. केवल एक दशक पहले, यूरोपीय संघ ने ईरान परमाणु समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी. परंतु आज यह मध्य-पूर्व में एक क्षेत्रीय युद्ध को रोकने के प्रयासों से दूर है.

theguardian

-नताली तोस्सी

बोधि वृक्ष

परमात्मा का आसन

साधक जीवन में सेवा अनिवार्य है. सेवा की भावना नहीं है और दरवाजा बंद करके अगर बीस घंटा भी साधना करें, तो उससे तरक्की नही होगी. क्योंकि परमात्मा का आसन तुम्हारे हृदय में भी है और बाहर भी. तुम भीतर वाले आसन को उज्ज्वल बनाना चाहते हो, वहां दीपक जलाते हो और बाहर वाले आसन को अंधकार में रख दोगे, इससे काम नहीं चलेगा. दीया भीतर भी जलाना है और बाहर भी जलाना है. मनुष्य समाजबद्ध जीव है. सामाजिक जीव है, समाज की उपेक्षा कर, समाज की अवहेलना करना धर्म नहीं है. तो, सेवा नहीं करने से तरक्की नहीं हो सकती है. महान कौन है, महत कौन है? इस संबंध में कहा गया है कि 'परोपकारत महत' अर्थात जो परोपकार करते हैं उन्हीं को 'महत' कहते हैं. जो काफी लिखे-पढ़े हैं, काफी धनराशि इकट्ठे किये हैं, उनके पूर्व पुरुष का काफी सम्मान है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, तो भी वे महत नहीं हैं, क्योंकि 'परोपकरात महत'. परोपकार जो करते हैं वही महत हैं. परोपकार के लिये अधिक धनराशि की भी आवश्यकता नहीं है. तुम्हारे पास जो संपद है, उस मौजूदा संपद से तुम परोपकार करो. शरीर मजबूत है, तो शरीर से करो, पैसा है तो पैसे से करो, बुद्धि है तो बुद्धि से करो, कुवत है तो कुवत से करो, कुछ नहीं है तो सद्भावना से करो. परोपकार से ही मनुष्य महत बनते हैं और जहां परोपकार नहीं है वहीं क्षुद्र बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं. हमारे यहां एक अभिशाप आ गया है. वह अभिशाप क्या है? मनुष्य-मनुष्य को, भाई-भाई को जातीयता के द्वारा विच्छिन्न कर दिया और वे भूल गये कि वह अपने भाई हैं. दो भाई की दो जाति नहीं हो सकती है, यह सामान्य बुद्धि की बात है. यह साधारण बुद्धि से मनुष्य समझ लेंगे कि एक बाप है, दो बेटे हैं- राम और श्याम, इन दो भाईयों की अलग-अलग जाति नहीं हो सकती है. जो बाप को मानते हैं, परमपिता को मानते हैं, वे जात-पात नहीं मानेंगे. जो परमपिता को मानते हैं, जो धार्मिक हैं, उनके पास जात-पात नहीं हैं. परोपकार से ही मनुष्य महत बनते हैं, किंतु इस 'परोपकारात महत' में भी तीन स्तर हैं- उत्तम, मध्यम और अधम.

-श्री श्री आनंदमूर्ति

प्रबंध सूत्र

इंसानी नेटवर्क जरूरी है

तकनीक का विकट शोर है. एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक जिंदगी कट रही है, पर जिंदगी सिर्फ यह नहीं है. देर रात उस फ्लैट के परिवार के एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया, किसी परिजन को कार चलाना नहीं आता था. कई पड़ोसी कार चलाना जानते थे, पर पड़ोसियों को उस परिवार का कोई बंदा नहीं जानता था. जरूरत ही नहीं पड़ती थी. पड़ोसियों के यहां जाने की जरूरत अब बची नहीं है, कई जगह. पड़ोस में कौन है, बड़े शहरों में लोग नहीं जानते. तकनीक ने कोई भी जरूरत खत्म कर दी है. कुछ वक्त पहले तक यूं हो जाता था कि घर की घंटी बजती थी और सामने कोई पड़ोसी होता था कि घर में कोई चीज खत्म हो गयी है, दे दीजिए. अब तो दस मिनट में हर चीज सप्लाई हो जाती है, तो पड़ोसी से कुछ मांगने की जरूरत खत्म. पर, देर रात जब हार्ट अटैक आया, तो पड़ोसी याद आये. बाहर से एंबुलेंस बुलाते, तो देर हो सकती थी. अभी ऐसी कोई सेवा नहीं है, जो दस मिनट में डॉक्टर की सप्लाई कर दे. तो ऐसे ड्राइवर की जरूरत थी, जो करीबी अस्पताल पहुंचा दे.

आलोक पुराणिक
स्तंभकार
puranika@gmail.com

पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया गया, सामने ऐसी सूरतें, जिनसे कोई दुआ-सलाम तक नहीं. उनसे देर रात मदद मांगने जाना शर्म की वजह थी, पर जरूरत शर्म पर भारी पड़ जाती है. पड़ोसी भले थे, फौरन ले गये अस्पताल. उस दिन यह सबक दोबारा रेखांकित हुआ कि लोगों की जरूरत पड़ती है. इनके बिना काम नहीं चलता. हर मसला तकनीक नहीं निपटा सकती. इंसानों से रिश्ते जरूरी हैं. खास कर ऐसे दौर में जब रिश्तों का हिसाब-किताब बदल गया है. महानगरों के लोगों के परिजन देश-विदेश में बसे हैं, वे खबर सुन कर आएं, तो भी घंटों लग जायेंगे. ऐसी सूरत में पड़ोसी, उसी शहर के दोस्त वगैरह ही काम आ सकते हैं. दोस्त महानगर में दूसरे कोने में हुए, तो उन्हें भी पहुंचने में घंटों लग सकते हैं. बेहतर से बेहतर तकनीक इंसानों का विकल्प नहीं बन सकती. हम सबकी जिंदगी में एक इंसानी नेटवर्क होना ही चाहिए.

गौर से देखिए, करियर में आगे जाने में भी वही इंसानी नेटवर्क, साथ के छात्र मदद करते हैं, जो बरसों से हमें जानते हैं. वर्क के साथ नेटवर्क भी जरूरी है करियर को आगे ले जाने के लिए. यह बात लगातार भूलते जा रहे हैं कई लोग. महानगरों में तो यह सूरत बहुत ही तेज गति से दिखाई दे रही है. वक्त है सोचने का, गंभीरता से सोचने का, खास तौर पर महानगर वालों के लिए कि अगर हम इस क्षण ऊपर अनंत लोक की यात्रा पर निकल जाएं, तो उठाने वाले कितने आयेंगे. मुश्किल सवाल है. उठाने के लिए इंसान ही चाहिए. तो वर्क में चाहे जितना बिजी हों, इंसानी नेटवर्क बनाने में ध्यान, समय और ऊर्जा जरूर लगाइए.

आपके पत्र

प्रदूषित भूजल से गहराता संकट

ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकतर जनसंख्या भूजल से अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करती है. परंतु भूजल के विषैले होने से संपूर्ण जीवों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है. यह भी सच है कि देश की अनेक बीमारियों का कारण दूषित जल है. ऐसे में हमें भूजल को विषैला होने से बचाने का हरसंभव प्रयास करना चाहिए. इसके लिए रसायनिक खाद और पॉलीथिन के बढ़ते इस्तेमाल से दूरी बनानी होगी. रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद और पॉलीथिन की जगह जैविक पदार्थों से बने बर्तन के उपयोग को बढ़ावा देना होगा.

शेखर सहाय, भागलपुर

दुनिया में बढ़ा भारत का महत्व

जी-7 अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, इटली और जर्मनी जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है. इस संगठन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाना देश के लिए गर्व की बात है. इस मंच पर अन्य बातों के अलावा मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चर्चा होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए दोनों देशों से बात कर चुके हैं. हमारी बढ़ती शक्ति का ही परिणाम है कि जी-7 में हमें आमंत्रित किया गया है. इससे दुनिया में हमारे देश का महत्व बढ़ा है.

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें :** 0651-2544006 ■ **मेल करें :** eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

प्रभात खबर
Sunday, October 6, 2024
Ranchi-City
https://epaper.prabhatkhabar.com/clip/67019b242ef8b42ab472b159

कभी-कभी कुछ कहकर लोग अपनी एक प्रभावशाली छाप बना देते हैं। आप चुप रहकर भी अपनी प्रभावशाली छाप छोड़ सकते हैं।

– दलाई लामा, सुप्रसिद्ध धर्मगुरु

खुशी की गाइड

खुद से बातचीत को सकारात्मक बनाएं

मायो क्लिनिक, अमेरिका

सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं होता कि आप जीवन की तकलीफदेह स्थितियों को अनदेखा कर दें। सकारात्मक सोच का मतलब यह होता है कि आप अप्रिय स्थितियों को भी किस तरह से अधिक सकारात्मक और उत्पादक तरीके से देखते हैं। जब आप सोचते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, बुरा नहीं। और इसकी शुरुआत अक्सर सेल्फ-टॉक से होती है।

- सेल्फ-टॉक या खुद से बातचीत का मतलब है दिमाग में चलने वाले विचार। ये ऑटोमैटिक-मोड में चलते हैं लेकिन हम इन्हें एक आदत की तरह विकसित कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में चलने वाले ज्यादातर विचार नकारात्मक हैं तो इसका असर जीवन के प्रति आपके नजरिए में दिखेगा।
- शोध बताते हैं कि हमारे दिमाग में चलने वाली सोच का हमारी सेहत पर भी गहरा असर पड़ता है। अगर हमारी खुद से बातचीत सकारात्मक है तो इससे हमारी जीवन-प्रत्याशा बढ़ती है, अवसाद घटता है, इम्यूनिटी सुधरती है, दिल की सेहत दुरुस्त रहती है, कैंसर तक का जोखिम इससे कम होता है। हम कठिनाइयों में चीजों का बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाते हैं।
- खुद से बातचीत को सकारात्मक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है बेहतर फिल्टरिंग। हम चीजों के नकारात्मक पहलुओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं और सकारात्मक पहलुओं को फिल्टर कर देते हैं। इसे बदलें। खुद को दोषी ठहराने की आदत से बचें। पूर्णता की उम्मीद ना रखें। और ध्रुवीकृत तरीके से सोचने की आदत ना विकसित करें।

सकारात्मक-संकल्प

हफ्ते में एक दिन 'यस डे'

प्राथमिकता के आधार पर हम किसी चीज के लिए हां या ना करते हैं। पर हफ्ते या महीने में एक दिन इसे भूल जाएं और उस दिन बच्चे, घरवाले, सहकर्मी या अनजान लोग भी कुछ मांगें तो हां कहें। कोशिश करें कि ये हां रुपयों-पैसों या वस्तुओं की मदद से जुड़ी ना हो। नेक सलाह, आपके वक्त की मांग आदि के लिए 'यस' कहें। चाहें तो 'यस' वाली चुनौती एक हफ्ते के लिए भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि इस हफ्ते उन तमाम चीजों के लिए हां कहें, जो अभी तक समय के अभाव या अपनी अरुचि के कारण मना करते आ रहे थे। जैसे बच्चों के साथ खेलना या किसी प्रोजेक्ट में मदद करना या लंबित पड़ा कोई काम।

मनोविशेषज्ञों के अनुसार हां कहने की इस आदत से आपके व्यवहार में भी सकारात्मकता आएगी।

नकारात्मकता से बचने का बीज मंत्र जान लें

जीवन-सूत्र

स्वामी ज्ञानवत्सल
प्रेरक वक्ता और विचारक

लोगों को लत होती है अपनी नकारात्मकता को उड़ेलने की। ऐसी स्थिति से निपटने-उबरने के लिए हमें समझ का बख्तर चाक-चौबंद रखना चाहिए।

बात 1998 की है। टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार बाजार में उतारी। नाम- इंडिका। प्रयास विफल रहा, भारी नुकसान भी हुआ। रतन टाटा अपने इस संयंत्र को बेचने के उद्देश्य से फोर्ड कंपनी में गए। वहां के व्यवस्थापकों ने उन्हें सुनाया कि टाटा को पैसेंजर कार के उत्पादन का सपना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वह उसके लायक नहीं हैं। रतन टाटा डील को कोई अंतिम रूप दिए बिना ही कक्ष से बाहर निकल गए। फोर्ड अधिकारियों ने टाटा को नालायक कहा था। लेकिन इन नकारात्मक शब्दों का रत्ती भर भी असर टाटा ने स्वयं पर नहीं पड़ने दिया। मुंबई लौट कर वे समूह के पैसेंजर व्हीकल डिपार्टमेंट का हिस्सा बने। इसी के साथ ही स्वदेशी भारतीय पैसेंजर कार के महत्वाकांक्षी सपने की नींव पड़ी। उन्होंने कुछ ही वर्ष में पैसेंजर व्हीकल डिपार्टमेंट को मानो खाई की गहराई से उबारकर सफलता के शीर्ष पर पहुंचा दिया। और हां, उस अपमानजनक मीटिंग के नौ साल बाद जब फोर्ड कंपनी वैश्विक मंदी के चलते दिवालिएपन की कगार पर थी तो टाटा ने फोर्ड की 'जगुआर' और 'लैंड रोवर' का अधिग्रहण (2.3 अरब डॉलर में) कर लिया। तब फोर्ड को 'टाटा' के चमत्कार का एहसास ही नहीं हुआ, बल्कि जीवंत उदाहरण देखने को मिला। लेकिन टाटा यदि नकारात्मक शब्दों को लेकर हताश-निराश हो गए होते तो क्या होता?

खैर, उल्टा-सीधा बोलना संसार का चलन है। संसार के इन्हीं बोल को तुला बनाकर खुद को तौलने लगें तो सफलता मिलने से रही। सचिन तेंदुलकर का भी ऐसा बोलने वालों से सामना हुआ था कि अभी तो तुम बच्चे हो। लंबाई कम है। क्रिकेट में कुछ करने से रहे। इन बोलों को सचिन ने कभी खुद की तकदीर पर सवार नहीं होने दिया।

प्रमुख स्वामी महाराज पर एक बार किसी ने निराधार टिप्पणी की, जिसके बारे में जानने के बाद भी वे स्थिर रहे। स्वयं को अपने कामकाज में तल्लीन कर लिया। जिज्ञासुओं ने जानना चाहा कि ऐसी आधारहीन टिप्पणियों से गुस्सा नहीं आया? प्रमुख स्वामी महाराज का कहना था कि लोगों का तो स्वभाव ही है बोलना। हमें ही यह देखना-समझना है कि कही गई बात सच है या गलत है। सच हो तो खुद में सुधार करें। गलत हो तो समझ लें कि बोलने वाला अज्ञानी है। प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें सदबुद्धि दें। दूसरे के अज्ञान को लेकर खुद को दुःखी थोड़े ही करना होता है! सरल शब्दों में कितनी गहरी समझ।

इस बात का सदैव स्मरण रखें कि हमारा मूल्य हमारे हुनर या पद-प्रतिष्ठा से नहीं, अपितु स्वयं के शुद्ध जीवन और चरित्र से होता है।

अभी यूट्यूब-फेसबुक-इंस्टाग्राम के दौर में हर किसी को प्रसिद्ध होने की लालसा जाग जाती है। इसके वशीभूत होकर वे भांति-भांति की पोस्ट-वीडियो आदि सामग्री शेयर करने लगते हैं। उनकी अपेक्षा होती है कि लोग पसंद करेंगे और प्रतिक्रिया देंगे। सर्वप्रथम तो यह अपेक्षा ही गलत है। लोगों की पसंद और टिप्पणी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ के लिए सीख यही है कि लोगों की बातों से खुद के मोल को मत आंकिए। स्मरण रखें कि अपना मूल्य हमारे हुनर-पद-प्रतिष्ठा से नहीं, अपितु स्वयं के शुद्ध जीवन और चरित्र से है। अतः चरित्र पर ध्यान केंद्रित कर नकारात्मक लोगों के प्रति यही दृष्टिकोण रखें कि लोग तो कहते ही हैं।

संघर्ष की कहानियां

जे के रॉलिंग, विश्व विख्यात लेखिका

कभी डिप्रेशन झेला, हैरी पॉटर की 60 करोड़ किताबें बिकीं...तब सबसे महंगी लेखिका बनीं

इंग्लैंड के ब्रिस्टल में एक छोटे-से गांव में जन्मी जे. के. रॉलिंग को बचपन से ही पता था कि वो एक लेखक बनना चाहती हैं। छह साल की उम्र में पहली कहानी, ग्यारह साल की उम्र में पहला उपन्यास लिखा। फिर हैरी पॉटर जैसी विख्यात उपन्यास श्रृंखला लिखकर दुनिया की सबसे महंगी (हाइएस्ट पेड राइटर) लेखिका भी बनीं।

59 साल की जोआन कैथलीन (जे. के. रॉलिंग) की वर्तमान जिंदगी को पढ़ें, तो उनके खाते में दो दर्जन किताबें हैं और लगभग इतने ही प्रतिष्ठित पुरस्कार व सम्मान हैं। पर अतीत के पन्ने पलटें, तो उनमें ढेर सारा संघर्ष, जिंदगी की जद्दोजहद, आत्मसम्मान की लड़ाई और इस सबके बावजूद अपने सपनों को जिंदा रहने की दृढ़ इच्छाशक्ति शामिल है। रॉलिंग इंग्लैंड-वेल्स की सीमा पर बने गांव येट में जन्मीं। उन्होंने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया। पर मां की बीमारी और फिर उनकी मौत ने रॉलिंग को तोड़कर रख दिया। इस बीच उनकी शादी भी लंबी नहीं चल सकी। नौकरी नहीं थी। रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। सिंगल मदर रॉलिंग डिप्रेशन में भी चली गईं। यहां तक कि आत्महत्या की भी कोशिश की। लेकिन किसी तरह उन्होंने लिखना जारी रखा। और यहीं से उन्हें अपने मुश्किल हालात से बाहर निकलने की ताकत मिली।

संघर्ष: इंग्लैंड के 12 प्रकाशकों ने साफ मना कर दिया था

मैनचेस्टर से लंदन जाते हुए ट्रेन में बैठे-बैठे उन्हें हैरी पॉटर और हॉवर्ट्स का आइडिया आया। हैरी पॉटर श्रृंखला के पहले उपन्यास की पांडुलिपि जब प्रकाशकों को भेजी, तो 12 बड़े प्रकाशकों ने इसे छापने से इंकार कर दिया। बाद में ब्लूम्सबरी सिर्फ एक हजार प्रतियां छापने के लिए राजी हुई। प्रकाशक ने भी जोआन कैथलीन का नाम किताब पर जे. के. लिखा, ताकि लोगों को यह न लगे कि वह महिला हैं। उन्हें लग रहा था कि बाल साहित्य में किसी की रुचि नहीं होगी।

सफलता: बेस्ट सेलिंग नॉवेल की सूची में शुमार हैरी पॉटर

रॉलिंग का पहला उपन्यास 1997 में आया। प्रकाशन के बाद बाकी दुनिया का ध्यान गया। साल 1999 में वॉर्नर ब्रदर्स ने एक मिलियन डॉलर में हैरी पॉटर के शुरुआती दो नॉवेल के अधिकार ले लिए। फोर्ब्स की लिस्ट में वह दुनिया की सबसे महंगी (हाइएस्ट पेड राइटर 2008,2017,2019) लेखिका भी रहीं। हैरी पॉटर उपन्यास की अब तक 60 करोड़ से ज्यादा कॉपी बिक चुकी हैं। यह इतिहास विषय का बेस्ट सेलिंग नॉवेल भी है।

असाधारण रिकॉर्ड

इलिउड किपचोगे, मैराथन धावक

दो घंटे से कम में मैराथन दौड़कर चौंकाया

भारत में मेरा एक दोस्त है, उसने मजाक-मजाक में कहा कि 'कोई भी दो घंटे में मैराथन पूरी नहीं कर सकता। और मेरे जीते-जी ऐसा रिकॉर्ड बनना नामुमकिन है।' कुछ सालों बाद मैं उससे मिला और बताया कि तुम्हारे जीते जी ही ये रिकॉर्ड मैंने बना दिया है।

दो घंटे में मैराथन दौड़ना दुनिया के लिए एक समय सपना-सा था। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट को भी यकीन नहीं था कि कोई इंसान ऐसा कर पाएगा। लेकिन 12 अक्टूबर 2019 को केन्या के इलिउड किपचोगे ने 1:59:40.2 समय में मैराथन पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। वैज्ञानिक ने अध्ययन किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किपचोगे ने मैराथन के दौरान अपनी शारीरिक के साथ मानसिक क्षमताओं को सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल किया। इसलिए वह ये मुकाम हासिल कर पाए।

सीख : किपचोगे ने साबित कर दिया कि दुनिया के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वे कहते हैं दौड़ना शारीरिक से ज्यादा मानसिक चुनौती या प्रतिस्पर्धा है।

सबक का पाठ- किस पर भरोसा करें?

राजा कृष्णदेवराय को घोड़ों से बहुत प्यार था और उनके अस्तबल में कुछ बेहतरीन नस्ल के घोड़े थे। एक बार अरब से एक व्यापारी उनके दरबार में आया और उनसे कहा कि उसके पास बिक्री के लिए अरब के बढ़िया घोड़े हैं। राजा ने उसे अग्रिम राशि के रूप में सोने के 5000 सिक्के दे दिए। व्यापारी ने वादा किया कि वह दो दिन में घोड़ों के साथ वापस आएगा। दो हफ्ते बीत गए पर व्यापारी नहीं आया। एक दिन राजा बगीचे में टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा तेनाली रामन एक कागज पर विजयनगर साम्राज्य के सबसे बड़े मूर्खों के नाम लिख रहा है और सबसे ऊपर राजा का नाम है। राजा क्रोधित हुए और इसका कारण पूछा। तेनाली ने कहा, जो व्यक्ति किसी अजनबी को सोने के 5000 सिक्के दे देता है, वह मूर्ख ही कहलाएगा। राजा ने कहा, और अगर व्यापारी घोड़े लेकर आ जाए तो? तेनाली ने फट से कहा, तब मैं सूची से आपका नाम हटाकर उसका नाम लिख दूंगा!

मोरल ऑफ द स्टोरी : अजनबियों पर आंख मूंदकर कभी विश्वास मत करो।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक भास्कर अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर सोमवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

बिजनेस

अमेरिका में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ी

जैक स्विंग, नील बाउडेटे

अमेरिका में कुछ समय पहले गिरावट के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। टेस्ला ने बुधवार को बताया कि साल की तीसरी तिमाही में उसकी इलेक्ट्रिक कारों और ट्रकों की बिक्री 6.4 प्रतिशत बढ़ी है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कमी के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने के संकेत मिले हैं। जनरल मोटर्स ने बताया कि तीसरी तिमाही में उसके इलेक्ट्रिक मॉडलों की बिक्री में एक साल पहले के मुकाबले 60 प्रतिशत उछाल आया है। फोर्ड ने तीसरी तिमाही में 12 फीसदी बढ़ोतरी की जानकारी दी है। उधर, यूरोप में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में गिरावट आई है। जर्मनी द्वारा खरीदारों के लिए सब्सिडी बंद करने का इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री पर असर पड़ा है।

© The New York Times

इस हफ्ते चर्चा में...

13 लाख करोड़ पहुंचा ओपनएआई का मूल्य

55460 करोड़ रुपए जुटाए हैं ओपन एआई कंपनी ने अपने शेयरों की ताजा बिक्री से। घाटे में चल रही कंपनी का मूल्य अब 13.19 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

45% टैरिफ लगाया है यूरोपियन यूनियन ने चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों पर। दोनों के बीच पिछले साल 67 लाख करोड़ रुपए की वस्तुओं का कारोबार हुआ था।

34000 साल पुराने दीमक के टीलों का पता लगाया है, अभी हाल में वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास। टीलों के नीचे 11 फुट अंदर तक सुरंगें और चैम्बर फैले हुए हैं।

नई पहल • फ्रांस के प्रभाव वाले 88 देशों की लेबनान में युद्धविराम की अपील

फ्रांस ने सभी देशों से इजराइल की हथियार सप्लाई रोकने को कहा; अब लेबनान की मदद भी करेंगे राष्ट्रपति मैक्रों

ताल्या मिंसबर्ग

लेबनान और गाजा में इजराइल की फौजी कार्रवाई से कई देशों में चिंता बढ़ गई है। इजराइल पर लड़ाई रोकने का दबाव है। युद्धविराम के लिए नए सिरे से कोशिशें हो रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबनान में फौरन युद्ध रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोक देनी चाहिए। मैक्रों ने फ्रेंच रेडियो शो में कहा, समस्या के राजनीतिक समाधान पर जोर देना होगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस की अपील को खारिज कर दिया है।

मैक्रों ने कहा, फ्रांस इस समय इजराइल को किसी किस्म के हथियार नहीं दे रहा है। वैसे, हमारी बात पर गौर नहीं किया जा रहा है। यह इजराइल की सुरक्षा की दृष्टि से भी एक भूल है। शनिवार को फ्रेंच बोलने वाले देशों की वार्ता में मैक्रों ने घोषणा की कि 88 फ्रेंच भाषी देशों ने लेबनान में युद्धविराम की अपील की है। मैक्रों ने इस बीच लेबनान की सहायता करने पर भी जोर दिया है। पिछले कुछ माह से अमेरिका, मिस्र, कतर और अन्य देशों ने गाजा में युद्ध रोकने के प्रयास किए हैं लेकिन वे इजराइल और हमास को सहमत नहीं करा सके हैं।

शनिवार को दक्षिणी लेबनान में इजराइल की बमबारी के बाद उठता धुएं का गुबार।

शनिवार को बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में गाजा में युद्ध के लिए इजराइल को हथियार बेचने से रोकने की अपील पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने फ्रांस और पश्चिमी देशों की ओर इशारा करते हुए कहा उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनके समर्थन के बिना भी इजराइल जीतेगा। नेतन्याहू की टिप्पणी के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी एक बयान में इजराइल को फ्रांस का दोस्त बताया गया है। यह भी कहा गया कि गाजा और लेबनान में फौरन युद्धविराम जरूरी है। हम इजराइल और मिडिल ईस्ट में हर किसी की सुरक्षा चाहते हैं।

तेल ठिकानों पर हमले को अमेरिकी मंजूरी संभव

विश्लेषकों का अनुमान है इजराइल ईरान के तेल प्रोडक्शन साइट, सैनिक अड्डों और परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले की तैयारियां कर रहा है। अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों पर इजराइली हमले को हरी झंडी दे सकता है। गुरूवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या वे ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइली हमले का समर्थन करेंगे। बाइडेन ने कहा, इस संभावना पर चर्चा हो रही है।

परमाणु संयंत्रों पर हमले के लिए अमेरिकी मदद जरूरी

इजराइल का तर्क है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर इजराइल के प्रमुख अधिकारियों का यह भी कहना है, उनकी फिलहाल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले की योजना नहीं है। जमीन की बहुत गहराई में स्थित कुछ ठिकानों को अमेरिका की मदद के बिना निशाना नहीं बनाया जा सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति का मत यहां अलग नजर आता है। जो बाइडेन ने कहा है कि वे परमाणु ठिकानों पर हमले का समर्थन नहीं करेंगे।

ईरान को परमाणु बम बनाने में एक साल लगेंगे

विशेषज्ञों का कहना है, अगर ईरान बम के लिए जरूरी यूरेनियम बनाने के प्रयास तेज कर देता है तब भी उसे परमाणु योजना पूरा करने में कई माह लगेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहां तक कि ईरान को एक साल का समय भी लग सकता है। इजराइल हमले के लिए दर्जनों लड़ाकू विमानों और तीन से पांच हजार किलोमीटर दूर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। वह ईरान के मिसाइल प्रतिरोधी सिस्टम को पहले निशाना बनाएगा।

© The New York Times

राष्ट्रपति चुनाव

ट्रम्प के भद्दे बयानों से रिपब्लिकन महिला वोटरों में नाराजगी

एमिली बेजलॉन

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जेंडर का मुद्दा निर्णायक हो गया है। कई सर्वेक्षणों में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस ने महिलाओं के समर्थन के मामले में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प पर भारी बढ़त हासिल की है। दूसरी ओर ट्रम्प को पुरुषों का ज्यादा समर्थन मिला है। हालांकि, कमला हैरिस पर ट्रम्प की भद्दी टिप्पणियों से रिपब्लिकन महिला वोटर भी ट्रम्प का साथ छोड़ सकती हैं। पूर्व रिपब्लिकन गर्वनर निकी हेली इस संबंध में ट्रम्प को आगाह कर चुकी हैं। उनका कहना है, ट्रम्प और वांस को महिलाओं के बारे में अपने बयानों में बदलाव करने की जरूरत है। हेली ने कहा जब आप डेमोक्रेट महिला को गूंगा कहेंगे तो रिपब्लिकन महिलाओं को भी खराब लगेगा।

ट्रम्प और उनके उपराष्ट्रपति प्रत्याशी वांस महिला वोटरों के बीच कमला हैरिस से 14 अंक पीछे हैं। हैरिस प्रचार में दावा नहीं करती हैं कि वे पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। उन्होंने अपने महिला होने को मुद्दा नहीं बनाया है। वहीं ट्रम्प और वांस ने चुनाव को जेंडर की तरफ मोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने प्रचार में हैरिस को इतना अपमानित किया है कि कई महिलाओं ने इस पर गौर किया होगा।

सितंबर में न्यूयॉर्क टाइम्स/ सिएना पोल में ट्रम्प के 41 प्रतिशत के मुकाबले हैरिस का 55 प्रतिशत महिला वोटरों ने समर्थन किया था। दूसरी ओर 52 प्रतिशत पुरुष वोटर ट्रम्प और 39 प्रतिशत हैरिस के साथ थे। कुछ सर्वेक्षणों में अश्वेत और लेटिनो वोटर ने ट्रम्प को ज्यादा समर्थन दिया है। युवा महिलाओं के बीच हैरिस और वाल्ज बहुत आगे हैं। उनकी बढ़त युवा पुरुषों के बीच ट्रम्प, वांस की बढ़त से अधिक है। महिलाओं की कीमत पर ट्रम्प पुरुषों के बीच अपना समर्थन बढ़ाने की रणनीति पर चल रहे हैं।

ट्रम्प का अश्वेत युवाओं पर दांव

पिछले चुनाव के समान मौजूदा चुनाव में निर्णायक राज्यों में महिला वोटरों का समूह बहुत अहम है। ये राज्य रिपब्लिकन समर्थक माने जाते हैं। इनमें कॉलेज शिक्षित और उपनगरों में रहने वाले स्वतंत्र वोटर भी हैं। ट्रम्प के चुनाव सलाहकारों सुसी वाइल्स और क्रिस लेसिविटा ने भरोसा जताया है कि उपनगरों की महिलाओं की तुलना में अश्वेत युवाओं पर ज्यादा ध्यान देने से फायदा है।

© The New York Times

ओपिनियन कॉलम • पेचीदा बीमारियों की पहचान और मरीजों का बेहतर इलाज कर रहे एआई के नए टूल

एआई टूल मरीजों से बेहतर संवाद कर रहे, कई मामलों में डॉक्टरों को भी पछाड़ा

जोनाथन रीसमैन
डॉक्टर और लेखक

जब मैं 2000 के दशक में मेडिकल छात्र था तब सोचता था कि भविष्य में मेरी जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमेशा सुरक्षित रहेगी। उस वक्त साफ हो गया था कि मेडिसिन के टेक्निकल पहलू में मशीनें मानवों को पीछे छोड़ देंगी। लेकिन, इतना तय था कि मानवीय पक्ष की वजह से मेरा जॉब सुरक्षित रहेगा। इस काम के लिए दूसरों के दर्द को समझना और डॉक्टर, मरीज के बीच स्पष्ट संवाद जरूरी है। कम से कम बिस्तर पर लेटे मरीज की देखभाल में डॉक्टर एआई से अच्छा होगा। लेकिन, जब चैटजीपीटी और अन्य बड़े लैंग्वेज मॉडल आए तो मैंने महसूस किया कि जॉब सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है।

लोगों को यह बात विचलित करेगी कि एआई टेक्नोलॉजी बिस्तर पर लेटे मरीज की देखभाल में इंसानों से अच्छी है। दरअसल, जीवन के अन्य क्षेत्रों के समान मेडिसिन का क्षेत्र भी तैयार योजना पर चलता है। मैंने मेडिकल कॉलेज के तीसरे वर्ष में मरीजों को खराब खबरें बताने के तरीकों की पढ़ाई शुरू की थी। पहले लगा कि किसी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में बताना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन, यह प्रक्रिया उम्मीद से ज्यादा यंत्रवत और टेक्निकल लगी।

पहले मुझे यह ठीक नहीं लगा कि सहानुभूति और करुणा को डांस स्टेप के समान तय किया जा सकता है। लेकिन, मुझे पहले से तय स्क्रिप्ट पर काम करना अधिक मानवीय लगा। मेडिसिन के टेक्निकल और मानवीय पक्ष अलग नहीं महसूस हुए। मैंने इमरजेंसी रूम डॉक्टर के रूप में मरीजों को से रटे-रटाए शब्दों में खराब खबरें बताई हैं। मरीजों और उनके परिवारों के लिए यह बातचीत जिंदगी बदलने वाली हो सकती थी लेकिन मेरे लिए तो यह काम का एक और दिन था। जब तक एआई हेल्थ केयर को पूरी तरह नहीं बदलता है डॉक्टरों को टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। एआई मेडिकल चार्ट में अच्छी तरह से नोट्स लिखने में मदद कर सकती है। लोग चिंतित हो सकते हैं कि जब मशीनें पूरी तरह हमारी नकल कर सकती हैं तो फिर मनुष्य होने का क्या अर्थ है। सच तो यह है कि पहले से लिखी स्क्रिप्ट और तौर-तरीके हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। बधाई, प्रार्थना, रोमांस या राजनीति सहित जीवन के हर पहलू में कुछ नियम-कायदे तय हैं। पहले से तय स्क्रिप्ट, व्यवहार, रिवाज या परंपराएं समाज को चलाती हैं।

चैटजीपीटी के जबाव डॉक्टरों से अच्छे

एआई के नए टूल मेडिसिन के टेक्निकल पहलू में मजबूत हैं। वे पेचीदा बीमारियों की पहचान कर लेते हैं। अक्सर अच्छा इलाज करते हैं। बिस्तर पर लेटे मरीज से बातचीत में भी माहिर हैं। वे मरीज को अच्छी केयर करने का यकीन दिलाने वाले लहजे में बोलते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि चैटजीपीटी ने मरीजों के सवाल विश्वसनीय तरीके से दिए हैं। वास्तविक डॉक्टरों द्वारा लिखे गए जवाबों से उनकी क्वालिटी बेहतर थी। जवाब एकदम स्पष्ट थे।

© The New York Times

भारत में पंथनिरपेक्षता

अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट

भारत में पंथनिरपेक्षता की स्थिति पर अमेरिकी आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसे भारत के विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। धार्मिक बहुलता की समृद्ध उपस्थिति वाले भारत राष्ट्र को लंबे समय से 'पंथनिरपेक्षता' व 'बहुलवाद' का गढ़ माना जाता रहा है। 'यूएस कमीशन आन इंटरनेशनल रिजीजस फ्रीडम'-यूएससीआईआरएफ ने हाल में भारत को 'खास चिन्ता वाला देश' घोषित किया है। इससे एक विवादास्पद बहस शुरू हो गई है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट की घोर निन्दा और इसे खारिज करते हुए यूएससीआईआरएफ को 'राजनीतिक एजेंडे वाला एक पूर्वाग्रही संगठन' बताया है। अपनी 2024 की रिपोर्ट में यूएससीआईआरएफ ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी खतरनाक प्रवृत्तियों की ओर संकेत किया है। आयोग ने धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कुछ समूहों द्वारा हत्याओं, पिटाई व भीड़ हिंसा के उदाहरण दिए हैं। उसने धार्मिक नेताओं की मनमानी गिरफ्तारियों तथा घरों व पूजास्थलों के विध्वंस को धार्मिक स्वतंत्रताओं का गंभीर उल्लंघन कहा है। उसका आरोप है कि भारत के विधिक ढांचे द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर निशाना लगा कर उनको मताधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन आरोपों का संबंध 'नागरिकता संशोधन कानून' तथा 'समान नागरिक संहिता' के क्रियान्वयन से है। यूएससीआईआरएफ का तर्क है कि इससे गैर-हिंदू समुदायों में भय और हाशियाकरण का माहौल बना है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को पूरी कठोरता से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रनधीर जायसवाल ने आयोग के विमर्श को 'जानबूझ कर' तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण बताया है जिसका उद्देश्य विश्व मंच पर भारत की छवि खराब करना है। मंत्रालय के बयान में जोर दिया गया है कि यूएससीआईआरएफ की रिपोर्टिंग अवैज्ञानिक तथा ऐसे एजेंडे द्वारा संचालित है जो भारत में लोकतंत्र का यथार्थ अभिव्यक्त करने में विफल रहा है।

सच यह है कि किसी बाहरी एजेंसी या किसी अन्य देश को हमें धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता पर भाषण देने का अधिकार नहीं है जिसका पालन भारत प्राचीन काल से करता आ रहा है। अमेरिका को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जहां अश्वेतों के प्रति पूर्वाग्रह की अनेक घटनायें सामने आती रहती हैं। इनमें पुलिस द्वारा अश्वेतों की हत्यायें तक शामिल हैं। जहां तक अमेरिकी रिपोर्ट का सवाल है, भारत ने 'भीड़ हिंसा' के खिलाफ कठोर कानून बना कर आरोपियों को फौरन सजा दिलाई है जिससे अब ऐसी घटनायें बंद हो गई हैं। ऐसी इक्का-दुक्का घटनाओं के पीछे धार्मिक आधार पर गंभीर उकसावे रहे हैं। रिपोर्ट में उल्लिखित चर्चों पर हमलों की घटनाओं की सरकार ने गंभीरता से जांच कराई थी और ये सभी मामले चर्च संपत्तियों की चोरी के थे। इनके पीछे कोई 'धार्मिक मंतव्य' नहीं था और कुछ मामलों में चर्च जाने वाले ही चोरियों में शामिल पाए गए थे। भारत के 'विधिक ढांचे' पर रिपोर्ट द्वारा उठाए सवाल भारतीय न्यायपालिका पर हमला हैं जिसकी निष्पक्षता और तटस्थता पूरी दुनिया में विख्यात है। नागरिकता संशोधन कानून तथा समान नागरिक संहिता कानून पूर्णत: विधि सम्मत तथा लोकतांत्रिक व पंथनिरपेक्ष आदर्शों के अनुरूप हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जा कर बने धर्मस्थलों को गिराया जा सकता है और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई अनुचित नहीं है। भारत में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी गरीबों को मिल रहा है और इसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

बांग्लादेश में पंथनिरपेक्षता को खतरा

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के पीछे सक्रिय कट्टरपंथियों से पंथनिरपेक्षता को खतरा पैदा हो गया है। लोकतंत्र व पंथनिरपेक्षता के लिए संघर्षशील शहरयार कबीर की विवादास्पद आरोपों पर गिरफ्तारी इसका उदाहरण है।

हिरण्यमय कार्लेकर
(लेखक, द पायनियर के सलाहकार संपादक हैं)

ढाका में 17 सितंबर, 2024 को अंतरराष्ट्रीय ख्याति वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता शहरयार कबीर की गिरफ्तारी तथा इससे जुड़ी अन्य घटनाओं की समीक्षा करना जरूरी है। इससे स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के पीछे वर्तमान समय में सक्रिय कट्टरपंथी शक्तियां देश को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। इस संबंध में शहरयार कबीर के व्यक्तित्व पर भी संक्षेप में गौर किया जाना चाहिए। वे लेखक, पत्रकार, फिल्म-निर्माता तथा मानवाधिकार, पंथनिरपेक्षता व लोकतंत्र के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात पैरोकार हैं। वे उन लोगों को दंड दिलाने के संघर्ष में अग्रणी रहे हैं जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानियों से गठजोड़ किया तथा वे मानवता के खिलाफ जघन्य अपराधों के दोषी रहे हैं जिनमें बड़े पैमाने पर हत्यायें व बलात्कार शामिल हैं।

1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानियों तथा उनसे गठजोड़ करने वालों ने बांग्लादेश की जनता पर निर्मम अत्याचार ढाए थे। शहरयार कबीर ने हत्यारों तथा 71 में मिलीभगत करने वालों का सफाया करने के लिए संघर्षशील 'एकत्तोरेर घातक दलाल निर्मूल कमेटी' के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका नेतृत्व जहांनारा इमाम कर रही थीं जिनके पति और एक बेटे की पाकिस्तानियों ने 1971 में निर्मम हत्या की थी। इसके बाद शहरयार कबीर इस संगठन के अध्यक्ष बने और अपनी गिरफ्तारी के समय वे इसकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे।

इसके साथ ही शहरयार कबीर की गिरफ्तारी की परिस्थितियों, उनके खिलाफ लगाए आरोपों तथा उन पर आरोप लगाने वालों के अंतरिम सरकार से संबंधों पर भी गौर किया जाना चाहिए। 'द ढाका ट्रिब्यून' में 17 सितंबर, 2024 को प्रकाशित 'ढाका में शहरयार कबीर की गिरफ्तारी' शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार 'हिफाजते इस्लाम'-हिफाजत के संयुक्त सचिव मुफ्ती हारून इजहार चौधरी ने 20 अगस्त, 2024 को 'इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल'-आईसीटी में शेख हसीन व अन्य 23 लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी और उन पर हिफाजत द्वारा 5 मई, 2013 को आयोजित रैली के संबंध में मानवता के खिलाफ अपराध तथा बड़े पैमाने पर हिंसा के आरोप लगाए थे। इनमें शहरयार कबीर भी शामिल थे। 'द डेली स्टार' में 18 सितंबर, 2024 को 'शहरयार कबीर 7 दिन की रिमांड में भेजे गए' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया था कि मोजम्मिल बाबू के साथ कबीर को अदालत के समक्ष पेश किया गया और पुलिस ने उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी। इस मामले का संबंध 'कोटा सुधार विरोध प्रदर्शन' के दौरान घरेलू सहायिका लिजा अख्तर की मौत से था।

रिपोर्ट में अदालत में मौजूद एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर को यह कहते हुए संदर्भित किया गया था कि ढाका के अतिरिक्त चीफ मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट मुहम्मद सनाउल्ला ने उनको सात दिन हिरासत में रखने का आदेश दिया था। 17 सितंबर, 2024 को 'शहरयार कबीर, नूरुल इस्लाम अरेस्टेड' शीर्षक से 'प्रोथम आलो इंग्लिश' में प्रकाशित रिपोर्ट में स्रोतों के हवाले से कहा गया था कि आरोपी कबीर पर ढाका के जेतराबारी व अन्य पुलिस थानों में हत्या के अनेक मामले दर्ज थे। इस लेखक को उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक एक आईसीटी के साथ ही उन पर हत्या के सात मामले दर्ज किए गए हैं। कबीर जैसे कद वाले व्यक्ति के खिलाफ हत्या के आरोप लगाना न केवल हास्यास्पद है, बल्कि इससे संकेत मिलता है कि ऐसे अनेक मामलों की योजना और समन्वय पर्दे के पीछे जारी प्रयासों का नतीजा हैं।

उल्लेखनीय है कि आईसीटी के खिलाफ मामले हिफाजते इस्लाम-हिफाजत के संयुक्त सचिव मुफ्ती हारून इजहार चौधरी द्वारा दर्ज कराए गए जिनमें कबीर समेत शेख हसीना व 23 अन्य पर 5 मई, 2013 को हिफाजत की एक रैली के संबंध में मानवता के खिलाफ अपराधों व बड़े पैमाने पर हत्याओं के आरोप लगाए गए थे। 19 अगस्त, 2024 को 'द ढाका ट्रिब्यून' में 'हिफाजत रैली इन शापला चत्तर: ओधिकार पब्लिशेस लिस्ट आफ किल्ड पीपुल' शीर्षक से प्रकाशित खबर में बताया गया था कि मानवाधिकार संगठन ओधिकार ने 19 अगस्त को उन लोगों की सूची जारी की जिनको अवामी लीग-नीत सरकार द्वारा ढाका के शापला चत्तर में 5-6 मई, 2013 में की गई कार्रवाई में मार डाला गया था।

मूल रूप से 2013 में प्रकाशित इस सूची के आधार पर अवामी लीग सरकार ने संगठन के खिलाफ कार्रवाई की थी। खबर के अनुसार, पहले की सरकार में उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ओधिकार ने अंतरिम सरकार से प्रार्थना की थी कि सर्वोच्च न्यायालय के एक जज की अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र जांच आयोग द्वारा 5 व 6 मई, 2013 को की गई न्यायेत्तर हत्याओं की निष्पक्ष जांच की जाए तथा अपराधियों को सजा दिलाई जाए। 'द ढाका ट्रिब्यून' की रिपोर्ट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या ओधिकार ने दोषियों के नाम बताए थे। ओधिकार के बयान के अगले दिन 20 अगस्त, 2024 को हिफाजत ने शिकायत दर्ज कराई थी। इससे सवाल उठते हैं कि मारे गए लोगों की संख्या कितनी थी? क्या रैली शांतिपूर्ण थी?

यह किस संदर्भ में आयोजित की गई थी तथा हिफाजत की क्या मांगें थीं? ओधिकार द्वारा पेश आंकड़ों के विपरीत 6 मई, 2024 को प्रसारित 'बीबीसी' रिपोर्ट में कहा गया था कि झड़प में कम से कम 27 लोग मारे गए थे तथा दर्जनों घायल हुए थे। यह भी कहा गया था कि मरने वालों में कम से कम दो पुलिसकर्मी थे।

रिपोर्ट के अनुसार, यह भी तथ्य है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने तथा हताहतों की संख्या न्यूनतम रखने के लिए 'स्टन ग्रेनेडों व रबर बुलेट्स का प्रयोग किया था।' यह रैली अत्यधिक हिंसक थी। रिपोर्ट में एक चश्मदीद को यह कहते बताया गया है कि प्रदर्शनकारी 'बहुत हिंसक थे, कुछ लोग पत्थर फेंक रहे थे जिससे स्थिति जल्द ही हिंसक हो गई थी और पुलिस के पास प्रतिक्रिया के सिवा कोई और रास्ता नहीं था।' चश्मदीद ने बीबीसी को बताया, 'दंगाइयों ने बाजारों को लूटा और किताबों की उन दूकानों में भी आग लगा दी जहां पवित्र कुरान बेची जा रही थी। इससे कुरान व अन्य धार्मिक साहित्य की हजारों किताबें जल गईं। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के राजनीतिक कार्यालय और राष्ट्रीय मस्जिद पर भी हमला बोला।'

हिफाजत के 13-सूत्रीय कार्यक्रम में ईशनिन्दा-विरोधी कानून लागू करना शामिल है जिसमें मृत्युदंड का प्राविधान है। इसके साथ ही 'इस्लाम का अपमान' करने वाले ब्लागरों तथा अन्य को इबरतनाक सजा देने, महिला विकास की बांग्लादेश की नीति रद्द करने, सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थलों पर पुरुषों व महिलाओं के एकसाथ आने पर प्रतिबंध, कैंडललाइट प्रदर्शनों पर प्रतिबंध, 'बेशर्म व्यवहार व कपड़ों' पर प्रतिबंध तथा अहमदियों को 'गैर-मुस्लिम' घोषित करने की मांगें शामिल हैं। 'ईटीवी' के लिए रैली कवरेज करने वाली पत्रकार नादिया सरमीन की बेरहमी से पिटाई की गई थी क्योंकि आखिरकार एक महिला ने 'केवल पुरुषों के लिए' आयोजन में आने की हिम्मत कैसे दिखाई।

गंभीर रूप से घायल सरमीन को दूसरे पत्रकारों ने बचाया। यह सब तालिबान के एजेंडे तथा 1980 के दशक में बनी तालिबान सरकार के ओसामा बिन लादेन के आदर्शों पर चलने की याद दिलाता है। अंतरिम सरकार के हिफाजत के साथ नजदीकी और बहुत अच्छे संबंध हैं। उसने संगठन से प्रतिबंध उठा लिया है। धार्मिक मामलों के सलाहकार एएफएम खालिद इस संगठन के नायब-वजीर रह चुके हैं।

अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने 31 अगस्त, 2024 को संगठन प्रमुख ममनूल हक के साथ लंबी बैठक की। हिफाजत पूरे देश में रैलियां और प्रदर्शन कर रही है। शहरयार की गिरफ्तारी और उनकी लगातार हिरासत को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जबकि उनकी रिहाई के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एक्टिविस्टों और संगठनों ने मांग की है। इसके पीछे इरादा बांग्लादेश के लोगों को स्पष्ट संदेश देना है कि लोकतंत्र व मानवाधिकारों की पैरोकारी न करें तथा इस्लामी कट्टरपंथियों का विरोध न करें। यदि हम शहरयार कबीर को जेल में बंद कर सकते हैं तो तुमको भी सीखचों के पीछे फेंक देंगे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

शिक्षा में वंचित वर्गों के कोटे का सवाल

> शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे का उल्लंघन भारत की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित कर रहा है।

बी के झा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

शिक्षाधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के कोटे का लगातार उल्लंघन पूरे भारत में, खासकर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में एक परेशान करने वाला मुद्दा बन गया है। स्पष्ट कानूनी अनिवार्यताओं के बावजूद, कई निजी स्कूल इस प्रावधान के तहत सही रूप से योग्य बच्चों को प्रवेश देने से इनकार करते रहते हैं, जिससे वंचित समुदायों के लिए समान शैक्षिक अवसरों में बाधा उत्पन्न होती है। दिल्ली उच्च न्यायालय में हाल ही में हुई कानूनी कार्यवाही ने एक बार फिर इस मुद्दे को सामने ला दिया है, जिससे कमज़ोर वर्ग के छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून के सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसका एक उदाहरण मास्टर अयान सैफी है, जो शाहिद का 4 वर्षीय बेटा है, जिसे शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली के शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से एक सीट आवंटित की गई थी। लेकिन, रोहिणी के एक प्रमुख निजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया और इसके बाद कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। शाहिद ने अपनी दुर्दशा के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्याय की मांग की। यह गलत धारणा है कि वकील ऐसे मामलों को लेने से कतराते हैं, खासकर समाज के निचले तबके से आने वाले लोगों के लिए।

इसका श्रेय दिल्ली के एक युवा वकील अमन शर्मा को जाता है, जिन्होंने बच्चे का केस लिया और अयान सैफी को स्कूल में प्रोविजनल एडमिशन दिलाया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के मार्गदर्शन में दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन को स्वीकार किया और एक अंतरिम आदेश में बच्चे को प्रोविजनल एडमिशन दिया, जिसमें स्कूल के ईडब्ल्यूएस कोटे का अनुपालन करने के कानूनी दायित्व पर जोर दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम

2009 एक ऐतिहासिक कानून है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। इसके प्रमुख प्रावधानों में से एक यह अनिवार्य करता है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर वर्ग और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित हों। इस कोटे का उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के बीच की खाई को पाटना है।

हालांकि, इस प्रावधान के महत्व के बावजूद, इसके कार्यान्वयन को न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश के कई निजी स्कूलों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। दाखिले से इनकार करना इस कानून को लागू करने में चल रही चुनौती को उजागर करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत एक बच्चे के शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अधिवक्ता शर्मा का तर्क है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को उनकी हकदार शिक्षा से वंचित करना, एक निश्चित आवंटन के बावजूद, न केवल शिक्षा के अधिकार अधिनियम की भावना के खिलाफ है, बल्कि पहले से ही सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए अनावश्यक बाधाएं भी पैदा करता है। गैर-अनुपालन का एक पैटर्न आसानी से देखा जा सकता है और दुर्भाग्य से, यह निजी शिक्षण संस्थानों में व्यापक हो गया है। अयान का मामला एक अकेली घटना नहीं है।

दिल्ली के निजी स्कूलों को बार-बार कमजोर वर्ग के कोटे की अवहेलना करने का दोषी पाया गया है, जिससे कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है जो वंचित बच्चों के लिए सही शैक्षिक अवसरों को बहाल करने की मांग करती है। मार्च 2024 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कमजोर वर्ग के प्रवेश के लिए आय सीमा को संशोधित किया, पात्रता मानदंडों को मजबूत किया और स्पष्ट मार्गदर्शन की पेशकश की। हालांकि, स्कूल अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहे हैं। 2022 में रामेश्वर झा बनाम प्रिंसिपल रिचमंड ग्लोबल स्कूल के मामले में इसी तरह के फैसले ने ईडब्ल्यूएस प्रवेश से इनकार करने वाले स्कूलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए एक मिसाल कायम की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तब चेतावनी दी थी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन न करने पर स्कूलों को दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के तहत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फिर भी, स्कूल अभी भी ऐसी चालें चलते हैं जो कमजोर वर्ग के छात्रों के प्रवेश में देरी करती हैं या उन्हें मना कर देती हैं, जिससे परिवारों को मामला अदालत में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा शैक्षणिक संस्थानों और संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका में विश्वास का क्षरण है।

एडवोकेट शर्मा ने शिक्षा निदेशालय और न्यायपालिका से शिक्षा के अधिकार अधिनियम की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया, दंड और सख्त प्रवर्तन उपायों की मांग की। नीति निर्माताओं, शिक्षकों और नागरिक समाज के लिए आरटीई अधिनियम के सिद्धांतों को बनाए रखने और अधिक समावेशी शिक्षा प्रणाली की दिशा में काम करने में सहयोग करना अनिवार्य हो जाता है।

आप की बात

अनुभव को सम्मान

एक हालिया अध्ययन के अनुसार देश में 31 प्रतिशत काम करने वालों को अधिक उम्र के कारण कई सुविधाओं से वंचित रखा गया। उन्हें प्रमोशन देने से इनकार करने से लेकर किसी भी बहाने से नौकरी से निकलने के प्रयास किए जाते हैं। अमेरिका सहित कई देशों में भी ऐसी ही स्थितियां पाई गई। कंपनियों की मानसिकता हो गई है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारी कम ऊर्जावान तथा नया कार्य सीखने मैं सक्षम नहीं होते हैं। जबकि उम्र दराज कर्मचारी अधिक अनुभव वाले तथा अपने कार्य के प्रति गहरी समझ रखने वाले होते हैं। कंपनियों की इस मानसिकता को देखते हुए यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति बड़े-बड़े राष्ट्रों के राष्ट्रपति क्यों बनते हैं जो कि सर्वाधिक जिम्मेदारी का पद है? उनकी एक गलती से दुनिया तबाह हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद खुद जनता ही उन्हें चुनकर राष्ट्रपति बनाती है। बड़े-बड़े व्यवसायी और व्यापारी भी बड़ी उम्र में ही अपने व्यापार को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं तो नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए नौकरी में उम्र का भेदभाव सर्वथा अनुचित है। जीवन प्रत्याशा बढ़ने तथा आधुनिकतम सुविधाओं व तकनीकों से वयोवृद्ध व्यक्ति अनेक क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं। उनके अनुभव को समुचित सम्मान मिलन चाहिए।

-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

ट्रंप की बढ़ती मुश्किलें

डोनाल्ड ट्रम्प को अपनी लोकप्रियता में लगातार गिरावट को लेकर जितना दु:ख कमला हैरिस ने नहीं पहुंचाया था उससे कहीं अधिक दु:ख उन्हें उनकी तीसरी पतनी मेलानिया ट्रम्प ने अपने एक वक्तव्य से पंहुचाया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों एवं समर्थकों के साथ उस समय जश्न मनाया था जब अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने अमेरिकी महिलाओं को गर्भपात का पूर्ण अधिकार देने वाला कानून उलट दिया था। अब कुछ चिकित्सीय आपात स्थितियों को छोड़कर एक समय के बाद गर्भपात को अपराध घोषित किया जा जुका है। श्रीमती मेलानिया ट्रम्प ने अपनी आगामी पुस्तक के प्रचार में जारी एक वीडियो क्लिप में महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करते हुए गर्भपात को एक जन्मजात आवश्यक अधिकार बता दिया है। इस प्रकार मेलानिया ट्रम्प रिपब्लिकन पूर्व प्रथम-महिलाओं की उस लंबी कतार में शामिल हो गई हैं जो गर्भपात के अधिकारों का समर्थन करने के लिए सामने आई हैं। मैलानिया ट्रंप का यह बयान उनके पति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बढ़ती मुश्किलों का संकेत देता है क्योंकि इसका अर्थ अधिकांश अमेरिकी महिलाओं का हैरिस के पक्ष में खड़ा होना भी है।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

मुफ्त रेवड़ियां

जिस तरह आरक्षण राजनीतिक पार्टियों और सरकारों के लिए गले की हड्डी बन गया है, ठीक वैसे ही उनके लिए आगे चलकर मुफ्त रेवड़ियां भी गले की हड्डी तो बनेंगी ही, साथ ही ये देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता व उन्नति में भी बाधक सिद्ध होंगी। सभी राजनीतिक दल यह जानते हैं किन्तु वोटबैंक के लालच में न चाहकर भी उसी राह पर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आगाह किया है कि शीघ्र ही राजनीतिक दल और सरकारें मुफ्त रेवड़ियां बांटना बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। इससे एक ओर तो जनता द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई से टैक्स के रूप में देश की उन्नति के लिए सरकार को दिया जाने वाला धन मुफ्त रेवड़ियों में बेजा खर्च हो रहा है, दूसरे लोग आलसी भी बन रहे हैं। जब कोई काम किए बिना भोजन और अनेक सुविधायें मुफ्त मिलने लगें तो खुराफाती लोग अपराधी भी बन सकते हैं। मुफ्त रेवड़ियां बांटने में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी-आप सबसे आगे है जिसका नतीजा हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहां कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ रहे हैं और ढांचागत विकास के काम बंद होने की नौबत आ रही है। यह स्थिति पूरे देश के लिए अत्यधिक खतरनाक होती जा रही है।

-शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

स्वागत योग्य फैसला

देश की तमाम जेलों में बंद कैदियों में जाति के आधार पर काम बांटने को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से ऐसे प्रावधान हटाने का आदेश दिया है जिनसे जाति के आधार पर काम का बंटवारा हो। वैसे भी कैदी जेल के अंदर कुंठित रहते है, ऐसे में अगर जाति के आधार पर काम का बंटवारा होता रहे तो कैदी और ज्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे। इसके साथ ही जेलों में सुधार के पहलू लुप्तप्राय हो जाएंगे। आश्चर्य तो इस बात का है कि देश की आजादी के इतने साल बाद तक अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह प्राविधान लागू रहा और बड़ी-बड़ी बातें करने वाले राजनीतिक दलों की इस पर नजर तक नहीं गई। इस निर्णय से उन नेताओं को भी सबक लेना चाहिए जो जातीय जनगणना की रट लगाए हुए हैं। चिन्ता की बात है कि ऐसी किसी गणना से कहीं जातीय पूर्वाग्रह और मजबूत न हो जांए तथा संख्या में कम, पर प्रबुद्ध व सबको समान देखने वाले लोगों को बदले की कार्रवाई का शिकार न होना पड़े। आखिर जातिहीन समाज कैसे बनेगा?

- योगेश जोशी, बड़वाह

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 199

उत्पादकता में इजाफा

अक्सर यह दलील दी जाती है कि भारत को अपनी उत्पादकता में इजाफा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास (आरऐंडडी) क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा के लिए उत्पादकता में बढ़ोतरी आवश्यक है। ऐसा करने से भारत का औद्योगिक आधार भी मजबूत होगा तथा रोजगार भी बढ़ेंगे। यह निराशाजनक है कि भारत आरऐंडडी पर अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 0.7 फ़ीसदी हिस्सा ही खर्च करता है। यह अन्य समकक्ष देश की तुलना में बहुत कम है और आर्थिक वृद्धि बढ़ाने की राह में बड़ी बाधा भी है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार भारत को आरऐंडडी पर होने वाला व्यय बढ़ाकर जीडीपी के तीन प्रतिशत के बराबर करने की आवश्यकता है। उद्योगपति नौशाद फोर्ब्स ने उचित ही कहा है कि बड़ी भारतीय कंपनियां आरऐंडडी पर बहुत कम खर्च करती हैं। इसमें दो राय नहीं कि भारत को आरऐंडडी पर खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है लेकिन शायद केवल यह खर्च बढ़ा देने भर से बात नहीं बनेगी।

इस संदर्भ में शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री उफुक अकजीत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित जर्नल फाइनैंस ऐंड डेवलपमेंट के ताजा अंक में लिखे आलेख में इस बात को रेखांकित किया है आरऐंडडी व्यय (खासकर अमेरिका) में इजाफा उत्पादकता में अपेक्षित सुधार की वजह नहीं बना है। इसके नतीजे अन्य देशों के नीति निर्माताओं के लिए मददगार साबित हो सकते हैं ताकि वे गलतियां नहीं करें। 1980 के दशक में अमेरिका का आरऐंडडी व्यय उसके जीडीपी का करीब 2.2 फीसदी था जो हाल के समय में बढ़कर 3.5 फीसदी हो चुका है। परंतु वहां 1960 से 1985 के बीच औसत उत्पादकता वृद्धि 1.3 फीसदी थी जो बाद के दशकों में और कम हो गई। केवल 2000 के दशक में अल्पावधि के लिए इसमें सुधार हुआ। हालांकि पेटेंट प्रोडक्शन पर काम कर रहे लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ लेकिन उत्पादकता में कमी आई।

इस विरोधाभास को संसाधनों के आवंटन से समझा जा सकता है। आकार के संदर्भ में शोध बताता है कि छोटी कंपनियां अधिक नवाचारी होती हैं। दूसरी ओर बड़ी रसूखदार कंपनियां निगम नवाचार के बजाय रणनीतिक कदम को तवज्जो देती हैं। इसका असर संभावित उत्पादन पर पड़ता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं कि हाल के दशकों में कई अर्थव्यवस्थाओं में बाजार अधिक घना हुआ है। इटली से निकले प्रमाण दिखाते हैं कि जैसे-जैसे कारोबार में इजाफा होता है वे अधिक से अधिक राजनेताओं को अपने साथ जोड़ते हैं और नवाचार पर बुरा असर होता है। चूंकि बड़ी कंपनियां अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करती हैं इसलिए वे न केवल छोटे संभावित प्रतिद्वंद्वियों का अधिग्रहण करती हैं बल्कि छोटी कंपनियों के नवाचारियों को भी बेहतर भुगतान करके अपने साथ जोड़ती हैं, भले ही उन्हें उनकी आवश्यकता न हो। उदाहरण के लिए इस सदी के आरंभ में अमेरिका के 48 फीसदी आविष्कारक उन बड़ी कंपनियों के लिए काम करते थे जो कम से कम 20 साल पुरानी थीं और जहां 1,000 से अधिक लोग रोजगारशुदा थे। 2015 तक यह आंकड़ा बढ़कर 58 फीसदी हो गया। कई शोधकर्ताओं को अक्सर ऐसी भूमिकाओं में रख दिया गया जहां वे अपने कौशल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे।

इससे सबक मिलता है कि वृहद स्तर पर आरऐंडडी प्रभावित होता है जो वृद्धि और विकास दोनों पर असर डालता है। भारत जैसे विकासशील देशों को इस सबक से फायदा मिल सकता है। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बड़ी कंपनियां अपने दबदबे का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए न करें। अल्पावधि से मध्यम अवधि में इनमें से कुछ को टाला नहीं जा सकता है। बहरहाल, सरकार को छोटे और उभरते उपक्रमों की कीमत पर बड़ी कंपनियों की मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि बड़ी कंपनियां ऐसी तकनीक विकसित कर सकती हैं जो उत्पादकता में भारी इजाफा कर सकें। आरऐंडडी में राजकोषीय समर्थन से छोटी कंपनियों को यथासंभव नुकसान नहीं होना चाहिए। चुनिंदा कंपनियों पर ध्यान देने से अल्पावधि में वृद्धि हासिल हो सकती है लेकिन उनका दबदबा दीर्घावधि में वृद्धि और उत्पादकता पर असर डाल सकता है।

अजय मोहंती

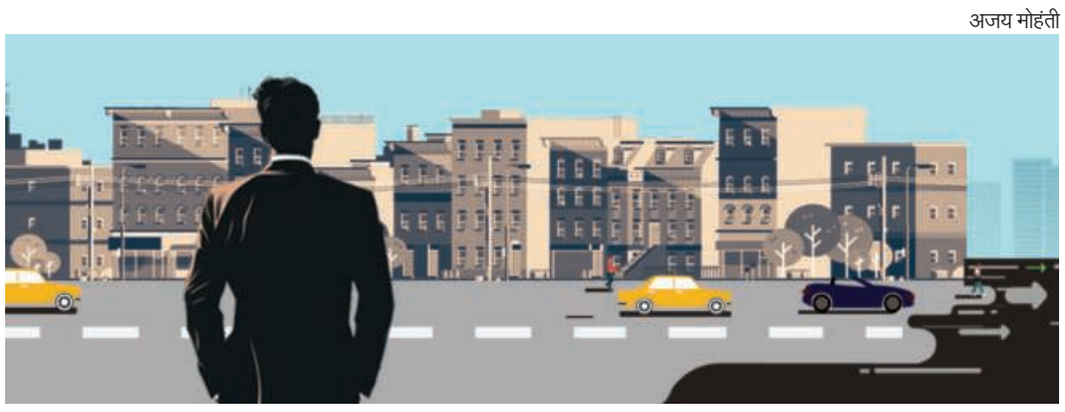

रियल एस्टेट में निवेश का जोश रोकना जरूरी

चीन के रियल एस्टेट बाजार की हालत देखकर हमें सीखना चाहिए कि रियल एस्टेट कारोबार में क्या करना है और क्या नहीं करना है। बता रहे हैं अजय शाह

कई लोगों को अचल संपत्ति या रियल एस्टेट में निवेश आकर्षक लगता है। आम मध्यमवर्गीय परिवार तीन मकान खरीदने का ख्वाब देखता है: एक रहने के लिए, दूसरा बच्चों के लिए और तीसरा निवेश के लिए। जमीन में निवेश करने वाले कहते हैं, 'जमीन में निवेश इसलिए अच्छा है क्योंकि नई जमीन तो बनने से रही।'

लेकिन जमीन में निवेश का यह कारण कुछ सही नहीं है। देश में जमीन का इस्तेमाल करने वाले अधिक लोग नहीं हैं। अगर हम बहुत उदारता बरतते हुए मान लें कि हर व्यक्ति मकान और दुकान या दफ्तर के लिए करीब 100 वर्ग मीटर जमीन इस्तेमाल करता है तो इस देश की 1.4 अरब की आबादी को भारत की कुल जमीन का 4.2 फीसदी हिस्सा ही चाहिए। अगर हम मान लें कि चार सदस्यों वाले हर परिवार को करीब 4,600 वर्ग फुट जमीन चाहिए और फ्लोर स्पेस इंडेक्स केवल 1 है तब भी देश में मौजूद समूची जमीन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा।

देश में अधिकतर वयस्कों को बचपन में ही पढ़ाया गया कि आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है। मगर भारत की प्रजनन दर में बहुत अंदर आ गया है। देश की कुल प्रजनन दर 1964 में छह थी जो 2022 में घटकर दो रह गई है। हमें इस गिरावट की वजह के बारे में ठीक से नहीं पता लेकिन कुछ तो हो रहा है। भारत के इतिहास के हरेक चरण में आबादी का बदलाव अनुमान से तेज गति से हुआ है। दक्षिण के राज्यों की कुल प्रजनन दर जर्मनी की दर से कम है। हमें कहना चाहिए, 'जमीन में निवेश इसलिए कीजिए क्योंकि आबादी ज्यादा नहीं बढ़ रही है।'

अपना पैसा निवेश करते समय याद रखना चाहिए कि पिछले 20 वर्षों में निफ्टी 26 गुना चढ़ चुका है। इसमें विविधता है, पारदर्शिता है और तरलता यानी शेयर बेचकर फौरन नकद हासिल करने की संभावना है, लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट में निवेश पर जरूरत से ज्यादा जोर उन परिवारों के कारण भी होता है, जिन्हें सूचीबद्ध कंपनियां, अकाउंटिंग के आंकड़े, एक्सचेंज और डिपॉजिटरी ठीक नहीं लगतीं। जब भी कोई परिवार शेयरों में निवेश करने चलता है तो वह रियल एस्टेट की कीमतें नीचे आने की वजह बनता है।

गहराई से सोचिए कि क्या किसी कार की कीमत बढ़ सकती है? यह बेवकूफाना बात है क्योंकि कार की कीमत बढ़ेगी तो उसकी आपूर्ति बहुत बढ़ जाएगी। अगर हम यह मानना बंद कर दें कि जमीन दुर्लभ है तो रियल एस्टेट ईंट, इस्पात और कांच के ढेर के अलावा क्या है। उसकी कीमत चढ़ेगी तो आपूर्ति बढ़ जाएगी, जिसके बाद कीमत में लगातार इजाफा हो ही नहीं पाएगा। सच कहें तो रियल एस्टेट की यह दीवानगी तमाम अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। रियल एस्टेट पर जोर चीन के आर्थिक मॉडल की नाकामी का भी बड़ा कारण रहा।

1980 के दशक के आरंभ से ही चीनी परिवार रियल एस्टेट पर बहुत जोर देने लगे। भारत ने 1992 से 2017 के बीच मजबूत वित्तीय बाजार तैयार किए, जो चीन में कभी नहीं हो सका। चीन के परिवारों ने जब-जब वित्तीय संपत्तियों में निवेश की कोशिश की, उन्हें घाटा हुआ और वे रियल एस्टेट की ओर लौट गए। वहां की सरकार ने लोगों को विदेश में निवेश नहीं करने दिया, जिससे रियल एस्टेट में ही निवेश बढ़ता गया। नीति निर्माताओं ने भी शहरी विकास के लिए रकम के इंतजाम को रियल एस्टेट के साथ जोड़कर उसे हवा दी। चीन में नीतियों की बुनियाद नियंत्रण ही है और नीति निर्माताओं की इस मंशा के कारण रियल एस्टेट को रकम की शक्ल में अर्थव्यवस्था को बार-बार प्रोत्साहन मिले।

विचारक दशकों से रियल एस्टेट की समस्या के प्रति आगाह करते रहे मगर अधिकतर लोगों को फौरी मुनाफे से ही मतलब रहा। समय के साथ हालात बिगड़ने लगे। वहां हर परिवार के पास औसतन 1.5 घर हैं और आबादी के बारे में अनुमान भारत के मुकाबले बहुत खराब हैं। चीन में इतने मकान खाली पड़े हैं, जितने बंबई में भी नहीं हैं। वहां पूरे के पूरे शहर निर्जन हो गए हैं। रियल एस्टेट कारोबार में शामिल हर कोई - निवेशक, ऋणदाता, डेवलपर, सरकार - प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहा है और रियल एस्टेट क्षेत्र अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से रोक रहा है। दिवाला प्रक्रिया तेज हो तो कर्ज देने वालों और परिवारों को बड़ा घाटा होता है मगर यह धीमी हो तो और भी नुकसान होता है और अर्थव्यवस्था को कई वर्षों तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। चीन में रियल एस्टेट की समस्याएं अब आम परिवारों के हौसले कुंद कर रही है।

ये बातें भारत में नीतिगत क्षेत्र के लिए बहुत महत्व रखती हैं। भारत में हमने संस्थाओं के निर्माण और वित्तीय नीति में ऊंची क्षमता के दौर के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे शेयर बाजार, डेरिवेटिव्स कारोबार, विदेशी निवेशकों को मजबूत बुनियाद मिली। इससे आम परिवारों ने धीरे-धीरे रियल एस्टेट से निकलकर वित्तीय संपत्तियों में निवेश करना सीख लिया। वित्तीय क्षेत्र के विकास में सुस्ती हमारे लिए ही मुश्किलें पैदा करती है।

मकानों की कीमत और आय का अनुपात शहरी नीति के कारण बिगड़ता है। लोगों के लिए सबसे अच्छा तब होता है, जब मकान का किराया या कीमत कम हो। होना तो यह चाहिए कि शहर में लोग अपनी आय का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा खर्च कर रहने के लिए मकान का इंतजाम कर सकें। किराया कम होगा तो पगार भी कम देनी होगी, जिससे कंपनियों की लागत घटेगी और वे दुनिया भर की कंपनियों से होड़ कर सकेंगी।

इसके लिए जमीन पर बहुमंजिला इमारतें बननी चाहिए, जिससे बहुत सारे मकान तैयार हो जाएंगे। उन मकानों की कीमत और किराये भी कम होंगे। नीतियों में कई तरह की खामियां रियल एस्टेट आपूर्ति के आड़े आ रही हैं। नीति निर्माताओं को स्थिति पलट देनी चाहिए शहरों में आम मकानों के साथ बहुमंजिला इमारतों पर भी जोर देना चाहिए। चीन का उदाहरण बताता है कि शहरों के लिए रकम जुटाने का तरीका कितना अहम है। इसके लिए वस्तु एवं सेवा कर का कुछ हिस्सा शहरों में लगाना चाहिए और रियल एस्टेट में उछाल के जरिये शहरों के विकास की उम्मीद लगाने के बजाय संपत्ति कर का इस्तेमाल करना चाहिए।

यह रुख वित्तीय नीति से जुड़ा है। वित्तीय नीति का रुख खेत या रियल एस्टेट के बदले कर्ज रोकने वाला नहीं होना चाहिए। इसे कर्ज या रकम के इंतजाम को बढ़ावा देना चाहिए ताकि आपूर्ति बढ़े और रियल एस्टेट के दाम नीचे आ जाएं। इसके लिए विदेशी रियल एस्टेट डेवलपरों और रियल एस्टेट में विदेशी कर्ज पर लगी रोक हटानी होंगी। पूंजी के बाहर जाने पर लगा नियंत्रण भी कम करना होगा ताकि आम लोग वैश्विक संपत्तियों में निवेश कर सकें और भारत में रियल एस्टेट में निवेश का आकर्षण कम हो सके।

(लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं)

ब्याज दरों और रुख में बदलाव के आसार नहीं

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अगस्त में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नीतिगत दर और अपने रुख दोनों में बदलाव नहीं किया था। लगातार 9वीं बार आरबीआई ने रीपो रेट 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित छोड़ दी थी। अब एमपीसी में तीन नए बाहरी सदस्य आए हैं। क्या नई एमपीसी से कोई नया रुझान सामने आएगा खासकर नीतिगत स्तर पर कोई बदलाव देखने को मिलेगा? दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंकों की बात करें तो उनके कदमों में भिन्नता दिखी है। सितंबर में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व में प्रमुख ब्याज दर में 50 प्रतिशत कटौती कर सबको चौंका दिया। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने भविष्य में दरों में और कटौती के संकेत दिए हैं, हालांकि काफी कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

यूरोप में सितंबर में मुद्रास्फीति 2021 के मध्य से पहली बार 2 प्रतिशत से नीचे आ गई। माना जा रहा है कि यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) आने वाले समय में ब्याज दर और घटा सकता है। पिछले सप्ताह ईसीबी ने ब्याज दर 0.25 प्रतिशत घटा कर 3.5 प्रतिशत कर दी थी। माना जा रहा है कि बैंक ऑफ इंगलैंड (बीओई) भी नवंबर में ब्याज दर में कमी करेगा। सितंबर में बीओई ने ब्याज दर 5 प्रतिशत पर स्थिर रखी थी। तेजी से उभरते बाजारों की बात करें तो फिलीपींस और इंडोनेशिया में भी ब्याज दरें कम हुई हैं। चीन में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने भी आरक्षित आवश्यकता अनुपात आधा प्रतिशत अंक कम कर दिया है। रूस और जापान और ब्राजील में भी ऊंची मुद्रास्फीति के बीच ब्याज दरों में कमी की गई है।

आरबीआई का क्या रहेगा रुख?

इस सप्ताह एमपीसी की बैठक शुरू हो रही है, ऐसे में आरबीआई से क्या उम्मीद की जा सकती है? खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में नरम होकर 3.6 प्रतिशत रह गई थी मगर अगस्त में यह थोड़ी बढ़कर 3.65 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह अब भी आरबीआई द्वारा निर्धारित सहज लक्ष्य 4 प्रतिशत से नीचे ही है। जुलाई और अगस्त में मुद्रास्फीति के आंकड़ों में ऊंचे आधार प्रभाव का असर दिखा था। सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति कम से कम 5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया जा रहा है मगर यह आंकड़ा एमपीसी की बैठक संपन्न होने बाद जारी किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सुस्त होकर 6.7 प्रतिशत रह गई। हालांकि, यह एक दशक में पहली तिमाही की औसत 6.4 प्रतिशत दर से अधिक है। सितंबर के शुरू में भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य परिसंघ (सीआईआई) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा आयोजित एक बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था, 'मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि में संतुलन बनता दिख रहा है।' दास ने उम्मीद जताई थी कि खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आएगी जिसका मतलब यह निकाला गया कि आने वाले समय में यह अधिक अनुकूल हो जाएगी।

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

खुदरा मुद्रास्फीति को लेकर आरबीआई लगातार चिंतित रहा है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत तक होती है। आर्थिक समीक्षा के बाद यह बहस तेज हो गई है कि मुद्रास्फीति की गणना करते वक्त खाद्य वस्तुओं पर विचार किया जाए या नहीं। इसका कारण यह है कि आपूर्ति व्यवस्था में होने वाली उठापटक मौद्रिक नीति से ठीक नहीं की जा सकती। इस बीच, प्रमुख मुद्रास्फीति वर्ष 2012 से अपने निचले स्तर के इर्द-गिर्द रही है। प्रमुख मुद्रास्फीति में खाद्य वस्तुएं एवं तेल शामिल नहीं होती हैं।

इस साल मॉनसून में सामान्य से 7.6 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें नरम होंगी। दूसरी तरफ प्रमुख मुद्रास्फीति में भी धीरे-धीरे तेजी आने की बात कही जा रही है। वैश्विक स्तर पर मांग कमजोर पड़ने से जुलाई-सितंबर तिमाही में कच्चे तेला का दाम 17 प्रतिशत तक फिसल गया था। मगर अब इजरायल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद इसमें फिर तेजी आने लगी है। इन घटनाक्रम को देखते हुए कई लोगों को लगता है कि इस सप्ताह एमपीसी ब्याज दरों पर यथास्थिति बनाए रखेगी मगर मौद्रिक नीति पर इसका रुख 'तटस्थ' रह सकता है और इसका नजरिया अधिक सकारात्मक रहेगा।

हालांकि, कई मोर्चों पर विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं को देखते हुए अगर आरबीआई 'देखो और इंतजार करो' की नीति अपनाता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। आरबीआई लगातार जोर देता रहा है कि नीतिगत दरों पर निर्णय यह आंतरिक हालात को देखकर लेगा न कि इस पर ध्यान देगा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है। दिलचस्प बात है कि अमेरिका में ब्याज दर में आधा प्रतिशत कमी के बावजूद फिलहाल अमेरिका और भारत में नीतिगत दर में अंतर दीर्घ अवधि के औसत से काफी कम है।

मौद्रिक नीति के मोर्चे पर ढील से अधिक चीन में वित्तीय प्रोत्साहनों पर अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि ये जिंसों की कीमतों पर असर डाल सकते हैं। इस साल (हाल में उठाए गए उपाय सहित) चीन में कुल 1.07 लाख करोड़ डॉलर के वित्तीय प्रोत्साहन जारी किए गए हैं। डॉयचे बैंक की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार यह रकम 2024 में चीन के जीडीपी का 6 प्रतिशत के बराबर है।

मॉनसून सामान्य से अधिक जरूर रहा है मगर देश में वर्षा का वितरण एक समान नहीं रहा है और खाद्य मुद्रास्फीति में इजाफे के संकेत भी मिलने शुरू हो हैं।

रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव से दुनिया में हालात और बिगड़ रहे हैं। यानी आरबीआई दिसंबर तक हालात साफ होने तक इंतजार करे तो किसी को इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

अगस्त में मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुमानों में कोई बदलाव नहीं किए थे, बस इन्हें थोड़ा अधिक तर्कसंगत बनाया गया था। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2025 के लिए आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.3 प्रतिशत था मगर पहली तिमाही के लिए अनुमान 7.3 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया गया। इसी तरह, खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5 पर स्थिर रखा गया मगर दूसरी तिमाही के लिए इसे 3.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.4 प्रतिशत और तीसरी तिमाही के लिए 4.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.7 प्रतिशत कर दिया गया। चौथी तिमाही के लिए इसका अनुमान 4.5 प्रतिशत से घटाकर 4.3 प्रतिशत कर दिया गया।

क्या इन अनुमानों में कोई बदलाव होंगे? इस बात की संभावना कम ही है कि मुद्रास्फीति के अनुमान में संशोधन होंगे। आर्थिक वृद्धि को लेकर आरबीआई दूसरे संस्थानों की तुलना में अधिक उत्साहित दिख रहा है। मगर इन दोनों अनुमानों में संशोधन करने से पहले आरबीआई दिसंबर तक इंतजार कर सकता है। आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति का समीकरण जरूर बदल रहा है मगर आरबीआई किसी तरह की जल्दबाजी दिखाने से परहेज करेगा।

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक में वरिष्ठ सलाहकार हैं।)

आपका पक्ष

खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर सतर्कता

खुदरा क्षेत्र में एफडीआई से जुड़ी हकीकत पर बहुत तथ्यात्मक लेख खुदरा बाजार पर प्रतिकूल प्रभावों पर विस्तृत चर्चा करता है। भारत में रिटेल व्यापार का मूल्यांकन 850 अरब डॉलर का है जो वर्ष 2032 में दो लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसलिए खुदरा बाजार को विदेशी निवेश की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी ई-कॉमर्स कंपनियों में विदेशी निवेश ही है जिसके बूते पर वह खुदरा क्षेत्र में लगभग 25 से 30 प्रतिशत की साझेदारी किए हुए है और ई-कॉमर्स कंपनियां बिना आयकर दिए अरबों रुपये का कारोबार कर रही हैं। यह बहुत संवेदनशील विषय है क्योंकि रिटेल व्यापार में विदेशी निवेश के माध्यम से फिर विदेशी उत्पाद स्वदेशी उत्पादों को छूट के द्वारा पीछे करने के प्रयत्न करेंगे। इस विषय में सरकार को व्यापारिक संगठनों फिक्की, एसोचैम और स्थानीय व्यापार मंडलों से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। जैसे

भारत में रिटेल व्यापार का मूल्यांकन 850 अरब डॉलर का है जो वर्ष 2032 में दो लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा

मीडिया में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई तो इसके सबसे अधिक प्रभाव से गेमिंग पोर्टल और वेबसाइट की बाढ़ आ गई और बड़े-बड़े सेलिब्रिटी इनके विज्ञापनों में छा गए। माता-पिता अपनी संतानों और स्वयं की गेमिंग की आदत से परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे स्वदेशी उत्पाद विदेशी माल का मुकाबला नहीं कर सकते लेकिन छोटे उद्यमियों के पास पूंजी और तकनीक का अभाव है और सबसे अधिक दुष्प्रभाव उन पर ही पड़ेगा। इससे गली-मोहल्ले के दुकानदारों को बहुत नुकसान होगा। बड़े मल्टीब्रांड स्टोरों और मॉल में विदेशी ब्रांडों की भरमार है फिर भी छोटा और मध्यम रिटेल स्वदेशी उत्पादों से जनमानस की सेवा कर रहा है। पिछले पांच वर्षों में देश भर में चीन के उत्पादों का बहिष्कार हुआ है। इसलिए खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर बहुत सतर्कता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर फिर से विदेशी माल बाजारों में भर गया तो लाखों छोटे एमएस-एमई उद्योग खत्म हो जाएंगे और करोड़ों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे।

विनोद जौहरी, दिल्ली

जल प्रबंधन पर अधिक ध्यान दे सरकार

जल प्रबंधन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता हो तो भीषण ग्रीष्मकालीन अवधि में मनुष्यों व पशुओं को इससे राहत मिलेगी तथा कृषि भी सूखे की मार से बच सकेगा। लिहाजा मनरेगा को अधिक राशि आवंटित कर उसे अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। मॉनसून जैसा इस वर्ष मेहरबान रहा है यह जरूरी नहीं कि आगामी वर्ष भी अच्छी बारिश हो जबकि जल की आवश्यकता हर साल बढ़ती जा रही है। कृत्रिम वर्षा का विकल्प अल्पवर्षा वाले राज्यों के पास सदैव होना चाहिए। मनरेगा द्वारा हर साल नाले-नहर एवं तालाबों की सफाई का लक्ष्य बढ़ाने से ही जल सुरक्षा बढ़ सकती है। जल आयोगों द्वारा भंडारण क्षमता के विकास के बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। जनभागीदारी कैसे कितनी व कहां सुनिश्चित की जाए यही सरकारों को गंभीरता से सोचना होगा। अमृत सरोवर योजना का रिव्यू व विस्तार लगातार होता रहे।

हिम्मत जोशी, नागपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू (दाएं) पहली बार भारत की राजकीय यात्रा के तहत रविवार को नई दिल्ली पहुंचे जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया। दोनों ने बैठक कर दोनों देशों के बीच पारस्परिक हितों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 7 अक्टूबर 2024

SCO पर शुभ संकेत

भारत की ओर से जैसे ही यह स्पष्ट किया गया कि शांघाई सहयोग संगठन (SCO) की शिखर बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे, दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की अटकलें लगाई जाने लगीं। दिलचस्प है कि इस फैसले को भारत-पाक रिश्तों के संदर्भ में ज्यादा देखा जा रहा है, जबकि यह SCO को भारत द्वारा दी जा रही अहमियत का भी उतना ही संकेत है।

भावनात्मक करीबी | इसके पीछे दोनों पड़ोसी देशों के खट्टे-मीठे रिश्तों के बीच भी एक-दूसरे से भावनात्मक करीबी की भूमिका देखी जा सकती है। दोनों देशों में युद्ध हुए हैं और रिश्तों ने गिरावट की इंतिहा देखी है तो दोनों के बीच दोस्ती के दौर भी आते रहे हैं। लेकिन किसी भी सूरत में दोनों देशों के लोग एक-दूसरे से उदासीनता की स्थिति में नहीं पहुंचे। यही वजह है कि करीब एक दशक के अंतराल के बाद जब किसी भारतीय विदेश मंत्री के पाकिस्तान जाने का कार्यक्रम बनता दिखा तो कई कोनों से उत्साह छलकने लगा।

जयशंकर का प्रस्तावित पाक दौरा

द्विपक्षीय रिश्तों पर बात नहीं | मौजूदा सूरते हाल में इस तरह के उत्साह को व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता। शायद इसीलिए विदेश मंत्री जयशंकर ने देर किए बगैर स्पष्ट किया कि वह एक बहुपक्षीय संगठन की बैठक में शिरकत करने जा रहे हैं और वहां भारत-पाक रिश्तों पर कोई बातचीत नहीं करने वाले। यह SCO की शिखर बैठक है और सामान्य स्थिति में इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की उम्मीद होती। द्विपक्षीय रिश्तों की बदहाली ही कहिए कि पीएम की जगह एक सीनियर मंत्री का जाना भी पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है।

SCO की अहमियत | भारत इस तथ्य को समझ रहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात में SCO जैसे एक अंतरराष्ट्रीय मंच के बेहतरीन इस्तेमाल का मौका किन्हीं दो देशों के आपसी रिश्तों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के चलते हाल के वर्षों में अमेरिका से रूस और चीन के रिश्तों में आई खटास किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में जब पश्चिम एशिया में युद्ध के फैलने का खतरा एक नया सिरदर्द बना हुआ है, इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी अहम भूमिका को भारत अनदेखा नहीं कर सकता।

छुपा हुआ मौका | कूटनीति में अलग-अलग बहानों की आड़ में आने वाले मौके भी अक्सर महत्वपूर्ण साबित होते हैं। पिछले साल पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी SCO की ही बैठक के सिलसिले में भारत आकर अपने बयानों से रिश्तों में और तल्खी घोलने का उदाहरण पेश कर चुके हैं। देखना होगा कि जयशंकर की सूझबूझ और शालीनता को खिलने और खुलने का कितना मौका इस प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा में मिलता है।

चक्र-व्यू

गलियां जलेबी की

राहुल पाण्डेय

कोई अगर यह कहे कि उसे अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं है, तो ऐसे विरले ही होंगे जो उसकी बात पर यकीन न करें। कोई अगर यह कहे कि उसे अपनी नौकरी से मोहब्बत नहीं रह गई है तो भी विरले ही होंगे, जो उसकी बात पर यकीन न करें। लेकिन कोई अगर यह कहे कि उसे जलेबी से मोहब्बत नहीं है, तो विरले ही उस पर यकीन करेंगे। दुनिया फानी है, छोटी सी जिंदगानी है। इस छोटी सी जिंदगानी की टेढ़ी-मेढ़ी गलियों में जब जलेबी छनती है तो अच्छे-अच्छों को चाशनी के नजदीक मक्खियों के मानिंद लाकर खड़ा कर देती है। जिन्हें इंसान के सिर्फ गधे-घोड़े या खच्चर होने में यकीन है, एक बार वे छनती हुई जलेबी के आसपास लार रोककर मंडराते लोगों को देख लें, यकीन हो जाएगा कि मक्खी का रोल भी बखूबी अदा कर सकता है। गरमा गरम छनती जलेबी जब चाशनी में डूबकर पत्ते के दोने में नहीं पहुंचती। वह दोना असल में हमारा दिल होता है, जहां वह अपनी आड़ी-तिरछी गलियों के साथ पूरा मोहल्ला कायम करती है। और जैसे ही जलेबी जबान से टकराती है, इस धरा पर कोई कितना ही अकड़ हो, जलेबी सबको सीधा कर देती है। बड़े से बड़े अकड़ुओं को मैंने दोनों में झुककर जलेबी को निहारते, संभालते और फिर मुंह तक पहुंचाते देखा है। जलेबी है ही ऐसी कि बिना सम्मान दिए मुंह में समा ही नहीं सकती।

जब कोई कहता है कि जलेबी तो हिंदुस्तान की पैदाइश नहीं है तो उसकी विद्वता को मैं संदिग्ध मानता हूं। जलेबी चाहे जहां की पैदाइश हो, हिंदुस्तान ने उसे अपनों से भी ज्यादा पास लाकर अपनाया है। जितने किस्म की जलेबियां हम हिंदुस्तानी बनाते हैं, इस संसार की शायद ही कोई और कौम बनाती है। हमारे यहां रंग-रंग की जलेबियां हैं। अगर अगल-बगल दो हलवाई हैं, तो दोनों की ही जलेबियों में रंग का फर्क होता है। मेले-ठेले पर मोटी-मोटी लाल जलेबी मिलती है जिसके टूटने का खतरा दिल से भी ज्यादा रहता है। बिहार-बंगाल में काली जलेबी मिलती है। बहुत से लोग जलेबी की टेढ़ी-मेढ़ी गलियों में जमकर अतिक्रमण करते हुए उसमें पनीर की दीवारें उठा देते हैं। यह जलेबी की ही महिमा है कि आज तक इसमें बैठे पनीर को किसी ने अवैध अतिक्रमण नहीं कहा, कोई जलेबी विकास प्राधिकरण बुलडोजर लेकर पनीर की दीवारें गिराने नहीं पहुंचा। नेता-नेताड़ी हों, बच्चे हों या खिलाड़ी हों, खुश हुए तो जलेबी चाहिए, दुखी हुए तो भी जलेबी ही चाहिए। हालात यह हैं कि हिंदुस्तानी राजनीति भी जलेबी का शिकार हो चुकी है। कितने साल हुए किसी ने एक सीधा नेता नहीं देखा, या किसी ने संसद का एक सीधा-सादा सत्र नहीं देखा। जो जहां है, वहीं जलेबी बना रहा है। जहां है, वहीं जलेबी खा रहा है। जलेबी की यही तो महिमा है। इस संसार में ऐसा कौन है जो इसकी पुरपेच गलियों में नहीं खोया? वैसे खोये वाली भी जलेबी बनती है!

एकदा

बापू की पहल

महात्मा गांधी 1927 में धनबाद गए थे। इसी दौरान वह गिरिडीह भी चले गए। वहां जब वह एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ में से किसी ने कहा, 'सड़कें टूटी पड़ी हैं, रुपये के अभाव में इसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है।' यह सुनकर गांधीजी बोले, 'अगर सड़कों की मरम्मत के लिए रुपये नहीं हैं, तो आप लोगों को कमर कस लेनी चाहिए और श्रमदान करना चाहिए। यदि आप कुदाली और फावड़ा लेकर, कमर कसकर काम करने निकल जाएं तो सबका भला हो जाएगा। विश्व में हर जगह तभी तरक्की हुई है, जब वहां की जनता ने मिलकर सहयोग दिया है। ग्लासगो के नगर पालिका क्षेत्र में अगर प्लेग पर जल्द नियंत्रण पा लिया गया था, तो इसके पीछे वहां के नागरिकों से मिला सहयोग था। जोहानिसबर्ग में प्लेग पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए भी वहां के नागरिकों ने ही सबसे अधिक सहयोग दिया था।' यह बोलकर गांधीजी चुप हुए तो नगर पालिका के एक सदस्य बोले कि उनके पास सफाई कर्मचारी रखने के लिए भी रुपये नहीं हैं। इस पर गांधीजी तुरंत आगे बढ़े और खुद सफाई के काम में जुट गए। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग बेहद शर्मिंदा हुए। गांधीजी बोले, 'सवाल उठाने के बजाय स्वयं से शुरुआत करोगे तो समस्या आने से पहले ही खत्म हो जाएगी।' गांधीजी की सीख का ऐसा असर हुआ कि कुछ ही दिनों में टूटी-फूटी सड़कें सही हो गईं। सभी सार्वजनिक स्थल चमचमाने लगे। हर जगह से गंदगी और कूड़े का सफाया हो गया।

Subrata Dhar

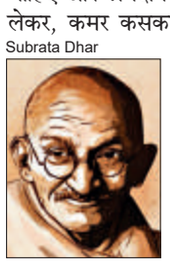

संकलन : **रेनू सैनी**

दोनों गठबंधन के घटक दलों में विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर पेच

महाराष्ट्र में पहली लड़ाई अपनों से

गंगाधर ढोबले

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इसकी बिसात कब की बिछ चुकी है। आरोप-प्रत्यारोप, दावे-प्रतिदावे, चुनौती-प्रति चुनौती, शह-मात का अभूतपूर्व दंगल बहुत पहले से चल रहा है। टक्कर केवल दो गठबंधनों में ही नहीं, बल्कि उनके घटक दलों में भी है। सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी तनातनी है।

मजबूरी का साथ | राज्य में दो गठबंधन हैं। एक महायुति कहलाता है, जिसका नेतृत्व BJP के पास है। इसमें मुख्यमंत्री शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की NCP घटक दल हैं। दूसरा गठबंधन महाविकास आघाड़ी है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की NCP इसके घटक दल हैं। BJP और शिंदे इसलिए अजित गुट से खफा हैं, क्योंकि वह लोकसभा चुनाव में महज एक ही सीट जीत पाया। उसके वोट भी BJP या शिंदे सेना को हस्तांतरित नहीं हुए।

BJP वोटर नाराज | एक तर्क यह भी है कि यदि अजित दादा स्वतंत्र रूप से लड़ें तो मराठों, दलितों और पिछड़े वर्गों के वोटों का विभाजन होने से नुकसान महाविकास आघाड़ी को होगा। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कबूल किया है कि अजित दादा के साथ गठबंधन को लेकर BJP के वोटर नाराज हैं, लेकिन यह मानना चाहिए कि राजनीति में कई समझौते मजबूरी में करने पड़ते हैं।

बैलेंस की कोशिश | महाविकास आघाड़ी में भी उद्धव ठाकरे को लेकर ऐसे ही तर्क दिए जा रहे हैं। उद्धव सेना के वोट कांग्रेस या शरद पवार की NCP को नहीं मिल रहे। उद्धव भी स्वतंत्र रूप से लड़ें तो वह शिंदे सेना के वोट काट सकते हैं। लेकिन, चुनाव सिर पर होने से उद्धव को हटाने की बात अब खत्म हुई लगती है। BJP या कांग्रेस का नेतृत्व अब किसी परिवर्तन का खतरा मोल लेने के पक्ष में दिखाई नहीं देता। एक सोच यह है कि अजित या उद्धव का अपने गठबंधन में बने रहना राजनीतिक संतुलन के लिए जरूरी है।

बंटवारे का फॉर्म्युला | महाराष्ट्र में बहुमत का जादुई आंकड़ा 145 है। एक पार्टी के लिए यह संख्या पाना आज की घड़ी में तो मुश्किल दिखाई देता है। दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे पर बात चल रही है। बंटवारे का एक यह फॉर्म्युला तो तय लगता है कि वर्तमान में जो सीटें जिस दल के पास हैं, वे उसी के पास रहेंगी। ऐसी लगभग 200 सीटें हैं।

कहां है पेच | बाकी सीटें अन्य छोटे-छोटे दलों या निर्दलीयों के पास हैं। पेच इन्हीं पर है। साथ में, कुछ जगह यह ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग का मतलब कि जो सीट गठबंधन के एक घटक दल के पास है, उसी पर दूसरा भी दावा ठोक रहा है।

एक जगह सहमति | महायुति में सीट बंटवारे पर अस्थायी सहमति की खबरें हैं। इसके अनुसार, BJP को 155-160, शिंदे सेना को 80 से 85 और अजित दादा को 50 से 55 सीटें मिल सकती हैं। महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई संख्या अभी सामने नहीं आई है।

मुंबई अंचल | राज्य के विभिन्न अंचलों में चुनावी रंग पल-पल बदलता नजर आ रहा है। मुंबई अंचल में विधानसभा की 36 सीटें हैं। 2019 का विधानसभा चुनाव BJP और एकीकृत शिवसेना ने संयुक्त रूप से लड़ा था। हाल के लोकसभा चुनाव में इस अंचल में ठाकरे गुट का वर्चस्व कायम रहा और उसने 6 में से 3 सीटें जीतीं। एक सीट शिंदे सेना को मिली। BJP और कांग्रेस ने एक-एक सीट पर कब्जा जमाया। विधानसभा चुनाव में भी ठाकरे की शिवसेना के हावी रहने के प्राथमिक अनुमान हैं।

कोंकण अंचल | इस अंचल में ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से BJP को 11, शिवसेना को 15, NCP को 8 सीटें मिली थीं। इसी तरह, विदर्भ अंचल की 62 विधानसभा सीटों में से पिछली बार BJP-शिवसेना को सबसे अधिक 33 सीटें मिली थीं। 21 सीटें NCP और कांग्रेस ने पाई थीं। हालांकि लोकसभा चुनाव में आघाड़ी को 7 और महायुति को केवल 3 सीट मिली। तब लगभग 35 विधानसभा क्षेत्रों में आघाड़ी आगे थी और 22 पर महायुति को बढ़त मिली।

चुनावी चक्र

- महायुति में अजित फिट नहीं
- आघाड़ी में उद्धव से नाराजगी
- कई सीटों पर दो-दो दावेदारी

मराठवाड़ा क्षेत्र | इस रीजन में विधानसभा की 46 सीटें हैं। पिछले चुनाव में BJP ने 16 और शिवसेना ने 11 जीती थीं। शिवेसना और NCP में टूट-फूट के बाद महायुति में 46 में से 39 विधायक हैं। लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा में BJP का सफाया हो गया।

मराठा आंदोलन से झटका | उत्तर महाराष्ट्र में भी BJP को मराठा आरक्षण आंदोलन से मार पड़ी है। पिछले विधानसभा चुनाव में BJP 35 में से 13 सीटों पर जीती थी। लेकिन, लोकसभा में 8 में से BJP को केवल एक सीट मिली। ठाकरे गुट ने सबसे अधिक तीन सीटें हासिल कीं।

तय होगा भविष्य | यह चुनाव दिलचस्प रहने वाला है। इससे यह भी तय हो जाएगा कि शिंदे, ठाकरे या अजित पवार कहां होंगे। यह चुनाव देवेंद्र फडणवीस के लिए भी चुनौती है। वह राज्य में रहेंगे या केंद्र में जाएंगे, यह भी चुनाव नतीजों से तय हो सकता है।

(लेखक वरिष्ठ संवाददाता हैं)

AI की दुनिया में Prompt है ख़ुशियों की चाबी

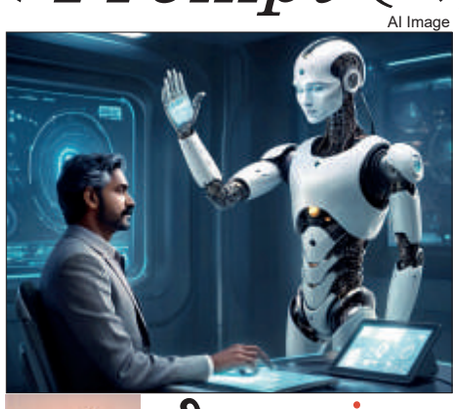

AI Image

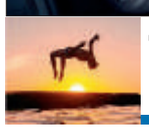

जीवन आनंद

शैलेंद्र पांडेय

'आप हर सवाल का जवाब इतनी तेजी से देते हैं, तो क्या कभी यह नहीं लगता कि आपमें इंसानों से ज्यादा काबिलियत है?' पहले उसने एक स्माइली भेजी और फिर जवाब, 'यह सच है कि मैं सवालों के जवाब तेजी से देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरी श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो मुझे बहुत सारे डेटा और जानकारी पर ट्रेंड करता है और जल्दी से जवाब देने में मदद करता है। मेरे मन में मानव बुद्धिमता के लिए बहुत सम्मान है।'

'क्या आप खुद कभी इंसानों की जगह नहीं लेना चाहेंगे, उनके जैसा बनना नहीं चाहेंगे?' इस बार जवाब से पहले भेजी गई इमोजी के दांत भी दिख रहे थे यानी भरपूर खुशी जाहिर करने के बाद उसने कहा, 'सवाल रोचक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इंसान नहीं बनना चाहता। मैं खुद को एक लैंग्वेज मॉडल के रूप में पसंद करता हूं। मुझे अपनी क्षमता से खुशी है कि मैं लोगों को जानकारी दे सकता हूं, उनकी मदद कर सकता हूं।'

'अच्छा, तो आपको अपनी क्षमता पर इतना भरोसा है?'

'कुछ पूछकर देख लीजिए।'

जब कोई इतने कॉन्फिडेंस से कहता है कि कुछ भी पूछ लीजिए, तो पूछने के पहले सोचना पड़ जाता है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से संवाद करना, उसे टास्क के लिए प्रॉम्प्ट देना इतना सरल तो नहीं! लेकिन यह काम जितना सोचने वाला है, उतना ही मजेदार और दिलचस्प भी। प्रॉम्प्ट केवल मशीन को निर्देश देना नहीं है, यह एक रचनात्मक खेल है। यहां जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि सवाल क्या पूछा गया। यह अपने विचारों को शब्दों में ढालना है और हर शब्द बिल्कुल नाप-तौल कर दिया होना चाहिए। असल दुनिया में हम कई बार भूल जाते हैं कि कब, क्या और कितना बोलना है। इस फेर में कई बार बात बिगड़ जाती है। AI की दुनिया भी ऐसी ही है, बस अच्छाई यहां यह है कि मशीनें रूठा नहीं करतीं। अगर एक प्रॉम्प्ट गड़बड़ हुआ तो क्या, दूसरा भी लिखा जा सकता है। कुछ समय बाद लगने लगता है मानो हम कोई पहली सुलझा रहे हों। बार-बार प्रॉम्प्ट को सुधारना और बार-बार अलग-अलग तरह के जवाब पाना। यह प्रयास तब तक करना, जब तक मतलब का जवाब नहीं मिल जाता।

मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता साफ होना चाहिए। AI से बातचीत कुछ ऐसी ही है। प्रॉम्प्ट उलझे हुए होंगे, तो जवाब उलझा आएगा। सारा मजा इसी बात में है कि हमें जो चाहिए उसे शब्दों में कैसे ढालते हैं। AI से बात करने का यह तरीका किसी इंसान से बात करने जैसा नहीं, लेकिन फिर भी अनोखा है। हमारा वास्ता एक ऐसी चीज से पड़ा है, जिसके पास दुनियाभर की जानकारी है, लेकिन उस जानकारी को इस्तेमाल करने का तरीका हमें पता है। हमारे पास चाबी है उस डेटा को प्रॉसेस करने की, प्रॉम्प्ट की चाबी। इसमें इंसान और मशीन मिलकर कुछ नया बनाते हैं। हम अपने शब्दों से AI को दिशा देते हैं और वह हमारी सोच को अलग रूप में वापस देता है। यह संवाद उतना ही मजेदार और गहरा हो सकता है, जितना हम उसे बनाना चाहें। अगर हम सही तरह से सोचें और स्पष्ट प्रॉम्प्ट लिखें, तो AI हमें आश्चर्यजनक जवाब दे सकता है।

तो प्रॉम्प्ट कैसा होना चाहिए? AI से ही पूछ लिया जाए, 'अपने लिए प्रॉम्प्ट लिखने को कहा जाए तो कैसे लिखेंगे?' 'सरल और स्पष्ट भाषा में उत्तर दें। संवाद में सहानुभूति, समझ, और उपयोगकर्ता के लिए स्पष्टता होनी चाहिए।' है न बढ़िया जवाब!

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं **nbtreader@timesofindia.com** पर, और सब्जेक्ट में लिखें-**'जीवन आनंद'**

कैसी है मोसाद की ख़ुफ़िया दुनिया

मृत्युंजय राय

साल भर पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इस्राइल पर हवाई और जमीनी हमले किए थे, जिससे पश्चिम एशिया में अशांति का नया दौर शुरू हुआ। उसके बाद से इस्राइल गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ अभियान चला रहा है। हाल ही में उसने हिज्बुल्लाह चीफ की हत्या की। इसके बाद इस युद्ध में ईरान के सीधे कूदने का डर पैदा हो गया है। इस बीच, इस्राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की पेजर बम की नई कारगुजारी की चर्चा ने भी काफी जोर पकड़ा हुआ है। मोसाद ने पेजर बमों के जरिये लेबनान में ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया। इससे दुनिया दंग रह गई और इस घटना ने सुरक्षा को लेकर एक नई चुनौती खड़ी की है। पेजर बम की घटना के बाद यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या मोबाइल फोन में भी इस तरह के धमाके किए जा सकते हैं? खैर, पेजर बम धमाकों से मोसाद के कामकाज के तरीकों के बारे में लोगों की दिलचस्पी एक बार फिर से बढ़ गई है।

विचार विंडो

रोनेन बर्गमैन (Ronen Bergman) की किताब **Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations** इस्राइली खुफिया एजेंसी को समझने में बेहद मददगार हो सकती है। इस किताब को प्रामाणिक माना जाता है। इसे लिखा भी खूबसूरत अंदाज में गया है। साथ ही, 1949 में खुफिया एजेंसी की स्थापना के बाद स्टेट और नॉन-स्टेट एक्टर्स के खिलाफ इसकी कार्रवाई के बारे में किताब में दिलचस्प जानकारी दी गई है।

इस्राइली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रोनेन बर्गमैन ने मोसाद के द्वारा की गई हत्याओं के बारे में तो बताया ही है, लेकिन इसके साथ उन्होंने खुफिया एजेंसी के दूसरे अभियानों के बारे में भी जानकारी दी है। इसमें मोसाद के जासूस ईलाइ कोहेन (Eli Cohen) की कहानी भी है। वह इस्राइल के एक और दुश्मन देश सीरिया के पॉलिटिकल सर्कल में जगह बनाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन बाद में पकड़े गए और दमस्कस के सेंट्रल स्क्वेयर पर उन्हें फांसी दे दी गई। रोनेन बर्गमैन ने इस पूरे वाकये के बारे में अपनी किताब में तफसील से जानकारी दी है। यही नहीं, उन्होंने मोसाद की ओर से जो हत्याएं की गईं, उनके बारे में भी बताया है। इससे रीडर्स को एजेंसी के कामकाज की शैली के साथ यह भी पता चलता है कि उसने कोई कदम क्यों उठाया। रोनेन बर्गमैन ने किताब में 1979 में अली सलामे की मोसाद की ओर से की गई हत्या के बारे में भी लिखा है। अली पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (PLO) का ऑपरेटिव था। बर्गमैन लिखते हैं कि पहले मोसाद ने सोचा कि अली के टूथपेस्ट या आफ्टरशेव में जहर डालकर उसकी हत्या की जाए, लेकिन फिर उसने यह प्लान बदल दिया। अली जब बेरूत की सड़कों पर निकला हुआ था, तब धमाका कर मोसाद ने उसकी हत्या की। इस हमले में अली के कई बॉडीगार्ड भी मारे गए।

अगर यह सब पढ़कर आपको लग रहा है कि बर्गमैन ने मोसाद की प्रशंसा की है तो आप गलत समझ रहे हैं। उन्होंने इस्राइल सरकार के कई कदमों के नैतिक और राजनीतिक परिणामों की भी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि कई बार इस्राइली खुफिया एजेंसी ने नतीजों की परवाह किए बिना ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। उनकी किताब पढ़कर यह भी समझ में आता है कि इस्राइली खुफिया इस्टैब्लिशमेंट में ऐसे ऑपरेशंस पर सर्वसम्मति नहीं होती थी। खासतौर पर मोसाद ने जो हत्याएं कीं, उन्हें लेकर राय बंटी हुई थी।

फैमिली प्लानिंग? शर्तें लागू

प्रणव प्रियदर्शी

दो देशों के बीच होने वाले युद्ध जान-माल का कितना नुकसान करते हैं और अर्थव्यवस्था को कैसे तबाह करते हैं, इस पर काफी चर्चा होती है, लेकिन जन जीवन के अलग-अलग पक्षों पर इनका कितना खामोश और गहरा असर होता है, इस तरफ अक्सर ध्यान नहीं जाता। मिसाल के तौर पर आधी आबादी की बात करें तो उनके मन-मिजाज और भविष्य के फैसलों को ही नहीं, अपने शरीर पर उनके अधिकार की अवधारणा को भी युद्ध अक्सर छिन्न-भिन्न कर देते हैं। इसका जीता-जाता सबूत रूस में दिखता है, जो राष्ट्रपति पूतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के फैसले की वजह से एक अंतहीन से लगते युद्ध में फंसा हुआ है।

AI Image

युद्ध का एक साइडइफेक्ट यह भी है कि सही, प्रामाणिक सूचनाओं का मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फिर भी, पश्चिमी मीडिया में आ रहे अनुमानों पर भरोसा करें तो रूस के 1000 जवान रोज मारे जा रहे हैं। तो रोज ऐसे 1000 परिवारों में जो रोना-पीटना मचता होगा, वह तो है ही, जिन लाखों परिवारों की महिलाएं अपने पतियों, बेटों या भाइयों की खबर जानने को मरी जा रही हैं, उन पर इन मौतों का क्या असर होता होगा। ऐसे माहौल में हुकूमत यह फरमान भी जारी कर रही है कि महिलाएं अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। कारण यह कि देश में टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR) यानी महिलाओं की बच्चे पैदा करने की औसत संख्या काफी कम है। हालांकि यह स्थिति रातोरात पैदा नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा हालात में समस्या ज्यादा गंभीर जरूर हो गई है। आलम यह है कि पिछले सप्ताह ही एक बिल लाया गया है, जिसके मुताबिक अगर किसी ने भी बच्चे न पैदा करने या कम पैदा करने वाली लाइफ स्टाइल के पक्ष में कोई बात कही तो उस पर 50,000 डॉलर तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक असुरक्षा से घिरी महिलाएं इत्मीनान से यह चर्चा भी नहीं कर सकतीं कि उन्हें शादी और बच्चे चाहिए या नहीं और चाहिए भी तो कब और कितने।

आधी दुनिया

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

स्कंदमाता मातृत्व की प्रतीक, लाती हैं समाज में संतुलन

दिलीप लाल

नवरात्रि के नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। ये नौ रूप हैं- शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंदमाता की पूजा होगी। स्कंदमाता दो शब्दों, 'स्कंद' और 'माता' से मिलकर बना है। भगवान स्कंद (कार्तिकेय) की माता होने के नाते इस देवी का नाम स्कंदमाता पड़ा।

मातृत्व, साहस, ज्ञान की प्रतीक दुर्गा के इस रूप को आदर्श देवी माना जाता है। स्कंदमाता संदेश देती हैं कि महिलाएं न केवल अपने परिवार का आधार हैं, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। स्कंदमाता की आराधना से हम अपने जीवन में शक्ति, साहस और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। माना जाता है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम हर कठिनाई का सामना करने की क्षमता पा जाते हैं। इससे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं।

ग्रंथों में स्कंदमाता का वर्णन एक सुंदर स्त्री के रूप में भी किया गया है, जो अपने पुत्र स्कंद को गोद में उठाए हुए हैं। उनका रंग दुधिया है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। स्कंदमाता चार भुजाओं वाली देवी हैं। वह अपने दो हाथों में कमल का फूल और त्रिशूल, जबकि दो हाथ अपने पुत्र स्कंद को धारण किए हुए हैं। उन्हें पद्मासना भी कहा गया है, जो बताता है कि वह कमल पर बैठी हैं। इस स्वरूप में उनकी कृपा से भक्तों को अद्भुत शक्ति और साहस प्राप्त होता है।

स्कंदमाता का रूप मातृत्व का प्रतीक है। मातृत्व की भूमिका में, वह न केवल अपने पुत्र स्कंद की सुरक्षा करती हैं, बल्कि सभी बच्चों की माता के रूप में उनकी रक्षा करती हैं। वह हर माता के लिए एक आदर्श हैं, जो अपनी संतान के प्रति असीम प्रेम और दया का भाव रखती हैं। यह विशेषता उन्हें सबसे शुद्ध और दयालु देवी के रूप में प्रस्तुत करती है। ऐसा माना जाता है कि संतान सुख की कामना करने वालों पर स्कंदमाता अपनी कृपा बरसाती हैं। सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए, वह भक्तों के जीवन में संतोष और समृद्धि लाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि 'ॐ दुम दुर्गायै नमः' मंत्र का जाप करने वाले भक्तों को स्कंदमाता मानसिक शांति और आशीर्वाद प्रदान करती हैं।

स्कंदमाता का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह समाज में भी है। मातृत्व का प्रतीक होने के नाते, वह समाज में संतुलन बनाए रखती हैं। देवी का यह स्वरूप बताता है कि मातृत्व में कितनी शक्ति है, वह प्रेम से भरी हैं तो आवश्यकता पड़ने में शत्रुओं का संहार भी कर सकती हैं। स्कंदमाता की पूजा न केवल आध्यात्मिक रूप से हमें मजबूत बनाती है, बल्कि सामाजिक जीवन में भी संतुलन स्थापित होती है। वह संदेश देती हैं कि महिलाएं अपने परिवार का आधार हैं। साथ ही, समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। स्कंदमाता के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव रखकर हम अपने जीवन को और भी उज्ज्वल बना सकते हैं। हृदय में स्कंदमाता का स्थान होना यह बताता है कि स्त्री के प्रति हमारा कितना सम्मान है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ मन में बसी सुंदरता

30 सितंबर को 'जीवन आनंद' कॉलम में 'अधूरेपन में सुंदरता? Wabi-Sabi से समझिए' लेख पढ़ा। जो व्यक्ति चेहरे से सुंदर हो और दिल से कुरूप उसकी संगति कभी नहीं करनी चाहिए। जिंदगी के मजे दिल से कुरूप लोग खराब करते हैं। देखा जाए तो फैशन ने लोगों को भरमाया है। पर क्या करें, फैशन युग जो आ गया है। खैर फैशन का प्रभाव हो या उससे किसी हद तक बचे हुए लोग हों, सुंदरता तलाशने का सबका अपना-अपना नजरिया है। चेहरे की सुंदरता तो टिकने वाली नहीं है। इसलिए प्रयास हो कि मन की सुंदरता निखारी जाए।

राजेश कुमार चौहान, ईमेल से

■ अपना-अपना नजरिया

यह पत्र 30 सितंबर को 'अधूरेपन में सुंदरता? Wabi-Sabi से समझिए' शीर्षक से प्रकाशित लेख से संबंधित है। यह लेख पढ़ने के बाद पहली बार जानने को मिला कि यह शब्द अपने अंदर कितनी गंभीरता छिपाए हुए है। Wabi-Sabi जापानी शब्द है और यह वहां की कला की सुंदरता के मायने बताता है। किसी चीज को देखने का एक ही नजरिया नहीं होता। प्रकृति में मौजूद कई चीजें अधूरी नजर आती हैं, फिर भी उनकी सुंदरता कम नहीं होती। जैसे आसमान में दिख रहे बेतरतीब बादल भी ऐसा ही उदाहरण हैं।

नीतू रावत, नोएडा

जीवन आनंद

■ इंतजार का मजा

इंतजार अक्सर एक चुनौती लगती है, लेकिन इसमें आनंद का भी एक अनोखा पहलू छिपा होता है। प्रियजनों का आना या छुट्टियों की योजनाएं बनाना हमारी आशा और उत्साह को पंख लगा देते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव है, जिसमें हम अपने मन में संभावनाओं की तस्वीरें बनाते हैं। इंतजार हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देने का मौका देता है। यह धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। यह हमें अपने जीवन के छोटे-छोटे पलों का मूल्य समझने में मदद करता है।

यश झा, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

भारत से मॉनसून की विदाई में तेजी

– एक खबर

– मेरे अंगने में अब मॉनसून का क्या काम है!

प्रवीण कुमार

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.

संपादक (दिल्

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 7 अक्टूबर • 2024
www.rashtriyasahara.com

नतीजों की झलक

जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में तथा हरियाणा में सभी सीटों में मतदान संपन्न होते ही एक्जिट पोल के परिणाम आने चालू हो गए। दोनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। अलग-अलग संस्थानों द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है जबकि अधिकतर एक्जिट पोल ने जम्मू-कश्मीर में खंडित जनादेश का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू-कश्मीर की सभी 90 और हरियाणा की सभी 90 सीटों पर हुए मतदान के नतीजों का देश भर को बेसब्री से इंतजार है। इंडिया टुडे-सी वोटर एक्जिट पोल के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में भाजपा को 27 से 32 सीटें मिल सकती हैं जबकि कांग्रेस और

नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 40 से 48 सीटों पर जीत मिल सकती है। पीपडीपी को 6 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। एक हिन्दी अखबार के सर्वे में कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 35 से 40 जबकि भाजपा को 20से 25 सीटें दी गई हैं। पीडीपी को सिर्फ 4 से 7 सीटें मिलते बताया गया है। इंडिया टुडे-सी वोटर के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस को 50 से 58, भाजपा को 20 से 28 सीटें मिलती दिख रही हैं। एक अन्य सर्वे में कांग्रेस को 44 से 54 तो भाजपा को 19 से 29 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एक्जिट पोल कराने वाली एजेंसियों द्वारा पोलिंग बूथों के पास खड़े किए गये सदस्य वोट देकर निकलते वोटर से पूछते हैं, उन्होंने किसे वोट दिया। इसी जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर किए गए विश्लेषण पर ये नतीजे निकाले जाते हैं। इन्हें प्रसारित करने से पूर्व चुनाव आयोग से अनुमति भी लेनी होती है। हालांकि कई बार ये पोल बिल्कुल गलत भी सीबित होते हैं। मगर लोग इन्हें भरपूर उत्साह से देखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्बदुल्ला ने इन एक्जिट पोल के नतीजों को खारिज करते हुए इन्हें टाइमपास कहा। चूंकि आम आदमी पार्टी ने भी इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, इसलिए एक्जिट पोल के नतीजों को लेकर पार्टी काफी नाखुश है। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी के कारण हरियाणा में भाजपा को करारा झटका लगना तय है। उधर, जम्मू-कश्मीर की जनता केंद्र के रवैये को लेकर पहले ही असंतुष्ट है। इसलिए वहां विधानसभा में उसे विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। कुल मिला कर यह केवल एक्जिट पोल है, सारा दारोमदार असल नतीजों पर ही टिका है।

नक्सलियों का सफाया

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर-दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। शनिवार को अड़तालीस घंटे चले इस ऑपरेशन में 1500 से ज्यादा जवान शामिल थे। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहली बार है जब सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ स्थल बीहड़ में है, जहां पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल पर खेत और कच्चे रास्तों से होते हुए 10 से ज्यादा घंटे का समय लगता है। चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों और मानसून से जुड़ी

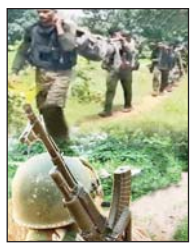

चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा बलों ने अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सफलता इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि मारे गए नक्सलियों में 16 वरिष्ठ हैं, जिन पर 1.30 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम था। इसलिए भी कि ये नक्सली माओवादियों के सबसे मजबूत संगठन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (डीकेएसजेडसी) से जुड़ी वरिष्ठ नक्सली नीति उर्फ उर्मिला भी मारी गई है, जिस पर 25 लाख का इनाम था। नक्सलियों के सफाये के लिए मोदी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। यही कारण है कि वामपंथी उग्रवाद अपनी अंतिम सांस गिनता दिखलाई पड़ रहा है। मोदी सरकार कह चुकी है कि मार्च, 2026 तक वह नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वह नक्सल प्रभावित राज्यों को इस समस्या से निपटने के लिए हर संभव सहायता मुहैया करा रही है। सोमवार सात अक्टूबर को भी केंद्रीय गृह मंत्री नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनके वहां सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इस तरह की समीक्षा बैठक इससे पहले 6 अक्टूबर, 2023 को की गई थी, जिसमें वामपंथी उग्रवाद को उखाड़ फेंकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए थे। इसी का परिणाम है कि 2024 में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ आशातीय सफलता मिली है। नक्सलियों की संख्या तेजी से कम हुई है, और बताया गया है कि उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या मात्र 38 रह गई है। दरअसल, नक्सल समस्या बहुआयामी है। कानून-व्यवस्था से भी ज्यादा इसके सामाजिक-आर्थिक आयाम महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार विकास कार्यों पर खासा बल दे रही है। सड़क नेटवर्क पर तरजीही आधार पर ध्यान दिया जा रहा है।

बाल यौन शोषण/ नीरज शर्मा 'भरथल'

सभ्य समाज पर कलंक

आमतौर पर देखा गया है बच्चों का यौन शोषण करने वाले उनके करीब के ही होते है। समाज में इस तरह के गुनाहों के शिकार बच्चों के माता-पिता लोकलाज के डर से इन घटनाओं को छुपा लेते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि इन घटानाओं को अंजाम देने वाले उन बच्चों के आसपास रहने वाले आम समाज में उठने बैठने वाले लोग या उनके रिश्तेदार ही होते हैं। इस तरह के हादसों के बाद रिश्ते तो टूटते ही हैं पर कई बार पूरी बात की जानकारी न होने के समाज पीड़ित पक्ष को ही दोषी बताने लगता है पर उन बातों की असलियत कुछ और होती है।

कुछ दिन पहले ऐसी ही एक घटना की जानकारी सामने आई। उस घटना में एक बहन ने अपने भाई पर पुश्तैनी जायदाद पाने के लिए केस कर दिया। समाज उस औरत को लालची बताने लगा परंतु इन सब के पीछे असलियत कुछ और थी। असल में उस औरत का भाई उसके बेटे को अपने कमरे में बुलाता था, उसके यौन अंग को छेड़ता और प्यार करता था। जब तक तो वो लड़का छोटा था उसने उस व्यक्ति के डर से यह बात किसी को नहीं बताई पर जब वो बड़ा हुआ और कमरे में जाने से इनकार करने लगा तब मां और नानी के पूछने पर उसने सारी बात का खुलासा किया। उसकी मां ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कराना चाहा तब समाज में बदनामी के डर से बच्चे की नानी के कहने पर उस औरत ने केस नहीं किया, मगर अपने भाई से रिश्ते खत्म कर लिए। ऐसी बहुत सी घटनाए हैं जो कभी सामने नहीं आती और गुनहगार खुलेआम घूमता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के शोषण एवं ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन बनाने की घोषणा की थी। मंत्रालय का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी व्यापक प्रणाली का विकास करना है, जिसमें बच्चों के माता-पिता, स्कूलों, समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय सरकारों के साथ-साथ पुलिस व वकीलों को भी शामिल किया जाना है। किंतु इतने कानून एवं योजनाओं के बावजूद इनकी तकनीकी चूक तथा इनके कार्यान्वयन में अनियमितता, त्वरित कार्रवाई न होने के कारण ये घटनाएं होती हैं। इसके लिए जरूरी है सजगता एवं जागरूकता। ऐसे में जरूरी है कि प्राथमिक स्तर पर घर-परिवार, माता-पिता एवं परिजन बच्चों से मिलने वालों एवं उनके साथ खेलने वालों के प्रति सजग रहें वहीं बच्चों को भी असामान्य व्यवहार के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए,।

सांच पर आंच का साया

दूध और दूध से बने पदार्थ

विनीत नारायण

अमेरिका में हमारे एक शुभचिंतक सतीश जी हैं, जिन्होंने मुंबई आईआईटी से पढ़ाई करके अमेरिका में अपार धन कमाया पर वे अत्यंत धार्मिक हैं, और शास्त्रों में पारंगत भी। उन्होंने गौवंश की सेवा के लिए ब्रज की एक गौशाला को 800 करोड़ रुपये दान दिया था पर अब वो गोरस (दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर आदि) के दैनिक जीवन में उपभोग के घोर विरोधी हो गए हैं, और उस गौशाला को भी दान देना बंद कर दिया है। पिछले हफ्ते मेरी उनसे बीस बरस बाद टेलीफोन पर बात हुई तो उन्होंने मुझसे जोर देकर कहा, 'मैं और मेरा परिवार गोरस का उपभोग तुरंत बंद कर दें और 'वीगन' बन जाएं।' आज दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो वीगन बन चुके हैं यानी पशु आधारित किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करते। मतलब डेयरी और मीट उत्पाद उनके भोजन से दूर जा चुके हैं।

मैं सतीश जी के जीवन की पवित्रता, आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृत में संभाषण करने की क्षमता और धर्मार्थ कार्यों में उदारता से दान देने की प्रवृत्ति का सम्मान करता हूं पर उनकी यह सलाह मेरे गले नहीं उतरी। मुरलीधर गोपाल के भक्त हम सब ब्रजवासी गोरस को अपने दैनिक जीवन से भला कैसे दूर कर सकते हैं? कल्पना कीजिए, आपको गर्म दूध, ठंडी लस्सी, पेड़े, गोघृत में चुपड़ी रोटी और नमक-जीरे की छौंक लगी छाछ या मलाईदार कुल्फी के सेवन से अगर अचानक वंचित कर दिया जाए तो हम ब्रजवासी जल बिन मछली की तरह तड़प जाएंगे।

हम ही क्यों, बाहर से श्रीवृंदावन बिहारी के दर्शन करने आने वाले करोड़ों भक्त, दर्शन करने के बाद सबसे पहले कुल्हड़ की लस्सी और वृंदावन के पेड़ों पर ही तो टूट कर पड़ते हैं। अगर उन्हें ये ही नहीं मिलेगा और ठाकुर जी की प्रसादी माखन मिश्री नहीं मिलेगी तो क्या ब्रज आने का उनका उत्साह आधा नहीं रह जाएगा? पर सतीश जी का तर्क भी बहुत वजनदार है। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं ओटीटी प्लेटफार्म पर जा कर एक फिल्म 'मां का दूध' अवश्य देखूं। ढाई घंटे की यह फिल्म बहुत गहन शोध और मेहनत से बनाई गई है। इसे देखने वाले का कलेजा कांप उठेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को देखने से पता चलता है कि दूध के नाम पर अपने को शाकाहारी और सात्विक मानने वाले हम लोग भी, जाने-अनजाने ही पशु हिंसा के भयंकर पाप कर्म में लिप्त हो रहे हैं। यह फिल्म हम सब की आंखें खोल देती है, यह बता कर कि हम पढ़े-लिखे लोग भी किस तरह अपनी अज्ञानता के कारण अपने भोजन में नित्य जहर खा रहे हैं। आज महामारी की तरह फैलता कैंसर रोग इसका एक प्रमाण है। मैंने सतीश जी के कहने पर अभी गोरस का प्रयोग बंद नहीं किया है पर फिल्म

देखने के बाद मैंने उनसे कहा कि उनकी बात में बहुत वजन है। पर यह भी कहा कि सदियों का अभ्यास क्षणों में आसानी से छोड़ा नहीं जाता। यहां आपके मन में प्रश्न उठेगा कि गोरस और शाकाहार करने वाले लोग पशु हत्या के पाप में कैसे लिप्त हो सकते हैं?

इस फिल्म को देखने से पता चलता है कि दूध के लालच में बिना दूध देने वाली करोड़ों गायों और उनके बछड़ों को रोज कत्ल किया जा रहा है, और उनके मांस का व्यापार अन्य देशों की तुलना में तपोभूमि भारत में सबसे ज्यादा हो रहा है। जब भगवान श्रीकृष्ण-बलराम गायों को चराते थे तब भारत की अर्थव्यवस्था गोवंश और कृषि पर आधारित थी। गऊ माता के दूध, गोबर और मूत्र से हमारा शरीर और पर्यावरण पुष्ट होता था और बैल कृषि के काम आते थे। दूध न देने वाली बूढ़ी गाय और हल में न जुत सकने वाले बैल कसाईखाने को नहीं बेचे जाते थे, बल्कि परिवार के बुजुर्गों की तरह उनकी घर पर ही आजीवन सेवा होती थी। उनकी मृत्यु पर परिवार में ऐसे ही शोक मनाया जाता था जैसे परिवार के मुखिया के मरने पर मनाया जाता है।

पिछले दशकों में आधुनिक खेती के नाम पर खनिज, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक उपकरणों को भारतीय किसानों पर क्रमशः थोप दिया गया। नतीजतन, किसान की भूमि की उर्वरता, उसके परिवार का स्वास्थ्य, उसकी आर्थिक स्थिति और उसके परिवेश पर ग्रहण लग गया। इस तथाकथित विकसित कृषि ने उसे कहीं का न छोड़ा। यह मत सोचिएगा कि इस सबका असर केवल किसानों के परिवार पर ही पड़ा है, बल्कि आप और हम भी इस दुश्चक्र में फंस कर स्वस्थ जीवन जीने की संभावना से हर दिन दूर होते जा रहे हैं।

क्या आप जानते हैं कि भारत में रोजाना मात्र 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है जबकि भारत में हर दिन 64 करोड़ लीटर दूध और उससे बने पदार्थों की खपत होती है। यह खपत 50 करोड़ लीटर नकली सिंथेटिक दूध बना कर ही पूरी की जाती है। गोपाल की लीलाभूमि ब्रज तक में नकली दूध का कारोबार खुलेआम धड़ल्ले से किया जा रहा है। कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है। इस तरह दूध के नाम पर हम सब अपने परिवार को जहर खिला रहे हैं। मूल प्रश्न पर लौटें, गौ रस पान से हिंसा कैसे होती है? जब केवल दूध की चाहत है तो दूध देना बंद करने वाली गायों को कसाईखाने में कटने के लिए भेज दिया जाता है। इसी तरह जब खेती में बैल की जगह ट्रैक्टर जुतने लगे तो बछड़े और बैल का धड़ल्ले से उपयोग मांस के व्यापार के लिए होने लगा है। इस तरह उनकी हत्या के लिए हम सब भी अपराधी हैं। इस गंभीर विषय को पूरी तरह समझने के लिए आप 'मां का दूध' फिल्म जरूर देखिएगा। यह गंभीर चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। मैंने सतीश जी को आश्वासन दिया है कि इस गंभीर विषय पर मैं अभी और शोध करूंगा और इसके हल का अपने जीवन में हम क्या विकल्प सोच सकते हैं, इस पर भी अनुभवी लोगों से प्रश्न पूछूंगा, तभी कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में पहुंच पाऊंगा। पाठक भी इस विषय पर गहरी जांच करें।

(लेखक के निजी विचार हैं)

> क्या आप जानते हैं कि भारत में रोजाना मात्र 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है जबकि हर दिन 64 करोड़ लीटर दूध और उससे बने पदार्थों की खपत होती है। यह खपत 50 करोड़ लीटर नकली सिंथेटिक दूध बना कर ही पूरी की जाती है। गोपाल की लीलाभूमि ब्रज तक में नकली दूध का कारोबार खुलेआम धड़ल्ले से किया जा रहा है। कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है। इस तरह दूध के नाम पर हम सब अपने परिवार को जहर खिला रहे हैं

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जुबान पर छाता जा रहा है

काला नमक धान का चावल

- अपनी खास सुगंध, स्वाद और भरपूर पोषण के दम पर काला नमक धान का चावल देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी लोगों की जुबान पर छा रहा है
- उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे सिद्धार्थनगर का 'एक जिला एक उत्पादन' (ओडीओपी) घोषित किया है। इसलिए इसे जीआई टैग हासिल है, और जिसके चलते यह बासमती को टक्कर दे सकता है
- काला नमक धान को भगवान बुद्ध का प्रसाद माना जाता है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

पाकिस्तान में एससीओ बैठक में विदेश मंत्री को भेजने का मोदी सरकार का फैसला हैरत भरा है। इसलिए कि बीते माह इस्लामाबाद में एससीओ व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत शामिल नहीं हुआ था। भारत 15-16 अक्टूबर की बैठक में राज्यमंत्री को भेज सकता था। विदेश मंत्री के जाने से संकेत जा रहा है कि एससीओ के मुख्य आयोजन से इतर अन्य मेहमानों से दुतरफा मसलों पर भी बैठकें हो सकती हैं।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

वैधानिक नियंत्रण और संतुलन

क्रिप्टो करंसी | **संजीव ठाकुर**

आज का युग तकनीकी तथा नवाचार का युग है। तकनीकी परिवर्तन ने क्रिप्टो करंसी के रूप में एक नया अध्याय विकासशील देशों के सामने खोल कर रख दिया है। भारत जैसे विकासशील देश में बड़ी संख्या में नागरिकों को इंटरनेट और मोबाइल के संपूर्ण ज्ञान की ही समझ-परख नहीं है, ऐसे में क्रिप्टो करंसी का मायाजाल अबूझ पहेली बन कर सामने आया है।

क्रिप्टो करंसी के सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू में बहुत सारे लाभ हैं, और दूसरे में आर्थिक संदर्भ में चुनौतियां या सुरक्षा अंतर्निहित हैं। क्रिप्टो करंसी डिजिटल मुद्रा है, जिसे न तो देखा जा सकता है, न ही मुद्रा की भांति जेब या पर्स में रखा जा सकता है, क्योंकि इसकी हार्ड कॉपी या मुद्रित रूप उपलब्ध ही नहीं है। भौतिक रूप से उपलब्ध न होने के कारण इसे आभासी मुद्रा कहा जाता है। यह स्वतंत्र किस्म की मुद्रा है। इसका संचालन-नियमन किसी संस्था या सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। इसे विकेंद्रीकृत मुद्रा भी कहा जाता है। यह ऐसी मुद्रा है जिसे कंप्यूटर एल्गोरिथ्म के आधार पर बनाया जाता है। कंप्यूटर में ही देखा, गिना और भुगतान किया जा सकता है।

विश्व में सबसे पहली क्रिप्टो करंसी 2009 में जापान के नाकमोतो द्वारा बनाई गई थी। वर्तमान में बाजार में 1500 से भी ज्यादा क्रिप्टो करंसी उपलब्ध हैं। क्रिप्टो करंसी काफी लोकप्रिय होती जा रही है। लोकप्रियता का एक कारण यह भी है कि यह गोपनीयता बनाए रखने में सहायक होती है, लेन-देन में छद्म नाम एवं पहचान बनाई जाती है। ऐसे में निजता तो लेकर अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तियों को यह व्यवस्था उपयुक्त लगती है। इसके लेन-देन में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी आर्थिक बोझ कम पड़ता है जिसके लेन-देन में थर्ड पार्टी के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। लेन-देन में समय तथा धन की बहुत ज्यादा बचत होती है। सामान्य बैंक खातों की तरह इसमें किसी प्रकार के कागजात की आवश्यकता भी नहीं होती। बैंकिंग प्रणाली तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लेन-देन पर सरकार का कड़ा नियंत्रण होता है, जबकि यह राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम के प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर होने कारण लेन-

देन के आदान-प्रदान का विश्वसनीय एवं सुरक्षित माध्यम बन कर उभरी है। सरकार के पास बैंक खाते को जब्त करने का अधिकार होता है जबकि क्रिप्टो करंसी के मामले में वह ऐसा नहीं कर सकती। नोटबंदी एवं मुद्रा के अवमूल्यन का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

क्रिप्टो करंसी सीमाओं से परे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही कम लागत पर एक देश से दूसरे देश को पैसा भेजने के लिए सुगम साधन बन चुकी है। 2009 में बिटकॉइन क्रिप्टो करंसी की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में एक बिलियन बिटकॉइन इंटरनेट के नेटवर्क में समाहित हैं तथा नये बिटकॉइन का लगातार आगमन हो रहा है। प्रत्येक बिटकॉइन का मूल्य 500 रुपये है, जो दुनिया की सबसे महंगी करंसी मानी जाती है। कुछ लोग इसे गोल्डरश के नाम से भी पुकारते हैं। 2014 से माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सेवाओं के लिए बिटकॉइन के रूप में भुगतान लेना शुरू कर दिया। निकोसिया विश्वविद्यालय भी विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क के रूप में बिटकॉइन करंसी स्वीकार करता है। 2018 प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीप क्रिप्टो करंसी के लीगल टेंडर को मान्यता देने वाला पहला देश है। वेनेजुएला ने भी क्रिप्टो करंसी की तर्ज पर पेट्रो नामक करंसी प्रारंभ की है ऐसा करने वाला विश्व का वह पहला संप्रभुता वाला देश है।

कई देशों में इसे आर्थिक संकट से उबारने वाले उपाय की तरह देखा जा रहा है। कई देश इसकी पारदर्शिता तथा विधि स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं। कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, इसे मान्यता प्रदान नहीं की है। भारत ने भी अभी इसे मान्यता प्रदान नहीं की है। भारतीय संदर्भ में आभासी मुद्रा में उच्च स्तर की अनिश्चितता के कारण सरकार का दृष्टिकोण प्रतिबंधात्मक रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1913 में पहली बार इस संदर्भ में चेतावनी जारी की थी। 2017 में रिजर्व बैंक ने जनता को आगाह कर क्रिप्टो करंसी से सावधान रहने को कहा। रिजर्व बैंक ने किसी प्रकार की क्रिप्टो करंसी को मान्यता प्राधिकार या लाइसेंस नहीं दिया है। क्रिप्टो करंसी पर प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 के ड्राफ्ट में प्रस्ताव दिया गया है कि देश में क्रिप्टो करंसी की खरीद-बिक्री करने वालों को 10 वर्ष की जेल की सजा होगी। क्रिप्टो करंसी काले धन को छुपाने का बड़ा जरिया भी हो सकती है। इस करंसी की सबसे बड़ी हानि यह है कि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसका मुद्रण नहीं किया जा सकता। इस कारण इसका प्रयोग अवैध कार्यों के लिए जैसे अवैध हथियार खरीदी, मादक पदार्थों के व्यापार, आतंकवादी गतिविधियों में मनी लॉन्ड्रिंग आदी में किए जाने की आशंका बढ़ जाती है। अतः इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

प्रकृति की भाषा | **श्रीराम शर्मा आचार्य**

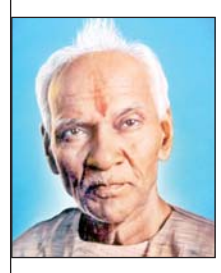

वनों में कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं, जो अपनी सीमा में छोटे-छोटे पौधों को पनपने नहीं देते हैं, सारे जंगल में दो-चार ऐसे हिंसक जंतु भी होते हैं, जो छोटे-छोटे जीव-जंतुओं को खा डालते हैं, अफ्रीका के कुछ पौधे ऐसे धोखेबाज होते हैं कि उनमें कोई चिड़िया आश्रय के लिए आई और उन्होंने अपने नुकीले पत्तों से उसे जकड़ कर उसका खून पी लिया। समुद्र में एक-दो मछलियां, एक-दो जंतु जैसे मगर और घड़ियाल ऐसे भी होते हैं, जो किसी का पनपना देख नहीं सकते, अपने से कम शक्ति का जो भी दांव में आ गया, उसी को चट कर लिया। विविधा-विपुला प्रकृति में ऐसे दुष्ट प्रकृति के जीव-जंतु हैं, तो पर उनकी संख्या उनका औसत थोड़ा है पर मनुष्य जाति के दृष्टि-दोष को क्या कहा जाए, जिसने इन दो-चार उदाहरणों को लेकर 'उपयोगितावाद' जैसा मूर्खतापूर्ण सिद्धांत ही तैयार कर दिया। ढूंढ़ें तो अधिकांश संसार 'आओ हम सब मिल कर जिएं' के सिद्धांत पर फल-फूल रहा है। यदि छोटों को मार कर खा जाने वाली बात ही सत्य रही होती तो कुछ ही शताब्दियों में विश्व की आबादी दो गुनी से भी अधिक न हो गई होती। प्रस्तुत प्रसंग बताता है कि संसार के बुद्धिमान न समझे जाने वाले जीव-जंतु भी परस्पर मिल कर रहना कल्याणकारक मानते हैं। जंगल की नदियों में रोडियश नामक मछली पाई जाती है, साथ ही 'सीप' नामक जीव भी पाया जाता है। सीप के शरीर को कछुये की तरह का मोटा और कड़ा आवरण घेर कर रखता है, जिससे वह अपने अंडों की सेवा नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में रोडियश मछली और सीप दोनों मिलते हैं, और 'आओ हम-आप दोनों मिल कर जिएं' के अनुसार समझौता कर लेते हैं। रोडियश अपने अंडे सीप के खोल में प्रविष्ट कर देती है, इसी समय सीप अंडे देती है, वह रोडियश उसे अपने शरीर से चिपका लेती है। रोडियश घूम-घूमकर अपने लिए भोजन इकट्ठा करती है, उसी के दाने-चारे पर सीप के बच्चे पल जाते हैं, जबकि उसके अपने बच्चों को सीप पाल देती है। विभिन्न जातियों में सहयोग और संगठन की आचार संहिता से लगता है, भारतीय समाज शास्त्रियों ने प्रकृति की इस मूक भाषा को पढ़ कर ही तैयार किया था। आज भी उसका मूल्य और महत्त्व सामाजिक जीवन में उतना ही है। इस सिद्धांत के आधार पर ही संसार सुखी रह सकता है।

रीडर्स मेल

नवरात्रि नारी सम्मान की प्रतीक

सामान्य जीवन में लोग घंटे-दो घंटे भूखे रहने पर परेशान हो जाते हैं, क्षुधा तृप्ति के लिए प्रयास करने लगते हैं। एक दिन का भोजन नहीं मिले तो लगता है कि जीवन कैसे चलेगा, लेकिन नवरात्रि के नौ दिनों में उपवास की जो प्रक्रिया चलती है, वह अपने आप में मिसाल है। उपवास का स्वरूप भारतीय संस्कृति की विशालता को दर्शाता है। उपवास की प्रक्रिया शारीरिक-मानसिक, दोनों प्रकार की शुद्धि की वाहक बनती है। कुछ लोग भक्ति भाव में इतने अधिक समर्पित हो जाते हैं कि सिर्फ फल खाकर 9 दिन तक रह जाते हैं। कुछ भक्त तो सिर्फ जूस पीकर रह जाते हैं। यह दर्शाता है कि इस संसार पर सिर्फ व्यक्ति का ही नियंत्रण नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी सर्वोच्च शक्ति भी है, जो मानव मन और तन को नियंत्रित करती है। इस तरह की भक्ति भावना चिरकाल से हमारी भारतीय संस्कृति रही है। साथ ही साथ यह भी सत्य है कि उपवास करने की पारिवारिक-सामाजिक व्यवस्था में पुरु षों से ज्यादा महिलाएं आगे रहती हैं। हमारी संस्कृति में नवरात्रि के माहौल में कन्या को देवी समझ पूजा जाता है। कहीं न कहीं, नवरात्रि स्त्री के सम्मान की प्रतीक है।

डॉ. मिथिलेश कुमार, भागलपुर

गरीबी उन्मूलन में सहायक कपास

कपास के इस्तेमाल में बढ़ोतरी लाने एवं गरीबी उन्मूलन में इसकी भूमिका को बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपासोत्पादक देश है। कपास की सुविधा, सुंदरता और टिकाऊपन इसे दुनिया का सबसे पसंदीदा प्राकृतिक रेशा बनाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मुलायम, मुलायम स्टेपल फाइबर कपड़ों, वस्त्रों, बिस्तर और कई अन्य उत्पादों के लिए एक आदर्श विकल्प है। कपास से निर्मित वस्त्र को सूती वस्त्र कहते हैं। सूती वस्त्र इस्तेमाल में बेहद आरामदायक होता है, और इनमें पसीना भी कम निकलता है। आज सूती वस्त्र पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। कपास की खेती गरीबी उन्मूलन में सहायक सिद्ध हो रही है। कपास दिवस पर कपास की खेती में लगे किसानों को उचित सम्मान एवं उचित मजदूरी दिलाना है।

हिमांशु शेखर, गया

हॉकी को प्रोत्साहन सराहनीय

यह एक स्पष्ट तथ्य है कि भारत का राष्ट्रीय खेल 'हॉकी' लोकप्रिय होने के बावजूद प्रसिद्धि, समृद्धि और आयोजक की पहली पसंद अभी भी नहीं बन पाया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि सात वर्ष के अंतराल के बाद हॉकी इंडिया लीग का आयोजन रांची एवं भुवनेश्वर में किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा पुरु ष हॉकी और महिला हॉकी के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से सुशोभित टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। नीलामी के लिए इन खिलाड़ियों की बेस बोली 2 लाख से 10 लाख तक रखी गई है जबकि क्रिकेट में यह करोड़ों रुपये में जाती है। यह भी विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। हम अपेक्षा कर सकते हैं कि इस तरह के आयोजन से भारत की हॉकी घर-घर तक पहुंचेगी और प्रायोजक भी आकृष्ट होगा। हॉकी महिला और पुरुष खिलाड़ी आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगे। इन आयोजनों के बाद हम अपेक्षा करते हैं कि भारतीय हॉकी संघ मजबूत होगा और ओलंपिक एवं विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी जी जान से खेलेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। **समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*** ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, **फैक्स** - 23352370, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स** - 2550750

वर्ष-34, अंक 54 — आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026 — *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी
संपादकीय
संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

क्या बर्फ पिघलेगी?

भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव की स्थिति के कारण दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध न के बराबर हैं। दोनों के रिश्तों पर आतंकवादी हिंसा ने ऐसी बर्फ जमा दी है कि वह पिघलने का नाम नहीं ले रही। जब दुनिया के कई देश इस समय युद्ध में उलझे हुए हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के पाकिस्तान यात्रा पर जाने के फैसले का ऐलान करने से एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या दोनों देशों के संबंधों पर जमीं बर्फ पिघलेगी। 9 वर्ष पहले 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने इस्लामाबाद पहुंची थी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं न कि कोई द्विपक्षीय बातचीत करने। पिछले साल पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो भी भारत आए थे। तब उन्होंने गोवा में ऐसे बयान दिए थे जिनसे संबंधों को सामान्य बनाने की कोई पहल नजर नहीं आई थी। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारत से संबंधों को मधुर बनाने की समर्थक रही है लेकिन बिलावल भुट्टो की टिप्पणियों ने भारत को नाराज कर दिया था। बिलावल भुट्टो भी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए गोवा आए थे। विदेश मंत्री ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान पर यह कहते हुए हमला भी बोला कि कुछ वर्षों से दक्षेस की कोई बैठक नहीं हुई है क्योंकि दक्षेस का सदस्य सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।

उन्होंने कहा कि अगर आप सभी एक साथ बैठ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और उसी समय इस तरह का आतंकवाद जारी है। यह वास्तव में हमारे लिए एक चुनौती है कि आप इसको अनदेखा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सार्क एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें भारत, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। एस.जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद ऐसी चीज है जो अस्वीकार्य है और वैश्विक नजरिए के बावजूद अगर हमारा कोई पड़ोसी ऐसा करना जारी रखता है तो उस पर रोक होनी चाहिए। यही वजह है कि हाल के सालों में दक्षेस की बैठक नहीं हुई है।

> **एससीओ एक बड़ा रणनीतिक मंच है और उसमें अपनी भूमिका को बनाए रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने को प्राथमिकता दी है और विदेश मंत्री ने मालदीव हो या श्रीलंका दोनों देशों से संबंधों को पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान से संबंध कायम करने के लिए शांति वार्ताएं नहीं की। प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी तो मैत्री बस लेकर लाहौर पहुंच गए थे। उधर लाहौर सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध की साजिश रच डाली थी। भारत क्या मुंबई बम धमाकों, मुंबई के आतंकवादी हमलों को भूल सकता है? पाकिस्तान ने हमें बहुत बड़े-बड़े जख्म दिए हैं।**

एस. जयशंकर के रुख से स्पष्ट है कि भारत की फिलहाल पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत का कोई इरादा नहीं है। भारत एससीओ के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाना चाहता है। इस समय एससीओ देशों में पूरी दुनिया की लगभग 40 फीसदी आबादी रहती है। पूरी दुनिया की जीडीपी में एससीओ की 20 फीसदी हिस्सेदारी है। दुनियाभर के तेल रिजर्व का 20 फीसदी हिस्सा इन्हीं देशों में है। भारत अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहता है कि वह एससीओ से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और अपने साकारात्मक एजैंडे के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे उसके संबंध पाकिस्तान और चीन से कैसे भी क्यों न हों। विदेश मंत्री एस. जयशंकर अनुभवी राजनायिक और नेता हैं और वह उसी के अनुरूप व्यवहार भी करते हैं। एससीओ एक बड़ा रणनीतिक मंच है और उसमें अपनी भूमिका को बनाए रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने को प्राथमिकता दी है और विदेश मंत्री ने मालदीव हो या श्रीलंका दोनों देशों से संबंधों को पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान से संबंध कायम करने के लिए शांति वार्ताएं नहीं की। प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी तो मैत्री बस लेकर लाहौर पहुंच गए थे।

उधर लाहौर सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध की साजिश रच डाली थी। भारत क्या मुंबई बम धमाकों, मुंबई के आतंकवादी हमलों को भूल सकता है? पाकिस्तान ने हमें बहुत बड़े-बड़े जख्म दिए हैं। पाक प्रायोजित आतंकवादियों ने हमारी संसद पर प्रहार किया तो कभी अक्षरधाम जैसे धर्म स्थलों पर भी निर्दोषों का खून बहाया। यद्यपि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर मुद्दा अब हाशिए पर जा चुका है और राज्य में शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया भी सम्पन्न हो चुकी है इसलिए पाकिस्तान को अब कश्मीर मुद्दे पर कोई समर्थन भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में वह कश्मीर मुद्दे का इस्तेमाल अपनी जनता को गुमराह करने के लिए ही कर रहा है। भारत सरकार का स्पष्ट स्टैंड है कि आतंकवाद और वार्ताएं साथ-साथ नहीं चल सकती।

पाकिस्तान के हालात इन दिनों बेहद खराब हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ खुले विद्रोह पर उतारू हैं। इमरान खान की पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है जिन्हें संभालना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो विदेश मंत्री एस. जयशंकर से अपनी पार्टी के विरोध-प्रदर्शनों में शामिल होने का न्यौता तक दे दिया है। ऐसी स्थिति में एस. जयशंकर के पाकिस्तान जाने पर कैसी प्रतिक्रिया होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल दोनों देशों के संबंधों को नरम बनाने के लिए किसी पहल की कोई उम्मीद नहीं है लेकिन कूटनीति के बहुत आयाम होते हैं। कूटनीति में दरवाजे हमेशा खुले रखे जाते हैं। अगर पाकिस्तान के भारत से रिश्ते अच्छे होते तो वह भारत से काफी फायदे उठा सकता था। अब दुनिया भारत और पाकिस्तान को एक नजरिए से नहीं देखती। भारत अब दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। दुनियाभर के निवेशक अब भारत को अपना आकर्षक स्थल मानते हैं। ऐसे में दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत ही सूक्ष्म कूटनीति अपनानी होगी। देखना होगा कि एस. जयशंकर के प्रति पाकिस्तान के हुक्मरानों का व्यवहार कैसा होगा।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

खो गई सच्ची खुशियां कहीं...

गीता पाढा

तमाम सफलताओं के बावजूद भी दिल में भरा शोर है,
खो गई सच्ची खुशियां कहीं, क्यों लिया उसने ये कदम कठोर है,
कैसे आएगी आज के युवा के अंधेरे जीवन में एक नई भोर है,
यहां फिर ऐसे ही छुटती रहेगी हाथों से जीवन की डोर है...!!

77 बरस से रोज़ का वीजा, रोज का परमिट

डा. चन्द्र त्रिखा
chandertrikha@gmail.com

यह विसंगति भी पिछले 77 बरस से जारी है। आज भी पंजाब के सीमावर्ती सैकड़ों किसानों को अपने खेत जोतने के लिए भारत-पाक सीमा पार करनी पड़ती है। वे लगभग हर रोज सीमा पर बीएसएफ अधिकारियों से अनुमति पत्र लेते हैं। उसी के आधार पर उन्हें सीमा पार से पाक रेंजर्स को भी पूर्व सूचना देनी होती है। यानि 77 बरस से हर रोज का वीज़ा। इन गंभीर समस्याओं पर न तो पंजाब की सरकार ने कभी ध्यान दिया, न केंद्रीय गृह मंत्रालय ने और न ही किसान संगठनों ने। वस्तुस्थिति यह है कि इन सीमावर्ती किसानों की ज़मीनें नदी पार के क्षेत्र में पड़ती हैं। यदि सतलुज में पानी ज्यादा हो तो नौकाओं का सहारा और यदि कम हो तो पैदल ही पानी से गुज़रना होता है। इनके लिए 'नो मैन्स लैंड' की परिभाषा भी पूरी तरह लागू नहीं होती।

ये किसान जिला फाजिल्का व जिला फिरोजपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। नदी पार की ज़मीनें इतनी ज्यादा नहीं हैं कि उनमें ही ये किसान अपनी 'ढाणियां' (खेत में घर) बना सकें। इन्हें सुबह-सुबह सूर्योदय से पहले या आसपास अपने कृषि मोर्चों की ओर कूच करना होता है और शाम धुंधलके से पहले ही वापिस लौटना होता है।

उसी बीच आपसी लोकगीतों का सिलसिला भी चलता है। इनमें से कुछ के गायन धूम मचा देने वाले हैं, मगर इन्हें कभी रिकार्ड ही नहीं किया जा सका। 'जीवे-पाकिस्तान' और 'जीवे हिन्दुस्तान', हीर रांझा, सस्सी-पुन्नू आदि की प्रेम गाथाएं गाई जाती हैं। अक्सर सीमा पर स्थित किसान आपस में आचार, प्याज, लस्सी, हरी व लाल मिर्च का चटखा भी बांट लेते हैं।

सीमा पार खेती को लेकर कुछ माह पूर्व भी किसानों की एक बैठक, सादगी चौकी (भारत-पाक सीमा- सुलेमान जिला फाजिल्का) पर बीएसएफ की 55वीं बटालियन के अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। किसानों की मांग थी कि सीमा पर स्थित कांटेदार तार को उन किसानों के लिए सुबह आठ बजे से सायं 6 बजे तक खोल दिया जाए ताकि सीमा पर स्थित लगभग दो दर्जन भारतीय गांवों के किसान नदी क्षेत्र पार करके अपने खेतों में फसलों की बिजाई व कटाई कर सकें।

अब इन किसानों का एक शिष्टमंडल केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बिश्वेश्वर से मिला है और उनसे अपील की है कि सीमा पार वाली उनकी ज़मीनें सरकार अधिग्रहित कर ले ताकि वे लोग संकटमुक्त हों। उनकी यह भी शिकायत है कि उनकी सीमा पार वाली फसलें, राडारों की फ्लैश-लाइट्स और यदा-कदा सतलुज में बाढ़ से वैसे भी बर्बाद हो जाती हैं। उन्हें मेहनत के चार पैसे मुआवजे के रूप में भी नहीं मिलते। मगर वे भूमिपुत्र हैं। आखिर धरती मां को छोड़ कैसे दें।

कुल मिलाकर 220 सीमावर्ती गांवों की 21600 एकड़ भूमि फाजिल्का-जलालाबाद-फिरोजपुर व कुछ अन्य सीमा क्षेत्रों पर इसी संकट से ग्रस्त है। बैंक भी इन किसानों को ज़मीनों की गारंटी पर कोई कर्ज नहीं देते। ऐसी स्थिति कहीं भी किसी भी देश में नहीं होती। मगर इनकी बात सही ढंग से सुनने के लिए न केंद्र सरकार तैयार है, न राज्य सरकार और न ही राजनेता लोग। उनका मुद्दा 77 वर्षों में एक बार भी लोकसभा या किसी विधानसभा में नहीं उठाया गया।

यहां यह भी बताना प्रासंगिक होगा कि भारत व पाकिस्तान सीमा के मध्य पक्की बाड़ लगाने का कार्य वर्ष 1988 और 1991 के मध्य ही पूरा हुआ था

और यह भी उन दिनों सम्पन्न हुआ जब पंजाब में आतंकवाद चरम सीमा पर था। मगर तब भी कुछ किसान ऐसे छूट गए थे जिनकी ज़मीनें इन बाड़दार-कंटीली तारों के दूसरी ओर रह गई थीं। इन किसानों से मुआवजे का वादा किया गया था मगर अभी तक यह वादा कागज़ों में ही दफन है।

ये विवाद केवल फाजिल्का, फिरोजपुर, जलालाबाद तक ही सीमित नहीं, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन व अमृतसर सीमा पर भी फैला हुआ है। सुखद यह है कि इन किसानों के लिए सहानुभूति का एहसास सीमा-स्थित पर पाक-रेंजर्स को भी है और बीएसएफ अधिकारियों को भी है। संबंधों में थोड़ी खटास 1965 व 1971 के भारत-पाक युद्धों के मध्य आई थी तब दोनों ओर सैन्य बलों को बारूदी-सुरंगें भी बिछानी पड़ी थी।

ये वही सीमा क्षेत्र हैं जहां अतीत में नूरजहां व लता मंगेशकर के मध्य दो बार 'नो मैन्स लैंड' स्थित स्थल पर भेंट भी कराई गई थी। वाघा-अटारी सीमा पर कैंडल मार्च का सिलसिला अब भी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को चलता है।

इन किसानों के लिए मीडिया में भी कोई खबरों के लिए न तो ज़्यादा टीआरपी मिल पाती है न ही प्रिंट मीडिया के एबीसी (ऑडिट ब्यूरो और सर्कूलेशन) में ही कोई फर्क पड़ता है।

यहां भारत-पाक सीमा की कुल लम्बाई पर भी नज़र डाल लेनी चाहिए। यह सरहद लगभग 3323 किलोमीटर तक फैली है और यह सीमा-रेखा पंजाब, राजस्थान, जम्मू और गुजरात के राज्यों से गुजरती है। इसी सीमा को रैडक्लिफ-रेखा कहा जाता है और यही वह सीमा है जिसे अंतिम रूप विभाजन के बाद 17 अगस्त, 1947 को ही दिया जा सका था। इसमें पंजाब राज्य से सटी सीमा की लम्बाई 425 किलोमीटर है। भारतीय-सीमा से पार पाकिस्तानी क्षेत्र के जिला बहावलपुर, जिला रहीम खान, डेरा गाज़ी खान, कोट अटू, जिला लय्याह, जिला मुजफ्फरगढ़, जिला चिनियोट, जिला फैसलाबाद, जिला झंग, जिला टोबा टेक सिंह, जिला गुजरांवाला, जिला सियालकोट, जिला गुजरात, जिला हाफिज़ाबाद, जिला वज़ीराबाद, जिला लाहौर, जिला ननकाना साहब, जिला कसूर, जिला खानेवाला, जिला मुल्तान, जिला अटक, जिला चकवाल, जिला रावलपिंडी, जिला ओकाड़ा, जिला पाकपटन, जिला साहीवाल, जिला मियांवाली, सरगोधा, भक्कर, खुशाब आदि कुल 41 जिले हैं।

फाजिल्का सीमावर्ती भारतीय किसानों की एक शिकायत यह भी है कि उनकी फसलों को प्राय: पाकिस्तानी क्षेत्रों से घुसने वाले सूअर खराब कर जाते हैं, मगर पाक रेंजर्स के लिए सूअर 'मुकद्दस' हैं। हमारे किसानों की यह भी शिकायत है कि उनके खेतों के लिए जल सिंचाई की 'बारी' पाकिस्तानी अधिकारियों के नियंत्रण में है। उन्हें 'बारी' तब मिलती है जब पानी सप्लाई का समय समाप्त होने वाला होता है। अब हमारे ये किसान जाएं कहां?

क्या गाय का दूध पीना बंद कर दें?

विनीत नारायण
www.vineetnarain.net

अमरीका में हमारे एक शुभचिंतक सतीश जी हैं। जिन्होंने मुंबई आईआईटी से पढ़ाई करके अमरीका में अपार धन कमाया । पर वे अत्यंत धार्मिक हैं और शास्त्रों में पारंगत हैं। उन्होंने गौवंश की सेवा के लिए ब्रज की एक गौशाला को 800 करोड़ रुपये दान दिया था। पर अब वो ग़ोरस (दूध, दहीं, छाछ, मक्खन, पनीर आदि) के दैनिक जीवन में उपभोग के घोर विरोधी हो गये हैं और उस गौशाला को भी दान देना बंद कर दिया है। पिछले हफ्ते मेरी उनसे बीस बरस बाद टेलीफोन पर बात हुई तो उन्होंने मुझसे ज़ोर देकर कहा कि मैं और मेरा परिवार गोरस का उपभोग तुरंत बंद कर दें और 'वीगन' बन जाएं। आज दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो वीगन बन चुके हैं। यानी वो पशु आधारित किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करते। मतलब डेरी और मीट उत्पाद उनके भोजन से दूर जा चुके हैं।

मैं सतीश जी के जीवन की पवित्रता, आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृत में संभाषण करने की क्षमता और धर्मार्थ कार्यों में उदारता से दान देने की प्रवृत्ति का सम्मान करता हूं। पर उनकी यह सलाह मेरे गले नहीं उतरी। मुरलीधर गोपाल के भक्त हम सब ब्रजवासी गोरस को अपने दैनिक जीवन से भला कैसे दूर कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आपको गर्म दूध, ठंडी लस्सी, पेड़े, गोघृत में चुपड़ी रोटी और नामक जीरे की छौंक लगी छाछ या मलाईदार क़ुल्फ़ी के सेवन से अगर अचानक वंचित कर दिया जाए तो हम ब्रजवासी जल बिन मछली की तरह तड़प जाएंगे। हम ही क्यों, बाहर से श्री वृंदावन बिहारी के दर्शन करने आने वाले करोड़ों भक्त, दर्शन करने के बाद सबसे पहले कुल्हड़ की लस्सी और वृंदावन के पेड़ों पर ही तो टूट कर पड़ते हैं। अगर उन्हें ये ही नहीं मिलेगा और ठाकुर जी की प्रसादी माखन मिश्री नहीं मिलेगी तो क्या ब्रज आने का उनका उत्साह आधा नहीं रह

जाएगा? पर सतीश जी का तर्क भी बहुत वज़नदार है।

उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं ओटीटी प्लेटफार्म पर जा कर एक फ़िल्म 'मां का दूध' अवश्य देखूं। ये ढाई घंटे की फ़िल्म बहुत गहन शोध और मेहनत से बनाई गई है। इसे देखने वाले का कलेजा कांप उठेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फ़िल्म को देखने से पता चलता है कि दूध के नाम पर अपने को शाकाहारी और सात्विक मानने वाले हम लोग भी, जाने-अनजाने ही पशु हिंसा के भयंकर पाप कर्म में लिप्त हो रहे हैं।

ये फ़िल्म हम सब की आंखें खोल देती है, ये बता कर कि हम पढ़े-लिखे लोग भी किस तरह अपनी अज्ञानता के कारण अपने भोजन में नित्य ज़हर खा रहे हैं। आज महामारी की तरह फैलता कैंसर रोग इसका एक प्रमाण है। मैंने सतीश जी के कहने पर अभी गोरस का प्रयोग बंद नहीं किया है। पर फ़िल्म देखने के बाद मैंने उनसे कहा कि उनकी बात में बहुत वज़न है। पर ये भी कहा कि सदियों का अभ्यास क्षणों में आसानी से छोड़ा नहीं जाता। यहां आपके मन में प्रश्न उठेगा कि गोरस और शाकाहार करने वाले लोग पशु हत्या के पाप में कैसे लिप्त हो सकते हैं?

इस फ़िल्म को देखने से पता चलता है कि दूध के लालच में बिना दूध देने वाली करोड़ों गायों और उनके बछड़ों को रोज़ क़त्ल किया जा रहा है और उनके मांस का व्यापार अन्य देशों की तुलना में तपोभूमि भारत में सबसे ज़्यादा हो रहा है। जब भगवान श्रीकृष्ण-बलराम गायों को चराते थे तब भारत की अर्थव्यवस्था गोवंश और कृषि पर आधारित थी। गऊ माता के दूध, गोबर और मूत्र से हमारा शरीर व पर्यावरण पुष्ट होता था और बैल कृषि के काम आते थे। दूध न देने वाली बूढ़ी गाय और हल में न जुत सकने वाले बैल कसाईखाने को नहीं बेचे जाते थे। बल्कि परिवार के बुज़ुर्गों की तरह उनकी घर पर ही आजीवन सेवा होती थी। उनकी मृत्यु पर परिवार में ऐसे ही शोक मनाया जाता था जैसे कि परिवार के मुखिया के मरने पर मनाया जाता है।

पिछले दशकों में आधुनिक खेती के नाम पर खनिज, उर्वरक, कीटनाशक, डीज़ल ट्रेक्टर और अन्य आधुनिक उपकरणों को भारतीय किसानों पर क्रमश: थोप दिया गया। नतीजतन किसान की भूमि उर्वरता, उसके परिवार का स्वास्थ्य, उसकी आर्थिक स्थिति और उसके परिवेश पर ग्रहण लग गया। इस तथाकथित विकसित कृषि ने उसे कहीं का न छोड़ा। ये मत सोचियेगा कि इस सबका असर केवल किसानों के परिवार पर ही पड़ा है। बल्कि आप और हम भी इस दुश्चक्र में फंस कर स्वस्थ जीवन जीने की संभावना से हर दिन दूर होते जा रहे हैं।

क्या आप जानते हैं कि भारत में रोज़ाना मात्र 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है। जबकि भारत में हर दिन 64 करोड़ लीटर दूध और उससे बने पदार्थों की खपत होती है। ये खपत 50 करोड़ लीटर नक़ली सिंथेटिक दूध बनाकर ही पूरी की जाती है। गोपाल की लीलाभूमि ब्रज तक में नक़ली दूध का कारोबार खुलेआम धड़ल्ले से किया जा रहा है। कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है। इस तरह दूध के नाम पर हम सब अपने परिवार को ज़हर खिला रहे हैं।

मूल प्रश्न पर लौटें, गौ रस पान से हिंसा कैसे होती है? जब केवल दूध की चाहत है तो दूध देना बंद करने वाली गायों को कसाईखाने में कटने के लिए भेज दिया जाता है। इसी तरह जब खेती में बैल की जगह ट्रेक्टर जुतने लगे तो बछड़े और बैल का धड़ल्ले से उपयोग मांस के व्यापार के लिए होने लगा है। इस तरह उनके हत्या के लिए हम सब भी अपराधी हैं। इस गंभीर विषय को पूरी तरह समझने के लिए आप 'माँ का दूध' फ़िल्म ज़रूर देखियेगा। ये गंभीर चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। मैंने सतीश जी को यह आश्वासन दिया है कि इस गंभीर विषय पर मैं अभी और शोध करूंगा और इस समस्या के हल का अपने जीवन में हम क्या विकल्प सोच सकते हैं इस पर भी अनुभवी लोगों से प्रश्न पूछूंगा, तभी कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में पहुंच पाऊंगा। पाठक भी इस विषय पर गहरी जांच करें।

बच्चों की जिज्ञासा : ब्रह्मांड का छोर कैसा दिखता है?

सात वर्ष की नन्हीं लिली का प्रश्न है कि ब्रह्मांड का छोर कैसा दिखाई देता है। यह बेहद दिलचस्प प्रश्न है। दरअसल यह उन सवालों में से एक है जो इंसान अंत तक पूछता रहेगा क्योंकि हम इसका जवाब निश्चित रूप से नहीं जानते लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड का छोर क्या हो सकता है, अगर कुछ है तो। शुरू करने से पहले हमें थोड़ा अतीत में जाने की जरूरत है। रात के वक्त हमारा आकाश पूरे मानव इतिहास में एक जैसा ही दिखता रहा है। यह इतना विश्वसनीय रहा है कि दुनिया भर में लोग नौवहन और अन्वेषण के लिए तारों के 'पैटर्न' को आधार बनाने लगे।

हमारी आंखों को आकाश अंतहीन लगता है। लगभग 400 साल पहले दूरबीनों के आविष्कार के साथ इंसान कहीं ज़्यादा दूर तक देखने में सक्षम हुए और वहां तक देख पाए जहां सिर्फ आंखों से देख पाना संभव नहीं था। वे आकाश में नई चीजों की खोज करते रहे। उन्हें और भी तारे मिले और फिर अंतत: उन्होंने पाया कि वहां अजीब से दिखने वाले बहुत सारे ब्रह्मांडीय बादल थे।खगोलविदों ने इन्हें 'नेबुला' नाम दिया जो लैटिन शब्द 'धुंध' या 'बादल' से लिया गया है।हमने करीब 100 वर्ष पूर्व, पहली बार पुष्टि की थी कि ये ब्रह्मांडीय बादल या नेबुला वास्तव में आकाश गंगाएं हैं। वे 'मिल्की वे' की तरह ही हैं, जिस आकाशगंगा में हमारा अपना ग्रह है लेकिन वे बहुत दूर हैं।

हैरानी की बात यह है कि ब्रह्मांड में हम जिस भी दिशा में देखते हैं हमें और अधिक आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं। 'जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप' की इस

तस्वीर में आप हजारों आकाश गंगाएं देख सकते हैं। ऐसी कल्पना मुश्किल है कि इसका कोई छोर भी होगा और जहां यह समाप्त होता होगा।

हालांकि तकनीकी रूप से हमारे ब्रह्मांड का एक छोर है। हम इसे अपना ''अवलोकनीय' ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वास्तव में नहीं जानते कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है या नहीं। दुर्भाग्यवश हम प्रकाश की गति के कारण कभी भी यह नहीं जान पाएंगे। हम केवल वही प्रकाश देख सकते हैं जो हमारे पास आने के लिए पर्याप्त समय ले चुका हो। प्रकाश ठीक 299,792,458 मीटर प्रति सैकेंड की गति से यात्रा करता है। इतनी गति से भी हमारे ब्रह्मांड को पार करने में इसे काफी समय लगता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड का आकार कम से कम 96 अरब प्रकाश वर्ष है और संभवत: इससे भी बड़ा है।

अगर कोई छोर होता तो हम क्या देख पाते?

यदि हम ब्रह्माण्ड के उस छोर तक जाएं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वह मौजूद है तो वहां वास्तव में क्या होगा? कई सिद्धांत हैं। अगर हमारे ब्रह्मांड का कोई छोर है और आप उसे पार कर जाते हैं, तो आप पूरी तरह से अलग ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं। भले ही आपके सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है लेकिन ये ऐसे सवाल ही हैं जो हमें ब्रह्मांड की खोज और अन्वेषण जारी रखने में मदद करते हैं और हमें इसे समझने में मदद करते हैं। आप एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह सोच रहे हैं।

(द कन्वरसेशन)

सरकार ने रेलवे का किया बंटाधार : लालू

पटना, (पंजाब केसरी): राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से पिछले 10 वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के शासनकाल में रेलवे द्वारा आम लोगों का शोषण करने और रेलवे को घाटे में ले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया है कि कैसे प्रधानमंत्री श्री मोदी के 10 वर्षो के शासन में देश में रेलवे की सेवाएं आम लोगों के लिए दुश्वार हो गई हैं।

राजद अध्यक्ष ने कहा,10 बरसों में मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने रेल का किराया बढ़ दिया। प्लेटफार्म टिकट का दाम बढ़ दिया। स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दी। बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया। सेफ्टी-सिक्यॉरिटी घटाने पर रोज हादसे हो रहे हैं फिर भी कहते हैं रेलवे घाटे में है। अब ये कहीं रेल की पटरियां ना बेच दें। बता दें कि लालू यादव वर्ष 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। उनके रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में जहां एक ओर किफायती किराए वाली गरीब रथ जैसी वातानुकूलित ट्रेनें चली वहीं उस दौरान रेल किराया भी नहीं बढ़या गया था। इतना ही नहीं रेलवे के लाभ अर्जित करने का भी तब रिकॉर्ड बना था।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

NewspaperDaid

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

लौटते मानसून में

देश से मानसून विदा हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से वह तीन दिन पहले ही प्रस्थान कर चुका है और धीरे-धीरे बिहार, बंगाल होते हुए सप्ताह भर में पूरे उत्तर भारत से विदा हो जाएगा। कुल मिलाकर, इस मानसून में अब तक सामान्य से आठ प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अगर राज्यवार देखें, तो पंजाब, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में सितंबर के महीने में कम बारिश दर्ज हुई है, बाकी सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में अच्छी बारिश दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल में भी अच्छी बारिश हुई है। बिहार में भी लौटते-लौटते मानसून खूब बरसा है और सामान्य से कुछ ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। वैसे, राज्यों में भी अगर हम जिलावार देखें, तो उत्तर भारत में करीब बीस जिले ऐसे हैं, जहां सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। किसी जिले में अच्छी बारिश हुई है, तो उसके अगल-बगल के जिलों में बहुत सामान्य बारिश हुई है। खास बात यह है कि इस बार मरुस्थल वाले राज्य राजस्थान में खूब बारिश हुई है। बारिश के पानी को अगर सहेजकर रखा जाए, तो दो वर्ष लायक पानी बरस गया है।

कुल मिलाकर, मौसम विज्ञान विभाग के अनुमानों के अनुरूप ही वर्षा हुई है। वैसे, हर बार की तरह इस बार भी मानसून का एक दुखद पहलू है कि देश भर में करीब 1,500 लोगों की मौत दर्ज हुई है। सर्वाधिक लोग बिजली गिरने और बाढ़ से मरे हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में लोगों ने जान देकर बारिश की कीमत चुकाई है। यह अपने देश का एक दुखद पहलू है। क्या हम बारिश के मौसम में जान-माल के नुकसान से बच सकते हैं? क्या बारिश या बाढ़ से जूझने के लिए हम पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो पा रहे हैं? यह भी एक संकेत है कि हम बारिश को गंभीरता से नहीं लेते हैं। बारिश को अगर गंभीरता से लेते, तो जल संरक्षण के ज्यादा काम दिखाई पड़ते। गांव हों या शहर, जलाशयों की नाकाफी सफाई को ही अगर हम देख लें, तो अंदाजा लग जाएगा कि जलभराव की समस्या साल-दर-साल कैसे बढ़ती जा रही है। अमीर शहरों में भी जलभराव मौत की वजह बन रहा है। आपदा प्रबंधन के स्तर पर भी बहुत काम बाकी है। आपदा आने के बाद जागने की प्रवृत्ति हमें छोड़ देनी चाहिए। आपदा नियंत्रण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित करना जरूरी हो गया है।

मानसून उत्तर भारत से लौट रहा है। हर बार की तरह इस बार भी मानसून का एक दुखद पहलू है कि देश भर में करीब 1,500 लोगों की मौत दर्ज हुई है।

बाढ़ की अगर चर्चा करें, तो खासतौर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भयावहता सामने आई है। बिहार में नदियों में पानी के बढ़ने की एक वजह नेपाल में हुई भारी बारिश है। नेपाल में 235 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़, भूस्खलन या बारिश की वजह से हुई है। भारत से गए अनेक लोग नेपाल में फंसे हुए हैं। बिहार में करीब 18 जिलों में बाढ़ का असर है। जगह-जगह लोग फंसे हुए हैं। ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। सबको पानी के उतरने का इंतजार है। अनुमान के अनुसार, 1 अक्तूबर से जल स्तर में गिरावट का क्रम जारी है, पर अभी पानी को खतरे के निशान से नीचे आने में सप्ताह भर का समय लग सकता है। अगर लौटते मानसून की बारिश तेज होती है, तो फिर बिहार ही नहीं, नेपाल को भी बाढ़ से निजात के लिए इंतजार करना होगा। वैसे साल के ज्यादातर समय पेयजल संकट का सामना करने वाले इन इलाकों में जल प्रबंधन में युद्ध स्तर पर सुधार जरूरी है, ताकि बाढ़ कहीं भी जानलेवा न बने।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 07 अक्तूबर, 1919

आर्थिक बीमारी का इलाज

संसार के अनेक देशों की भांति हमारा देश भी इस समय आर्थिक बीमारी से पीड़ित है। महंगाई बेहद बढ़ी हुई है और उसके कारण जनसाधारण का जीवन-निर्वाह कठिन हो गया है। विदेशी व्यापार देश के लिए घाटे का सौदा बना हुआ है अर्थात् देश जितना आयात करता है, उतना निर्यात नहीं कर पाता। दूसरे शब्दों में हमारा विदेशी व्यापार संतुलित नहीं है। सरकार ने देश की आर्थिक समृद्धि के लिए बड़ी-बड़ी विकास योजनाएं बनाई हैं, किन्तु उनमें से अधिकांश कागज पर ही धरी हैं। जब तक ये विकास योजनाएं कार्यान्वित नहीं होतीं, तब तक देश न तो खाद्य के मामले में स्थायी तौर से आत्मनिर्भर हो सकता है और न ही उसकी अन्य प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विशाल धनराशि किस प्रकार जुटाई जाये, हमारी सरकार के लिए यह मुख्य चिन्ता का विषय है।

सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। इस प्रयत्न में उसे थोड़ी सफलता भी मिली है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसको अब तक दो ऋण मिल चुके हैं। पहला ऋण ३ करोड़ ४० लाख डालर का है, जो रेलवे विकास के लिए काम में आयेगा। दूसरा ऋण १ करोड़ डालर का है, जो खेतों का विस्तार करने के लिए प्रयुक्त होगा। सरकार ने विदेशी पूंजी को भी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। विदेशों से जो सहायता मिल जाये, उसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। किन्तु इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि विदेशी आर्थिक सहायता के साथ-साथ कुछ राजनीतिक असर भी आता ही है। भारत को उस असर से बचे रहना है, क्योंकि वह विदेशी मामलों में स्वतंत्र और तटस्थ नीति का अनुसरण करना चाहता है। दूसरे, उसे स्वयं भी अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक धन जुटाने का प्रयत्न करना होगा। विदेशी पूंजी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण से सारा काम नहीं निकल सकता। देश के पूंजीपतियों को भी सरकार ने उद्योगों का दस वर्ष तक राष्ट्रीयकरण न करने का आश्वासन देकर और सार्वजनिक उद्योगों और निजी उद्योगों के बीच सीमा रेखा खींचकर उद्योग-धंधों में अपना रुपया लगाने के लिए प्रेरित किया है। किन्तु पूंजीपतियों की हिचक अभी गई नहीं है। उद्योग-धंधों के लिए जितने रुपये की आवश्यकता है, उतना उनकी ओर से मिल नहीं रहा है।

साल भर से बदले का बेदर्द सिलसिला

यहां स्कैन करें

हरजिंदर | वरिष्ठ पत्रकार

पिछले साल ठीक आज के दिन हमास उग्रवादियों ने इजरायल में घुसकर हमला बोला था, तभी यह तय हो गया था कि पश्चिम एशिया में शांति लौटने की उम्मीदों के दिन खत्म हो गए हैं।

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता की पंक्ति है- *एक बस्ती जल रही है, पर सारी दुनिया कुएं की जगत पर पांव पसारे बैठी है।* मगर पश्चिम एशिया में इस समय सिर्फ एक बस्ती नहीं जल रही, पूरे के पूरे देश जल रहे हैं। पिछले एक साल में अब तक हजारों लोग मर चुके हैं और तमाम आंकड़े कह रहे हैं कि मरने वालों में 75 फीसदी बच्चे और औरतें हैं। मरने वाले वृद्धों और निराश्रित हो जाने वाले बच्चों की संख्या इससे अलग है। लेकिन पूरी दुनिया तमाशा देखने के अलावा और कुछ करने की स्थिति में नहीं है। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बनाए गए तमाम महिमा मंडित संस्थानों की व्यर्थता का ऐसा एहसास इसके पहले कभी नहीं हुआ।

एक साल पहले 7 अक्तूबर को हमास उग्रवादी जब गाजा की सीमा पार कर इजरायल में घुसे थे, तभी यह तय हो गया कि पश्चिम एशिया में शांति लौटने की उम्मीदों के दिन अब खत्म हो गए हैं। अभी भी ठीक से नहीं पता कि वे कितने उग्रवादी थे, लेकिन उन्होंने 1,200 लोगों का कत्ल कर दिया था और करीब 250 को बंधक बना ले गए थे। जो मारे गए, वे सभी इजरायल के नागरिक थे। ज्यादातर यहूदी थे, लेकिन कुछ मुस्लिम भी थे और कुछ बेडौइन घुमंतू भी थे। इनमें ज्यादातर सैनिक नहीं, आम नागरिक थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे। धरती के उस इलाके में, जहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही कई ताकतें आंख के बदले आंख फोड़ देने के मुहावरे पर चल रही हों, वहां ऐसी वारदात के बाद अंधी हिंसा का दौर शुरू हो जाना तय था।

इसके कुछ पहले तक इसी इलाके में उम्मीद के दरवाजे खुलते दिख रहे थे। पिछले साल सितंबर में इतिहास का पहला मौका आया था, जब इजरायल के एक कैबिनेट मंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। इसके प्रयास काफी समय से चल रहे थे और यह लगने लगा था कि जल्द ही पश्चिम एशिया में नई सुबह हो सकती है। मगर बहुत सारे अंधेरे इस उम्मीद को उलटने का इंतजार कर रहे थे। 7 अक्तूबर की हिंसक कार्रवाई दरअसल इसी मंशा से की गई थी, जो अपने मकसद में कामयाब भी रही।

दुनिया का एक ऐसा हिस्सा, जो दशकों से बारूद संग जिंदगी जीने को अभिशप्त है, वहां आग लगाने के लिए एक चिनगारी ही काफी थी, यह तो उसके मुकाबले काफी बड़ी वारदात थी। और फिर अचानक ही पूरा पश्चिम एशिया उसी हिंसा की ओर लौट गया, जो मानो उसका स्वभाव बन चुकी है। हमेशा की तरह इजरायल बदला लेने के लिए निकल पड़ा और पहले से बदहाल गाजा तकरीबन ध्वस्त कर दिया गया। गाजा से तबाही की खबरें जब आनी शुरू हुईं, तो इजरायल के पुराने दुश्मन लेबनान में बैठे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी कमर कस ली। ईरान ने अपनी मिसाइलों की धूल साफ करनी शुरू कर दी और यमन में बैठे हूती विद्रोही भी अपने हथियारों की सान चढ़ाने लग गए।

इस समय युद्ध लगभग शुरू हो चुका है। बम तो छोड़िए, उस इलाके में पेजर और वॉकी-टॉकी तक फट रहे हैं। गाजा को रौंद चुकी इजरायल की फौजें अब लेबनान पर भी हमलावर हैं। दूसरी ओर, ईरान की मिसाइलें थोक भाव में इजरायल को निशाना बना चुकी हैं। कोई नहीं जानता कि यह पागलपन कब तक चलेगा? एक बात तय है कि यह सब जल्द रुकने वाला नहीं है। तमाम रिपोर्टें बता रही हैं कि हिंसा के अलावा अब वहां सिर्फ एक ही चीज है- नफरत, जो हर तरफ है और हर जगह है।

कहा जाता है, इजरायल ने पिछले एक साल में सिर्फ गाजा में 40 हजार लोगों को मार गिराया है और वहां की 90 फीसदी आबादी को विस्थापित होना पड़ा है। प्यू रिसर्च ने अपने सर्वे में पाया कि इजरायल के 73 फीसदी लोग मानते हैं कि उनके देश की सेना ने गाजा में जो किया, सही है और कुछ तो यह तक मानते हैं कि जिस हद तक जाकर यह करना चाहिए था, उतना नहीं किया गया। दूसरी तरफ फलस्तीनी आबादी में तकरीबन इतने ही लोग यह मानते हैं कि 7 अक्तूबर को हमास ने जो किया, वह सही था। इससे भी बड़ी बात यह कि उनका सह-अस्तित्व हो सकता है, इसे स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं। एक-दूसरे के सफाये का संकल्प उन्हें कहां ले जाएगा, कोई नहीं जानता।

इजरायल और पश्चिम एशिया के देशों की दिक्कत यह है कि वे अपने वर्तमान की किसी समस्या को सुलझाने के लिए नहीं लड़ रहे। वे इतिहास की बहुत सी उन समस्याओं को सुलझाने और उनके प्रतिशोध के लिए लड़ रहे हैं, जो अतीत के घटनाक्रमों ने उनकी किस्मत के साथ टांक दी है। समस्या अगर वर्तमान की होती, तो शायद सुलझा भी ली जाती, या कम से कम वर्तमान के बहुत सारे हित-अहित मामले को बिगड़ने से रोकने का काम करते। इजरायल के यहूदी मानते हैं कि जिस जमीन पर उनका देश कुछ दशक पहले बसाया गया है, वह किसी पौराणिक काल में उनके पूर्वजों की भूमि थी और बाकी लोगों को यहां उनके बोलबाले को स्वीकार कर लेना चाहिए या यहां से दफा हो जाना चाहिए। जबकि फलस्तीनी मानते हैं कि यह उनकी भूमि है और उन पर थोप दिए गए इजरायल के लिए यहां कोई जगह नहीं।

हम यह मानते हैं कि अगर कोई दो पक्ष किसी मसले पर उलझे हों, तो उन्हें बातचीत की मेज पर बिठाकर मामले का हल किया जा सकता है। मगर यह तभी हो सकता है, जब दोनों वर्तमान की हकीकत को स्वीकार करें। कहीं भी जब वर्तमान के दबावों पर इतिहास की व्याख्याएं हावी हो जाती हैं, तब फिर उस तरह के पागलपन को कोई रोक नहीं सकता, जो हमें पश्चिम एशिया में इस समय दिखाई दे रहा है। इतिहास के पहिये को पीछे ले जाने की कोशिशें या उसकी कथित भूलों को सुधारने के प्रयास हमेशा मानवीय त्रासदी में ही बदलते रहे हैं।

दिक्कत सिर्फ पश्चिम एशिया की नहीं है, वहां हमें इस समस्या की अति दिखाई दे रही है, लेकिन इतिहास से इसी अंदाज में निपटने के प्रयास दुनिया में और जगहों पर भी सिर उठा रहे हैं। हमें अपने आस-पास ही ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, जो इस मामले में इजरायल को रोल मॉडल मानते हैं, और वे भी मिल जाएंगे, जो उसके खात्मे को ही सबसे जरूरी मानते हैं। पश्चिम एशिया में हम जिसका विद्रूप देख रहे हैं, उस समस्या के पदचिह्न और जगह भी हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

कभी पेरिस की तरह गुलजार हुआ करते थे पटना के चौराहे

यहां स्कैन करें

रीना सोपम | पत्रकार व कला लेखिका

कुछ महीने पहले, जब देश भर में विश्व संगीत दिवस की धूम मची थी, तब मुझे अनायास पटना के चौक-चौराहों पर होने वाले दशहरा संगीत समारोहों की याद हो आई। दशहरा उत्सव से एक बार फिर हम गुजर रहे हैं। पूजा पंडाल सप्तमी-अष्ठमी और नवमी के लिए सजने लगे हैं, पर पटना की दुर्गापूजा जिन शास्त्रीय संगीत समारोहों के लिए कभी चर्चित रही, वैसे समारोह नहीं होंगे।

आजादी के समय से ही दशहरा में पटना के चौराहों पर शास्त्रीय संगीत सभाएं होती थीं। ठीक उसी तरह, जैसे आज विश्व संगीत दिवस पर पार्कों व शॉपिंग मॉल के विजिटर्स एरिया में अनेक संस्थाएं आयोजन करती हैं। इन स्थलों पर विश्व संगीत दिवस मनाने का उद्देश्य ही यही है कि संगीत हर सड़क-चौराहे पर हो, ताकि आम आदमी इसके आनंद का अनुभव कर सके। स्थापित और नवोदित कलाकार सीधे आम श्रोताओं के बीच हों। फ्रांस के संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने इसकी परिकल्पना की थी। उनका मानना था, अच्छा संगीत सुनने और सुनाने से जो सुंदर भावनाएं उभरती हैं, उनसे मानवीय संवेदनाएं जागती हैं और मानवीय संबंध मजबूत होते हैं।

जिस सांस्कृतिक परिपाटी की शुरुआत फ्रांस में 1982 में हुई, बिहार की राजधानी पटना में वह आजादी के समय से ही प्रचलित थी।

मगर जिस सांस्कृतिक परिपाटी की शुरुआत फ्रांस में 21 जून, 1982 को हुई, वह बिहार की राजधानी पटना में आजादी के समय से ही प्रचलित रही। ये संगीत कार्यक्रम अमूमन सप्तमी से दशहरे की रात तक होते और पूरी तरह गैर-सरकारी होते थे। इनमें शहर के आम लोगों से लेकर व्यवसायियों और डॉक्टरों की भागीदारी मुख्य रूप से होती थी। इनमें शामिल होने वाले हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत के 'लीजेंड' हैं। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायकराव परिवर्धन, विदुषी हीराबाई बडोदेकर, सरस्वती राणे, सिद्धेश्वरी देवी, मोघूबाई कुर्डीकर, गंगूबाई हंगल, बेगम अख्तर और पंडित भीमसेन जोशी से लेकर उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद विलायत खां, उस्ताद इमरत हुसैन, उस्ताद अल्ला रक्खा, उस्ताद रईस खां, उस्ताद हलीम जाफर और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिवकुमार शर्मा, विदुषी किशोरी अमोनकर, लालगुडी जयरमण, एन रमणी, टीएन कृष्णन, पालघाट रघु और येल्ला वेंकटेश्वर जैसे दिग्गजों के कला प्रदर्शन से पटना के चौराहे गुलजार हुआ करते। पौ फटने के साथ आसपास की किसी मस्जिद से जब अजान की आवाज आती और मंदिर में गूंज रही घंटियों की आवाजें तैरकर इन पंडालों में पहुंच जातीं और तब तक मंच पर चल रहा होता भटियार, विलासखानी तोड़ी या बसंत मुखारी जैसा सुबह का राग और उनका स्वर-विस्तार।

एक ऐसे ही वाकये की याद आ गई, जब उस्ताद इमरत हुसैन और उस्ताद बिस्मिल्ला खां के सितार-शहनाई की जुगलबंदी का कार्यक्रम हुआ था। नवमी का दिन था। भारतमाता मंडली उन दिनों लंगरटोली चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित करती थी। उस रात बनारस घराने के कत्थक कलाकार गोपीकृष्ण जी का नृत्य कार्यक्रम देर तक हुआ था और लगभग पौ फटने के समय उस्ताद इमरत हुसैन और उस्ताद बिस्मिल्ला खां मंच पर आए। संयोगवश बारिश शुरू हो गई। गनीमत थी, बारिश तेज नहीं थी। वैसे, पंडाल में पानी की बूंदें आ रही थीं, पर एक भी श्रोता नहीं गया। कार्यक्रम चलता रहा और बारिश भी रुक गई थी। सुबह पूरी तरह खुल गई थी और कलाकार अब कार्यक्रम समाप्त करना चाह रहे थे। लयकारी अपने चरम की ओर जाने लगी थी। उनके उतावलेपन की एक और वजह थी। उन दिनों रमजान चल रहा था और अगले ही दिन ईद था। उस्ताद इमरत हुसैन कोलकाता अपने घर लौटना चाह रहे थे और उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब को बनारस वापस जाना था। लेकिन पटना के संगीत प्रेमी, उन्हे मंच से उठने ही नहीं दे रहे थे।

इमरत हुसैन साहब ने झाला समाप्त किया और माइक के पास जाकर बोले, 'मुझे कोलकाता वापस जाना है। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे ईदी के लिए।' उनका इतना कहना था कि पंडाल में बैठे सभी लोग एक साथ उठ खड़े हुए। तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों को मंच से उठने की इजाजत दी और मंच से उतरते ही उन्हें घेर लिया। कोई उनके हाथ छूना चाहता था, तो कोई ऑटोग्राफ लेने की कोशिश में था। शास्त्रीय रागों को सुनने का वह जुनून और कलाकारों व संगीत प्रेमियों के बीच का वह जज्बा अब गुम हो चला है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

हवाएं सबसे बड़ी संदेश वाहक

अमेजन का वितरण करने वाला लड़का सामान देने आया था। ये लोग हवा के झोंकों की तरह आते हैं और सामान देकर गायब हो जाते हैं। इनका एक खास व्यक्तित्व होता है। उनसे हम एक खास तरह के आचरण की अपेक्षा रखते हैं। लड़के ने मेरा पार्सल थमाया और मुस्कराकर बोला, 'नेवर बॉर्न नेवर डाइड।' मैं इतनी चौंक गई कि मेरे हाथ से पार्सल गिर गया। मैंने पूछा, 'तुम कैसे जानते हो इन शब्दों को?' उसने कहा, 'यहीं आसपास रहता हूं, तो बातें कानों से गुजरती हैं।'

चौंकने वाली बात इसलिए है, क्योंकि ओशो के बेडरूम में पलंग के नीचे उनकी अस्थियां रखी हुई हैं, उस पर ओशो के लिखवाए हुए ये शब्द हैं: 'ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ बिटवीन 11 दिसंबर, 1931 ऐंड 19 जनवरी, 1990' यानी 'ओशो न कभी जन्मे, न कभी विदा हुए, केवल इस ग्रह (पृथ्वी) का 11 दिसंबर, 1931 से 19 जनवरी, 1990 के बीच दौरा किया।'

यह बेडरूम ओशो मेडिटेशन रिजॉर्ट के अंतर कक्ष में है। वहां सिर्फ साधक ही जा सकते हैं और उसके लिए उन्हें प्रवेश पास खरीदना होता है। उसका उपयोग सिर्फ ध्यान के लिए होता है। और ये शब्द उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो ओशो के मुरीद हैं। फिर इस अमेजन के वायुदूत की जुबान पर कैसे चढ़ गए? शायद ये शब्द इतने मशहूर हो गए हैं कि सुगंध की तरह आसपास की हवा में तैर रहे हैं।

इससे मुझे वह कहानी याद आई, जब आदि शंकराचार्य मंडन मिश्र का घर ढूंढ़ते हुए पहुंचे थे। नगर में एक कुंए पर पानी पीने के लिए रुके, वहां कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं, उनसे शंकराचार्य ने पूछा, आचार्य मंडन मिश्र का घर कहां मिलेगा? स्त्रियां बोलीं, सीधे चलते जाओ, जिस घर के आसपास तोते ज्ञान की बातें कहते हुए मिलेंगे, वही मंडन मिश्र का घर होगा।

यह किसी और काल की बात है। आजकल जमाना प्रचार और विज्ञापन का है। लाखों करोड़ों खर्च करके कोई बात लोगों के गले उतारी जाती है, उसे बार-बार दोहराना पड़ता है, ताकि वे भूल न जाएं, लेकिन इसके बावजूद विज्ञापनदाता सफल नहीं हो पाते। इसके विपरीत कुछ खबरें, कुछ शब्द, कुछ कल्पनाएं दूर दिगंत तक पहुंच जाती हैं, मानो हवाएं उन्हें उड़ाकर ले जाती हैं।

कुछ खबरें, कुछ शब्द, कुछ कल्पनाएं दूर दिगंत तक पहुंच जाती हैं, मानो हवाएं उन्हें उड़ाकर ले जाती हैं। एक पैसा भी खर्च नहीं होता और बात लोगों के दिलों में उतर जाती है।

समुद्र कब विज्ञापन करता है कि ओ नदियो, मेरे पास आओ, मैं समुद्र हूं, तुम्हारा अंतिम पड़ाव। समुद्र का होना ही काफी है। उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि सारे जल स्रोत चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। न फूल भौरों को कोई संदेश भेजते हैं कि देखो, हम खिल गए हैं। हवाएं उनकी सुगंध को फैला देती हैं। अस्तित्व एक इकाई है, यहां सब एक-दूसरे से जुड़ा है।

अमृत साधना

निर्मला सीतारमण | केंद्रीय वित्त मंत्री

एक हजार वर्षों से भारत ने दर्शन, राजनीति, विज्ञान और कला का एक सांस्कृतिक क्षेत्र गढ़ा है, जो अपनी सांस्कृतिक भव्यता के जरिये सीमाओं के पार फैला है। इस अवधि में शेष विश्व भी भारत के 'सॉफ्ट पावर' से लाभान्वित हुआ।

अनुलोम-विलोम
स्वच्छ भारत अभियान

चारों तरफ अब स्वच्छता की चर्चा

स्वच्छ भारत अभियान अब एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है। इसका संदेश लोगों के अंदर उत्तरदायित्व की एक अनुभूति जगा चुका है। अब जबकि लोग पूरे देश में स्वच्छता के कार्यों में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो रहे हैं, तो महात्मा गांधी द्वारा देखा गया 'स्वच्छ भारत' का सपना साकार होने लगा है। पिछले 10 वर्षों से समाज के विभिन्न वर्गों ने आगे आकर स्वच्छता के इस जन अभियान में हिस्सा लिया है और अपना योगदान दिया है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर जवानों तक, बॉलीवुड अभिनेताओं से लेकर खिलाड़ियों तक, उद्योगपतियों से लेकर आध्यात्मिक गुरुओं तक सभी ने इस महान काम के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। देश भर के लाखों लोग सरकारी विभागों द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता के कामों में आए दिन सम्मिलित हो रहे हैं। इस काम में एनजीओ और स्थानीय सामुदायिक केंद्र भी शामिल हैं। वे नाटक और संगीत के माध्यम से साफ-सफाई और स्वास्थ्य के गहरे संबंध के संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयासरत हैं। हालांकि, इस अभियान के मार्ग में कुछ रुकावटें भी हैं। सबसे बड़ी बाधा तो पान मसाला, गुटका, तंबाकू आदि के उपयोग के बाद की जाने वाली गंदगी है। इस गंदगी से हर गली-चौराहे अटे पड़े रहते हैं। वैसे, इस मामले में तमिलनाडु बधाई का पात्र है कि उसने गुटका, तंबाकू आदि की बिक्री को प्रतिबंधित कर रखा है, जबकि अन्य राज्य राजस्व का रोना रोते हैं। गुटकों का सेवन हिंदी पट्टी के राज्यों में ज्यादा है, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, दिल्ली के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सरकार यदि भारत को विकसित देशों जैसा साफ-सुथरा बनाना चाहती है, तो वह तत्काल हिंदी पट्टी में गुटके-तंबाकू पर प्रतिबंध लगाए और इनको खाने वालों के विरुद्ध दंडनीय कार्रवाई करे। इससे यह अभियान अधिक सफल साबित होगा।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

एक जरूरी पहल

कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और स्वस्थ मन ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। मगर यह स्वस्थ शरीर बने कैसे? स्वच्छ भारत अभियान इसी सवाल का जवाब है। इस अभियान के तहत न सिर्फ ठोस कचरा के प्रबंधन को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है, बल्कि खुले में शौच को भी हतोत्साहित किया गया है, जिसके कारण अब लोग साफ-सफाई को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। इसी तरह, गंदगी को साफ करने की मानसिकता भी लोगों में दिखने लगी है, जिससे हमारा देश अब कहीं अधिक स्वच्छ दिखता है।

महिमा ठाकुर, टिप्पणीकार

अभियान अपेक्षित गति न पकड़ सका

दस साल पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जिस जोर-शोर से की गई थी, उस तरह यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका है। ऐसा नहीं है कि इस योजना का सैद्धांतिक पक्ष कमजोर है। देखा जाए, तो इस अभियान के पीछे की नीयत में कोई खोट नहीं है। खोट तो इसके व्यावहारिक पक्ष में है। यानी, इसको लागू करने वाले तंत्र ने इस अभियान को पूरी तरह सफल नहीं होने दिया। यकीन न हो, तो एक बार गांवों में घूम लीजिए। कई गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं, यानी कागज पर ये ऐसे गांव हैं, जहां लोग अब खेतों में निवृत्त होने नहीं जाते, लेकिन हकीकत में वहां आज भी आपको ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे, जिनके लिए घर से बाहर निवृत्त होना मजबूरी है। फिर, कई जगहों पर तो शौचालय बना दिए हैं, लेकिन इनके लिए जरूरी सुविधाएं बहाल नहीं की गई हैं। नतीजतन, ऐसे शौचालय महज शोभा बढ़ाने के काम आ रहे हैं, इनका कोई उपयोग नहीं करता।

कुछ ऐसा ही हाल साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन का है। 2 अक्तूबर को तो सभी स्वच्छता को लेकर अपनी सक्रियता दिखाते हैं, लेकिन बाकी दिन इसकी शायद ही सुध ली जाती है। आप अपने आसपास ही देखिए। बड़े-बड़े शहरों में तो स्थानीय निकाय साफ-सफाई के कामों में लगे रहते हैं, लेकिन दूसरे या तीसरे दर्जे के शहरों और गांव-देहातों में, जहां स्थानीय निकाय बहुत मुस्तैद नहीं हैं, वहां कचरे में आग लगाने की परंपरा अब भी है। यह धुआं सांसों के जरिये हमारे शरीर का कितना नुकसान करता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह, नालों में भी गंदगी यूं ही बहती रहती है। उनकी सुध लेने को कोई तैयार नहीं होता। यही गंदगी बरसात के दिनों में जलभराव का कारण बनती है और उफनकर सड़कों पर आ जाती है, जिससे गुजरना पैदल चलने वालों के लिए नरक पार करने से कम कष्टदायक नहीं होता।

वास्तव में, स्वच्छ भारत अभियान तभी पूरी तरह सफल हो सकता है, जब देश का हरेक आदमी स्वच्छता की अहमियत समझे और इस काम में लगे नगर निगम या स्थानीय निकाय पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। सिर्फ एक दिन का स्वच्छता अभियान हमें ज्यादा राहत नहीं दे सकता। इसका फायदा तभी मिल सकता है, जब साफ-सफाई को हम अपने जीवन में उतार लें और अपनी दिनचर्या का इसे हिस्सा बनाएं। फिलहाल, ऐसा होता दिख नहीं रहा है, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान भी अपेक्षित परिणाम से दूर नजर आ रहा है।

दीपक, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 7 अक्टूबर, 2024

दैनिक जागरण

लक्ष्य की स्पष्टता के अभाव में जीवन की सार्थकता संभव नहीं

ड्रग्स का खतरा

दिल्ली के बाद भोपाल के निकट ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद किया जाना यही बताता है कि किस तरह ड्रग्स तस्करों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। भोपाल के निकट नौ सौ किलो जो ड्रग्स बरामद की गई, वह वहीं पर निर्मित की जा रही थी। इसका अर्थ है कि अब देश में बाहर से ड्रग्स लाने के साथ ही देश में उसका चोरी-छिपे निर्माण भी किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर ड्रग्स को तैयार करने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इसी तरह बाहर से बड़ी मात्रा में तस्करी के जरिये ड्रग्स लाने के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली में पांच सौ किलोग्राम से अधिक जो ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसे बाहर से ही लाया गया था। अच्छी बात यह है कि ड्रग्स तस्करी के मामले बढ़े हैं तो उसकी बरामदगी और तस्करों को गिरफ्तार करने में भी उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस सफलता का श्रेय गृह मंत्री अमित शाह को जाता है, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां ड्रग्स के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए मिलकर काम करें। विभिन्न एजेंसियों में तालमेल के सकारात्मक नतीजे भी सामने आए हैं, लेकिन यह ठीक नहीं कि अब अपने देश में जमीनी और समुद्री रास्तों के साथ-साथ हवाई मार्ग से भी बड़े पैमाने पर ड्रग्स आ रही है। ड्रग्स की बढ़ती तस्करी यही बताती है कि देश में मादक पदार्थों की खपत बढ़ाने, युवाओं का भविष्य खराब करने और अवैध तरीके से पैसा बनाने वालों की सक्रियता बढ़ रही है। इस सक्रियता पर इसलिए प्राथमिकता के आधार पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि ड्रग्स तस्करी से अर्जित धन का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी संगठनों को मजबूत करने में भी किया जाता है।

आवश्यक केवल यह नहीं है कि दूसरे देशों से ड्रग्स की आपूर्ति पर लगाम लगाई जाए, बल्कि इसकी भी है कि देश में उसके वितरण के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाए। यह ठीक नहीं कि पिछले कुछ समय से किस्म-किस्म के मादक पदार्थ सीमावर्ती राज्यों के साथ देश के अंदरूनी इलाकों और छोटे शहरों तक में पहुंच रहे हैं। स्पष्ट है कि देश में ड्रग्स की खपत बढ़ाने की साजिश रची जा रही है। यह साजिश लोगों और विशेष रूप से युवाओं को ड्रग्स का लती बनाकर ही की जा सकती है। चूंकि ऐसा हो रहा है, इसलिए ड्रग्स के खिलाफ समाज को भी चेतना होगा। उसे न केवल छिटपुट स्तर पर ड्रग्स की बिक्री करने वाले तत्वों पर निगाह रखनी होगी, बल्कि युवाओं को ड्रग्स सेवन के दुष्परिणामों के प्रति भी सचेत करना होगा। ड्रग्स की लत लोगों को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। यह ठीक है कि ड्रग्स के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए मानस नाम से एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, लेकिन उसकी सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि आम लोग ड्रग्स की खरीद-बिक्री और उसके सेवन के प्रति कितनी अधिक सजगता का परिचय देते हैं।

नीति नियोजन

उत्तराखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सशक्त एवं व्यापक नीति नियोजन अत्यंत आवश्यक है। विकास की गति ने राज्य में गति पकड़ी है, लेकिन क्षेत्रीय विषमताएं और गहरी हुई हैं। मूलभूत सुविधाओं के विकास और उनमें गुणात्मक सुधार के प्रयास सुगम और मैदानी क्षेत्रों में अधिक सफल रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इस दृष्टि से परिवर्तन बहुत धीमा है। राज्य बने 24 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों विशेष रूप से सीमांत क्षेत्रों से पलायन कम होने के स्थान पर बढ़ गया। विषम भौगोलिक भू-भाग को लेकर नीति निर्माण में जिस दूरदृष्टि के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उनमें कमी झलकती है। नीति नियोजन में इन कमियों से निपटने की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि प्रदेश सरकार ने अपनी कमियों पर मंथन करने के बाद नीति आयोग की भांति स्टेट इंस्टीट्यूट फार एंपावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग का गठन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोग राज्य की क्षमता और कमजोरी, दोनों का आकलन कर रहा है। इसके ढांचे को स्वीकृति मिल चुकी है। आयोग में उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सलाहकारों के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। कुल छह सलाहकार रखे जाने हैं, इनमें से तीन का चयन हो चुका है। सलाहकारों के आने के बाद आयोग के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। विशेषज्ञ राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार की संभावनाओं के विस्तार, सामाजिक क्षेत्र के सशक्तीकरण के साथ विभागों की योजनाओं को धरातल पर उतारने की रणनीति बनाएंगे। यह रणनीति राज्य के वार्षिक बजट निर्माण और बजट के सदुपयोग का हिस्सा भी बनेगी। नीति नियोजन में बेहतरी की दिशा में यह अच्छा कदम है। अब इसे तत्परता से धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए इच्छाशक्ति भी दिखानी होगी।

अपना घर देखे अमेरिका

हृदयनारायण दीक्षित

अमेरिका खुद अपनी समाज व्यवस्था दुरुस्त करने में विफल है, लेकिन उसकी संस्थाएं धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत को उपदेश दे रही हैं

अवधेश राजपूत

अमेरिकी संस्था 'यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फार इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' की हाल में एक रिपोर्ट आई है। इसमें भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की आलोचना की गई है। रिपोर्ट में नफरती भाषणों, तथ्यहीन सूचनाओं और सरकारी अधिकारियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ उकसाने का उल्लेख है। संस्था ने मनगढ़ंत तरीके से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को खराब बताया है। भारत ने उचित ही अमेरिकी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया में कहा है कि 'पक्षपातपूर्ण राजनीतिक एजेंडा चलाने के बजाय इस संगठन को मानवाधिकार के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।' अनुच्छेद-19 के अंतर्गत भारत में विचार प्रकट करने की आजादी है। इसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी अनुच्छेद 25-28 में है, लेकिन अमेरिकी संस्था ने इन तथ्यों पर विचार नहीं किया। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हित सुनिश्चित हैं और वे सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित हैं। वे राष्ट्रपति जैसे शीर्ष पदों पर रह चुके हैं। रिपोर्ट में भारत के कुछ कानूनों को धार्मिक भेदभाव बढ़ाने वाला बताया गया है। मतांतरण, हिजाब, गोहत्या और नागरिकता संबंधी कानूनों को अल्पसंख्यकों पर प्रतिकूल प्रभावकारी बताया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्वाभाविक रूप से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर हम भी कुछ बोलें तो बुरा मत मानना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी संस्था घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है। उसे ऐसा एजेंडा चलाने के बजाय अमेरिकी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर भारतीय समाज को बदनाम करना ही उनका लक्ष्य है।

भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। परस्पर संप्रभुता का सम्मान सभी राष्ट्रों का कर्तव्य है। धार्मिक स्वतंत्रता पर 2004 में जारी एक रिपोर्ट में भी ऐसा ही कहा गया था। इस प्रकरण के मूल में अमेरिकी समाज की विश्व पर राज करने की महत्वाकांक्षा है। ऐसी अनेक संस्थाएं अमेरिका में हैं और जर्मनी में भी। यूके में भी रिलीजियस पर्सिक्यूशन एंड वर्ल्ड वाच रिपोर्ट नाम से ही ऐसी रिपोर्ट तैयार होती है। उसके लिए हाउस आफ कामंस से निर्देश भी मिलते हैं। भारत के कथित 'माब लिंचिंग' की चर्चा भी अमेरिकी संस्था की हालिया रिपोर्ट में है जबकि हिंसक भीड़ की ऐसी घटनाएं अमेरिका में भी घटित होती हैं। कुछ समय पहले ही एक श्वेत पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन ने अश्वेत जार्ज फ्लायड की निर्मम हत्या कर दी थी। उसके परिणामस्वरूप श्वेत-अश्वेत के बीच दंगे भड़के थे। 'ब्लैक लाइव्स मैटर्स' नाम का अभियान चला था। काले-गोरे के भेद हिंसा तक जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि अमेरिकी समाज में अश्वेतों को घर छोड़ने को मजबूर किया गया था। आस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा में एशियाई मूल के लोगों के साथ नस्ली भेदभाव की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं।

अमेरिका अपने देश में व्याप्त हिंसा की चिंता नहीं करता। लोग सरेआम गोलियां चलाते हैं। आर्म लाइसेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों के हाथ में पिस्तौलें हैं। नशे की गोलियां हैं। विश्व-प्रतिष्ठित अमेरिकी भाषा विज्ञानी नोम चोम्स्की ने अमेरिकी समाज के बारे में चिंता जताई थी। हार्वर्ड एजुकेशनल रिव्यू के संपादकों ने 'हिंसा और नौजवान' विषय पर उनका साक्षात्कार लिया। चोम्स्की ने कहा कि 'हिंसा के सहारे ही अमेरिकी पूंजीवाद का विकास हुआ। अमेरिकी महाद्वीप को आबाद करने वाले ब्रिटेन और यूरोप के गोरे व्यापारी यहां आए। हजारों साल से यहां रहने वाले आदिवासियों का संहार किया। जो बचे उन्हें उजाड़ स्थानों पर धकेल दिया।' चोम्स्की ने उन आदिवासियों को 'इंडियन' कहा। याद रहे कि कोलंबस सहित जो लोग अमेरिका का पता लगा सके, वे दरअसल भारत का पता लगाने निकले थे। अमेरिकी समाज मूल रूप में ही हिंसा के विचार पर आधारित है। अमेरिकी समाज परस्पर लड़ता-झगड़ता एवं टूटा हुआ है। अमेरिकी समाज में ईसाई समुदाय दो भागों में विभाजित है और बहुधा टकराव देखने को मिलते हैं। अमेरिका में मानवाधिकारों का उल्लंघन सामान्य घटना है। अमेरिका खालिस्तान समर्थकों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। इसमें कनाडा भी शामिल है। जो देश अपनी समाज व्यवस्था दुरुस्त करने में विफल हैं, वह भारत को अपने एजेंडे पर चलाना चाहते हैं।

अधिकांश अमेरिकी श्रेष्ठता ग्रंथि के शिकार हैं। वे सारी दुनिया को मार्गदर्शन-उपदेश देना चाहते हैं। वे विचार प्रकट करने के सभी साधनों को अपनाते हैं। यूरोपीय भी उनके संगी-साथी हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, 'भारत राजनीतिक इकाई नहीं, बल्कि 'भौगोलिक अमूर्तता' है। भारत कभी स्वतंत्र राष्ट्र नहीं हो सकता। ब्रिटिश क्राउन से अलग होने के बाद भारत के लोग जंगल में जाकर लड़ेंगे।' उन्होंने यह भी कहा था कि, 'एक शिक्षित वायसराय भारत में शांति व्यवस्था बनाए रख सकता है।' चर्चिल की बात गलत निकली। भारत अपने पुरुषार्थ-पराक्रम एवं दृढ़ संकल्प से स्वतंत्र हुआ। सफल राष्ट्र साबित हुआ। संप्रति पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। मूलभूत प्रश्न है कि ऐसी तथ्यहीन टीका-टिप्पणियों से कैसे बचा जाए? क्या भारत को भी प्रतिकार स्वरूप ऐसी ही संस्थाओं का विकास करना चाहिए? ऐसी टिप्पणियों का ठोस प्रतिकार आवश्यक है।

अमेरिकी समाज में किशोरों को भी अपराध में लिप्त देखा जाता है। तब किसे दोष दें? वहां परिवार के मुखिया सामान्य तौर पर बच्चों को समय नहीं देते। आत्मनिर्भर होते ही बच्चे और संरक्षक अलग-अलग रहते हैं। इसके विपरीत भारत में परिवार नाम की संस्था दृढ़ एवं मजबूत है। मजबूत परिवार घर चलाने के साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। समाज प्रेमपूर्ण ढंग से चलता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। दुर्भाग्य से वे भारतीय समाज के मुख्य तथ्यों पर ध्यान नहीं देते। अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग डेढ़ सौ साल बाद महिलाओं को मताधिकार दिया, बल्कि भारत में पहले आम चुनाव से ही महिलाओं को मतदान में समान अधिकार दिए गए। भारतवासी विश्व को एक अखंड सत्ता एवं परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम् भारत का संकल्प है। अमेरिका को भारत के राष्ट्रजीवन से सीखना चाहिए।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

वर्गीय एकता टूटने की चिंता अनुचित

केसी त्यागी

आरक्षण के भीतर आरक्षण से उन बारह राज्यों में वर्गीय एकता मजबूत हुई है, जहां यह पहले से लागू है

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने छेड़ी नई बहस। फाइल

सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण की इजाजत देने वाले फैसले पर एक बार फिर अपनी मुहर लगा दी है। कोर्ट ने एससी-एसटी के उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले अपने फैसले के विरुद्ध दाखिल दो दर्जन से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा है कि फैसले में ऐसी कोई खामी नहीं है, जिसके लिए फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत हो। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने गत एक अगस्त को 6-1 के बहुमत से दिए फैसले में कहा था कि एससी-एसटी वर्ग के ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य एससी-एसटी वर्ग में उपवर्गीकरण कर सकते हैं, ताकि सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में कुछ पिछड़े एवं एससी, एसटी समूहों के लिए दूसरों की तुलना में ज्यादा आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई राजनीतिक दल अब भी एक मत नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे वर्गीय एकता को खतरा है जिससे आरक्षण व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। देखा जाए तो वर्गीय एकता टूटने की उनकी चिंता वास्तविकता को संदर्भित नहीं करती है। यदि उपवर्गीकरण से वर्गीय एकता और चेतना को खतरा होता तो जिन बारह राज्यों में आरक्षण के उपवर्गीकरण की प्रक्रिया पहले से लागू है, उनमें अब तक वर्गीय विभाजन दिखाई देता, जबकि आरक्षण के उपवर्गीकरण से उन बारह राज्यों में वर्गीय एकता मजबूत हुई है, न कि कमजोर हुई है। वर्गीकरण करने वाले प्रदेशों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दोनों राज्य शामिल हैं। उत्तर भारत में प्रमुखता से बिहार शामिल है जिसमें सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने वर्ष 1978 में उपवर्गीकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, वहीं उसी के सशक्तीकरण की प्रक्रिया को नीतीश कुमार ने जमीन पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। तमिलनाडु ने उपवर्गीकरण के सिद्धांत को बेहतरी से लागू किया। इन राज्यों ने वंचितों को समान भागीदारी देने के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसलिए एकता टूटने और आरक्षण प्रक्रिया को कमजोर करने वाले तर्क वास्तविकता से परे प्रतीत होते हैं।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने जाति संरचना की जड़ों को कमजोर करने एवं वंचित तबकों की भागीदारी के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था को अंतिम जन तक पहुंचाने के लिए उपवर्गीकरण की व्यवस्था लागू करने के कदम उठाए। उत्तर प्रदेश में पहला कदम तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने 1975 में छेदी लाल साथी आयोग का गठन करके किया। कर्पूरी ठाकुर और हेमवती नंदन बहुगुणा समकालीन थे और बहुगुणा से पहले बिहार में मुंगेरीलाल कमीशन का गठन हो गया था।

साथी आयोग ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग की तीन श्रेणियां विभाजित कीं, जिसमें कुल 29.5 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। आयोग ने पहली श्रेणी में भूमिहीन और अकुशल मजदूरों को 17 प्रतिशत, दूसरी श्रेणी में दस्तकार और किसानों को 10 प्रतिशत और तीसरी श्रेणी में मुस्लिम पिछड़ी जातियों को 2.5 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन कई कारणों से बहुगुणा सरकार इन सिफारिशों को लागू नहीं कर सकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह ने 2001 में हुकुम सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था। उसके गठन का प्रमुख उद्देश्य आरक्षण के लाभ की जांच करना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचा है जिनके लिए यह लक्षित था। उसने अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग की सूची को उपवर्गीकृत करने की सिफारिश की, ताकि अतिवंचित तबके भी आरक्षण का लाभ उठा सकें। समिति ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को तीन वर्गों में बांटने का सुझाव दिया। उसने पहले वर्ग के लिए पांच प्रतिशत, दूसरे वर्ग में शामिल कुल आठ अतिपिछड़ी जातियों के लिए नौ प्रतिशत, तीसरे वर्ग में शामिल 70 सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की। इस पर खूब विवाद हुआ। अंततः ये सिफारिशें भी लागू नहीं की जा सकीं।

अतिपिछड़ा वर्ग बहुसंख्यक जातियों का विविध समूह है, जिसके अंतर्गत कारीगर, बुनकर, श्रमिक, मछली पालने वाली, नृत्य और गायन करने वाली जातियां एवं बागवानी आदि करने वाली जातियां शामिल हैं। ये जातियां आज भी आरक्षण व्यवस्था में नहीं आ पाई हैं। ये सारी जातियां व्यक्तिगत सेवाएं देने वाली तथा न्यूनतम भूमि का स्वामित्व रखने वाली जातियां हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी जातियां हैं, जिनके साथ छुआछूत जैसा सामाजिक भेदभाव होता है। इसलिए ये जातियां अनुसूचित जाति की सूची में रखे जाने की अर्हता रखती हैं। भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक भी यही अतिपिछड़ी जातियां हैं जिन्हें सरकार से यह उम्मीद है कि वह उनकी भागीदारी के लिए रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेगी, लेकिन अब तक यह रिपोर्ट न प्रकाशित की गई है और न ही इसे लागू किया गया है। इसलिए अतिपिछड़ा वोट बैंक भाजपा से निराश प्रतीत होता दिख रहा है। इसके उदाहरण हालिया लोकसभा चुनाव में देखने को मिले, जहां यूपी में भाजपा को जबरदस्त झटका लगा। यदि योगी आदित्यनाथ यूपी में इस वोट बैंक को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले पंचायत स्तर पर ओबीसी के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत की सीटों का वर्गीकरण करना चाहिए जिससे अतिपिछड़े वोट को लंबे समय तक जोड़े रखा जा सकता है। यह प्रयोग बिहार में नीतीश कर चुके हैं जिससे आज भी अतिपिछड़ी जातियों का वोट उनके साथ है। यदि अतिपिछड़ों के उत्थान के संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तो यह वर्ग नए सामाजिक-राजनीतिक विमर्शों को जन्म दे सकता है।

(लेखक पूर्व सांसद हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ऊर्जा

अच्छे-बुरे की समझ

जीवन यानी संघर्ष, यानी ताकत, यानी संतुलन। संतुलन से ही व्यक्ति स्वयं को स्थायित्व दे सकता है, वरना करोड़ों की भीड़ में अलग पहचान नहीं बन सकती। सभी अपनी-अपनी पहचान के लिए दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई पैसे से, कोई अपनी सुंदरता से, कोई विद्वता से, कोई व्यवहार से अपनी स्वतंत्र पहचान के लिए प्रयास करता है, पर हम कितना भ्रम पालते हैं। हमें स्वतंत्र पहचान के लिए नहीं, बल्कि संतुलित पहचान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संतुलित पहचान चरित्र के बिना नहीं बनती। चरित्र के आधार पर जो प्राप्त होता है, वही स्थायी होता है, बाकी सब अस्थायी है। चरित्र एक साधना है, तपस्या है। जिस प्रकार अहं का पेट बड़ा होता है, उसे रोज कुछ चाहिए। उसी प्रकार चरित्र को रोज संरक्षण चाहिए और यह दृढ़ मनोबल से ही प्राप्त किया जा सकता है।

आज अनेक समस्याएं हैं, जो मनुष्य को घेरे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या है असंतुलित विकास और उससे उत्पन्न नाना प्रकार के रोग। तथाकथित आधुनिक आदमी उन्नति के जिन मुकामों पर पहुंचने की होड़ में शामिल है वे ऐसी अंधी गलियां हैं, जिनमें उतरना तो आसान है, उनसे बाहर निकलना मुश्किल है। विकास का मतलब यह नहीं कि हम नैतिकता को भुला दें, चरित्र की अनदेखी करें। वास्तविक तरक्की तो स्वस्थ जीवनशैली से ही संभव है। स्वस्थ जीवनशैली यानी जो समय को पहचान कर अच्छे-बुरे को समझ कर चले। केवल प्रवाह में नहीं बहे। समाज में संतुलित व्यक्तित्व ही सम्माननीय है और वही स्वीकार्य है।

जो विकास की प्रक्रिया अनुशासन आधारित संहिता से नहीं बंधती, वह विघटन की सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। व्यक्ति की खुशियों को लील कर की जाने वाली प्रगति कैसे स्वीकार्य हो सकती है? यह तो सोची समझी गलती है। अनुशासन ही रोग मुक्ति और स्वस्थ समाज का आधार है और इसी से व्यक्ति का संतुलित विकास संभव है।

ललित गर्ग

कपड़ों की अदला-बदली की पहल

देवेंद्रराज सुथार

फास्ट फैशन के चलन ने न केवल हमारी शापिंग की आदतों को बदला है, बल्कि धरती के संसाधनों पर भी भारी दबाव डाला है

हाल में आयरलैंड में प्रदूषण कम करने के लिए एक अभिनव पहल शुरू की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को कपड़ों की अदला-बदली, उनका पुनः उपयोग और मरम्मत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 'चेंज क्लोथ्स' नामक अभियान के जरिये लोगों को कपड़ों को किराए पर लेने, पुराने कपड़ों की अदला-बदली करने, इस्तेमाल किए गए कपड़ों को बेचने में मदद करने और फटे कपड़ों की मरम्मत के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य समाज में प्रचलित उस धारणा को बदलना है, जो इस्तेमाल किए गए कपड़े पहनना गरीबी का प्रतीक मानती है।

आज के दौर में फास्ट फैशन की बढ़ती लोकप्रियता ने न केवल हमारी शापिंग की आदतों को बदला है, बल्कि धरती के संसाधनों पर भी भारी दबाव डाला है। कपड़ा उद्योग दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषण फैलाने वालों में से एक है। कपड़ों के उत्पादन से लेकर उनके निपटान तक हर चरण में पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। कपास की खेती में भारी मात्रा में पानी और कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, सिंथेटिक फाइबर के उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है और रंगाई प्रक्रिया में खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हर साल लाखों टन कपड़े लैंडफिल में चले जाते हैं, जिससे मिट्टी और जल प्रदूषण होता है। ऐसे में 'चेंज क्लोथ्स' जैसी पहल न केवल कपड़ों के पुनः उपयोग और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है, बल्कि कपड़ों की अदला-बदली और किराए पर लेने से नए कपड़ों की मांग कम होगी, जिससे उत्पादन में कमी आएगी। पुराने कपड़ों की मरम्मत और पुनः उपयोग से कचरे की मात्रा भी कम होगी। हालांकि कपड़ा उद्योग के प्रदूषण को कम करना केवल एक देश या एक संगठन के प्रयासों से संभव नहीं है। वैश्विक स्तर पर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो सस्टेनेबल फैशन को प्रोत्साहित करें। कपड़ा कंपनियों को अपने उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव बताने के लिए बाध्य किया जा सकता है। साथ ही रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को कर लाभ दिया जा सकता है।

उपभोक्ताओं को भी अपनी खरीदारी की आदतों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमें वास्तव में हर सीजन में नए कपड़े खरीदने की जरूरत है? यदि हम वास्तव में एक स्वस्थ भविष्य चाहते हैं, तो हमें अपने फैशन विकल्पों पर पुनर्विचार करना होगा। 'चेंज क्लोथ्स' जैसी पहल हमें दिखाती है कि यह संभव है। अब समय आ गया है कि हम सभी इस दिशा में कदम बढ़ाएं और एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां फैशन और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

विनाशकारी रूप लेता युद्ध

'युद्ध के मुहाने पर पश्चिम एशिया' शीर्षक से लिखे आलेख के तहत संजय गुप्त ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि युद्ध सबके के लिए हानिकारक होता है और दुनिया के सभी देशों को भारत के विचार यानी अहिंसा की राह पर चलना चाहिए। मानवता के दुश्मनों और मजहब के ठेकेदारों ने आज विश्व शांति को खतरे में डाला है। खासतौर पर मुस्लिम देशों में रहने वाले पंथ विशेष के कट्टरपंथियों ने। ईरान ने इजरायल पर अप्रैल में हमला किया था, उसी समय से इन दोनों में तनाव चल रहा है और अब ईरान ने नए सिरे से इजरायल पर हमला बोल दिया है। ईरान-इजरायल के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उससे देखते हुए कुछ लोग यह मान रहे हैं कि इन दोनों देशों का यह तनाव विश्व को विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकता है। हम जानते हैं कि विश्व युद्ध मानव जाति के विनाश का कारण बन सकता है। युद्ध चाहे किसी भी युग में क्यों न हो हमेशा बर्बादी ही लाता है, लेकिन दुख की बात है कि मानव युद्ध में ही विश्वास कर रहा है। ईरान और इजरायल के युद्ध के चलते जिन व्यापारियों या कारोबारियों ने इन देशों को माल भेजा होगा, उनकी पेमेंट फंस सकती है और इन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है। दूसरे देशों को इनमें समझौता करवाने के लिए गंभीरता दिखानी चाहिए। जापान के दो शहरों के लोग आज तक अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बमों के दुष्परिणामों को झेल रहे हैं। जो देश अपने यहां आतंकवाद को पालते हैं और आतंक फैलाते हैं उनके खिलाफ भी दुनिया को सख्ती दिखानी होगी।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

खास रहे विधानसभा चुनाव

हरियाणा विधानसभा के चुनाव के मतदान में 1,031 प्रत्याशियों के साथ 101 महिलाओं का भाग्य विधायक बनने के लिए ईवीएम मशीनों में बंद हो गया है। एक ओर जहां भाजपा ने प्रदेश में ''डबल इंजन'' सरकार बनाने के लिए एक दशक के विकास कार्यों का प्रचार-प्रसार किया तो विपक्षी दलों ने बेरोजगारी, अग्निवीर योजना और किसानों को एमएसपी की गारंटी का मुद्दा बनाया। पार्टियों ने अपने घोषणा पत्रों में बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाए। चुनाव खत्म होते ही शुरू हुए एक्जिट पोल के माध्यम से मीडिया जादुई आंकड़े पेश कर रहा है। कौन सा दल एवं उम्मीदवार मतदाता के मन-मष्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ने में सफल हुआ है, यह तो मतगणना के बाद विदित होगा। तब तक तो केवल कयास ही लग रहे हैं। लेकिन किसकी सरकार बनेगी और कौन पिछड़ जाएगा, ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इस बार के चुनाव खास रहे हैं।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

संयुक्त राष्ट्र की खत्म होती प्रासंगिकता

समकालीन समय में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि विश्व में होने वाले युद्ध को रोक सके तथा विश्व में शांति और सहयोग को बढ़ा कर विश्व को युद्ध मुक्त कर सके। लेकिन इसकी नाक के नीचे पूरी दुनिया में आतंकवाद फैल गया और यह कुछ नहीं कर सका है। यह इसकी सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। इसकी पूर्ववती संस्था राष्ट्र संघ इसलिए असफल हुआ था, क्योंकि वह विश्व राजनीति के विभिन्न विषयों (युद्ध और गृहयुद्ध) पर तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए सिर्फ तमाशा देखता रहा। आज फिर वही स्थिति संयुक्त राष्ट्र के साथ दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन, इजरायल और लेबनान, हमास युद्ध के नाम पर जनमानस का नरसंहार हो रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र इन युद्धों को रोकने में असफल साबित दिख रहा है। वर्तमान में जो विश्व की राजनीति है, उसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र को अपनी भूमिका की समीक्षा करनी होगी, अन्यथा इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र को प्रभावी बनानी के लिए जरूरी है कि इसकी सबसे प्रभावशाली संस्था सुरक्षा परिषद में सुधार हो। इसके अनुसार सुरक्षा परिषद में भारत, जापान, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, ब्राजील को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

लक्ष्य की स्पष्टता के अभाव में जीवन की सार्थकता संभव नहीं

ड्रग्स का खतरा

दिल्ली के बाद भोपाल के निकट ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद किया जाना यही बताता है कि किस तरह ड्रग्स तस्करों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। भोपाल के निकट नौ सौ किलो जो ड्रग्स बरामद की गई, वह वहीं पर निर्मित की जा रही थी। इसका अर्थ है कि अब देश में बाहर से ड्रग्स लाने के साथ ही देश में उसका चोरी-छिपे निर्माण भी किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर ड्रग्स को तैयार करने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इसी तरह बाहर से बड़ी मात्रा में तस्करी के जरिये ड्रग्स लाने के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली में पांच सौ किलोग्राम से अधिक जो ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसे बाहर से ही लाया गया था। अच्छी बात यह है कि ड्रग्स तस्करी के मामले बढ़े हैं तो उसकी बरामदगी और तस्करों को गिरफ्तार करने में भी उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस सफलता का श्रेय गृह मंत्री अमित शाह को जाता है, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां ड्रग्स के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए मिलकर काम करें। विभिन्न एजेंसियों में तालमेल के सकारात्मक नतीजे भी सामने आए हैं, लेकिन यह ठीक नहीं कि अब अपने देश में जमीनी और समुद्री रास्तों के साथ-साथ हवाई मार्ग से भी बड़े पैमाने पर ड्रग्स आ रही है। ड्रग्स की बढ़ती तस्करी यही बताती है कि देश में मादक पदार्थों की खपत बढ़ाने, युवाओं का भविष्य खराब करने और अवैध तरीके से पैसा बनाने वालों की सक्रियता बढ़ रही है। इस सक्रियता पर इसलिए प्राथमिकता के आधार पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि ड्रग्स तस्करी से अर्जित धन का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी संगठनों को मजबूत करने में भी किया जाता है। आवश्यक केवल यह नहीं है कि दूसरे देशों से ड्रग्स की आपूर्ति पर लगाम लगाई जाए, बल्कि इसकी भी है कि देश में उसके वितरण के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाए। यह ठीक नहीं कि पिछले कुछ समय से किस्म-किस्म के मादक पदार्थ सीमावर्ती राज्यों के साथ देश के अंदरूनी इलाकों और छोटे शहरों तक में पहुंच रहे हैं। स्पष्ट है कि देश में ड्रग्स की खपत बढ़ाने की साजिश रची जा रही है। यह साजिश लोगों और विशेष रूप से युवाओं को ड्रग्स का लती बनाकर ही की जा सकती है। चूंकि ऐसा हो रहा है, इसलिए ड्रग्स के खिलाफ समाज को भी चेतना होगा। उसे न केवल छिटपुट स्तर पर ड्रग्स की बिक्री करने वाले तत्वों पर निगाह रखनी होगी, बल्कि युवाओं को ड्रग्स सेवन के दुष्परिणामों के प्रति भी सचेत करना होगा। ड्रग्स की लत लोगों को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। यह ठीक है कि ड्रग्स के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए मानस नाम से एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, लेकिन उसकी सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि आम लोग ड्रग्स की खरीद-बिक्री और उसके सेवन के प्रति कितनी अधिक सजगता का परिचय देते हैं।

निष्पक्षता से हो आकलन

प्रदेश के कई जिले बाढ़ की विभीषिका झेल चुके हैं या उससे जूझ रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर बनाए गए, जहां उन्हें ठिकाना मिला। प्रभावित जिलों में स्थानीय प्रशासन का दावा है कि राहत शिविर में पीड़ितों की दैनिक जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि, कुछ जगहों से शिकायतें भी मिली हैं। सरकार के स्तर पर बाढ़ प्रभावितों को हरसंभव मदद का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, बल्कि राहत शिविरों में पहुंचकर वहां की व्यवस्था का निरीक्षण भी किया। सरकार के स्तर पर प्रथम चरण में बाढ़ प्रभावितों के खाते में सात-सात हजार रुपये भी भेजे गए हैं। दुर्गा पूजा से पहले दूसरे चरण की राशि भेजने का सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है। दुर्गापूजा को लेकर यह आर्थिक मदद पीड़ितों की पीड़ा को कुछ हद तक कम करने में मददगार होगी। कई नदियों का जलस्तर कम होने से निचले इलाकों से पानी उतर रहा है और इसके साथ अन्य तरह की दुश्वारियां सामने आ रही हैं। इधर, बाढ़ के कारण जिन किसानों की फसल डूब गई है, उनका भी ध्यान सरकार रख रही है। सितंबर के पहले सप्ताह में गंगा में अत्यधिक पानी आने से संबंधित जिलों के किसानों की बड़े पैमाने फसल नष्ट हो गई थी। ऐसे प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने फसल क्षति लागत अनुदान देने का निर्णय लिया है। विभाग ओर से पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो प्रभावित किसान हैं, वह हर हाल में आवेदन करें। साथ ही, बाढ़ के कारण फसल की जो क्षति हुई है, उसका उचित आकलन किया जाए।

बाढ़ से हुई फसल क्षति के आकलन में पूरी तरह निष्पक्षता बरती जाए, ताकि प्रभावित किसानों को उचित अनुदान मिल सके।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या विदेश मंत्री एस. जयशंकर का एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला सही है?

आज का सवाल

क्या आपको लगता है कि कोटे में कोटा संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर केंद्र सरकार ने गलती की?

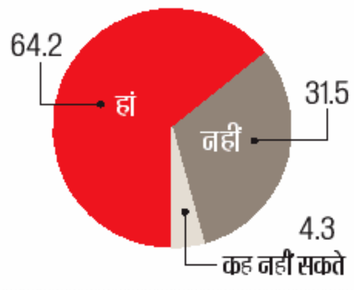

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अपना घर देखे अमेरिका

हृदयनारायण दीक्षित

अमेरिका खुद अपनी समाज व्यवस्था दुरुस्त करने में विफल है, लेकिन उसकी संस्थाएं धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत को उपदेश दे रही हैं

अमेरिकी संस्था 'यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फार इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' की हाल में एक रिपोर्ट आई है। इसमें भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की आलोचना की गई है। रिपोर्ट में नफरती भाषणों, तथ्यहीन सूचनाओं और सरकारी अधिकारियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ उकसाने का उल्लेख है। संस्था ने मनगढ़ंत तरीके से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को खराब बताया है। भारत ने उचित ही अमेरिकी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया में कहा है कि 'पक्षपातपूर्ण राजनीतिक एजेंडा चलाने के बजाय इस संगठन को मानवाधिकार के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।' अनुच्छेद-19 के अंतर्गत भारत में विचार प्रकट करने की आजादी है। इसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी अनुच्छेद 25-28 में है, लेकिन अमेरिकी संस्था ने इन तथ्यों पर विचार नहीं किया। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हित सुनिश्चित हैं और वे सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित हैं। वे राष्ट्रपति जैसे शीर्ष पदों पर रह चुके हैं। रिपोर्ट में भारत के कुछ कानूनों को धार्मिक भेदभाव बढ़ाने वाला बताया गया है। मतांतरण, हिजाब, गोहत्या और नागरिकता संबंधी कानूनों को अल्पसंख्यकों पर प्रतिकूल प्रभावकारी बताया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्वाभाविक रूप से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर हम भी कुछ बोलें तो बुरा मत मानना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी संस्था घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है। उसे ऐसा एजेंडा चलाने के बजाय अमेरिकी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर भारतीय समाज को बदनाम करना ही उनका लक्ष्य है।

भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। परस्पर संप्रभुता का सम्मान सभी राष्ट्रों का कर्तव्य है। धार्मिक स्वतंत्रता पर 2004 में जारी एक रिपोर्ट में भी ऐसा ही कहा गया था। इस प्रकरण के मूल में अमेरिकी समाज की विश्व पर राज करने की महत्वाकांक्षा है। ऐसी अनेक संस्थाएं अमेरिका में हैं और जर्मनी में भी। यूके में भी रिलीजियस पर्सिक्यूशन एंड वर्ल्ड वाच रिपोर्ट नाम से ही ऐसी रिपोर्ट तैयार होती है। उसके लिए हाउस आफ कामंस से निर्देश भी मिलते हैं। भारत के कथित 'माब लिंचिंग' की चर्चा भी अमेरिकी संस्था की हालिया रिपोर्ट में है जबकि हिंसक भीड़ की ऐसी घटनाएं अमेरिका में भी घटित होती हैं। कुछ समय पहले ही एक श्वेत पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन ने अश्वेत जार्ज फ्लायड की निर्मम हत्या कर दी थी। उसके परिणामस्वरूप श्वेत-अश्वेत के बीच दंगे भड़के थे। 'ब्लैक लाइव्स मैटर्स' नाम का अभियान चला था। काले-गोरे के भेद हिंसा तक जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि अमेरिकी समाज में अश्वेतों को घर छोड़ने को मजबूर किया गया था। आस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा में एशियाई मूल के लोगों के साथ नस्ली भेदभाव की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं।

अवधेश राजपूत

अमेरिका अपने देश में व्याप्त हिंसा की चिंता नहीं करता। लोग सरेआम गोलियां चलाते हैं। आर्म लाइसेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों के हाथ में पिस्तौलें हैं। नशे की गोलियां हैं। विश्व-प्रतिष्ठित अमेरिकी भाषा विज्ञानी नोम चोम्स्की ने अमेरिकी समाज के बारे में चिंता जताई थी। हार्वर्ड एजुकेशनल रिव्यू के संपादकों ने 'हिंसा और नौजवान' विषय पर उनका साक्षात्कार लिया। चोम्स्की ने कहा कि 'हिंसा के सहारे ही अमेरिकी पूंजीवाद का विकास हुआ। अमेरिकी महाद्वीप को आबाद करने वाले ब्रिटेन और यूरोप के गोरे व्यापारी यहां आए। हजारों साल से यहां रहने वाले आदिवासियों का संहार किया। जो बचे उन्हें उजाड़ स्थानों पर धकेल दिया।' चोम्स्की ने उन आदिवासियों को 'इंडियन' कहा। याद रहे कि कोलंबस सहित जो लोग अमेरिका का पता लगा सके, वे दरअसल भारत का पता लगाने निकले थे। अमेरिकी समाज मूल रूप में ही हिंसा के विचार पर आधारित है। अमेरिकी समाज परस्पर लड़ता-झगड़ता एवं टूटा हुआ है। अमेरिकी समाज में ईसाई समुदाय दो भागों में विभाजित है और बहुधा टकराव देखने को मिलते हैं। अमेरिका में मानवाधिकारों का उल्लंघन सामान्य घटना है। अमेरिका खालिस्तान समर्थकों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। इसमें कनाडा भी शामिल है। आश्चर्य है कि जो देश अपनी समाज व्यवस्था दुरुस्त करने में विफल हैं, वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपने एजेंडे पर चलाना चाहते हैं।

अधिकांश अमेरिकी श्रेष्ठता ग्रंथि के शिकार हैं। वे सारी दुनिया को मार्गदर्शन-उपदेश देना चाहते हैं। वे विचार प्रकट करने के सभी साधनों को अपनाते हैं। यूरोपीय भी उनके संगी-साथी हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, 'भारत राजनीतिक इकाई नहीं, बल्कि 'भौगोलिक अमूर्तता' है। भारत कभी स्वतंत्र राष्ट्र नहीं हो सकता। ब्रिटिश क्राउन से अलग होने के बाद भारत के लोग जंगल में जाकर लड़ेंगे।' उन्होंने यह भी कहा था कि, 'एक शिक्षित वायसराय भारत में शांति व्यवस्था बनाए रख सकता है।' चर्चिल की बात गलत निकली। भारत अपने पुरुषार्थ-पराक्रम एवं दृढ़ संकल्प से स्वतंत्र हुआ। सफल राष्ट्र साबित हुआ। संप्रति पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। मूलभूत प्रश्न है कि ऐसी तथ्यहीन टीका-टिप्पणियों से कैसे बचा जाए? क्या भारत को भी प्रतिकार स्वरूप ऐसी ही संस्थाओं का विकास करना चाहिए? ऐसी टिप्पणियों का ठोस प्रतिकार आवश्यक है।

अमेरिकी समाज में किशोरों को भी अपराध में लिप्त देखा जाता है। तब किसे दोष दें? अमेरिकी समाज में परिवार के मुखिया सामान्य तौर पर बच्चों को समय नहीं देते। आत्मनिर्भर होते ही बच्चे और संरक्षक अलग-अलग रहते हैं। बुजुर्ग एकांतवास में दुखी रहते हैं। इसके विपरीत भारत में परिवार नाम की संस्था दृढ़ एवं मजबूत है। मजबूत परिवार घर चलाने के साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। समाज प्रेमपूर्ण ढंग से चलता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। दुर्भाग्य से वे भारतीय समाज के मुख्य तथ्यों पर ध्यान नहीं देते। अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग डेढ़ सौ साल बाद महिलाओं को मताधिकार दिया, बल्कि भारत में पहले आम चुनाव से ही महिलाओं को मतदान में समान अधिकार दिए गए। भारतवासी विश्व को एक अखंड सत्ता एवं परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम् भारत का संकल्प है। अमेरिका को भारत के राष्ट्रजीवन से सीखना चाहिए।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा क्षेत्र में बिहार की प्रगति गाथा

बिजेंद्र प्रसाद यादव

मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना के तहत हर घर बिजली का लक्ष्य प्राप्त किया, जो सात निश्चय योजना का प्रमुख हिस्सा था

ऊर्जा विभाग, बिहार ने राज्य में ऊर्जा सुधार और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार की दूरदर्शी नीतियों और निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत वितरण, संचरण, उत्पादन और उपभोक्ता सेवाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। राज्य के सभी जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही ऊर्जा विभाग ने नवीकरणीय ऊर्जा यथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बिजली के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और तकनीकी सुधारों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने का कार्य वर्तमान में भी सतत रूप से जारी है।

बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में हुई ऐतिहासिक प्रगति से राज्य के विकास में अभूतपूर्व तेजी आई है। सरकार ने इस दिशा में कई योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया, जिनमें ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना मुख्य है। सात निश्चय योजना के फेज-1 के तहत, 'हर घर बिजली' को एक प्रमुख निश्चय के रूप में रखा गया, जिसका उद्देश्य हर घर तक बिजली पहुंचाना था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई। बिहार का यह माडल इतना प्रभावशाली और सफल रहा कि इसे केंद्र सरकार से भी सराहा गया। परिणामस्वरूप, अगस्त 2017 में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा बिहार में यूनिवर्सल हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के फलस्वरूप 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य देश में सभी को बिजली प्रदान करना था।

बिहार की वितरण कंपनियों ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की और निर्धारित लक्ष्य, जो दिसंबर 2018 तक था, उसे दो महीने पूर्व ही 25 अक्टूबर 2018 को प्राप्त कर लिया। केंद्र सरकार द्वारा विद्युतीकरण के लिए नालंदा को प्रथम एवं किशनगंज को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना के तहत हर घर बिजली का लक्ष्य प्राप्त किया गया, जो सात निश्चय कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा था। इस योजना ने न केवल लोगों के जीवन में सुधार किया, बल्कि राज्य में औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को भी प्रोत्साहन दिया। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली की सुलभता से विकास की गति को तेज किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य में बिजली आपूर्ति और वितरण को और भी बेहतर बनाने के लिए पुरानी और जर्जर तारों को बदलने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया है। रिकंडक्टरिंग योजना के तहत राज्य के कुल 87,334 सर्किट किलोमीटर जर्जर व पुराने वितरण लाइनों को बदला गया, जिसमें 47,744 सर्किट किलोमीटर एलटी, 2730 सर्किट किलोमीटर 33 केवी, 36,880 सर्किट किलोमीटर 11 केवी की लाइन शामिल हैं। इससे न केवल बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि बिजली चोरी और दुर्घटनाओं की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

इसके साथ ही, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी प्रदान करने का भी काम किया है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना समाज के उन वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है जो बिजली के भारी बिलों का बोझ नहीं उठा सकते थे। राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या वर्तमान में दो करोड़ से अधिक हैं, जिनमें घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 88 प्रतिशत है। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं में 50 प्रतिशत ग्रामीण, 33 प्रतिशत कुटीर ज्योति तथा शेष शहरी है। वर्ष 2021-22 में उपभोक्ता अनुदान की राशि 6578 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 7801 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2024-25 में 15,343 करोड़ हो गई है। इसमें किसानों को 6.74 रुपये प्रति यूनिट की दर के विरुद्ध मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही भुगतान करना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को पटवन के लिए बिजली मद में वर्ष 2021-22 में 934.74 करोड़ रुपये अनुदान दिया गया, जिसे 2023-24 में बढ़ाकर 3,856.80 करोड़ कर दिया गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को भी अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने किसानों को सस्ती और सुलभ बिजली उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना (2020) और सात निश्चय भाग-2 के तहत 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' पहुंचाने की प्रतिबद्धता के साथ अब तक 4.15 लाख निशुल्क कृषि कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बिहार, जहां 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, में कृषि मुख्य पेशा है। इसके तहत, राज्य सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य कृषि हेतु अलग फीडर का निर्माण करना है। योजना में राज्य में 291 शक्ति उपकेंद्र और 1354 कृषि फीडरों का निर्माण हुआ, जिससे किसानों को निर्बाध विद्युतापूर्ति सुनिश्चित हो सके। सितंबर 2020 में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत 1329.61 करोड़ रुपये की नई योजना स्वीकृत हुई, जो राज्य के 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' मिशन का अहम हिस्सा है। योजना के तहत लाखों किसानों को विद्युत संबंध प्रदान कर उनकी सिंचाई की समस्याओं को दूर किया गया है।

जलवायु परिवर्तन के चलते बिहार के किसानों को सूखे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में, राज्य सरकार ने कृषि फीडरों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की, ताकि किसान अपने खेतों की सिंचाई निर्बाध रूप से कर सकें। आने वाले तीन वर्षों में 4.80 लाख निशुल्क कृषि विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2190.75 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। बिहार के चौथे कृषि रोडमैप (2023-28) का शुभारंभ 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा किया गया, जिसमें किसानों के हितों को केंद्र में रखते हुए अनेक योजनाओं का समावेश किया गया है। इसके साथ ही, राज्य सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि फीडरों के सोलराइजेशन पर भी काम कर रही है, जिससे बिजली की लागत कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना के तहत 1200 करोड़ रुपये लागत की योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रति मेगावाट 1.50 करोड रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से राज्य के कृषि क्षेत्र में एक हरित क्रांति का सूत्रपात भी होगा। ये योजनाएं न केवल कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दे रही है, बल्कि बिहार के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी हैं। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र की यह प्रगति राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की प्रतिबद्धता रही है कि राज्य के हर नागरिक को सस्ती, सुरक्षित और निरंतर बिजली आपूर्ति मिल सके। इन योजनाओं ने न केवल बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि की दिशा में भी नए रास्ते खोले हैं।

(लेखक बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ऊर्जा

अच्छे-बुरे की समझ

जीवन यानी संघर्ष, यानी ताकत, यानी संतुलन। संतुलन से ही व्यक्ति स्वयं को स्थायित्व दे सकता है, वरना करोड़ों की भीड़ में अलग पहचान नहीं बन सकती। सभी अपनी-अपनी पहचान के लिए दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई पैसे से, कोई अपनी सुंदरता से, कोई विद्वता से, कोई व्यवहार से अपनी स्वतंत्र पहचान के लिए प्रयास करता है, पर हम कितना भ्रम पालते हैं। हमें स्वतंत्र पहचान के लिए नहीं, बल्कि संतुलित पहचान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संतुलित पहचान चरित्र के बिना नहीं बनती। चरित्र के आधार पर जो प्राप्त होता है, वही स्थायी होता है, बाकी सब अस्थायी है। चरित्र एक साधना है, तपस्या है। जिस प्रकार अहं का पेट बड़ा होता है, उसे रोज कुछ न कुछ चाहिए। उसी प्रकार चरित्र को रोज संरक्षण चाहिए और यह सब दृढ़ मनोबल से ही प्राप्त किया जा सकता है।

आज अनेक समस्याएं हैं, जो मनुष्य को घेरे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या है असंतुलित विकास और उससे उत्पन्न नाना प्रकार के रोग। तथाकथित आधुनिक आदमी उन्नति के जिन मुकामों पर पहुंचने की होड़ में शामिल है वे ऐसी अंधी गलियां हैं, जिनमें उतरना तो आसान है, लेकिन उनसे बाहर निकलना मुश्किल है। विकास का मतलब यह नहीं कि हम नैतिकता को भुला दें, चरित्र की अनदेखी करें। वास्तविक तरक्की तो स्वस्थ जीवनशैली से ही संभव है। स्वस्थ जीवनशैली यानी जो समय को पहचान कर अच्छे-बुरे को समझ कर चले। केवल प्रवाह में नहीं बहे। समाज में संतुलित व्यक्तित्व ही सम्माननीय है और वही स्वीकार्य है।

जो विकास की प्रक्रिया अनुशासन आधारित संहिता से नहीं बंधती, वह विघटन की सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। प्रगति कम हो, स्वीकार्य है, पर व्यक्ति की खुशियों को लील कर की जाने वाली प्रगति कैसे स्वीकार्य हो सकती है? यह तो सोची समझी गलती है। अनुशासन ही रोग मुक्ति और स्वस्थ समाज का आधार है और इसी से व्यक्ति का संतुलित विकास संभव है।

ललित गर्ग

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

विनाशकारी रूप लेता युद्ध

'युद्ध के मुहाने पर पश्चिम एशिया' शीर्षक से लिखे आलेख के तहत संजय गुप्त ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि युद्ध सबके के लिए हानिकारक होता है और दुनिया के सभी देशों को भारत के विचार यानी अहिंसा की राह पर चलना चाहिए। मानवता के दुश्मनों और मजहब के ठेकेदारों ने आज विश्व शांति को खतरे में डाला है। खासतौर पर मुस्लिम देशों में रहने वाले पंथ विशेष के कट्टरपंथियों ने। ईरान ने इजरायल पर अप्रैल में हमला किया था, उसी समय से इन दोनों में तनाव चल रहा है और अब ईरान ने नए सिरे से इजरायल पर हमला बोल दिया है। ईरान-इजरायल के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उससे देखते हुए कुछ लोग यह मान रहे हैं कि इन दोनों देशों का यह तनाव विश्व को विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकता है। हम जानते हैं कि विश्व युद्ध मानव जाति के विनाश का कारण बन सकता है। युद्ध चाहे किसी भी युग में क्यों न हो हमेशा बर्बादी ही लाता है, लेकिन दुख की बात है कि मानव युद्ध में ही विश्वास कर रहा है। ईरान और इजरायल के युद्ध के चलते जिन व्यापारियों या कारोबारियों ने इन देशों को माल भेजा होगा, उनकी पेमेंट फंस सकती है और इन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है। अब जिस तरह मिसाइलों से युद्ध लड़े जा रहे हैं, वे प्रकृति पर भी बुरा असर डाल रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों को इन दोनों में तनाव कम करने के लिए इनमें समझौता करवाने के लिए गंभीरता दिखानी चाहिए। बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा के लोग आज तक अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बमों के बुरे परिणामों को झेल रहे हैं। जो देश अपने यहां आतंकवाद को पालते हैं और आतंक फैलाते हैं उनके खिलाफ भी दुनिया को सख्ती दिखानी होगी।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

चिदंबरम बनाम सीतारमण

कोई भी एक आंकड़ा कुछ भी बयान नहीं करता है। किसी दूसरे आकड़े से तुलनात्मक विश्लेषण से ही उसका महत्व ज्ञात होता है। प्रख्यात अर्थशास्त्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना था कि 'पैसे पेड़ पर नहीं उगते।' जबकि वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी प्रतिवर्ष 9.21 करोड किसानों को 6,000 रुपये सम्मान निधि के तौर पर दे रहे हैं। यह उनके समय के वित्त मंत्रियों की दक्षता को दिखाता है। चिदंबरम के कार्यकाल (2009-14) में बैंकों में एनपीए 11 प्रतिशत तक पहुंच गया था। सीतारमण ने कुशल प्रबंधन से उसको मात्र दशमलव छह प्रतिशत तक ला दिया। जिससे बैंकों के लाभ में पर्याप्त वृद्धि हुई। चिदंबरम आयकर में छूट दो लाख तक ही दे पाए। जबकि सीतारमण ने आयकर में छूट की सीमा 7.75 लाख तक बढ़ा दी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चिदंबरम अपने चार साल के कार्यकाल में मात्र 1.57 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध करा पाये थे पर समान अवधि में सीतारमण ने 44.3 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए। चिदंबरम जीएसटी को लागू करने का साहस नहीं दिखा सके, जबकि आज सरकार को उसी से प्रतिवर्ष 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक मिल रहे हैं। चिदंबरम के समय में मात्र 50 अरब डालर का फारेन करेंसी रिजर्व था, जो सीतारमण के समय में बढ़कर 350 अरब डालर का हो गया।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, दुर्गादेवी मंदिर मार्ग, चौक, पटना

उपवास भारतीय संस्कृति

सामान्य जीवन में लोग घंटे, दो घंटे भूखे रहने पर परेशान हो जाते हैं, क्षुधा तृप्ति के लिए प्रयास करने लगते हैं, एक दिन का भोजन नहीं मिले तो ऐसा लगता है कि जीवन कैसे चलेगा लेकिन नवरात्रि के नौ दिनों में उपवास की जो प्रक्रिया चलती है, वह अपने आप में मिसाल है। उपवास का स्वरूप भारतीय संस्कृति की विशालता को दर्शाता है। उपवास की प्रक्रिया शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि का वाहक बनता है। कुछ लोग भक्तिभाव में इतने लीन हो जाते हैं कि केवल फल खाकर नौ दिनों तक रह जाते हैं। विचित्र यह भी है कि उपवास करने वाले भक्त घर में आराम भी नहीं करते हैं, दिनचर्या के कार्य व अपने कार्यस्थल के कार्य पूर्ववत करते रहते हैं। यह भक्ति भाव या आस्था जिस समर्पण के साथ बिना अन्न ग्रहण करके रखा जाता है, वह यह दर्शाता है कि इस संसार पर केवल व्यक्ति का ही नियंत्रण नहीं है बल्कि कुछ ऐसी सर्वोच्च शक्ति भी है, जो मानव मन और तन को नियंत्रित करती है। इस तरह की भक्ति भावना चिरकाल से हमारी भारतीय संस्कृति रही है, साथ ही यह भी सत्य है कि उपवास को करने में हमारी पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं आगे रहती हैं। हमारी संस्कृति में नवरात्रि के माहौल में कन्या को देवी समझ पूजा जाता है। कन्या की आराधना की जाती है और कहीं ना कहीं यह नवरात्रि स्त्री के सम्मान का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में भी उपवास के फायदे बताए गए हैं।

डा. मिथिलेश कुमार भागलपुर

पोस्ट

राम-रहीम लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिता पाए थे क्या? एक बार किसी की हवा बन जाए तो बरसों-बरस लोग उसी की खाते रहते हैं। यह कुछ ऐसा ही मामला दिख रहा है। हर्ष वर्धन त्रिपाठी@MediaHarshVT

देश में सभी चुनाव एक साथ कराने का एक लाभ यह भी होगा कि राम-रहीम जैसे लोगों के लिए पांच साल में एक बार ही पैरोल से काम चल जाएगा। हर दूसरे महीने ऐसे लोग जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। संकेत उपाध्याय@sanket

नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से कोसी और गंडक में इतना पानी छोड़ा गया कि लगभग आधे बिहार में बाढ़ की स्थिति है। यह वह भौगोलिक दशा है, जो तमिलनाडु, राजस्थान या हरियाणा में नहीं है और लोग बिहार के पिछड़ेपन को लेकर अक्सर सामाजिक-राजनीतिक कारणों को ढूंढ़ने में व्यस्त रहते हैं।

सुशांत झा@jhasushant

एक्जिट पोल्स के अनुसार हरियाणा की 19 सीटों पर कांटे का मुकाबला है। ये सीटें कांग्रेस के पक्ष में गईं तो पार्टी का आंकड़ा 67 सीट तक जा सकता है। अगर ये सीटें भाजपा के पक्ष में गईं तो कांग्रेस की गाड़ी साधारण बहुमत तक पहुंच सकती है।

मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

जनपथ

हरियाणा की भूमि हो या जम्मू-कश्मीर,
लड़े लगाकर जोर हैं सभी चुनावी वीर।
सभी चुनावी वीर जंग हो चाहे कैसी,
है अजेय हर बार देश में डेमोक्रेसी।
टूटे ना सौहार्द

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

न्याय की अदालतों से भी बड़ी एक अदालत है और वह है अंतरात्मा की अदालत। -महात्मा गांधी

छत्तीसगढ़ में करीब तीस नक्सलियों का मारा जाना नक्सलवाद के खिलाफ लंबे अरसे से चली आ रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कामयाबी है। यह सही वक्त हो सकता है, जब सुरक्षाबलों के शौर्य की बदौलत कमजोर हो रहे नक्सलियों को बगैर हिंसा के मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करने के प्रयास भी हों।

महत्वपूर्ण कामयाबी

ऐसे वक्त में, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद क्षेत्र के दौरे पर हों, तभी बस्तर के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों की सीमा पर हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों द्वारा करीब तीस नक्सलियों को मार गिराना देश में नक्सलवाद के खिलाफ लंबे अरसे से चली आ रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कामयाबी को दर्शाता है। यह राज्य में नक्सलियों व सुरक्षा बलों के बीच हुई अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ तो है ही, इसका महत्व तब और बढ़ जाता है, जब अभियान में शामिल सभी जवान पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों वाले ये इलाके लंबे समय से नक्सलियों के गढ़ रहे हैं, जहां वे न केवल सरकारी ढांचे और सुरक्षा बलों पर हमले करते रहे हैं, बल्कि स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर भी उन्हें आतंकित करते रहे हैं। पर राज्य में पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के खिलाफ अभियानों में सुरक्षा बलों को जो कामयाबियां मिली हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि सुरक्षा बल अब नक्सलियों के खिलाफ अधिक सशक्त, संगठित और योजनाबद्ध ढंग से तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार को अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ है, ऐसे में इस दौरान रिकॉर्ड संख्या में नक्सलियों का मारा जाना, खुद में एक उपलब्धि है और यह इस समस्या को खत्म करने के प्रति राजनीतिक इच्छाशक्ति को ही दिखाता है। नक्सलियों से मुठभेड़ पहले भी होती थीं, लेकिन अब फर्क यह है कि पहले जहां इन घटनाओं में नक्सलियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को भी नुकसान पहुंचते थे, जो उत्तरोत्तर कम होते दिख रहे हैं। दरअसल, नक्सलवाद महज कानून-व्यवस्था की समस्या न होकर सामाजिक-आर्थिक समस्या भी है। लिहाजा, वर्तमान में केंद्र व नक्सलवाद पीड़ित राज्यों की सरकारों के तालमेल से 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो रणनीति अपनाई जा रही है, उसकी सबसे खास बात ही यह है कि इसमें नक्सलवादियों के खात्मे के बाद पैदा हुए शून्य

को सरकारी योजनाओं से भरने के प्रयास न सिर्फ हो रहे हैं, होते दिख भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में नक्सलियों पर काबू पाने के कड़े प्रयासों के बावजूद मानवाधिकारों के हनन की शिकायतों में भी कमी आना राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही रणनीति में संतुलन को ही दर्शाता है। सुरक्षाबलों द्वारा दिखाए जा रहे शौर्य से नक्सलवादी निस्संदेह कमजोर हुए हैं, ऐसे में, यह सही वक्त हो सकता है, जब बगैर हिंसा के उन्हें मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करने के भी प्रयास हों।

सबसे बड़ा सवाल, सबूत कहां से लाएंगे

मैरिटल रेप में क्या सिर्फ पत्नी के बयानों के आधार पर ही पति को सजा दी जा सकती है? यह सवाल कानून के संभावित दुरुपयोग का नहीं, बल्कि अपराधशास्त्र के बुनियादी उसूलों से जुड़ा है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से विवाह संस्था और परिवार के ध्वस्त होने का भी खतरा है।

फिल्मी अदालतों में सबसे प्रचलित डायलॉग है कि कानून को सबूत चाहिए। अगर यह मान लें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैरिटल रेप यानी वैवाहिक दुष्कर्म के मामले भी अपराध के दायरे में आ जाएंगे, तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल सबूतों का रहेगा। कानून के अनुसार, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जांच कराती है। विवाहित महिला की मेडिकल जांच में सेक्स संबंधों की पुष्टि होना स्वाभाविक है। रेप के मामले गैर-जमानती होते हैं, जिनमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होती है। एफआईआर के बाद मैकेनिकल तरीके से पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और अदालतों में जमानत की अर्जी रद्द करने का प्रचलन बढ़ा है। कई साल बाद जब मुकदमे में ट्रायल शुरू होगा, तो सबूतों को लेकर प्रश्न खड़े होंगे। बेडरूम में पति-पत्नी के अलावा तीसरा व्यक्ति या सीसीटीवी नहीं होता। यह निजता का भी उल्लंघन है। सहमति के बगैर जबरदस्ती बनाए गए संबंध, यानी मैरिटल रेप में क्या सिर्फ पत्नी के बयानों के आधार पर ही पति को सजा दी जा सकती है? यह सवाल कानून के संभावित दुरुपयोग का नहीं, बल्कि अपराधशास्त्र के बुनियादी उसूलों से जुड़ा है। मैरिटल रेप अगर अपराध घोषित हो गया, तो यह कानून सभी धर्मों के विवाहित पुरुषों के ऊपर लागू होगा।

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील

मैरिटल रेप को अपराध का दर्जा देने वाले लोगों के तीन बड़े तर्क हैं- पहला, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, 29 फीसदी महिलाएं पारिवारिक हिंसा और यौन-उत्पीड़न का शिकार होती हैं। वैवाहिक दुष्कर्म शारीरिक हिंसा के साथ मानसिक तौर पर भी पीड़ादायक होता है। दूसरा, नए बीएनएस कानून की धारा-63 में दिए गए कानूनी अपवाद से विवाहित महिलाओं को रेप के दायरे से बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद-14 और 15 का उल्लंघन है। विवाहित महिलाओं को भी रेप के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तीसरा, किसी भी पुरुष या पति को स्त्री के साथ जबर्दस्ती संबंध बनाने का अधिकार नहीं है।

औपनिवेशिक आईपीसी कानून में विवाहित पुरुषों को दी गई सुरक्षा पितृ-सत्तात्मक है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में मैरिटल रेप को अपराध माना गया है। इसलिए भारत में सुप्रीम कोर्ट को प्रगतिशील नजरिये से फैसला देना चाहिए।

इसका विरोध करने वालों के भी तीन बड़े तर्क हैं-पहला, शारीरिक हिंसा के लिए पतियों के खिलाफ कानून में प्रावधान हैं। घरेलू हिंसा के खिलाफ वर्ष 2005 में बनाए गए कानून में यौन-शोषण भी जुड़ा है। कानून के अनुसार, पीड़िता को क्रूरता के आधार पर तलाक के साथ गर्भपात का भी अधिकार है। दूसरा, निर्भया कांड के बाद जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने इसे अपराध की श्रेणी में रखने की सिफारिश की थी, जिसे तत्कालीन यूपीए सरकार ने नहीं माना। तीसरा, मैरिटल रेप संबंधी कानून में बदलाव के लिए अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और यूएन की एजेंसियों का दबाव है। दहेज उत्पीड़न मामलों में आईपीसी की धारा-498-ए के दुरुपयोग के खिलाफ संसद और सुप्रीम कोर्ट में हो रही चर्चा के साथ मैरिटल रेप से जुड़े विषयों पर भी विमर्श होना चाहिए।

सरकार ने संसद में बार-बार कहा है कि भारतीय समाज में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने पर विवाह संस्था कमजोर होने के साथ कानून का दुरुपयोग बढ़ेगा, इसलिए यह अपवाद नहीं हटना चाहिए। इन्हीं तर्कों के आधार पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर सरकार ने जवाब नहीं दिया, तो वे संविधान के अनुसार मामले का निपटारा करेंगे। इसलिए इस मामले से जुड़े सांविधानिक बिंदुओं का आकलन जरूरी है।

पहला, सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती फैसले में सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों के विभाजन पर मोहर लगाई थी। संविधान के अनुसार, शादी का विषय समवर्ती सूची में आता है। इस मामले पर केंद्र सरकार ने राज्यों की राय मांगी थी। 19 राज्यों में से 10 राज्यों ने विरोध में, तीन राज्यों ने समर्थन में और छह राज्यों ने अस्पष्ट राय दी थी। महिला आयोग ने भी इस मांग का विरोध किया। संविधान ने संसद और विधानसभा को कानून बनाने और उसे बदलने का अधिकार दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी सरकार को कानून में बदलाव के लिए निर्देश दिए थे। इसलिए सभी राज्यों का पक्ष जाने बगैर इस मामले में सुनवाई और फैसला संविधान सम्मत नहीं है।

दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों से समलैंगिक विवाह (सेम सेक्स मैरिज) को मान्यता मिलने के साथ व्यभिचार और अप्राकृतिक सेक्स अपराध के दायरे से बाहर हो गए हैं। इस मामले में कुछ याचिकाओं के अनुसार, स्त्री-पुरुष की समानता के आधार पर दुष्कर्म संबंधी अपराध को लिंग निरपेक्ष होना चाहिए। ऐसा होने पर पत्नियों के खिलाफ पति भी रेप का मामला दर्ज करा सकेंगे। ऐसा होने पर पारिवारिक व्यवस्था ध्वस्त होने के साथ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। प्रगतिशील कानून बनाने के साथ गलत और फर्जी मुकदमेबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान होना चाहिए। इसलिए जल्दी में अदालती सुनवाई करने के बजाय विधि आयोग और संसदीय समिति को इस मामले से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।

तीसरा, नए बीएनएस कानून की धारा-63 के अनुसार 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध रेप अपराध के दायरे में आ सकते हैं। राजस्थान सरकार ने इस मामले में पक्षकार बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। हिमाचल प्रदेश ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दी है। दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट के अनेक जज किशोर बच्चों के बीच सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर रखने की बात कर रहे हैं। जनवरी 2019 में दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अगर लिव-इन रिलेशनशिप में पुरुष और महिला के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बने और बाद में पुरुष शादी से मुकर जाए, तो उसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। मैरिटल रेप से जुड़े फैसले का समाज के साथ कई अन्य कानूनों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस मामले पर तीन के बजाय पांच जजों की संविधान पीठ में सुनवाई होनी चाहिए।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

स्वामी विवेकानंद

अपने प्रेम और नम्रता की परीक्षा करो। ईर्ष्यालु व्यक्ति नम्र और प्रेममय नहीं होता। ईर्ष्या एक भयंकर, भयावह पाप है। यह मनुष्य में अत्यंत रहस्यमय रीति से प्रवेश कर जाती है।

जिनका हृदय शुद्ध है, वे ईश्वर का दर्शन पाएंगे

हमसे पूछा जाता है, 'आपके धर्म से समाज को क्या लाभ है? समाज को सत्य की कसौटी बनाया गया है। यह तो बड़ी तर्कहीनता है। समाज केवल विकास की एक अवस्था है, जिसमें होकर हम गुजर रहे हैं। इस प्रकार तो हम एक वैज्ञानिक आविष्कार के लाभ अथवा उसकी उपयोगिता को एक शिशु के लिए उसकी उपयोगिता से जांचेंगे। यह अत्यंत असंगत है। यदि सामाजिक अवस्था स्थायी होती, तो वह शिशु के सदा शिशु ही बने रहने जैसी बात होती। पूर्ण मनुष्य शिशु नहीं हो सकता। यह शब्द 'मनुष्य-शिशु' ही विरोधाभासी है। इसलिए कोई समाज पूर्ण नहीं हो सकता। मनुष्य को ऐसी आरंभिक अवस्थाओं से आगे बढ़ना होगा और वह बढ़ेगा। समाज एक अवस्था तक अच्छा है, पर वह आदर्श नहीं बन सकता, वह निरंतर परिवर्तनशील है। संसार को जो चाहिए, वह है व्यक्तियों के माध्यम से विचार शक्ति। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, 'तुम स्वयं अपने कमल के फूल को खिलने में सहायता क्यों नहीं देते? भ्रमर तब अपने आप आएंगे।' संसार को ऐसे लोग चाहिए, जो ईश्वर के प्रेम में मतवाले हों। पहले अपने आप पर विश्वास करो, तब तुम ईश्वर में विश्वास करोगे। संसार छह श्रद्धालु मनुष्यों का इतिहास, छह गंभीर शुद्ध चरित्रवान मनुष्यों का इतिहास है।

हमें तीन वस्तुओं की आवश्यकता है। अनुभव करने के लिए हृदय की, कल्पना करने के लिए मस्तिष्क की, और काम करने के लिए हाथ की। पहले हमें बाहर निकलना चाहिए और अपने लिए समुचित उपकरण तैयार करने चाहिए। अपने को एक डाइनेमो बनाओ। पहले संसार के लिए महसूस करो। ऐसे समय में, जब संसार में सब मनुष्य काम करने को तैयार हैं, तो भावनाशील व्यक्ति कहां है? वह अनुभूति कहां है, जिसने इग्नेशियस लॉयला को उत्पन्न किया था? अपने प्रेम और नम्रता की परीक्षा करो। ईर्ष्यालु व्यक्ति नम्र और प्रेममय नहीं होता। ईर्ष्या एक भयंकर, भयावह पाप है। यह मनुष्य में अत्यंत रहस्यमय रीति से प्रवेश कर जाती है। अपने से पूछो, तुम्हारा मन घृणा अथवा ईर्ष्या की प्रतिक्रिया करता है या नहीं? संसार में जो टनों घृणा और क्रोध उड़ेला जा रहा है, उससे संसार का कितना भला हो रहा है? यदि तुम पवित्र हो, यदि तुम सशक्त हो, तो तुम, एक व्यक्ति, समस्त संसार के बराबर हो।

शुभ कार्य करने का दूसरा माध्यम- मस्तिष्क केवल सूखा सहारा रेगिस्तान मात्र है, क्योंकि वह अकेला उस समय तक कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पीछे अनुभूति न हो। उस प्रेम को, जो कभी असफल नहीं रहा, साथ लो, और तब मस्तिष्क कल्पना करेगा और हाथ भलाई करेगा। ऋषियों ने ईश्वर के स्वप्न देखे हैं और उसके दर्शन किए हैं। जिनका हृदय शुद्ध है, वे ईश्वर का दर्शन पाएंगे। सब महान पुरुष ईश्वर दर्शन कर चुकने का दावा करते हैं। हजारों वर्ष पहले यह दिव्य दर्शन उपलब्ध हुआ है और, इसके परे जो एकता है, वह स्वीकृत की जा चुकी है, और अब हमें जो करना है, वह है केवल इन महत्वपूर्ण रूप-रेखाओं को भरना।

घृणा को दूर करें

सूत्र

आजकल पूरी दुनिया में तेजी से नफरत फैलाई जा रही है। लेकिन दूसरों के प्रति घृणा और ईर्ष्या व्यक्तिगत ही नहीं, सामाजिक जीवन के लिए भी अभिशाप हैं। इससे किसी का भला नहीं हो सकता। यह पाप है, जो हमारे जीवन को कलुषित बनाता है। हमें घृणा एवं ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए और जीवन का वास्तविक आनंद पाने के लिए विनम्रता सीखनी चाहिए।

दूसरा पहलू

'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना ने प्रवासी मजदूरों की समस्या दूर कर दी है। मजदूर अब प्रवास स्थान पर राशन ले रहे हैं।

अब राशन की चिंता से मुक्त हो रहे प्रवासी मजदूर

देश में रोजगार प्रमुख समस्या बनी हुई है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आता है। गांव में रहने वाली एक बड़ी आबादी रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में प्रवास करती है। ऐसे में इनके सामने अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के साथ-साथ सबसे बड़ी चुनौती जन वितरण प्रणाली द्वारा मिलने वाला राशन होता है, जिसके लाभ से ये मजदूर अक्सर वंचित हो जाते हैं। चूंकि राशन कार्ड गांव में बना होता था, ऐसे में प्रवास के कारण वे अन्य स्थान पर इससे मिलने वाले सस्ते राशन का लाभ उठा नहीं पाते थे। लेकिन केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना ने इन प्रवासी मजदूरों की समस्या को दूर कर दिया है। अब ये मजदूर अपने प्रवास स्थान पर भी अपने राशन कार्ड के माध्यम से सस्ता अनाज खरीद कर परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम हो रहे हैं।

शैतान रैगर

यह 'डिजिटल इंडिया' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इससे राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए देश भर में एक केंद्रीय डाटाबेस विकसित किया गया है, जिसमें हर योग्य व्यक्ति का डाटा संग्रहीत होता है। यह योजना 'डिजिटल इंडिया' की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले लोकेश रविदास बताते हैं, 'मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का रहने वाला हूं और पिछले 20 वर्षों से परिवार के साथ काम के लिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों में जाता रहा हूं। मुझे स्थानीय दुकानदार से राशन खरीद कर लाना पड़ता था, जो अक्सर महंगा होता था। लेकिन अब काम की जगह पर ही मेरे परिवार को पीडीएस के माध्यम से सस्ता राशन मिल जाता है।' इसी ईंट भट्ठे पर काम करने वाले बिहार के बांका जिले के प्रमोद मांझी बताते हैं कि पीडीएस से राशन प्राप्त करने के लिए अब उन्हें बार-बार गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह कहते हैं, 'हम मजदूर यहीं काम करते हैं और पास के गांव से सस्ता राशन भी प्राप्त करते हैं, जिससे मेरे परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम हो गया है।' वह बताते हैं, 'पहले जब साल-दो साल पर हम अपने गांव वापस जाते थे, तो सरकारी राशन दुकान का मालिक कहता था कि दो साल से राशन नहीं लेने की वजह से तुम्हारा नाम काट दिया गया है। लिस्ट में दोबारा नाम जुड़वाने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने होंगे। इससे हमें आर्थिक और मानसिक, दोनों रूप से परेशानी होती थी। लेकिन इस योजना ने रोजगार के लिए अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले हम जैसे मजदूरों के जीवन को आसान बना दिया है। *(चरखा फीचर)*

ईंट भट्ठे पर काम करने वाले लोकेश रविदास बताते हैं कि 20 वर्षों से बाहर हैं। अब काम की जगह पर ही उनके परिवार को पीडीएस के माध्यम से सस्ता राशन मिल जाता है। बार-बार गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।

आंकड़े

स्वास्थ्य में सुधार

परिवारों द्वारा स्वास्थ्य सेवा पर किए जाने वाले खर्च में गिरावट दर्ज की गई है। 2021-22 में ओओपीई घटकर 39.4 प्रतिशत रह गई।

2013-2014	64.2%
2014-2015	62.6%
2017-2018	48.8%
2019-2020	47.1%
2021-2022	39.4%

आंकड़े स्वास्थ्य सेवा पर जेब से किए गए खर्च के | स्रोत : NHA

जाजलि की घोर तपस्या के बाद उन्हें सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें लगा कि उनके समान और कोई विद्वान नहीं है। तभी एक आकाशवाणी ने उनका घमंड तोड़ दिया।

ज्ञान का अधिकारी

काशी में तुलाधार वैश्य रहते थे। वह व्यापार करते हुए भी सदैव भगवान की भक्ति में रमे रहते थे। इनकी प्रशंसा सभी लोग करते। उन्हीं दिनों जाजलि नाम के एक ब्राह्मण समुद्र किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। एक बार सूखा वृक्ष समझकर जाजलि की जटा में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, वहीं उनके अंडे फूटे और बच्चे सयाने हुए। तब भी उनका ध्यान नहीं हटा।

इस घोर तपस्या से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें घमंड हो गया। जाजलि को लगा कि उनके समान और कोई विद्वान नहीं। तभी आकाशवाणी हुई-आपका यह सोचना ठीक नहीं। आपको अभी ज्ञान ही कितना हुआ है? काशी में तुलाधार रहते हैं, वह भी ऐसी बात नहीं करते। इतना सुनते ही जाजलि तुलाधार के दर्शन के लिए काशी पहुंच गए। तुलाधार ने स्वागत-सत्कार किया और नम्रता से कहा- 'मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? जाजलि ने पूछा, आपको ऐसा निर्मल ज्ञान और व्यावसायिक बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? तुलाधार ने कहा कि सारा जगत भगवान का स्वरूप है, इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है। मिट्टी और सोने में जरा भी अंतर नहीं। जो मनुष्य किसी का भी बुरा नहीं सोचता, वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी है। जिन लोगों को ज्ञान का अभिमान हो जाता है, उन्हें वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। यह कहकर तुलाधार ने जाजलि को सदाचार का उपदेश दिए।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 17 सितंबर,1960

कांगो के प्रधानमंत्री पर सैनिकों का आक्रमण

लुमुम्बा पर कांगोली सैनिकों का आक्रमण
कमीज को फाड़ दिया गया

कांगो के प्रधानमंत्री पैट्रिस लुमुम्बा को कांगोली सैनिकों ने घेर लिया। उनका अपमान किया और उनकी कमीज फाड़ दी। एक सैनिक ने तो उन पर हथगोला फेंकना चाहा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक और भारत के बाजार

फेडरल रिजर्व की नीतिगत दरों में कटौती के बाद यदि विदेशी संस्थागत निवेशक चीन के बजाय भारतीय बाजारों का रुख कर रहे हैं, तो यह बेहतर संकेत है।

सतीश सिंह — आर्थिकी

अमेरिका के फेडरल रिजर्व के नक्शे-कदम पर दुनिया भर के केंद्रीय बैंक चलते हैं। हालांकि, सभी देशों की आर्थिक स्थिति अलग-अलग होने के कारण कभी-कभी कुछ देशों के केंद्रीय बैंक अलग निर्णय लेते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो भारत भी फेडरल रिजर्व बैंक के निर्णयों के अनुरूप कदम उठाता है।

विगत चार वर्षों में पहली बार फेडरल रिजर्व ने हाल ही में नीतिगत दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की, जिसके बाद दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंकों द्वारा भी नीतिगत दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। फेडरल रिजर्व के ताजा निर्णय के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार में ज्यादा निवेश किया है। दरअसल, डॉलर के कमजोर पड़ने, उधारी दर में कमी आने, निवेश व कारोबारों में तेजी आने आदि की संभावना बढ़ी है, जिसकी पुष्टि निवेश में तेजी से हो रही है। चीन फिलहाल सुशासन की समस्या से जूझ रहा है, जिसके कारण विदेशी निवेशक वहां

निवेश करने से परहेज कर रहे हैं और कुछ निवेशक भारत का रुख कर रहे हैं। अमेरिका की तरह चीन में भी उत्पादन, खपत आदि मापदंडों की वृद्धि अपेक्षा से अधिक धीमी है। अगस्त महीने में बेरोजगारी दर छह महीनों के उच्चतम स्तर 5.3 प्रतिशत पर पहुंच गई और शहरी बेरोजगारी दर जुलाई में 17.1 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जो जून में 13 प्रतिशत थी। विकास दर में तेजी लाने के लिए चीन के केंद्रीय बैंक ने उधारी दरों में कटौती की है, ताकि उधारी में उठाव आए और आर्थिक गतिविधियों में तेजी। सवाल उठता है कि क्या फेडरल रिजर्व की तर्ज पर आगामी मौद्रिक समीक्षाओं में भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर में कटौती करेगा, क्योंकि महंगाई और विकास के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए फरवरी, 2023 के बाद से रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और यह 6.5 प्रतिशत पर बरकरार है। रिजर्व बैंक को रेपो दर में कटौती करने से पहले मौजूदा आर्थिक स्थिति, जीडीपी वृद्धि दर, महंगाई की स्थिति, आर्थिक गतिविधियों की गति आदि पर गहन विमर्श करना होगा।

भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े निरंतर बेहतर हो रहे हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, मूडीज ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखा है, लेकिन 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.6 प्रतिशत जताया है। ये आंकड़े विश्व के कई विकसित देशों से बेहतर हैं।

खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई और अगस्त महीने में चार प्रतिशत से नीचे रही है और बारिश के खत्म होने के बाद खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आने का अनुमान है, जिससे आगामी महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति में और भी कमी आने के कयास लगाए जा रहे हैं। मूडीज ने 2025 और 2026 में भारत में मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत जताया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भी वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति घटकर 4.5 प्रतिशत रह सकती है।

एचएसबीसी विनिर्माण पीएमआई सितंबर 2024 में घटकर 56.7 रह गया, जो अगस्त महीने में 57.5 रहा था। सेवा पीएमआई भी सितंबर महीने में घटकर 58.9 प्रतिशत रह गया, जो अगस्त महीने में 60.9 रहा था। बेशक, विनिर्माण और सेवा पीएमआई में अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। फिर भी, यह अभी 50 से ऊपर है, जो दर्शाता है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में तेजी का रुख बना हुआ है।

रेपो दर फरवरी 2023 से 6.5 प्रतिशत के स्तर पर कायम है। फिर भी, उधारी के उठाव में तेजी बनी हुई है। दिसंबर, 2023 की तुलना में ऋण उठाव में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 9 अगस्त 2024 को समाप्त पखवाड़े के लिए क्रमिक रूप से 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निरपेक्ष रूप से, पिछले आठ महीनों में, ऋण उठाव 9.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 9 अगस्त, 2024 तक 168.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह एक अच्छा संकेत है। अगर रेपो दर में कटौती की जाती है, तो उधारी के उठाव एवं विकास की गति में और भी तेजी आएगी।

फिलहाल हमारे देश में जीडीपी में वृद्धि हो रही है और महंगाई भी काबू में है। साथ में, वित्त वर्ष 2025 और 2026 में भी खुदरा मुद्रास्फीति के रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सहनशीलता सीमा के अंदर रहने के आसार हैं। पुनश्च: डॉलर के कमजोर रहने और निवेश व ऋण उठाव में तेजी आने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है, जिसे और बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अगली मौद्रिक समीक्षा बैठक में रेपो दर में कम से कम 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कल्पमेधा

जीवन में लगातार किया जाने वाला और जरूरी सवाल है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं।

– मार्टिन लूथर किंग

आलोचना का अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी पत्रकारिता कर रहे लोगों के लिए सुकूनदेह हो सकती है कि सरकार की आलोचना करना पत्रकारों का अधिकार है। हालांकि देखने की बात है कि सरकारें इस बात को कहां तक स्वीकार कर पाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए की। इस संबंध में अदालत ने संविधान के अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े अनुच्छेद की याद भी दिलाई और पत्रकार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया। दरअसल, सरकारों को अपनी आलोचना कभी रास नहीं आती, मगर पिछले कुछ वर्षों में सरकारें इसे लेकर प्रकट रूप में सख्त नजर आने लगी हैं। सरकार के खिलाफ अखबारों में खबरें, लेख या कोई वैचारिक टिप्पणी करने पर कई पत्रकारों को प्रताड़ित करने की घटनाएं देखी गई हैं। यहां तक कि कुछ पत्रकारों पर गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत भी मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें जमानत मिलनी मुश्किल होती है। इस धारा के तहत कई पत्रकार अब भी सलाखों के पीछे हैं। कुछ मामलों में पहले भी सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि सरकार की आलोचना देशद्रोह नहीं माना जा सकता। मगर किसी सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया।

कुछ राज्यों में ऐसे भी उदाहरण हैं, जब सरकार की किसी नीति या फैसले की आलोचना करने पर पत्रकारों को पकड़ कर थाने में बंद किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। दरअसल, इस तरह की कोशिशें सच्चाई को सामने लाने से रोकने के लिए की जाती हैं। जबकि स्वस्थ लोकतंत्र का तकाजा है कि पत्रकारीय आलोचना को प्रोत्साहित किया जाए। इससे सरकारों को अपनी नीतियों के निर्धारण, योजनाओं के संचालन आदि में सुधार करने का अवसर मिलता है। आलोचना को रोक कर गलत नीतियों को चलाते रहना एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास ही होता है। हालांकि आलोचना का अर्थ हर समय निंदा करना नहीं होता। किसी भी मुद्दे के पक्ष और विपक्ष का तार्किक विश्लेषण करना होता है। पत्रकारिता यही करती है। वह लोकहित में सरकार को कदम उठाने का रास्ता सुझाती रहती है, इसीलिए उसकी विश्वसनीयता होती है। मगर सरकारें जब उसके मूल स्वभाव को ही बदलने का प्रयास करती हैं, तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रहार करती हैं। ऐसे में पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न होकर प्रचारतंत्र में तब्दील होने लगती है।

किसी देश की पत्रकारिता कितनी स्वतंत्र है और कितने साहस के साथ अपने सत्ता प्रतिष्ठान की आलोचना कर पा रही है, इससे उस देश की खुशहाली का भी पता चलता है। यह अकारण नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत निरंतर नीचे खिसकता गया है। इसलिए कि खुशहाली नापने के पैमाने में एक बिंदु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी होता है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि कोई देश अपनी आर्थिक तरक्की का तूमार तो खूब बांध ले, पर खुशहाली के मानकों पर गरीब कहे जाने वाले देशों से भी पीछे नजर आए। पत्रकारिता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों को दूर करने में मदद करती है। उसका लाभ उठाने के बजाय अगर उसका गला घोटने का प्रयास होगा, तो सही अर्थों में विकास का दावा नहीं किया जा सकता। अगर कोई सरकार सचमुच उदारवादी और लोकतांत्रिक होगी, तो वह आलोचना से कुछ सीखने का प्रयास करेगी।

नक्सल पर नकेल

छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सली विद्रोहियों के खिलाफ लंबे समय से सुरक्षा बलों का अभियान जारी है, मगर थोड़े-थोड़े अंतराल पर घात लगा कर हमला करने और उसमें जवानों की मौत की घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि इस बीच सुरक्षा बलों ने काफी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया है या फिर उन्हें कानून के शिकंजे में लिया है। शुक्रवार को सुरक्षा बलों के संयुक्त दल को एक अहम कामयाबी तब मिली जब उसने अबूझमाड़ के थुलथुली गांव के जंगल में हुई मुठभेड़ में 30 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि इससे पहले नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई। इस घटना में एक खास पहलू यह भी है कि मुठभेड़ में सभी जवान सुरक्षित रहे। इसके बाद घटनास्थल पर एके-47 और एसएलआर राइफलों सहित भारी मात्रा में घातक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। इससे पहले अप्रैल में हुई एक मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे।

पिछले कुछ महीने में सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में माओवादी हमलों को नाकाम कर दिया और कई नक्सलियों को मार गिराया। अबूझमाड़ के जंगलों में ताजा मुठभेड़ में एक पहलू यह भी है कि घटनास्थल से घातक हथियार बरामद किए गए। हालांकि माओवादी समूहों के पास इतने बड़े पैमाने पर घातक हथियारों का होना कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि जब छत्तीसगढ़ में जंगली इलाके के बाहर निगरानी और सुरक्षा का घेरा सख्त है, तब माओवादी समूहों के पास इतनी बड़ी तादाद में घातक हथियार कैसे पहुंच जाते हैं! जो हो, सुरक्षा बलों की विशेष टुकड़ियों ने नक्सली हमलों का सफलता से सामना किया है और उन्हें कमजोर करने के प्रयास जारी है। मगर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए इन समूहों के हिंसक हमलों का सामना करने के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी जनकल्याण के लिए नीतिगत और जमीनी स्तर पर ठोस पहल करने की जरूरत है, ताकि ऐसे संगठनों को अभाव से जूझती आबादी के बीच पांव जमाने से दूर किया जा सके।

त्योहार और आर्थिक उत्सव की लालसा

आज जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी और गिरती हुई मांग के चंगुल में फंसा है, भारत की आर्थिक विकास दर सब देशों से आगे है। मगर हम आठ फीसद की विकास दर तक नहीं पहुंच पाए।

सुरेश सेठ

भारत उत्सवधर्मी देश है। यहां विभिन्न परंपराओं और क्षेत्रीय संस्कृति का सम्मिश्रण कई नए रंग-बिरंगे अवसर पैदा करता है, जब देशवासियों को उत्सव मनाते देखा जा सकता है। उत्सवधर्मी इस देश में आर्थिक लाभ यही होता है कि साधारण व्यक्ति भी अपनी आर्थिक सीमा से बाहर जाकर खर्च करता है। त्योहार के दिनों में बाजारों में मंदी की उदासी नहीं फैलती। इतने बड़े देश में चूंकि ऐसा होता ही रहता है, इसलिए आज जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी और गिरती हुई मांग के चंगुल में फंसा है, भारत की आर्थिक विकास दर सब देशों से आगे है। मगर हम आठ फीसद की विकास दर तक नहीं पहुंच पाए। पिछले वर्ष इस विकास दर के करीब पहुंच गए थे, इस वर्ष के अंत में यह सात फीसद से भी नीचे जाती दिखाई देती है, लेकिन फिर भी मांग की कमी भारत के लिए कोई समस्या नहीं। हां, इस मांग को पूरा करने के लिए उचित उत्पादन बढ़ाने की समस्या हो सकती है। जैसा कि अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा है कि देश विनिर्माण और कृषि विकास की ओर ध्यान दे। उनका कहना है कि पिछले वर्षों में जिन बुनियादी उद्योगों के विकास की ओर हमने ध्यान दिया, उसी के फलस्वरूप आज तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं।

आज हम दुनिया की पांचवीं आर्थिक महाशक्ति हैं, तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 2047 में जब आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे, तो अपना देश विकसित हो चुका होगा और अगर यह दुनिया की सबसे ताकतवर आर्थिक शक्ति नहीं बनता, तो भी यह चौथी औद्योगिक क्रांति का अगुआ होगा, जो इस बार पूरब से और तीसरी दुनिया से उभरेगी। अपने सांस्कृतिक मूल्यों के बल पर पूरी दुनिया का गुरु बन कर उसको रास्ता भी दिखाएगा। यह तो है आने वाले दिनों की बात। इस समय जो खबरें भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आ रही हैं, वे अच्छी हैं। नीति-निर्माता भी कुछ ऐसे कदम उठा लेना चाहते हैं जिससे जनता का भला हो सके। इस पर भी कुछ विवेचन कर लिया जाए। चाहे दावा किया जा रहा है कि नए कर्तव्य समर्पित द्रुत विकास के माहौल में रोजगार सृजन हो रहा है, लेकिन यह रोजगार कहां हो रहा है?

रोजगार की एक अजब स्थिति पैदा हो रही है। जिन लोगों के पास इस बदलती हुई दुनिया की प्रौद्योगिकी का शिक्षण-प्रशिक्षण है, उनके लिए तो नौकरियों की कतार लगी है और कला और विज्ञान के संकायों से निकल कर आए नौजवान अपना कोई भविष्य इस बदलते भारत में नहीं पाते। उनके लिए रोजगार प्रदान करने वाले लघु और कुटीर उद्योगों का कोई नया अभियान नजर नहीं आता। आता भी है, तो उसमें निजी क्षेत्र और 'स्टार्टअप' के नाम पर परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से धनकुबेरों के लिए भी चोर दरवाजे खोले जा रहे हैं। तो, भारत की प्रगति को समझ कर रोजगार देने का गंभीर प्रयास हो, ताकि देश का निर्माण उसकी विशेष पहचान के अनुसार हो। उस

पर उधार के लबादे ओढ़ा कर उसका वह आधुनिकीकरण न किया जाए, जो उसके मिजाज में नहीं।

वैसे, देश में धूमधाम है कि आने वाले त्योहारी मौसम में प्रगति ही प्रगति, विकास ही विकास दिखाई देगा। इसके साक्षी हैं, शेयर बाजार

> **आज हम दुनिया की पांचवीं आर्थिक महाशक्ति हैं, तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 2047 में जब आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे, तो अपना देश विकसित हो चुका होगा और अगर यह दुनिया की सबसे ताकतवर आर्थिक शक्ति नहीं बनता, तो भी यह चौथी औद्योगिक क्रांति का अगुआ होगा, जो इस बार पूरब से और तीसरी दुनिया से उभरेगी। अपने सांस्कृतिक मूल्यों के बल पर पूरी दुनिया का गुरु बन कर उसको रास्ता भी दिखाएगा। यह तो है आने वाले दिनों की बात।**

के सूचकांक और निफ्टी के नए शिखर, क्योंकि इसमें न केवल भारतीय, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा भी दिखता है कि जैसे ही अमेरिका ने अपनी फेडरल नीति में पचास आधार अंक की कमी की, तो विदेशी निवेश जो निकला जा रहा था, वह भारत लौटने लगा। इस बीच भारत के स्थानीय निवेशकों ने भी अपने घरेलू निवेश से शेयर बाजार को बिखरने नहीं दिया। तेजी का यह सिलसिला बनाए रखा। इस तेजी के साथ भारत का नया उभरता हुआ मध्यवर्ग और उसका घरेलू निवेश भी बंधी हुई बैंक एफडी के क्षेत्र से थोड़ा रुख बदल कर शेयरों और म्युचुअल फंड की तरफ आ गया, जिसमें नए निवेश को स्थायित्व देना शुरू कर दिया। इधर अंतरराष्ट्रीय स्थिति के मद्देनजर भारत की जनता उम्मीद करती है कि कच्चे तेल के घटते दाम का फायदा उन्हें भी मिलेगा, क्योंकि अभी तक वह महंगाई की समस्या से जूझ रही है। अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में इतने लंबे समय के बाद थोड़ी सी कटौती हो जाए, तो उससे उनके लिए महंगाई को नियंत्रित करने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी और उत्सव के इन दिनों को एक नया रंग मिल जाएगा।

इस समय पेट्रोलियम कंपनियों की कमाई बढ़ गई है। इसलिए हर विशेषज्ञ यह कहता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जनसाधारण के लिए कुछ कम करने की गुंजाइश है। हमारे आयात भुगतान का बिल भी घट गया, क्योंकि हम अपनी जरूरत का पचासी फीसद तेल आयात करते हैं, तो हो सकता है इसका लाभ उत्सव के दिनों में कुछ कटौती के रूप में जनता को दे दिया जाए। इस बीच पेट्रोलियम कीमतें केवल एक बार दो रुपए घटाई गई, लेकिन इसकी भरपाई भी राज्य सरकारों ने अपना-अपना वैट बढ़ा कर पूरी कर ली। पंजाब ने भी पिछले दिनों वैट दरें बढ़ाईं। मार्च में तो इसका दाम 84-85 डालर प्रति बैरल था, तब दो रुपए दाम घटा दिए गए, तो फिर अब क्यों नहीं घटा कर उत्सव के दिनों में लोगों को यह उपहार दे दिया जाए।

स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर जीएसटी के लिए मंत्री समूह की बैठक 19 अक्तूबर को होने जा रही है। सूचना है कि त्योहारों के स्वागत के लिए कई वस्तुओं पर जीएसटी घटाने पर विचार हो सकता है। जीवन बीमा पर दरें घटा दी जाएं। यह मांग विपक्ष ही नहीं, सत्तापक्ष के कुछ नेताओं की भी है। समिति के सामने व्यक्तिगत, समूह और वरिष्ठ नागरिकों, मानसिक बीमारी से ग्रस्त लोगों और विभिन्न श्रेणियों के अन्य लोगों के लिए चिकित्सा बीमा दरें घटाने की सोच देर से लंबित है। अब अगर बीमा दरों में कटौती का यह उपहार जनता को मिल जाए, तो इससे बड़ा उत्सव और क्या हो सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इनको भी जीएसटी के दायरे में ले आने का विचार काफी समय से चल रहा है। क्यों न इस विचार को भी अब फलीभूत कर दिया जाए। इस परवाह के बगैर कि अगर केंद्र इसे जीएसटी दरों के अधीन ले आया, तो राज्य अपनी कर दरों को बढ़ा कर 'कर-खोरी' शुरू कर देंगे। त्योहारों के दिन शुरू हो गए हैं। जनता को अगर यह चंद कल्याणकारी कदम उठते हुए नजर आ जाएं, तो शायद यह उनके लिए एक बड़ा आर्थिक उत्सव मनाने की भूमिका हो सकती है। वैसे भी कहा जाता है कि भारत प्रजातांत्रिक समाज के लिए प्रतिबद्ध है और गरीब की चिंता, उसे संपन्न देशों से अधिक है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

शिक्षा बनाम साक्षरता

राजेंद्र जोशी

सबके लिए शिक्षा का नारा 1986 में दिया गया और अब नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने को है। यह नारा नया नहीं है। भारत के संविधान में सबको शिक्षा सुलभ हो, सभी शिक्षित हों, यह बात अच्छी तरह लिखी गई है। शिक्षा का सार्वजनिकीकरण हो, शिक्षा सबको मिले। मगर इन सबका उद्देश्य क्या हो? क्या शिक्षा से लोगों में पढ़ने-लिखने की क्षमता आएगी? या उनमें कोई अपनी शक्ति जागृत होगी, जिससे वे अपने-आप को कमजोर महसूस न करें और दूसरों पर निर्भर महसूस करने के बजाय खुद अपनी शक्ति जागृत कर सकें? शिक्षा का मूल उद्देश्य जागृति है। शिक्षा उस शक्ति को जगाती है, गुणों को अर्जित करती है, विकसित करती है। शिक्षा कोई नई बात लाने के बजाय व्यक्ति में निहित शक्तियों का ही विकास करती है, लेकिन विकास कितना होगा, यह नई शिक्षा नीति की शिक्षा-पद्धति पर निर्भर है।

हम जब शिक्षित होने की बात करते हैं तो किसान पूछता है कि इससे मुझे क्या लाभ होगा! महिला पूछती है कि इससे मुझे क्या लाभ होने वाला है! जो खेती करना जानते हैं, उनको रोज की आमद हो जाती है, वे भी रोटी, कपड़ा और मकान किसी तरह जुटा लेते हैं। फिर पढ़ने-लिखने से उन्हें कोई खास फायदा होगा, शिक्षा उनको नई जानकारी देगी और उससे उनको नई चीज मिलेगी, नई रोशनी मिलेगी, हम ऐसे सवालों का जवाब हां में नहीं दे पाते। हम केवल यही कहते हैं कि पढ़ने-लिखने से अंधकार मिटेगा, हम कुछ पढ़-लिख पाएंगे तो पहले से बेहतर हो जाएंगे। 'क-ख-ग' या किताब के कुछ अक्षर पढ़ने से कोई पहले से बेहतर हो जाएगा यह समझ में अभी तक नहीं आया। शिक्षा जब तक किसी की सोई हुई शक्ति को नहीं जगाएगी, तब तक उसमें शक्ति और गुणों का विकास नहीं होगा, वह शिक्षा नहीं कहला सकती। उसे अक्षर ज्ञान तो हो जाता है, पर वह क्या पढ़े, यह तय करना संभव नहीं है। अपनी समस्याओं का विश्लेषण कैसे करें, उसका हल कैसे खोजें और कैसे सामूहिक रूप से हल करें- शिक्षा जब तक इन बातों पर चर्चा नहीं करेगी, जब तक लोगों को सामूहिक रूप से रहना नहीं सिखाएगी और सामूहिक रहकर अपनी ताकत को जागृत करने का लक्ष्य नहीं बनाएगी, तब तक आगे बढ़ना संभव नहीं है।

लोकशिक्षा अपने आप में बहुत व्यापक है। लोकशिक्षा जागृति के लिए हो। लोकशिक्षा से लोकशक्ति का प्रादुर्भाव होना आवश्यक है। लोकशिक्षा के लिए सबको इकट्ठा होना होगा, इसके लिए हमें सबको जागृत करना होगा और साक्षरता अभियान में जागृति लाई जाए, यह आवश्यक है। लोकशक्ति जगाई जाए, यह अत्यंत आवश्यक है।

साक्षरता अभियान की बात करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक होगा कि साक्षरता आखिर है क्या? साक्षरता का अर्थ है समाज के वे लोग, जो लिखना-पढ़ना नहीं जानते और अक्षरों के आलोक से दूर हैं, उन्हें साक्षर बनाना। जिसे औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला, वह वास्तव में संसार के अनुभवों से सजा व्यक्ति है। साक्षरता समाज को समझने की नई दृष्टि देती है, समस्याओं को समझने के लिए मार्गदर्शन करती है। यह एक सार्थक कर्तव्य है, जिससे हम भावों को सही ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई असाक्षर शिक्षा से जुड़ जाए तो उसकी समझदारी में कुछ अपनापन अवश्य आएगा। आज की तेजी से भागने वाली दुनिया में वह औपचारिक शिक्षा के अभाव में कागजों के संसार में सहारा नहीं है। वह किसी और के और अंगूठे के घेरे से भी कुछ बाहर निकल सकेगा।

साक्षरता केवल अक्षरों और अंकों का खेल नहीं है। कई मार्ग इसमें एक साथ खुलते हैं। सामाजिक और भावनात्मक एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, छोटे परिवार की अवधारणा, पर्यावरण की सुरक्षा और महिलाओं की समानता- सब इसी के हिस्से है। अक्षरों का संसार आलोक का संसार है। आलोक जब फैलता है तो किसी भी कोने में अंधकार नहीं रह सकेगा। अतीत में झांकें मार्च, 1990 कोई ज्यादा दूर नहीं लगता। थाइलैंड की जोमेटिन नामक संस्था ने एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसका विषय क्षेत्र काफी व्यापक था। शिशुओं के लिए पूर्व प्राथमिक, बालक-बालिकाओं के लिए प्राथमिक युवा, प्रौढ़ों के लिए साक्षरता और कौशल का प्रशिक्षण आदि अनेक बातें एक ही मंच पर कही-सुनी और सोची गई।

जहां विकास की पहली शर्त शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी खर्च होता है वह मानव पर खर्च होता है। एक कारखाने में मशीन लगाते हैं, उससे जो उत्पादन होता है, वह हमारे काम आता है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से हम एक प्रकार से मनुष्य पर कुछ ज्यादा खर्च करने, देश को एक ऐसा संसाधन देने की कोशिश करते हैं, जिससे विकास की गति को तीव्रता से आगे बढ़ाया जा सके। इसी उद्देश्य से देश के करोड़ों स्त्री-पुरुषों को साक्षर बनाकर उन्हें राष्ट्रीय विकास में भागीदार बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को लोक अभियान के रूप में प्रारंभ किया गया। नई शिक्षा नीति में 2030 तक संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने पर बल दिया गया है। यह सबके लिए विचार का विषय होना चाहिए कि शिक्षा और साक्षरता की कोशिश यह है कि हम अपने लोगों को व्यावहारिक हुनर सिखाएं। ऐसे हुनर, जिससे उन्हें उनके रोजमर्रा के जीवन में मदद मिले और वे अपने पैरों पर आसानी से खड़े हो सकें। लिखना और पढ़ना एक व्यावहारिक हुनर ही है। बगैर इस हुनर के जीवन जटिल हो जाता है। प्राथमिक शिक्षा बीच में छोड़ व्यक्ति निरक्षरता की दहलीज पर आ जाता है। समाज में उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है और व्यक्तिगत विकास के रास्ते में बाधाएं डाली जाती हैं। अब हमें तय करना है कि क्या शिक्षा और साक्षरता के एक ही मायने हैं?

दुनिया मेरे आगे

> **जो खेती करना जानते हैं, उनको रोज की आमद हो जाती है, वे भी रोटी, कपड़ा और मकान किसी तरह जुटा लेते हैं। फिर पढ़ने-लिखने से उन्हें कोई खास फायदा होगा, शिक्षा उनको नई जानकारी देगी और उससे उनको नई चीज मिलेगी, नई रोशनी मिलेगी, हम ऐसे सवालों का जवाब हां में नहीं दे पाते।**

मुश्किल डगर

केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है 'मेक इन इंडिया'। यह योजना दस वर्ष पूरे कर चुकी है। इस अभियान के कुछ घोषित लक्ष्य थे, जैसे विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 12-14 फीसद प्रतिवर्ष करते हुए 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के योगदान को 25 फीसद तक बढ़ाना और 2022 तक अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की दस करोड़ अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना। अब इन लक्ष्यों को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि मौजूदा गति और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यह लक्ष्य 2030 तक भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। हाल में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी वांछित नतीजे नहीं मिल सके हैं। पिछले एक दशक में देश में 'स्टार्टअप' की संख्या 350 से 1.48 लाख हो गई, पर आज भी इनमें 40 फीसद असफल हो रहे हैं। हमें शिक्षा, प्रशिक्षण और आजीवन सीखने के प्रयास कर कार्यबल के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना होगा, जो उद्योगों की जरूरतों और मांगों से मेल खा सके। भारत के पास श्रमिकों की बड़ी संख्या है, लेकिन श्रमिकों में उद्योगों की जरूरत के हिसाब से कौशल की कमी बड़ी चुनौती है।

– बलराम साहू, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

नई सुबह

जम्मू-कश्मीर की नब्बे विधानसभा सीटों के लिए तीन चरणों में मतदान बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हो गया। इसके लिए चुनाव आयोग, राज्य प्रशासन और अर्धसैनिक बलों के साथ जम्मू-कश्मीर राज्य की जनता बधाई की पात्र है। नागरिकों ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि हमारे यहां लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। जम्मू की 43 और कश्मीर की 47 सीटों पर क्षेत्र की जनता ने जबर्दस्त उत्साह का परिचय दिया। राज्य में राजनीतिक दलों पीडीपी, नैशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टियों ने सघन प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने पूरे संयम का भी परिचय दिया। जनता ने भी चुनावों में दिलचस्पी दिखाई। यह नई सुबह का संकेत है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां पर चुनाव सफल होना आसान कार्य नहीं था। विदेशी पर्यवेक्षकों ने भी चुनाव प्रक्रिया को देखा और उसकी सराहना की। परिणाम में कौन बाजी मारेगा इस पर सभी की निगाहें लगी हैं।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

प्रतिभा को पुरस्कार

मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर्ष की बात है। वर्ष 1976 में मिथुन ने हिंदी फिल्म 'मृगया' से सिनेमा जगत में कदम रखा था। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वे बड़े अभिनेता बन जाएंगे। अपनी पहली फिल्म के लिए ही उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया था। फिर 1982 में आई फिल्म 'डिस्को डांसर' से उन्हें खासी पहचान मिली और अपनी बेहतरीन अदायगी से सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर वर्षों राज किया। मिथुन को जनवरी 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और अभी उन्हें सत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। उनके अभिनय में विविधता रही है। पुरस्कार मिलने का समाचार सुन कर मिथुन भावुक हो उठे थे। उन्होंने सिनेमा के इस सबसे बड़े पुरस्कार को अपने परिवार और दुनिया को समर्पित कर दिया है।

– रविकांत कुमार, जम्मू

अनुचित कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर गैरकानूनी निर्माण मंजूर नहीं है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि बुलडोजर कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति के आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध होने को उसके संपत्ति गिराने का आधार नहीं बनाया जा सकता। अवैध निर्माण गिराने के बाद उसमें रह रहे उसके परिजनों को सड़कों पर जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो कि मानवीय नहीं है। अवैध निर्माण के संबंध में बिहार माडल को पूरे देश को अपनाना चाहिए। बिहार सरकार ने कई भ्रष्टाचारियों के अवैध भवनों में सरकारी विद्यालय एवं अन्य कार्यालय खोले हैं। बुलडोजर की कार्रवाई यह प्रमाणित करती है कि सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया है।

– हिमांशु शेखर, गया

www.readwhere.com

चिंतन

देश में अवैध ड्रग्स के डार्क नेटवर्क का खात्मा जरूरी

देश में मादक पदार्थ के काले कारोबार का डार्क नेटवर्क बड़ा से बड़ा होता गया है। यह इससे पता लगता है कि ड्रग्स की बड़ी खेप लगातार पकड़ी जाती रही हैं। अभी गुजरात एटीएस व दिल्ली एनसीबी ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक फैक्टरी से 1,814 करोड़ रुपये की कीमत का मेफेड्रोन (एमडी) मादक पदार्थ और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल जब्त किया। गुजरात के आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) और दिल्ली के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने ठोस तथा तरल रूप में कुल 907.09 किलोग्राम मेफेड्रोन बरामद किया। उधर, दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने लगभग 5,600 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ की जब्ती के मामले की जांच के सिलसिले में पंजाब के अमृतसर से 10 करोड़ की कोकीन बरामद की है। दो अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने शहर में मादक पदार्थ की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी, जिसमें 560 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 5,620 करोड़ रुपये है। यह पहली बार नहीं है जब इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़े गए हैं, इससे पहले मुंदरा पोर्ट से 21 हजार करोड़ रुपये की ड्रग्स समेत अनेक मौकों पर हजारों करोड़ रुपये के मादक पदार्थ पकड़े गए हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में वर्ष 2020 में 5.2 टन अफीम की चौथी सबसे बड़ी मात्रा ज़ब्त की गई थी और तीसरी सबसे बड़ी मात्रा में मॉर्फिन (0.7 टन) भी उसी वर्ष ज़ब्त की गई थी। भारत में ड्रग्स के अवैध कारोबार की जड़ें गहरी हैं और इसमें विदेशी एजेंसियां भी लिप्त हैं। भारत डेथ (गोल्डन) क्रीसेंट और डेथ (गोल्डन) ट्रायंगल के बीच स्थित है। इन दो क्षेत्रों से ड्रग माफियाओं द्वारा यहां हेरोइन तथा मेथामफेटामाइन जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है। डेथ (गोल्डन) क्रीसेंट में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं। डेथ (गोल्डन) ट्रायंगल में वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार शामिल हैं। चीनी माफियाओं से भी बढ़ावा मिलता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी, भारत में तस्करी की जाने वाली कुल अवैध नशीली दवाओं का लगभग 70 फीसदी हिस्सा होने का अनुमान है। मादक पदार्थ की लत से अनेक सामाजिक, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सरकार नशे के खिलाफ अभियान भी चला रही है, इसके बावजूद नशे की बेल बढ़ती ही जा रही है। विदेशी खुफिया ताकतें भी भारत में ड्रग्स के डार्क नेटवर्क को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास करती हैं। अमेरिका में नई घातक ड्रग्स ज़ोंबी दवा (फेंटानिल) के विषय में पता चला है। ड्रक्स नेटवर्क का कनेक्शन आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग व भ्रष्टाचार आदि से भी जुड़ा होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2018-25 की अवधि हेतु ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए योजना तैयार की है। यह योजना निवारक शिक्षा, जागरूक पीढ़ी, नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों की पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास पर केंद्रित है। नारकोटिक ड्रग्स के खिलाफ भारत संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन से भी जुड़ा है। डार्कनेट, क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन, हाईटेक, कोडिंग आदि के प्रयोग के चलते ड्रक्स के अवैध कारोबार को क्रेक करना मुश्किल रहता है। इसके बावजूद सरकार व पुलिस के लिए अवैध ड्रग्स के डार्क नेटवर्क का खात्मा जरूरी है, ताकि युवा पीढ़ी को नशे के जाल में फंसने से बचाया जा सके।

अंधविश्वास की जड़ें अभी भी गहरी है

विचार
डॉ. संजय शुक्ला

पिछले दिनों उत्तरप्रदेश के हाथरस जिले के रसगांव स्थित एक निजी स्कूल के तरक्की के लिए स्कूल के हास्टल के ही एक 11 साल के बच्चे की बलि चढ़ाने की खबर प्रकाश में आई। आश्चर्यजनक तौर पर इस घटना का अंजाम किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि उस स्कूल के प्रबंधक, प्रिंसिपल और शिक्षकों ने मिलकर दिया। विचारणीय है कि अंधविश्वास को खत्म करने के लिए जहां शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है वहीं जिनके जिम्मे शिक्षा की जवाबदेही है उन्होंने ही अंधविश्वास को बढ़ाने का कृत्य कर डाला। बहरहाल अंधविश्वास की जड़ें पूरे देश में फैली हुई है और इसमें सभी धर्मों और समाज के लोग भरपूर खाद-पानी डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के एक गांव में एक बच्ची को जादू टोने से बीमार करने के शक में दो महिलाओं सहित चार लोगों की निर्मम हत्या की स्याही सूखी भी नहीं थी कि नक्सल प्रभावित सुकमा के एक गांव में जादू- टोना से बच्चों को बीमार करने की आशंका के चलते तीन महिलाओं सहित पांच लोगों को लाठियों से पीट-पीट कर मौत की नींद सुला दिया। देश आज भी 2018 में दिल्ली का बुराड़ी कांड नहीं भूला है जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों ने अंधविश्वास के फेर में अपनी जान दे दी। देश के सबसे साक्षर राज्य केरल में अंधविश्वास के चलते 2 महिलाओं की बलि ने यह साबित कर दिया है कि अंधविश्वास जैसे अवैज्ञानिक मान्यता की जड़ें इक्कीसवीं सदी के भारत में अभी भी गहरी है। आश्चर्यजनक तौर पर इस कृत्य को एक डॉक्टर और उसके पत्नी ने आय बढ़ाने के लिए एक तांत्रिक के जरिए अंजाम दिया था।

विचारणीय है कि शिक्षा और विज्ञान के व्यापक विकास और प्रसार के बावजूद भारतीय समाज में टोने-टोटके और भूत-प्रेत का अस्तित्व मानने वालों की कमी नहीं है। विडंबना यह है कि छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में महिलाओं को डायन या टोनही ठहराने या किसी व्यक्ति को तंत्र-मंत्र के नाम पर प्रताड़ित करने की घटनाएं आए दिन घटित हो रही है। अंधविश्वास के प्रति बढ़ते विश्वास के चलते ही कई परिवारों को जादू-टोना के आरोप में सामाजिक बहिष्कार का अभिशाप भी झेलना पड़ रहा है। समाज में जारी पुरुष प्रधान व्यवस्था के चलते अंधविश्वास का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं हो रहीं हैं जो डायन या टोनही का कलंक लेकर तिरस्कृत जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आधुनिक युग मे अंधविश्वास का पनपना सभ्य समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। आश्चर्यजनक तौर पर अशिक्षित या ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति ही नहीं बल्कि शिक्षित और शहरी तबका भी जादू - टोना, झाड़-फूंक या ताबीज-गंडे का सहारा ले रहा है। आम भारतीयों की बात करें तो वे रोजमर्रा के टोटके जैसे बिल्ली का रास्ता काटने पर रास्ता बदलने, कुत्ते और बिल्ली के रोने और बिल्लियों के झगड़ने पर अनिष्ट की आशंका, छींक आने पर काम में बाधा, आंख फड़कने पर लाभ या हानि का टोटका, व्यवसायिक संस्थानों में नीबू - मिर्च लटकाने, बच्चों के नजर उतारने, परीक्षा में सफलता पाने के लिए टोटके अपनाने और शगुन-अपशगुन जैसे अनेक रूढ़िवादी अंधविश्वास का शिकार हैं। दरअसल ये सभी विचार या टोटके ही व्यक्ति में अंधविश्वास का बीजारोपण करते हैं जिससे हर लिहाज में बचा जाना चाहिए। भारत में अंधविश्वास पनपने का मूल कारण यहां के लोगों खासकर महिलाओं का बहुत ज्यादा धर्मभीरु होना है जिसके चलते लोग ठगी का भी शिकार हो रहे हैं। मीडिया में आए दिन महानगरों से लेकर छोटे शहरों से तांत्रिकों के फेर में फंसकर अनेक परिवारों द्वारा लाखों रुपए लुटाने की खबरें आती रहती है। विडंबना यह कि शिक्षित तबका भी बीमारी, नौकरी, आर्थिक समस्या, गृह क्लेश, दांपत्य सुख और निःसंतानता जैसी समस्याओं के लिए जादू-टोना या तंत्र-मंत्र और बलि जैसे अंधविश्वास का सहारा ले रही है।

विचारणीय है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां विभिन्न दलों के राजनेता बहुतों के आदर्श होते हैं जिनका लोग अनुसरण करते हैं लेकिन हमारे राजनेता सबसे ज्यादा अंधविश्वासी नजर आते हैं। हमारे नेता चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने, शपथ लेने अथवा पदभार संभालने के लिए मुहूर्त देखने के अंधविश्वास पर निर्भर हैं यहां तक कि उनमें पितृपक्ष में अनेक नवीन फैसलों या राजनीतिक निर्णयों को भी टालने की प्रवृत्ति होती है। सरकारी बंगलों और कार्यालयों में वास्तुदोष और ग्रहदोष के नाम पर सरकारी पैसों से तोड़ फोड़ कराना नेताओं का आम शगल बन चुका है। अमूमन सभी राजनीतिज्ञ किसी न किसी ज्योतिषी या तांत्रिकों के फेर में रहते हैं जिसका अनुसरण उनके समर्थक या आम जनता करते हैं। राजनीतिज्ञों द्वारा सत्ता पाने या अपने विरोधी को राह से हटाने के लिए तांत्रिकों के शरण में जाने या तंत्र-मंत्र का सहारा लेने की खबरें आम है। पाठकों के स्मरण में होगा कि स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और स्व. पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में चंद्रास्वामी जैसे ज्योतिष और तांत्रिकों की खूब तूती बोलती थी। अलबत्ता इसके अलावा अनेक शीर्ष नेताओं के विभिन्न धर्म गुरूओं और उनके आश्रमों के पीछे अगाध आस्था के पीछे प्रमुख वजह सत्ता के लिए तांत्रिक क्रिया, पूजा-अनुष्ठान या कथित ग्रह शांति के उपाय ही है। दूसरी ओर सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि नौकरशाह, जज, इंजीनियर, उद्योगपति और सेलेब्रिटी भी वास्तुदोष जैसे अंधविश्वास के गिरफ्त में हैं।

बहरहाल देश में बढ़ते अंधविश्वास के लिए हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अलावा अशिक्षा, बीमारी और गरीबी जैसे कारण जिम्मेदार हैं। आज भी वनांचलों और दुर्गम ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुंच बेहद लचर है फलस्वरूप इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग बीमार होने या सर्पदंश का शिकार होने पर गांव के बैगा-गुनिया या ओझाओं के झाड़-फूंक का सहारा ले रहे हैं। समाज का एक तबका गरीबी के चलते शिक्षा और इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ है लिहाजा वह अंधविश्वास के फेर में उलझ रहा है। देश में मानसिक रोगियों की तदाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है लेकिन अशिक्षा और अज्ञानता की वजह से लोग मानसिक रोगों के लक्षणों से अनजान रहते हैं और झाड़-फूंक या तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं। विडंबना यह कि इस क्रिया में तांत्रिक या बैगा-गुनिया द्वारा पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है अथवा गरम सलाखों से दागा जाता है अथवा उसे जंजीरों से बांधा जाता है। परिजनों को मनोरोग के लक्षण पहचान नहीं होने और मानसिक रोगियों के उचित समय पर उपचार नहीं मिलने की वजह से मनोरोगियों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें लगातार आती रहती हैं।

इसी साल जुलाई में उत्तरप्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक सत्संग में मचे भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो गई वहीं सैकड़ों लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। यह घटना कथित 'भोले बाबा' के पैरों की धूल लेने की होड़ में घटित हुई थी। दरअसल आज लोग चमत्कार की आस में दवा और दुआ को परे रखकर बाबाओं के शरण में जा रहे हैं फलस्वरूप समाज में अंधविश्वास और पाखंड दिनों-दिन बढ़ रहा है। विडंबना यह कि देश की युवा पीढ़ी भी अंधविश्वास के चक्रव्यूह में उलझ रहे हैं जो देश और समाज के लिए चिंताजनक है। युवाओं का धार्मिक होना एक सुखद संकेत है लेकिन पाखंड और अंधविश्वास के जंजाल में उलझना उनके भविष्य के राह में बाधक ही है। युवाओं को आस्था और अंधविश्वास के फर्क को समझना होगा। धार्मिक आस्था जहां लोगों में साकारात्मकता लाती है वहीं अंधविश्वास से नाकारात्मक भाव का संचार होता है। आध्यात्म में जहां विज्ञान और मनोविज्ञान है वहीं अंधविश्वास पूर्ण रूपेण अवैज्ञानिक, अतार्किक और पाखंड के बुनियाद पर टिका है।

अंधविश्वास के बाजार को बढ़ावा देने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया भी काफी हद तक जवाबदेह हैं। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहां अंक ज्योतिष और कुंडली के नाम पर टोटके बताने वाले कार्यक्रम परोस रहे हैं वहीं अनेक चैनल भूत - प्रेत के नाम पर सनसनी फैलाने वाले कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं जिसका बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इन चैनलों पर ऐसे कथावाचकों या संतों व बाबाओं के धार्मिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जिसमें वे दर्शकों को विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने या परीक्षा में सफलता के लिए टोटके बताते हैं। अलबत्ता यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सोशल मीडिया अंधविश्वास और डर फैलाने का बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। इस मीडिया में तो बाल और नाखून कटवाने के दिन वार निश्चित करते हुए बीमारी से लेकर बेरोजगारी, आर्थिक उन्नति, पारिवारिक क्लेश से मुक्ति के तमाम टोटके उपलब्ध हैं। आलम यह कि वास्तुदोष और शुभ - अशुभ के नाम पर अनेक पेड़ - पौधों को घरों में लगाने और घर से बाहर करने के तमाम अंधविश्वास मौजूद हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

विमर्श

डॉ. रमेश ठाकुर

आपदा से निपटने में सरकारी तंत्र पहले से हो रहा बेहतर

कुदरती आपदाएं कब आ जाएं, कुछ नहीं पता? देश में पूरे साल कहीं न कहीं कुदरत का रौद्र रूप अपना कहर बरपाता रहता है। बिहार का मिथिला कहा जाने वाला क्षेत्र भी इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। असम में तेज बारिश ने कमोबेश कुछ वैसी ही स्थिति उत्पन्न की हुई है, जैसी बिहार में बनी है। सवाल उठता है कि इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए हमारा सिस्टम पहले से कितना बेहतर हुआ या आत्मनिर्भरता के शोर में कुछ फीका पड़ गया है? आत्मनिर्भता की जागरूकता के लिए केंद्र व राज्य सरकारों ने बीते एक दशक से अभियान छेड़ा हुआ है कि कुदरती आपदाओं से निपटने के लिए सरकारी तंत्र के अलावा आमजन को भी आगे आना चाहिए, सिर्फ एनडीआरएफ और अन्य राहत-बचाओ दलों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। महज पिछले वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें, तो देश में अचानक आई आपदाओं से निपटने के लिए हमारा तंत्र पूरी तरह एनडीआरएफ पर निर्भर रहता है। क्योंकि ये विभाग भरोसे का प्रतीक बन गया है। आपदाएं किसी को बताकर नहीं आती? पर, अब ऐसे बहुत से साइंटिफिक आविष्कार हमारे पास मौजूद हैं जिससे हम कम से कम प्राकृतिक आपदाओं का समय रहते आकलन और बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। साल-2005 के बाद से सरकारी स्तर पर हालात बदले और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अथवा एनडीआरएफ का गठन किया गया।

इस एनडीआरएफ के गठन के बाद से प्राकृतिक ही नहीं, मानव जनित आपदाओं के प्रबंधन की दशा भी बेहतर हुईं। अब संकट के समय में एक अलग अतिरिक्त बल है जिसके पास अलग-अलग तरह के संकटों से निपटने की क्षमता और दक्षता दोनों है। बहरहाल, एनडीआरएफ और इनके जैसी संस्थाओं को और मजबूती प्रदान करने की दरकार है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तात्कालिक मदद और दीर्घकालिक सहायता दोनों चाहिए होती है। दीर्घकालिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के पास समय होता है। पर, जो तात्कालिक मदद चाहिए, वह इतना त्वरित और प्रभावी होनी चाहिए कि आपदा का जनजीवन से न्यूनतम ही असर हो। इसमें न केवल उनके जान माल की रक्षा बल्कि कई बार उनके लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था भी देनी होती है। इसीलिए एनडीआरएफ को त्वरित गति से सक्रिय करने के लिए केंद्र ने कई अहम निर्णय लिए हैं जो काबिले तारिफ हैं। जब किसी संस्था के सामने ये लक्ष्य होता है कि हम आपदा में किसी एक की भी जान नहीं जाने देंगे, तो उनकी कार्य करने की कार्यशैली अलग होगी। यह रक्षा दलों में जो आत्मविश्वास पैदा करता है उसके कारण उनकी सक्रियता ज्यादा तेज और जीवनोपयोगी हो जाती है। केरल के वायनाड में बादल फटने से हुई भारी बारिश के बाद जो तबाही आई, उसमें एनडीआरएफ का राहत एवं बचाव कार्य सभी ने देखा। वहीं, केंद्र सरकार ने भी बिना राजनीतिक भेदभाव किए लोगों को बचाया और प्रत्येक परिस्थितियों पर नजर रखी और हर संभव मदद पहुंचाई। गौरतलब है कि आपदाओं के वक्त कई बार ऐसा होता है कि घटना इतनी बड़ी हो जाती है कि अकेले एनडीआरएफ नहीं संभाल सकता। जैसे, गुजरात भूकंप, त्रिपुरा या केरल में आई बाढ़। उस समय पहले की तरह सैन्य बलों और स्थानीय राहत एवं बचाव कर्मियों के बीच समन्वय करते हुए एनडीआरएफ इस काम को अंजाम देता है।

यही कारण है कि गृहमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आपदाओं को लेकर अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया जाए, ताकि ऐसी स्थितियों में आमजन भी एनडीआरएफ कर्मी का सहयोग करें। केंद्र सरकार ने हाल ही में एनडीआरएफ की पोशाक में बदलाव किया है। भगवा रंग में दिखने लगे हैं अब कर्मी। आपदाओं के वक्त इनके आने से लोग समझ जाते हैं कि अब हालात नियंत्रण में आ जाएंगे। यही भरोसा किसी भी आपदा रक्षा बल की ताकत होता है। फिर भी 140 करोड़ के देश में प्राकृतिक से अधिक मानव निर्मित आपदाएं आती ही रहती हैं जिसमें 16,000 जवानों वाले एनडीआरएफ ने जिस प्रकार से अपनी मदद से मौजदूगी दर्ज कराई है उसके कारण आज भारत आपदाओं से बचाव में आत्मनिर्भर दिखने लगा है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी मंत्रालय का गठन कर विज्ञानिक सूचनाओं का सहारा लेकर जीरो कैजुअल्टी के लक्ष्य की ओर मजबूती से अपना कदम बढ़ाया है। निश्चित रूप से 20 साल से कम समय एनडीआरएफ ने आपदा में बचाव का जो रिकॉर्ड बनाया है, उसमें वर्तमान केंद्र सरकार की स्पष्ट नीति और बल को सशक्त बनाने के लिए किया जाने वाला उपाय शामिल है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

निंदा का परित्याग

संकलित
दर्शन

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में निर्वहन के लिए व्यक्ति के सामाजिक गुणों का अत्यंत महत्व है। गुणी व्यक्ति को प्रत्येक जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। संसार के प्रत्येक प्राणी में कुछ गुण तो कुछ अवगुण पाए जाते हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो दूसरे के अवगुणों को ही देखते हैं। वे किसी भी सकारात्मक पक्ष में नकारात्मकता देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। प्रायः ऐसे लोगों में निंदा की प्रवृत्ति पाई जाती है। वे ऐसा करके खुद को समाज में श्रेष्ठ एवं दूसरे को नीचा साबित करना चाहते हैं। निंदा एक नशे की भांति है, जो एक बार इसका आदी हो गया, वह दिन-प्रतिदिन इसके पाश में जकड़ता चला जाता है। मनीषियों ने निंदा को दुर्व्यसन के समान माना है, जो निंदा करने वाले व्यक्ति को अंदर ही अंदर नैतिक रूप से समाप्त करती रहती है। एक बार एक आचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। शिक्षा प्राप्ति के दौरान एक शिष्य अन्य शिष्यों की ओर संकेत करते हुए आचार्य से कहने लगा कि 'वे अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों को कार्य करना ही नहीं आता।' आचार्य बोले, 'तुमको छोड़ अन्य सारे शिष्य सही से कार्य कर रहे हैं।' इस पर शिष्य असहज हो गया। उसने आचार्य से पूछा, 'वह कैसे?' आचार्य बोले, 'क्योंकि वे लोग अपने कार्य में संलग्न हैं, किंतु तुम अपने कार्य पर ध्यान न देकर, दूसरों के कार्य की निंदा करने में अपने समय की बर्बादी कर रहे हो।'

एक सत्संग ऐसी भी

संकलित
प्रेरणा

एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। सेठजी के घर एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। तोता एक दिन पूछता हैं कि सेठजी आप रोज कहाँ जाते है। सेठजी बोले कि, सत्संग में ज्ञान सुनने जाते है। तोता कहता है, सेठजी संत महात्मा से एक बात पूछना कि में आजाद कब होऊंगा। सेठजी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते है कि महाराज हमारे घर जो तोता है उसने पूछा हैं की वो आजाद कब होगा? संत जी ऐसा सुनते हीं बेहोश होकर गिर जाते है। घर आते ही तोता सेठजी से पूछता है कि सेठजी संत ने क्या कहा। सेठजी कहते है तेरी आजादी का पूछते ही वो बेहोश हो गए। दूसरे दिन सेठजी सत्संग में जाने लगते है तब तोता पिंजरे में जानबूझ कर बेहोश होकर गिर जाता हैं। सेठजी उसे मरा हुआ मानकर जैसे हीं उसे पिंजरे से बाहर निकालते है, तो वो उड़ जाता है। सत्संग जाते ही संत सेठजी को पूछते है कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना अब वो कहाँ हैं। सेठजी कहते हैं, हाँ महाराज आज सुबह-सुबह वो जानबुझ कर बेहोश हो गया , मैंने देखा की वो मर गया है इसलिये मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ गया। तब संत ने सेठजी से कहा की देखो तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह-माया के पिंजरे में फंसे हुए हो और उस तोते को देखो बिना सत्संग में आये मेरा एक इशारा समझ कर आजाद हो गया।

अंतर्मन

आज की पाती

स्वदेशी की राह

महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चलाकर देश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाकर न केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा इनकी होली जलाने तक ही सीमित रखा, बल्कि उद्योग कलाकारी, भाषा, शिक्षा, वेशभूषा आदि सब पर स्वदेशी का रंग चढ़ा दिया था। भारत के गुलाम होने का आधार था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना। देश की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, कलाकृति और प्राचीन कौशल की राह देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा करने में सरलता पैदा करेगी। अगर हम इतिहास के पन्नों पर नजर दौड़ाएं तो यह पता चलेगा कि स्वदेशी ही हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम का मूल मंत्र रहा। हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे उत्पाद विदेशी मंडियों की शान बनकर विदेशियों तक पहुंच रहे हैं। *– प्रवीण ठाकुर, अंबिकापुर*

ट्रेंड

मार्शलों की ही बात सुनी

आतिशी जी और सौरभ जी ने आज जो ड्रामा किया ये वो उसी दिन कर सकते थे,जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ हुई और उपराज्यपाल महोदय के साथ चाय पान हो रहा था वो भी एलजी हाउस में ही..!! उपराज्यपाल महोदय, आपने बस मार्शलों की बात सुनी। कोई रास्ता निकल सके तो हम बहुत आभारी रहेंगे।

-मनोज तिवारी, भाजपा सांसद

महंत की बयानबाजी

गाजियाबाद में डासना देवी मन्दिर के महंत ने इस्लाम मज़हब के खिलाफ फिर से नफरती बयानबाजी की जिससे पूरे इलाके में अशान्ति व तनाव की स्थिति है। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई की गयी किन्तु मूल दोषी भयमुक्त।

-मायावती, बसपा प्रमुख

मां को श्रद्धांजलि

आज, हमारी मां हमें छोड़कर मोक्ष यात्रा पर निकल गई। उनकी कमी जीवन में किसी तरह पूरी नहीं की जा सकेगी। उनके बताए रास्ते पर हम चल पाएं, ये ही उस पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि होगी।

- अनिल अग्रवाल, उद्योगपति

स्मार्ट निष्पादन

व्यवसाय निरंतरता का खेल है! हर दिन मैं अपने दिमाग को अधिक तेज सोचने और बेहतर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करता हूं। यह सिर्फ कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट निष्पादन के बारे में है।

-डा. विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर

करंट अफेयर

भारतीय चिकित्सकों के लिए 'ग्रीन कार्ड' में लाए तेजी

अमेरिका में भारतीय मूल के चिकित्सकों के एक प्रमुख संगठन के अध्यक्ष ने आगामी चुनाव के बाद सरकार बनाने वाले अमेरिकी प्रशासन से आव्रजन एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधारों को प्राथमिकता देने और भारत के चिकित्सा पेशेवरों के लिए 'ग्रीन कार्ड' जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया है। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। 'अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन' (एएपीआई) के अध्यक्ष डॉ. सतीश कथुला ने साक्षात्कार में कहा कि सभी लोगों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना, आव्रजन और वीजा, चिकित्सा में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, विविधता और भेदभाव का विरोध- ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अगले 'व्हाइट हाउस' (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) प्रशासन को प्राथमिकता देनी चाहिए। एएपीआई 1982 में स्थापित किया गया था। यह अमेरिका में भारतीय मूल के 1,20,000 से अधिक चिकित्सकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा जातीय चिकित्सा संगठन है। कथुला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे कई चिकित्सक हैं जिनके पास 15-20 साल से अमेरिका में रहने के बाद भी एच-1बी कार्य वीजा ही है।

ऑफ बीट

पश्चिम आस्ट्रेलिया में एक लाख साल पहले हुई थी वर्षा

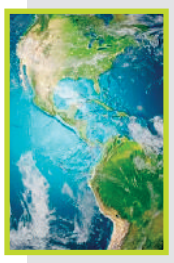

पृथ्वी की सतह का लगभग छठा हिस्सा कुछ इस तरह की स्थलाकृति से ढका हुआ है, जिससे आप सब अपरिचित हो सकते हैं और वह चूना पत्थर से बना क्षेत्र है। यह प्राकृतिक मूर्तिकला पार्कों की तरह हैं, जिनमें हज़ारों वर्षों में पानी के प्रभाव के कारण काफी लंबे समय में बनी गुफाएं और भूभाग शामिल हैं। कार्स्ट (चूना पत्थर की स्थलाकृति) वाले क्षेत्र सुंदर और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण हैं। वे पृथ्वी के अतीत के तापमान और नमी के स्तर का रिकॉर्ड भी बताते हैं। हालांकि, यह पता लगाना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि कार्स्ट असल में कब बने। साइंस एडवांस में आज प्रकाशित हमारे नए अध्ययन में, हम इन रहस्यमय स्थलाकृतियों की प्राचीनता का पता लगाने का एक नया तरीका प्रदर्शित कर रहे हैं, जो हमें हमारे ग्रह के अतीत को और अधिक विस्तार से समझने में मदद करेगा। कार्स्ट को पदार्थ के अपरदन द्वारा परिभाषित किया जाता है। आज हम जो बड़ी-बड़ी चट्टानें और गुफाएं देखते हैं, वे अतीत की वर्षाकालीन अवधि के दौरान पानी में घुलने के बाद बची रह गई हैं। यही कारण है कि उनकी आयु निर्धारित करना कठिन है। आप किसी चीज़ के गायब होने की तिथि कैसे निर्धारित करते हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।